



ISSN 2347-369X

panacea INTERNATIONAL Research Journal

A Quarterly Bilingual Inter-disciplinary
Peer Reviewed Referred Journal

UGC Approved Peer Reviewed Referred Journal Sr. No. 40939

Volume 13, no. 3-4

January-March and April-June 2026 Joint Issue



Honorary Editor-in-Chief
Dr G L Sharma

PANACEA Research Foundation

www.journalpanacea.com

ISSN 2347-369X

PANACEA INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL

(A Quarterly Bilingual Inter-disciplinary Peer Reviewed Referred journal)

पैनासीआ इन्टरनेशनल रिसर्च जर्नल
(त्रैमासिक अन्तरअनुशासनात्मक द्विभाषी शोध-पत्रिका)

Volume No. 13, No. 3-4 January-March and April -June 2026 Joint Issue

Honorary Editor- in - Chief

Dr. G L Sharma

Editor

Dr. Avdhesh Kumar Sharma

Co-Editor

Dr. Yogesh Kumar Sharma

Prof. N K Gupta, Astha Sharma

Editorial Board & Editorial Review Committee

Ramanand Rathi, Dr. Rekha Yadav, Prof RP Pathak, Jayant Chaubey, Vasundhara Sharma
Dr. Satish Chand Mangal, Dr. Pranu Shukla, Dr. Gaurav Singh, Dr. Bhavesh Kumar
Singhwal Vedant Garg, Dr. Lokendra singh, Dr. Rakesh Kumar, Dr. Surendra Kumar Dhaka,
Dr. Subhash Misra, Dr. Pragya Sharma Dr. Yajuvendra Bansal, Dr. Prashant Gurjar,
Ramakant Dixit.

Editorial Advisory Committee

Dr. Rajesh Kumar Sharma, Prof. Neeraj Sharma Dr. Keerti Singh, Dr. Ayushman Goswami
Dr. Usha Sharma, Dr. Sunita Bhargava, Dr. Kailash Chand Saini Dr. Sanjay Tiwari, Ashok
Kumar Sharma, Dr. Rajesh Kumar Kaswan, Dr. CM Meena, Dr. Surendra Kumar Dhaka,
Dr. Rahil Ahmed, Dr. Dharmendra Sharma, Dr. Bhupendra Singh, Dr. Ajeet Kumar Jain,
Dr. Satish Chand Saini, Dr. Gomti Sankhala, Dr. Mukesh Kumar Sharma, Dr. Ashok Kumar
Bairwa, Jitendra Sharma, Dr. Lalit Sharma, Dr. Roopram Yadav.

Publisher

PANACEA RESEARCH FOUNDATION

“Shanti-Kuteer” 81, Vishvesariya vistar, Triveni Nagar, Jaipur - 302018

panaceairj@gmail.com; Mob.+91 - 9829264747.

www.journalpanacea.com

Index

S.No.	Paper Title	Author Name	Page No.
1.	आत्मनिर्भर भारत में महिला सशक्तिकरण एवं उद्यमिता के अवसर एवं चुनौतियां	मनोज कुमार सैनी	1-4
2.	आत्मनिर्भर भारत रोजगार सृजन एवं कौशल विकास के आधार एवं चुनौतियां	डॉ. मोहन सिंह	5-11
3.	प्राचीनकालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020	डॉ. गौरव सिंह	12-17
4.	आत्मनिर्भर भारत: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में	डॉ. सतीश चन्द मंगल रमाकान्त दीक्षित	18-23
5.	भारत में युवा सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका	डॉ. नीरज कुमार तिवारी	24-27
6.	भारत में कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण	डॉ. बृजलता चौधरी	28-31
7.	आत्मनिर्भर भारत: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपेक्ष्य में	नलिनी डॉ. गौरव सिंह	32-37
8.	भारत में कौशल विकास, युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण	नरेश कुमार माली	38-46
9.	शिक्षकों के व्यवहार का विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन	नवरत्न सिंह	47-52
10.	भारत में कौशल विकास, युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण	मनीष शर्मा	53-57
11.	शिक्षक शिक्षा एवं कौशल विकास : एक समग्र सिद्धांत	पूजा	58-60
12.	वर्तमान संदर्भ में भारत के विकास में युवाओं की भूमिका: विभिन्न आयाम	राजेश देव	61-68
13.	आत्मनिर्भर भारत में महिला उद्यमिता का योगदान एवं प्रासंगिकता	मुकलेश माली	69-74
14.	शिक्षकों के कौशल विकास का महत्व	भूपेंद्र सिंह गुर्जर	75-81
15.	शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रभाव	डॉ. मीरा कुमारी धाकड़	82-86

S.No.	Paper Title	Author Name	Page No.
16.	शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं रोजगार सृजन : एक समग्र अध्ययन	रोहित	87-89
17.	कला जगत में रोजगार सृजन के अवसर	भावेश गर्ग	90-95
18.	महिला सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता	श्री संजय कुमार	96-102
19.	आत्मनिर्भर भारत: रोजगार सृजन और कौशल विकास में अवसर और चुनौतियाँ	कुलदीप सिंह	103-106
20.	उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की भूगोल पाठ्यपुस्तकों में निहित चित्रात्मक सामग्री का विश्लेषणात्मक अध्ययन	सरोज कुमारी डॉ. गौरव सिंह	107-110
21.	शिक्षक शिक्षा एवं कौशल विकास राष्ट्र निर्माण के सशक्त माध्यम	अमित कुमार डॉ. निर्मला सिंह राठौड़	111-113
22.	भारत में शिक्षक शिक्षा में कौशल विकास की संभावनाएँ	डॉ. मुकेश कुमार शर्मा	114-119
23.	माध्यमिक स्तर के अध्यापकों में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं दृष्टिकोण का अध्ययन	डॉ. छैलबिहारी	120-126
24.	21 वीं सदी की शिक्षा प्रणाली में भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता	डॉ० दीपिका शर्मा दीपांशु सांवरिया	127-133
25.	Constructive Education as the Backbone of Atmanirbhar Bharat: Rethinking Soft Skill Development in NEP 2020	Rekha Karnath Unny Dr. Gaurav Singh	134-138
26.	Teacher Education and Skill Development	Dr. Meghaben H. Patel	139-141
27.	Opportunities for Employment Generation in the Field of Arts	Dr. Roshankumar. R. Patel	142-143
28.	Communication and Classroom Management Skills for Inclusive Teaching	Axina Geo Augustine Dr. Gaurav Singh	144-148
29.	Value-Based Moral Teacher Education as the Foundation of Character Building	Dr. Vinod Kumar H. Pandya	149-151
30.	Career Opportunities in Visual Arts – An Overview	Dr. Meenakshi Thakur	152-155
31.	Educational Technology, Multi-Media Program and Its Opportunities for Employment Generation.	Jagrutiben B. Patel Dr Gitaben D Dave	156-157

S.No.	Paper Title	Author Name	Page No.
32.	Teacher Education and Skill Development: A Catalyst for Transformative Learning in the 21st Century	Uddhav Kumar	158-160
33.	Environmental Conservation in Indian Knowledge System	Mrs. Anjana Pareek	161-163
34.	A Study on Students Awareness and Satisfaction Towards Mobile Commerce	Dr. Deepika Sharma Ayasha Badgoti	164-168
35.	Indian Knowledge Systems and the Evolving Role of the Teacher	Mrs. Rukmani Sharma Dr. Mukesh Kumar Sharma	169-174
36.	Geography and Indian Knowledge System (IKS): An Interdisciplinary Perspective for Sustainable Development and Environmental Understanding	Mrs. Rukmani Sharma Ms. Urmila Saini	175-179
37.	Impact of Foreign Universities on Indian Higher Education: An Analytical Study	Dr. Bijendra Singh	180-182
38.	Cross-Cultural Dimensions of Kingship in Early Medieval Kāmarūpa: Bloodline, Ritual Desire, and Sacred Power	Seema Bai Chandaniya Dr. Manju Sharma	183-188
39.	Different Aspects Affecting the Growth and Development of Autistic Children Under Three Years of Age: A Multidimensional Analysis of Biological, Cognitive, Educational, and Environmental Factors	Cristeena Sujith Dr. Gaurav Singh	189-191

आत्मनिर्भर भारत में महिला सशक्तिकरण एवं उद्यमिता के अवसर एवं चुनौतियां

मनोज कुमार सैनी

प्राचार्य, महात्मा गांधी कॉलेज, महवा, दौसा, राजस्थान

सारांश

आत्मनिर्भर भारत के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महिलाओं के योगदान का सबसे प्रभावित तरीका उनका आर्थिक विकास करना ही है। महिला उद्यमिता देश को आत्मनिर्भर बनाने का अहम पहलू है। इससे रोजगार के अवसर जुटाकर अर्थव्यवस्था तो मजबूत होती है, महिलाओं का भी सामाजिक और व्यक्तिगत दृष्टि से उत्थान होता है। इस लेख में महिला उद्यमियों के महत्व उनके सामने आने वाली चुनौतियों, भारतीय अर्थव्यवस्था में उनकी अहम भूमिका और आत्म निर्भर भारत के निर्माण में उनके योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया है। भारत की आर्थिक नीतियों में हमेशा से ही खास तौर से महिलाओं समेत गरीब हाशिये के लोगों और गरीब तबकों के लोगों के विकास पर जोर दिया गया है। सरकार की योजनाओं में सामाजिक लामबंदी और पूंजी निर्माण सामुदायिक उद्यमिता तथा समुदाय के नेतृत्व में

उत्पाद और उत्पादकता विकास के महत्व को रेखांकित किया गया है। भारत में नीति निर्माताओं और योजनाकारों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास में महिलाओं की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून 2022 उद्यमी भारत का शंखनाद किया जो उद्यमिता के महत्व और इसकी क्षमता को रेखांकित करता है। पिछले दो वित्त वर्ष कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से ग्रस्त रहे। इस वैश्विक महामारी की वजह से अन्य क्षेत्रों की तरह ही स्वरोजगार करने वालों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार ने इस स्थिति से उबरने के लिए एक समग्र नजरिया अपनाया जिसके सकारात्मक संकेत दिखाई देने लगे हैं।

मुख्य शब्द – आत्मनिर्भर भारत, वैश्विक महामारी, पूंजी निर्माण, सामुदायिक उद्यमिता, अर्थव्यवस्था।

प्रस्तावना

महिला उद्यमियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और विभिन्न उद्योगों में उन्हें पहचान और मान्यता भी मिल रही है। रोजगार के नए अवसर जुटाने और सकल घरेलू उत्पादन बढ़ाने तथा गरीबी दूर करने और सामाजिक समावेशन के माध्यम से महिलाएं उद्यमशीलता और आर्थिक विकास से जुड़ी गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान कर रही हैं। सरकार महिला उद्यमिता का महत्व समझती है और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की कई पहल कर रही है। एक अध्ययन के अनुसार महिला उद्यमियों को बढ़ावा

देने से उद्यमों की सफलता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने से जुड़े विभिन्न पहलुओं में आकांक्षा, कौशल और अनुभव, परिवार का समर्थन बाजार (बिक्री) संभावना, स्वतंत्रता, सरकारी सहायता और कार्य संपन्न करने का संतोष आदि शामिल हैं।

वर्तमान परिवेश में महिला उद्यमशीलता की अवधारणा का विश्लेषण और व्याख्या करना और भारतीय उद्यमियों के समक्ष चुनौतियां और विशेष पहलुओं की व्यापक समीक्षा करना तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमियों की भूमिका और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनके योगदान पर

विशेष ध्यान देना जरूरी है। महिला उद्यमी वही है जो अपना उद्यम शुरू करने, उसकी व्यवस्था संभालने और उसके लिए वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करने के सभी दायित्व निभाती है। भारत सरकार के अनुसार महिला उद्यमी होने के लिए उद्यम की वित्तीय भागीदारी में कम से कम 51 प्रतिशत योगदान होना आवश्यक है। इस तरह प्रमुख वित्तीय भागीदारी होने पर ही वह महिला उद्यमी की श्रेणी में मानी जाएगी।

आत्मनिर्भरता में महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र बनाना है, जिससे भी अपने निर्णय स्वयं ले सकें और देश की प्रगति में सक्रिय योगदान दे सकें।

आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है— ऐसा भारत जो हर क्षेत्र में स्वयं सक्षम और मजबूत हो, लेकिन क्या यह संभव है जब देश की आधी आबादी यानी महिलाएं पीछे रह जाएं?

बिल्कुल नहीं, इसलिए महिला सशक्तिकरण आत्मनिर्भर भारत की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। महिला सशक्तिकरण का मतलब केवल महिलाओं को अधिकार देना नहीं, बल्कि उन्हें इतना सक्षम बनाना है कि वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं से कर सकें, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें और समाज में सम्मान के साथ जी सकें। 'एक सशक्त महिला एक सशक्त परिवार और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती है।'

महिला सशक्तिकरण का अर्थ

महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार देना नहीं है बल्कि उन्हें इस स्तर तक सक्षम बनाना है कि वह अपने जीवन के हर निर्णय स्वयं से ले सकें, अपने अधिकारों को समझें और उनका उपयोग करें तथा समाज में सम्मान समानता और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जी सकें।

महिला सशक्तिकरण के मुख्य पहलू

निर्णय लेने की शक्ति—महिलाओं को शिक्षा, कैरियर, विवाह और स्वास्थ्य जैसे व्यक्तिगत और

सार्वजनिक मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए।

समान अवसर— समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर मिलना जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन।

आत्मविश्वास और स्वाभिमान—महिलाओं में यह विश्वास जगाना कि वह अपनी पहचान खुद बना सकती हैं और किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है।

संसाधनों पर नियंत्रण— आर्थिक संसाधनों, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक महिलाओं की आसान पहुंच और उन पर उनका नियंत्रण सुनिश्चित करना।

भेदभाव का अंत—लिंग के आधार पर होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव हिंसा या शोषण को समाप्त करना।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार—

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान करना है जिससे समाज का समग्र विकास हो सके। भारत में सावित्रीबाई फुले को महिला सशक्तिकरण और नारी शिक्षा की अग्रदूत माना जाता है।

सशक्त होने का वास्तविक आशय

पूरे विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य की पंक्ति है कि – **दिवस कमजोरों के मनाए जाते हैं, मजबूत लोगों के नहीं।** सशक्त होने का आशय केवल घर से बाहर निकालकर नौकरी करना या पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना भर नहीं है। शिक्षक होने का आशय यहां पर उनके निर्णय ले सकने की क्षमता का आधार है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले रही हैं या इसके लिए वह किसी और पर निर्भर है। इसी प्रकार आज आर्थिक रूप से सशक्त होना उनके लिए बहुत आवश्यक है। यदि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है तो वह

कभी भी सशक्त नहीं हो सकेगी, इसलिए यह एक और अन्य महत्वपूर्ण पहलू है।

‘आत्मनिर्भर भारत में महिला उद्यमिता अवसर एवं चुनौतियाँ’

आत्मनिर्भर भारत में महिला उद्यमिता न केवल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का साधन है, बल्कि वह देश की जीडीपी और विकास दर को बढ़ाने के लिए भी अनिवार्य है वर्तमान समय में महिलाएं शिक्षा और तकनीक के माध्यम से पारंपरिक व्यवसायों के साथ स्टार्टअप्स और तकनीकी क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। यहां आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में महिला उद्यमिता के मुख्य अवसर और चुनौतियों का विवरण दिया गया है—

महिला उद्यमिता के अवसर

आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत महिलाओं के लिए कई नए रास्ते खुले हैं—

सरकारी योजनाएं और वित्तीय सहायता

सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, महिला ई-हार्ट और स्वावलंबिनी पहला जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो महिलाओं के बिना किसी गारंटी के और रन प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।

डिजिटल क्रांति और ई-कॉमर्स—

सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग ने महिलाओं के लिए घर बैठे अपना व्यवसाय शुरू करने और वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के अवसर पर पैदा किए हैं।

स्वयं सहायता समूह

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं छोटे उद्योग जैसे हस्तशिल्प कृषि उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण में आत्मनिर्भर बन रही हैं।

नवाचार और स्टार्टअप

आधुनिक भारत में महिलाएं केवल पारंपरिक व्यवसायों तक सीमित नहीं हैं वे शिक्षा, स्वास्थ्य,

तकनीक और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में नए स्टार्टअप्स का नेतृत्व कर रही हैं।

कौशल विकास

सरकार और निजी संस्थान द्वारा संचालित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों से महिलाओं की तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं में सुधार हो रहा है।

प्रमुख चुनौतियाँ

अवसरों के बावजूद महिला उद्यमियों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है—

पितृसत्तात्मक मानसिकता

समाज में आज भी महिलाओं की नेतृत्व क्षमता पर संदेह किया जाता है जो उनके विकास में एक बड़ी बाधा है।

कार्य जीवन संतुलन—

पारिवारिक जिम्मेदारियों और बच्चों की देखभाल के कारण महिलाएं अक्सर अपनी व्यवसाय को पूरा समय नहीं दे पाती हैं।

वित्त तक सीमित पहुंच—

कई बैंक और निवेशक अभी भी महिलाओं के व्यवसायों को उच्च जोखिम वाला मानते हैं, जिससे उन्हें ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

नेटवर्किंग और मार्गदर्शन की कमी

पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास व्यावसायिक संपर्कों और मेंटर की कमी होती है, जो बाजार की समझ के लिए आवश्यक है।

तकनीकी ज्ञान का अभाव

विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और आधुनिक तकनीक के ज्ञान की कमी के कारण महिलाएं प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाती हैं।

विपणन का बिचौलियों की समस्या

उत्पादों के सही विपणन की कमी के कारण महिलाएं अक्सर बिचौलियों पर निर्भर रहती हैं जो उनके लाभ का बड़ा हिस्सा ले जाते हैं।

निष्कर्ष

जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्रता होती है तो वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति में योगदान देती हैं।

महिला को विविध कार्य करने होते हैं और अनेक दायित्व निभाने पड़ते हैं जिससे उसे सामाजिक बंधनों के कारण अपना उद्यम चलाने के वास्ते कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सरकारी योजना और कार्यक्रमों से महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के उपाय उपलब्ध कराए गए हैं। भारतीय महिलाएं सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा मुहैया

किए जा रहे विकास अवसरों के बारे में अनभिज्ञ रहती हैं। महिलाओं को सफलत उद्यमी बनाने में सहायता देने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाने चाहिए ताकि उनकी प्रतिभा और कौशल को दिखाया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. लाल मधुरिमा, एंड सहाय शिखा, 2008, विमेन इन फैमिली बिजनेस, इंडियन स्कूल का बिजनेस हैदराबाद में फैमिली बिजनेस पर आयोजित प्रथम एशियाई इन्विटेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत।
2. हेडबुक ऑन विमेन ऑन्ड एमएमईज, चैलेजेज एंड एपॉर्चुनिटीज इन पॉलिसेज एंड प्रोग्राम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर नॉलेज इकोनामी एंड एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट।
3. श्री कृष्णमूर्ति और आर. बालसुब्रमणि 'मोटिवेशनल फैक्टर अमंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड देयर एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेस: ए स्टडी' इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च एंड बिजनेस स्ट्रेटजी।
4. बोवेन, डोनाल्ड डी और हि रॉबर्ट डी (1986) द फीमेल एवं प्रेन्योर: ए कैरियर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू: वॉल्यूम अंक 3 पृष्ठ 393-407.
5. मायर्स, एस.पी. 1984 द कैपिटल स्ट्रक्चर्स पजल।
6. व्हाई रिसर्च नीडेड इन विमेन एवं प्रीन्योरशिप इन इंडिया: ए व्यूप्वाइंट आर्टिकल इन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल इकोनॉमिक, फरवरी 2018.
7. विकास समर्पित मासिक योजना सितंबर 2021.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार सृजन एवं कौशल

विकास के आधार एवं चुनौतियां

डॉ. मोहन सिंह

प्राचार्य, महात्मा गांधी टी.टी. कॉलेज महवा, दौसा, राजस्थान

सारांश

भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था। गांधी जी के अनुसार गांव में लोग अपने ही व्यवसाय में कुशलता प्राप्त कर उस व्यवसाय का लाभ भी गांव को ही मिले। व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, वह चाहे संज्ञानात्मक हो, चाहे व्यावहारिक चाहे प्रेरणास्पद या अनुशासनात्मक, कौशल प्राप्त कर ही, स्वयं भी सशक्त हो सकता है और राष्ट्र को भी विकसित कर सकता है। सशक्तिकरण का एक कारक शिक्षा हो सकती है परंतु केवल पाठ्यक्रम की शिक्षा प्राप्त कर उपाधियां हासिल करना, ना विकास है, ना सशक्तिकरण। विकास व्यक्तिगत हो सकता है परंतु सशक्तिकरण समष्टि के लिए होता है।

माननीय प्रधानमंत्री ने देश में व्यवस्था का विवेकीकरण करने, विकास प्रक्रिया को नव प्रवर्तित करने निर्माण की उत्पादकता बढ़ाने एवं लागत घटाने के साथ विकास की गति को अनवरत करने हेतु, कौशल मानव शक्ति की आवश्यकता महसूस की तथा 2015 में कौशल विकास पर कार्य प्रारंभ किया। बिना कौशल के 40 –80 करोड़ लोग अपना रोजगार गंवा बैठेंगे अर्थात् उन्हें

कौशल प्राप्त कर नव रोजगार की आवश्यकता होगी। कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा भारत 95 अकुशल श्रमिकों को अधिकांशतः उपयोगी बनाया जा सकता है और इसी को ध्यान में रखकर कौशल विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है। भारत में विश्व के सर्वाधिक युवा रहते हैं, इसके बावजूद इन कार्यक्रमों में चुनौतियां बनी हुई हैं।

कौशल विकास कार्यक्रम, इनमें चुनौतियां और युवा सशक्तिकरण आपस में एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंधित हैं अतः इन पर विचार-विमर्श अति आवश्यक है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा “कौशल विकास सरकार की, गरीबी के खिलाफ एक जंग है और भारत का प्रत्येक गरीब और वंचित युवा इस जंग का सिपाही है।”

मुख्य शब्द— कौशल विकास, उत्पादकता आत्मनिर्भर राष्ट्र, औद्योगिक क्रान्ति।

प्रस्तावना

विश्व में समय के साथ औद्योगिक क्रांतियां हुई हैं, निरंतर औद्योगिक क्रान्ति विकास में अग्रसर हैं। इन क्रांतियों में कौशल के मुख्य भूमिका रही है। श्रमिक ने जब-जब अपने व्यवसाय या कार्य में कौशल प्राप्त किया है, स्वयं का विकास किया ही है, परिवार और समाज के साथ, राष्ट्र के विकास में योगदान देकर स्वयं को और सशक्तिकरण सशक्त भी किया है।

कार्यशील लोगों का गुणवत्तापूर्ण उपयोग करने, देश में उत्पादकता का स्तर बढ़ाने, कौशल पूंजी निर्माण, आय व रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु तथा युवा शक्ति का राष्ट्र निर्माण में अधिकतम योगदान के उद्देश्य से सरकार ने कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के रूप में 9 नवंबर 2014 को प्रोन्नयन कर दिया गया है। यह मंत्रालय देश में अन्य मंत्रालयों व

महत्वपूर्ण विभागों के साथ तालमेल करके देश में युवा को , कौशल विकास प्रशिक्षण शिक्षा रोजगार प्राप्ति व स्वरोजगार प्राप्त कर श्रम से आत्मनिर्भर स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रयासरत है।

कौशल विकास की आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यकता एवं महत्व

भारत में प्राप्त संसाधनों के बहु आयामी सदुपयोग और बढ़ती आबादी के साथ उचित समायोजन हेतु बड़े पैमानों पर उचित मानकों पर आधारित कौशल विकास ऐसी शुद्धता उद्यम परंपरा पैदा करेगा ताकि देश की सारी जनसंख्या के लिए रोजगार एवं आय का सृजन होगा। इस हेतु लोगों को उनके व्यवसाय में प्रशिक्षित कर कुशल बनाने की आवश्यकता है। लोग कुशल होंगे तभी वह आत्मनिर्भर होंगे तथा देश के लोग आत्मनिर्भर होंगे तभी तो भारत भी आत्मनिर्भर हो सकेगा । 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित एक दूरदर्शी पहल "आत्मनिर्भर भारत" जिसका उद्देश्य देश को आर्थिक तकनीकी और सामाजिक रूप से स्वतंत्र बनाना है । कोविड-19 महामारी के दौरान घोषित 20 लाख करोड़ रूपयों की विशेष आर्थिक पैकेज के साथ, इसका लक्ष्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता कम करना है । यह 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र के साथ भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र (लसवइंस भन्ड) बनाने का प्रयास है। आत्मनिर्भर भारत के पांच प्रमुख स्तंभ हैं

- (i) अर्थव्यवस्था (Economy)
- (ii) अव संरचना (Infrastructure)
- (iii) व्यवस्था (System)
- (iv) जीवंत जनसांख्यिकी (Vibrant Demography)
- (v) मांग (Demand)

आत्मनिर्भर भारत के अवसर—

- (i) रोजगार सृजन की योजनाएं
- (ii) कौशल विकास

(iii) रोजगार में वृद्धि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत "दुनिया के लिए मेक" (Make for the world and Make in India) का नारा दिया ,जिसका अर्थ देश में उत्पादन कर वैश्विक बाजार में योगदान ।

यह अभियान भारत को 2047 तक विकसित भारत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का आधार है।

भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने हेतु व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र में उत्पादकता व समृद्धि हेतु निम्न बिंदुओं पर जोर देने की आवश्यकता है।

- (i) रोजगार एवं आय में वृद्धि हेतु गुणात्मक कौशल व्यवस्था करना
 - (ii) प्रशिक्षण – ढांचे एवं प्रशिक्षकों की क्षमता में सुधार लाना
 - (iii) कौशल प्रशिक्षण एवं सामान्य शिक्षा व्यवस्था में तालमेल बैठाना
 - (iv) कुशल –श्रम की मांग के अनुसार आपूर्ति की व्यवस्था
 - (v) सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछले वर्गों को उपयुक्त प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना
 - (vi) कौशल प्रशिक्षण में आधी आबादी यानी महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना
 - (vii) भारत को विश्व कौशल का मुख्य केंद्र बनाना
- उक्त में भारत सरकार एवं राष्ट्र के युवाओं एवं महिलाओं द्वारा कौशल विकसित कर तथा कौशल प्रशिक्षण एवं दृढ़ इच्छाशक्ति द्वारा संकल्पित होकर अनेकानेक कार्य किए गए हैं, जिनमें से कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं –

शोध श्री में डॉक्टर सुमन देवी, एसोसिएट प्रोफेसर, गोल्ड फील्ड कॉलेज आफ एजुकेशन फरीदाबाद हरियाणा ने अपने शोध पत्र में लिखा है कि योगा और मेडिटेशन केवल शारीरिक अभ्यास मात्र नहीं हैं बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि हेतु आवश्यक औजार हैं । आजकल के इस भागदौड़ और तनाव भरे समय में यदि तन्मयता और

कुशलता के साथ योगा और मेडिटेशन किया जाता है, तो व्यक्ति न केवल स्वयं को स्वस्थ रखता है बल्कि देश को भी समृद्ध करने का कार्य करता है। शोध श्री में श्री राजकुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गोल्ड फील्ड कॉलेज आफ एजुकेशन फरीदाबाद हरियाणा ने अपने शोध पत्र में लिखा है कि विद्यार्थियों के नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए मूल्य शिक्षा अनिवार्य है, जो उन्हें नैतिक चुनौतियों से निपटने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए तैयार करती है, अर्थात् मूल्य शिक्षा द्वारा चारित्रिक विकास भी राष्ट्र को समृद्ध बनाने में बड़ा योगदान देता है।

शोध श्री में डॉक्टर सुरेंद्र मोहन शर्मा, वरिष्ठ निजी सहायक राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, ने अपने शोध पत्र "रामायण काल में भारतीय समाज व राज्य" में सामाजिक व्यवस्था में, ब्राह्मणों के कर्तव्य, क्षत्रियों के कर्तव्य, वैश्यों के कर्तव्य, शूद्रों के कर्तव्य, रामायण कालीन आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम आदि पर प्रकाश डाला और बताया कि सामाजिक व्यवस्था भी राष्ट्र निर्माण और भारत के आत्मनिर्भर होने में अपनी भूमिका निभाती है।

डॉक्टर आरती तंवर, जोधपुर, ने अपने शोध पत्र में लिखा कि महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में पुरुषों के समान सक्रिय रूप से भाग लेकर भारत सरकार को समृद्ध कर सकती हैं, अतः बालिकाओं को अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सुव्यवस्थित शिक्षा में कठिनाइयों का निवारण करना चाहिए।

नारायण दास वैष्णव ने अपने शोध पत्र में, सौर ऊर्जा टीकाऊ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आशाजनक तरीका बनकर उभर रही है, जो वैश्विक ऊर्जा मांग को हल करने के लिए, एक महत्वपूर्ण समाधान प्रदान करती है, अर्थात् देश की प्रगति एवं आत्मनिर्भरता के लिए तथा युवाओं को

रोजगार देने हेतु सौर ऊर्जा भी, एक अवसर हो सकता है।

रामदेव जाट ने अपने शोध पत्र में महाराज राम सिंह द्वितीय के शासन काल में जयपुर में हस्तकला उद्योग पर एक ऐतिहासिक अवलोकन में लिखा है कि लघु एवं कुटीर उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऊन का उत्पादन, मूर्ति शिल्प कला, रेशम ज्वैलरी शिल्प कला, ब्लू पॉटरी, लाख कला, पीतल पर नक्काशी, हाथी दांत पर चित्रांकन, जयपुर प्रिंट हस्तकला, गलीचा उद्योग, चांदी वर्क हस्तशील्य कला जैसे उद्योगों ने राज्य को किस कदर आत्मनिर्भर एवं समृद्धि किया है।

डॉ.तनु शर्मा ने अपने शोध पत्र में लिखा है कि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति दीर्घकालिक एवं स्थाई आर्थिक समृद्धि का एकमात्र क्रांतिकारी उपाय ग्रामीण विकास और ग्रामीण महिला विकास से ही संभव है, अर्थात् ग्रामीण महिलाओं को सशक्त कर ही भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

आत्मनिर्भर भारत, युवा सशक्तिकरण, राष्ट्र निर्माण तथा सरकार के इस दिशा में प्रयास, दृढ़ इच्छाशक्ति, साहस और समर्पण कुछ इस प्रकार भी हैं –

तकनीकी से घर बैठे सीखीं 24 विदेशी भाषाएं, भाषा सीखने वालों की ग्लोबल कम्युनिटी से जुड़ीं अंबुजाक्षी

90 साल की उम्र में चल रही हैं डिजिटल रसोई सेमीकंडक्टर हब बन गुजरात सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए स्किल टैलेंट तैयार कर रहा गुजरात

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने कहा है कि पारंपरिक कौशल आत्मनिर्भरता की नई दिशा घड़े समाज गूगल के पिचाई को दिया 6400 करोड़ का भारी वेतन पैकेज, कौशल का ही करिश्मा है।

गर्मी में बच्चों को राहत देगा आईना का बनाया कूलिंग बैग मिलेगी 10000 रुपयों की स्कॉलरशिप

आंखों में अंधेरा सपनों में उजाला 10 स्वर्ण पदक जीते सवाई माधोपुर के मानपुर गांव के दृष्टिहीन सूरजभान ने भारतीय पैरा स्विमिंग में जीते 10 स्वर्ण पदक

सुरों से दिल जीता अब सियासत में जिम्मेदारी लोक गायिका मैथिली ठाकुर सबसे कम उम्र की बिहार विधानसभा के सदस्या

दहलीज से कारोबार तक फाइल पंख , नारी का नया आसमान युवा स्वरोजगार में 3600 महिलाओं ने किया आवेदन, स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक ऋण, 180.35 करोड़ के ऋण आवेदन जोश और दृढ़ता की झलक: पासिंग आउट परेड में छाई देश की बेटियां ,योग में नारी शक्ति का जज्बा

सरकारी स्कूल में पढ़ी नौ नौकरी कर ,अब एसडीएम महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ रही हैं- मूर्ति मीणा

पांचवीं तक पढ़ी अब तकनीक से खेती

रेल की रफ्तार पर नारी शक्ति की पकड़

मेरी भी एक स्टूडेंट मीना सोनी ने जयपुर मेट्रो चलाई

दृढ़ इच्छा शक्ति से ही रावतभाटा का डॉक्टर अनुज देश भर में यूपीएससी परीक्षा में अब्बल

महारानी गायत्री देवी द्वारा संचालित राजस्थान पत्रिका डूबने की स्थिति में थी और स्वर्गीय कपूर चंद कुलिश जी के हाथों में सत्य और साहस का 7 दशकों का सफलतम सफर वेटरनरी शिक्षा में डिजिटल क्रांति –बदलेगी तस्वीर

पाइथन लैंग्वेज सीख कर मिलेंगे मौके ही मौके

स्टार्टअप की दुनिया में प्रतियोगिता कैसे निपटें

हरित और टीकाऊ उद्योगों पर टिका भविष्य –पूर्व निदेशक (आईडीएफजे)

(13:03, 4/6/2026) क्त. डवींद 'पदही: जीडीपी ही नहीं हैपिनेस पर हो नजर, तय हों स्थाई विकास के नए लक्ष्य

सभी जिलों में हो कम से कम एक-एक मेडिकल कॉलेज

एआई स्मार्ट तकनीक से रोक सकते हैं, जल की बर्बादी

ग्रीन एनर्जी में मध्य प्रदेश ने बनाई पहचान

खेती की ताकत, किसानों को सम्मान फिनलैंड से अब हाई-टेक रिश्ते, विद्यार्थियों को मिलेंगे मौके

जब मझला व्यापारी मजबूत होगा, तभी सशक्त हो पाएगा भारत

आयुर्वेद विश्वविद्यालय की पहल, बुजुर्गों की सेवा रोजगार

स्मार्ट पुलिसिंग – एक फोटो और पुलिस के हाथ में होगी क्रिमिनल कुंडली – हाथ लगा ब्रह्मास्त्र एप

एआई टूल्स ने किया बेहिसाब उत्पादन चितलवाना गांव में संकल्प ने हटा दिया जल संकट

जल परियोजनाओं को राष्ट्रीय दर्जा (केंद्रीय बजट 2026 – 27)

बिना ताले की निःशुल्क लाइब्रेरी, लोगों में पढ़ने की आदत विकसित करने का मॉडल- राधेश्याम माहेश्वरी इंदौर ,

अकाल की तस्वीरें देख छेड़ी पानी बचाने की मुहिम – अमला रुइया

दौसा में बिक रहे बाजरे के घेवर

खेतों में खुशहाली..... 10 सालों में किसानों के आय दोगुनी हुई

भारत अंतरिक्ष में बनाएगा डिजिटल किला-

121 वीं बार रक्तदान कर अजय घूमना ने बचाई मरीज की जान

एआई में भारत के नेतृत्व को वैश्विक समर्थन

कूटनीति के मैदान में छाई एआई की धाक

लोकतंत्र की मजबूती के लिए निर्भीक और खोज परक पत्रकारिता की जरूरत

सूर्य किरण ने बिखेरी चमक – सारंग के स्टंट ने जीता दिल— बटोरी तालियां – हम किसी से कम नहीं

टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैरियर ,12वीं पास 4 वर्षीय कोर्स , मिलेंगे मौके ही मौके

स्टूडेंट स्टार्ट अप..... क्यों बन रहे आज की जरूरत

इंफ्लुएंसर बनने के लिए कौन से स्किल्स का होना है जरूरी – ढेर सारे अवसर

एआई सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स में भारत को बड़ा बूस्ट

बीज से बाजार तक मीठे प्याज से शेखावाटी में बदली खेती की तस्वीर वस्त्र नगरी के वैश्विक उड़ान , धागों से बुनी आर्थिक समृद्धि

कैट सफलता के लिए टिप्स –बनाइए कैरियर

शब्दों के जादूगर हैं, तो किताब लिखकर सपनों को दे उड़ान

प्लास्टिक से ब्लेजर तैयार कर, पिता – पुत्र पर्यावरण का कर रहे हैं ,संरक्षण एआई बूम आईटी सर्विस सेक्टर के लिए अंत की आहट या नई शुरुआत चुनौतियां

भारत दुनिया के मानकों में कौशल विकास के क्षेत्र में निचले पायदान पर है । जहां विकसित देशों में कुशल कार्य बल, कुल कार्य बल का 60 से 90 फिसदी के बीच है, भारत में औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा के साथ 4.7 के निचले स्तर पर है। अमेरिका में 52, इंग्लैंड में 68, जर्मनी में 75, जापान में 80 और दक्षिणी कोरिया में 96। श्रमबल औपचारिक कौशल प्राप्त है। श्रम बाजार की स्थितियों और तीव्र आर्थिक वृद्धि की जरूरत को देखते हुए , भारत में कौशल तंत्र को विकसित करने में काफी चुनौतियां हैं ।

(i) खराब है असक्षम शिक्षा पाने वाले युवाओं की संख्या में लगातार वृद्धि

(ii) जनसंख्या की तुलना में प्रशिक्षण क्षमताओं का सीमित व असमान वितरण

(iii) कुशल कामगारों के ऊंची मांग और रोजगार पाने की कम योग्यता (iv) विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय का अभाव (v) आधारभूत सुविधाओं की कमी (vi) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास पर ध्यान नहीं देने के कारण प्रशिक्षण का अभाव, प्रशिक्षण के प्रति निष्क्रियता, प्रशिक्षण के प्रति लापरवाही

(vii) अवसरों की जानकारी व काउंसलिंग का अभाव

(viii) मरणासन्न कुटीर उद्योगों की तरफ सरकार का ध्यान व सहायता का नहीं होना

(i) कंफर्ट जोन की जीवनशैली अपनाना ,केवल सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ना ,पैतृक व्यवसाय के प्रति सम्मान की कमी

प्रशिक्षण के बाद भी रोजगार के अभाव

चुनौतियों के साथ ही कुछ खतरे भी हैं उन पर भी विचार करना जरूरी है— उदाहरणार्थ –डिजिटल अरेस्ट और सिम स्वीप से बचने की सलाह

सावधान ट्राई अधिकारी बनकर ठगी पुलिस ने जारी की चेतावनी

देवस्थान विभाग की वेबसाइट ठगों को दान में दे रही ट्रस्टों का डाटा

अनुसंधान की खामियों से आरोपी का दोष मुक्त होना पीड़ित पक्ष के लिए सजा

यूट्यूब से सीखा डेट बदलकर एक्सपायरी माल बेचना

साथियों से ज्यादा भरोसा एआई पर विचार टकराए तो खुद पर शक

कागजों में कौशल: राज्य में 4019 में से 2499 स्कूलों में एक भी व्यावसायिक प्रशिक्षक नहीं

कौशल विकास पर एक नजर

जुलाई 2015 से शुरू कौशल भारत मिशन के अंतर्गत विकास और उद्यमिता मंत्रालय की

प्लेगशिप योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, अभी तक 1. 21 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। राष्ट्रीयता शिक्षता संवर्धन योजना (NAPS) के तहत 7.5 लाख युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही जन शिक्षण संस्थान में 14 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया किया जा चुका है। 25 लाख युवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में 50 लाख युवा PMKVY में और 25 लाख युवा शुल्क आधारित कार्यक्रम में प्रशिक्षण ले चुके ले रहे हैं। PMKVY द्वारा पूर्व शिक्षण (PRL) को मान्यता के तहत मौजूद कार्य बल के प्रमाणीकरण को सक्षम बनाया गया है। RPL में 2015 – 22 के तहत 10 जुलाई 2021 तक 37 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 63 लाख से अधिक लाभार्थी प्रमाणित हो चुके हैं। SSDM के माध्यम से राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की गई जो PMKVY के तहत परियोजनाओं के लिए ऑन-बोर्ड किए गए थे। कामगारों के रूप में लगे 69000 से अधिक उम्मीदवारों को विभिन्न जॉब रोल्स में प्रमाणित किया गया है। RPL&BIC में के तहत 13 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है। परिधान निर्माण से लेकर एयरोस्पेस तक 9 लाख से अधिक 35.9 महिलाएं भी प्रमाणित हुई हैं, जिनमें 4.5 लाख परिधान निर्माण से लेकर एयरोस्पेस तक 9 लाख से अधिक 35.9 प्रतिशत महिलाएं भी प्रमाणित हुई हैं, जिनमें 4.5 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं, ऑर्गेनिक ग्रोअर्स, बॉयलर फॉर्म वर्कर, श्रीम्प फॉर्मर, फार्मिंग के लिए ड्रोन सिमुलेटर एवं फूड प्रोसेसिंग जैसे अनेक पाठ्यक्रमों में प्रमाणित की गई हैं।

रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की कगार पर सशस्त्र बल कर्मियों को सीखे कौशल को उपयोगी बनाने हेतु ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण दिया गया है। अब तक 60000 सैनिक व पूर्व सैनिक प्रमाणित किए जा चुके हैं। RPL के प्रमाणीकरण के बाद कार्य बल आय में 25% वृद्धि हुई है, 47% लोगों के वेतन में वृद्धि, 63%

लाभार्थियों ने अपने कार्य स्थल पर उच्चतर स्थान प्राप्त किया है।

देश भर में विभिन्न योजनाओं और संगठनों के माध्यम से विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम संचालित हैं जैसे:-

1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
2. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUKVY)
3. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSET)
4. प्रधानमंत्री युवा विकास अभियान (PMYUVA)
5. ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना
6. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
7. दीनदयाल अंत्योदय योजना
8. प्रधानमंत्री कौशल केंद्र
9. तक्षशीला
10. उड़ान
11. हिमायत
12. राष्ट्रीय कैरियर सेवा

परन्तु उक्त योजनाओं के बारे में समुचित प्रचार-प्रसार के अभाव के साथ ही प्रेरणा का भी अभाव है। देश के युवाओं को इन योजनाओं की जानकारी देकर प्रोत्साहित कर कुशल बनाया जा सकता है और कुशल युवा ही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं। किसी भी कार्य के प्रति समर्पण ही उसमें सफलता का बिजांकुरण कर सकता है। अधुरे मन से कभी भी सफलता की संभावनाएं नहीं बनती। कार्य के प्रति ईमानदारी, मेहनत, समर्पण, जिज्ञासा एवं कुछ नया करने का साहस रूपी आहुतियां ही सफलता रूपी यज्ञ की संपूर्णता हो सकती है। यहां शिव खेड़ा का एक कोटेशन उद्धृत करना समयोचित होगा “भारत को किसी आतंकवादी से कोई खतरा नहीं है, परन्तु देश का पढ़ा लिखा युवा यदि अकर्मण्य हो गया तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा।”

अतः सभी विशेषकर शिक्षक समुदाय देश की नई पौध को सक्रिय, सुसंस्कारी, चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाने के उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे तो निश्चित ही राष्ट्र वैश्विक जगत में नेतृत्व भी करेगा।

संदर्भ सूची

वेबसाइट्स

- www.shaikshikmanthan-com
- www.education-nic
- <http://www-desertation-com>
- <http://www-indianjournals-com>
- www.shodhganga-inflibnet-ac-in

प्राचीनकालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

डॉ. गौरव सिंह

सहायक आचार्य, महात्मा गाँधी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

महवा, दौसा, राजस्थान

सारांश

भारत में शिक्षा का एक लम्बा और गौरवशाली इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय शिक्षा, जो गहन रूप से आध्यात्मिक और मानवतावादी थी का उद्देश्य न केवल ज्ञान प्राप्त करना था, बल्कि बुद्धि, अनुशासन और आत्म साक्षात्कार का विकास भी था। यह परम्परा, सामुदायिक जीवन और गुरु-शिष्य के घनिष्ठ संबंधों में निहित थी। आधुनिक युग में, शिक्षा के उद्देश्य, तरीके और संरचना में बड़े बदलाव आए हैं। वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और बदलते सामाजिक – आर्थिक परिदृश्य ने शिक्षा प्रणाली के सामने नई चुनौतियाँ

खड़ी कर दी है। इन चुनौतियों से निपटने और इक्कीसवीं सदी की जरूरतों के हिसाब से एक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और नवाचार-उन्मुख शिक्षा के इतिहास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 एक महत्वपूर्ण कदम है जो कई बुनियादी बदलावों का प्रस्ताव करती है, जिनमें बहु-विषयक शिक्षा, अनुभवात्मक अधिगम, महत्वपूर्ण सोच का विकास, कौशल-आधारित शिक्षा और भारतीय ज्ञान परंपराओं के पुनरुत्थान पर जोर शामिल है।

मुख्य शब्द – प्राचीनकालीन शिक्षा, वैश्वीकरण, समग्र विकास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020।

परिचय

भारत में शिक्षा की प्राचीन काल से ही गौरवशाली परम्परा रही है। प्राचीन भारत में मुनियों एवं महर्षियों ने सभ्यता के ऊषाकाल में ही शिक्षा के महत्व को समझ लिया था। शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति, समाज एवं देश का कल्याण संभव है। प्राचीन भारतीय शिक्षा का महत्व इस बात से ही जाना जा सकता है की यहां अनेक मनीषियों व विचारकों ने अपना तत्व चिंतन प्रस्तुत किया। इसके साथ ही दर्शन, मनोविज्ञान, न्याय, गणित, आयुर्वेद आदि विविध शास्त्रों के ज्ञान क्षेत्र में ऐसे भौतिक विचारक एवं मनीषी उत्पन्न हुए जिनसे हमारा देश आज भी गौरवान्वित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार लाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार

द्वारा जुलाई 2020 में घोषित एक बड़ी और दूरदर्शी नीति है। इसका लक्ष्य भारत की शिक्षा व्यवस्था को संपूर्ण, लचीला, कई विषयों वाला, अच्छी गुणवत्ता वाला और 21 वीं सदी की जरूरत के मुताबिक बनाना है। यह नीति स्कूल की पढ़ाई से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण बदलाव सुझाती है। इसमें अनुभव से सीखना, गहरी सोच विकसित करना, कौशल बढ़ाना भारतीय ज्ञान परंपराओं को बढ़ावा देना और तकनीक का इस्तेमाल करना शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का लक्ष्य रखती है।

प्राचीनकालीन भारतीय शिक्षा : एक अवलोकन

प्राचीनकालीन शिक्षा प्रणाली, जो अपनी सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत में गहराई से निहित है, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित

शिक्षा प्रणालियों में से एक है। प्राचीन भारत में शिक्षा को एक महानतम उपहार माना जाता है। इस काल के दौरान भारतीय समय की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की विभिन्न प्रणालियों का उदय हुआ। इनमें से प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था ने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई।

प्राचीनकालीन शिक्षा

प्राचीन काल की शिक्षा भारतीय समाज और संस्कृति की प्रारंभिक और मौलिक आधार थी। इसे 'प्रकाश का स्रोत', 'अंतर्दृष्टि', 'ज्ञान चक्षु' और 'मनुष्य का तीसरा नेत्र' कहा गया था। उस समय माना जाता था कि शिक्षा का प्रकाश मनुष्य के संश्यों को दूर करता है और उसकी बाधाओं को समाप्त करता है। शिक्षा से प्राप्त अंतर्दृष्टि व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और कुशलता को बढ़ाती है। शिक्षा मनुष्य को जीवन के वास्तव महत्व को समझने की क्षमता प्रदान करती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है। शिक्षा के महत्व के बारे में यह विश्वास था कि यह कामधेनु या कल्पतरु की भांति मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है। और सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। इसी विचार को स्पष्ट करते हुए डॉ. ए.एस.अल्तेकर ने लिखा है "शिक्षा को प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था, जो हमारी मानसिक, शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति तथा क्षमताओं का निरंतर एवं सामंजस्यपूर्ण विकास करके, हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उसे उत्कृष्ट बनाती है।

प्राचीनकालीन शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध शिक्षा प्रणाली

प्राचीनकालीन भारत की शिक्षा प्रणाली सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध और उन्नत थी। प्राचीन शिक्षा प्रणाली का आधार धर्म था। क्योंकि धर्म ने शिक्षा प्रणाली में प्रमुख भूमिका निभाई। इसका अंतिम उद्देश्य 'मोक्ष' (सा विद्या या

विमुक्तये) प्राप्त करना था। "ज्ञान वह है जो मुक्ति देता है।" यह हमें लालच, महत्वाकांक्षा, जुनून आदि की भौतिक दुनिया से मुक्ति दिलाता है।

सख्त आचार संहिता का प्रभुत्व

गुरुकुल पारम्परिक आवासीय शिक्षण विद्यालय थे, आमतौर पर शिक्षक का घर या मठ हुआ करते थे। यह प्रायः प्राकृतिक वातावरण में गांव या नगर से दूर स्थित होता था। शिष्य वहीं रहकर शिक्षा, भोजन, सेवा और साधना करते थे। शारीरिक दंड का कोई प्रावधान नहीं था अनुशासन स्वतंत्र था आत्म-सम्मान, आत्म-अनुशासन और आत्म-संयम यह तीनों ही जीवन को सर्वोच्च शक्ति की ओर ले जा सकते थे। आत्म-अनुशासन सर्वोत्तम अनुशासन था। प्राचीन भारतीय शिक्षा में कठोर नैतिक आचार संहिता का बोलबाला था। प्राचीनकाल में विद्यार्थी अपने गुरु को अपना माता-पिता मानता था।

नागरिक जिम्मेदारियां और समाजिक मूल्यों का विकास

भारत में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नागरिक गुणों और समाजिक मूल्यों का विकास था। गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद ब्रह्मचारी, समाज में वापस लौटकर अमीरों और गरीबों की सेवा करते थे, रोगियों और संकटग्रस्त लोगों की सहायता करते थे। उनसे अतिथियों का सत्कार करने और जरूरतमंदों के प्रति दानशील होने की अपेक्षा की जाती थी। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व था कि वह राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा करें और ज्ञान के प्रसार के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करें।

प्राचीनकालीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य और आदर्शों का वर्णन करते हुए डॉ. ए.एस.अल्तेकर ने कहा है कि इसका लक्ष्य ईश्वर भक्ति और धार्मिकता का विकास, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक एवं नागरिक कर्तव्यों की भावना का समावेश, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार था। प्राचीन काल में प्राथमिक शिक्षा की

कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी उस समय बालक का परिवार ही उसका शिक्षा केंद्र था। प्रारम्भिक शिक्षा का आरंभ पांच वर्ष की आयु में 'विद्यारम्भ संस्कार' से होता था और यह सभी जातियों के बालकों के लिए अनिवार्य था। इसकी अवधि लगभग छह वर्ष मानी जाती थी। पाठ्यक्रम में पहले वादयंत्रों के उच्चारण और बोलने का अभ्यास करवाया जाता था। भाषा का ज्ञान हो जाने पर साहित्य और व्याकरण पढ़ाया जाता था। इस प्रकार पाठ्यक्रम वैदिक मंत्रों का स्मरण, पढ़ना, लिखना, भाषा, साहित्य पर आधारित था। प्राचीन काल में शिक्षा के लिए अनेक संस्थाएं स्थापित थी। इनमें टोल, जहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती थी। चरण, जिसमें वेद के किसी एक अंग की शिक्षा दी जाती थी। घटिका, जहाँ धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा अनेक शिक्षक मिलकर देते थे। परिषद, जिसमें दस शिक्षक विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान करते थे तथा गुरुकुल जहाँ वेद, साहित्य और धर्म शास्त्र पढ़ाये जाते थे। इस प्रकार प्राचीन शिक्षा ने भारतीय शिक्षा की आधारशिला रखी और आगे आने वाले वैदिक कालीन शिक्षा तंत्र की नींव तैयार की।

प्राचीनकालीन शिक्षा

प्राचीनकालीन शिक्षा प्राचीन भारतीय शिक्षा का व्यवस्थित और संगठित स्वरूप मानी जाती है। इस काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश आत्मज्ञान, धर्मपालन, चरित्र निर्माण और जीवन में उच्च आदर्शों की स्थापना करना था। वैदिक शिक्षा का आधार वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक थे, जिनके माध्यम से धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान प्रदान किया जाता था। इस काल में प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था मुख्यतः गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी।

गुरुकुल प्रणाली

शिक्षा की इस प्रणाली में विद्यार्थियों को घर से दूर रहना पड़ता था। गुरुकुल में प्रवेश लेने के पश्चात छात्र शुद्धता का जीवन व्यतीत करते थे,

आचार्य की सेवा करते थे तथा ज्ञान प्राप्त करते थे। गुरुकुल प्रणाली में प्रवेश की आयु उपनयन संस्कार से जुड़ी हुई थी। उपनयन संस्कार को शिक्षा प्रणाली में बहुत ही महत्व दिया जाता था। इसे जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। उपनयन का अर्थ है गुरु के समीप ले जाना, अर्थात् शिक्षा का प्रारंभ करना। इस संस्कार में बालक को जनेऊ धारण कराया जाता है और उसे गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है। इसे द्विजत्व या दूसरा जन्म भी कहा जाता है। परम्परा के अनुसार ब्राह्मण का उपनयन 08 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में और वैश्य का 12वें वर्ष में होता था। उपनयन के बाद बालक वेदाध्ययन, यज्ञ और धार्मिक कर्तव्यों का अधिकारी बनता था। वास्तव में उपनयन संस्कार शिक्षा, धर्म और आध्यात्मिकता की ओर पहला कदम होता था। उपनयन संस्कार के साथ ही छात्र ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता था। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने जीवन के निर्दिष्ट पथ पर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। गुरुकुल में केवल अविवाहित ही विद्यार्थी बन सकते थे। आचरण की शुद्धता को परम महत्व माना जाता था। विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करने पर विद्यार्थी को सुगंधित, अंगराग या नशीली वस्तुओं का प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी। विद्यार्थियों को अध्ययन अवधि के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया था। पहला वसु-24 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने वाले को वसु कहा जाता था, यह विद्यार्थी ब्रह्मचर्य व्रत को अल्प अवधि तक निभाते थे। जो विद्यार्थी 36 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करते थे, वे रुद्र कहलाते थे, यह छात्र अधिक समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करते और गहन अध्ययन करते थे। और 48 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त ग्रहण करने वालों को आदित्य कहा जाता था। यह जीवन भर गुरुकुल और ब्रह्मचर्य में रहने वाले विद्यार्थी माने जाते थे। यह अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा, तप, और ज्ञान के लिए समर्पित कर देते थे। गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं था, बल्कि नैतिकता,

अनुशासन और संस्कारों का विकास करना भी था। शिक्षा पूर्ण करने के बाद छात्र गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इस अवस्था में वह विवाह कर परिवार का पालन पोषण करता और समाज के प्रति अपने कर्तव्य करता था।

नारी शिक्षा

प्राचीनकालीन शिक्षा में नारी शिक्षा को उच्च स्थान प्राप्त था। वे धर्म, दर्शन और साहित्य में निपुण होती थीं। उस समय की विदुषी स्त्रियों में गार्गी, मैत्रेयी, आपला और लोपामुद्रा के नाम प्रमुख हैं। स्त्रियां केवल गृह कार्य तक सीमित नहीं थी बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों और वैचारिक चर्चाओं में भी भाग लेती थीं। उपनिषदों और ग्रंथों में नारी की विद्वता के अनेक प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार प्राचीन काल में नारी शिक्षा का स्थान अत्यंत सम्मानजनक और प्रेरणादायक था।

पाठ्यक्रम संरचना और शिक्षण पद्धति

प्राचीनकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन और व्यक्तित्व का समग्र विकास था। शिक्षा का आधार वेदों और उनसे संबंधित साहित्य पर आधारित था। पाठ्यक्रम में सबसे पहले सभी वेदों (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद) का अध्ययन अनिवार्य माना गया था। इन वेदों के अध्ययन में वेदांगों की शिक्षा दी गयी थी, जिसमें वेदों के उच्चारण, व्याकरण शब्दों का अर्थ, छंद अनुष्ठान और यज्ञ विधि और ज्योतिष प्रमुख थे। इसके साथ ही उपनिषदों के माध्यम से ईश्वरीय सिद्धांत, आत्मा और ब्रह्मा अवधारणा और आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन किया जाता था। व्यावहारिक जीवन के लिए यज्ञ, संस्कार, नीति, आचरण, और चारित्रिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल थे। शारीरिक विकास के लिए धनुर्विधा, युद्धकला, कुश्ती और व्यायाम सिखाये जाते थे। कला और शिल्प में संगीत, गान, वादन, नृत्य और शिल्पकला को भी स्थान दिया गया था। गणित और खगोल के माध्यम से गणना, मापन और ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान सिखाया जाता था। इस प्रकार वैदिक काल

में पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक, शारीरिक सभी मानकों को शामिल किया जाता था।

शिक्षण पद्धति

प्राचीनकालीन शिक्षा मुख्यतः गुरुप्रणाली के अंतर्गत दी जाती थी, जहां शिष्य गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षण का प्रमुख आधार मौखिक परम्परा थी, जिसमें श्रवण, मनन और निदिध्यासन पर बल दिया जाता था। गुरुमंत्र और श्लोकों के उच्चारण को शिष्य बार-बार कंठस्थ करते थे। संवाद और प्रश्नोत्तरी पद्धति भी महत्वपूर्ण थी जिसके उदाहरण उपनिषदों में मिलते हैं। क्रियाविधि के माध्यम से शिष्य गुरु के आचरण से शिक्षा ग्रहण करता था। व्यावहारिक और अनुभवात्मक शिक्षा के लिए यज्ञ, अनुष्ठान, धनुर्विद्या, संगीत, नृत्य और शिल्प का अभ्यास किया जाता था। शिक्षा अत्यंत अनुशासित थी और शिष्य को ब्रह्मचर्य, सेवा, आत्मसंयम तथा तपस्या का पालन करना था। प्रत्येक छात्र की क्षमता और रुझान के अनुसार व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया गया था।

गुरु – शिष्य संबंध

प्राचीनकालीन शिक्षा व्यवस्था का आधार गुरु-शिष्य संबंध था। गुरुकुल में दी गई शिक्षा, जहां शिष्य गुरु के आश्रम में शिक्षा के अलावा केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं करता था, बल्कि जीवन के हर सिद्धांत में उन्हें गुरु का मार्गदर्शन मिलता था। शिष्य को गुरु के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता, सम्मान और सेवा भाव रखना आवश्यक था। वह आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन करता था, गुरु के परिवार की सेवा करता था और कठोर अनुशासन का पालन करता था। गुरु-शिष्य के बौद्धिक विकास के साथ-साथ उसके नैतिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन को भी आकार देता था। शिक्षा केवल शास्त्र ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन शैली, संस्कार, निर्देश और आत्मसंयम भी सिखाये जाते थे। शिष्य की

सफलता और समाज में प्रतिष्ठता का आधार गुरु का अशीर्वाद माना जाता था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 को डॉ. कस्तूरीरंगन समिति ने तैयार किया था और भारत सरकार ने 29/07/2020 में लागू किया जो देश की तीसरी शिक्षा नीति है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक समग्र, बहुविषयक, लचीला और भारतीयता-आधारित बनाना है। इस नीति में पारम्परिक 10+2 संरचना के स्थान पर 5+3+3+4 की नई संरचना लागू की गई है, जिसमें प्रारम्भिक अवस्था से ही आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर जोर दिया गया है। मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी गयी है। और त्रिभाषा सूत्र को प्रोत्साहित किया गया है। उच्च शिक्षा में बहुविषयक अध्ययन, चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम अकादमिक बैंक क्रेडिट तथा शोध को बढ़ावा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, नीति में शिक्षक शिक्षा के स्तर को सुधारने पर बल दिया गया है। और 2030 तक न्यूनतम योग्यता चार वर्षीय बी.एड. निर्धारित की गयी है। मूल्यांकन प्रणाली को परीक्षा केंद्र पद्धति से हटाकर समग्र और दक्षता आधारित मूल्यांकन की दिशा में परिवर्तित किया गया है। नीति का विशेष पहलू यह है कि इसमें भारतीय ज्ञान परम्परा, कला, साहित्य और संस्कृति को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनने पर जोर दिया गया है। साथ ही डिजिटल शिक्षा ऑन लाईन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर शिक्षा को सुलभ और गुणवत्ता पूर्ण बनाने की दिशा में प्रयास किया गया है।

गुण

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य बहुविषयक और अंतर्विषयक उदार शिक्षा प्राप्त करना है।
- व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 2035 में बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।

निष्कर्ष

शिक्षा किसी भी समाज की उन्नति और विकास का आधार होती है, और इसका स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। भारत में शिक्षा की एक अत्यंत समृद्ध और प्राचीन परम्परा है, जिसकी जड़ें प्राचीन काल में गहरी जमी हुई हैं। प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली, जो गुरुकुलों और आश्रमों पर आधारित थी, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं थी। इसमें छात्रों के स्वांगीण विकास, नैतिक मूल्य के आत्मसातीकरण और समाज के प्रति उनके कर्तव्य की समझ पर विशेष ध्यान दिया जाता था। हालांकि औपनिवेशिक काल और उसके बाद के वैश्विक प्रभावों ने शिक्षा को उपयोगिता, परीक्षाओं और डिग्रियों की ओर मोड़ दिया। भारत में वर्तमान शिक्षा संरचित, तकनीकी रूप से सक्षम और राजगारोन्मुखी है। भारत की शैक्षिक विरासत दुनिया की सबसे प्राचीन और व्यापक विरासतों में से एक है। सभ्यता के प्रारम्भिक काल से ही, भारत में शिक्षा ने व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास और समाज की सांस्कृतिक निरंतरता में उच्च महत्व का स्थान रखा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- आर्य दीपक (2021), वैदिक काल गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। साहित्य संहिता, 7 (11), 9–16.
- आलतेकर ए.एस (2008), प्राचीन भारत में शिक्षा, वसुंधरा प्रकाशन गोरखपुर, पृष्ठ संख्या 13–15।
- तोमर लज्जा राम (2022), प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, सुरुचि प्रकाशन, दिल्ली।
- पाण्डेय राम सकल (2010), भारत में शिक्षा का विकास, प्रकाशन— श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा, पृष्ठ संख्या 17–19।
- वालिया जे.एस. (2018), भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, बुक मैन प्रकाशन, यू. पी।

- वशिष्ठ के. के. एवं शर्मा, एल. डी. (1992), वेबसाइट्स
भारतीय शिक्षा की नई दिशा, आर. लाल बुक डिपो मेरठ।
 - www.shaikshikmanthan-com
 - www.education-nic
 - <http://www-desertation-com>
 - <http://www-indianjournals-com>
 - www.shodhganga-inflibnet-ac-in
- श्रीवास्तव चंदन (2021), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण से भारत में उच्चतर शिक्षा का विकास, भारतीय आधुनिक शिक्षा, 42 (02) 82–88.

आत्मनिर्भर भारत: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में

डॉ. सतीश चन्द मंगल (उप-प्राचार्य)

श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय केशव विद्यापीठ, जामडोली, जयपुर, राजस्थान

रमाकान्त दीक्षित (शोधार्थी)

सहायक आचार्य, महात्मा गाँधी टी.टी. कॉलेज महवा, दौसा, राजस्थान

सारांश

आत्मनिर्भर भारत अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारत सरकार द्वारा शुरू दो प्रमुख पहलें हैं। दोनों का अंतिम उद्देश्य भारतीय आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। जहाँ आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करती है। यह शोध पत्र आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मध्य संबंधों तथा भारतीय अर्थव्यवस्था तथा शिक्षा प्रणाली पर उनके संभावित प्रभाव की परख करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 आत्मनिर्भर भारत बनाने की परिकल्पना के साथ, कक्षा छठी से ही कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ करने की वकालत करती है। इसमें शिक्षार्थियों के

सर्वांगीण विकास के लिए अनुभव-आधारित शिक्षा पर भी जोर दिया है। जो व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक कौशलों को बढ़ावा दे और अंततः एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहायक हो। यह शोध पत्र इन उपबंधों के कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की भी पहचान करता है। तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संभावित सुझाव प्रस्तुत करता है। इन पहलों के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वित प्रयास एवं सहयोग की जरूरतों पर प्रकाश डालता है और भारत के सतत् विकास को बढ़ावा देने हेतु समग्र तथा सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देता है।

मुख्य शब्द – भारत, आत्मनिर्भर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

भारत के राष्ट्रीय विकास और प्रगति की दिशा में एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए हैं आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020। भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई दो प्रमुख पहलें हैं। प्रथम पहल मई 2020 में आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और विदेशी आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। मेरियम-वेबस्टर के अनुसार—“आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने स्वयं के संसाधनों और प्रतिभाओं पर निर्भर रहने की क्षमता”। इस पहल का उद्देश्य शैक्षिक सुधारों के साथ-साथ देश को आर्थिक

स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाना है। द्वितीय पहल भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए एक व्यापक ढांचा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो भारत के शैक्षिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी की बदलती मांगों को पूरा करना है। यह नीति समावेशी, लचीली और अंतर्विषयक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने के लक्ष्य पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 स्वदेशी उद्यमिता, नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने पर बल देती है।

केन्द्रिय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान (5 सितम्बर, 2025) ने अपने आलेख "द टीचर इन अ चेंजिंग वर्ल्ड" में लिखा है कि एन.ई.पी.-2020 भारत की आत्मनिर्भरता की मुख्य कड़ी है और इसे एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय प्रयास माना जाना चाहिए।

कौशिक अनुराग एवं मिश्रा महीप (2023) मानद वि.वि. हापुर यू.पी. द्वारा "नई शिक्षा नीति-2020 और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना: एक आंकलन" विषय पर लिखित शोधपत्र में बताया कि शिक्षा किसी भी देश और समाज के विकास की महत्वपूर्ण आधार होती है शिक्षा के बलबूते ही किसी भी देश का विकास तेजी से किया जा सकता है।

सिंह डॉ. सुनील कुमार (जून 2020) चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा "आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भूमिका: विश्लेषण, आवश्यकता एवं भविष्य" विषय पर लिखित आलेख में बताया कि शिक्षा ही एक माध्यम है, जो कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति और उसके आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। भारत सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और आत्मनिर्भर योजना, इसी सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगी जिससे भारत का हर नागरिक, हर क्षेत्र में एक उत्कृष्ट सेवा और संस्कार से एक समृद्ध एवं विकासशील समाज का निर्माण कर सकेगा।

पटेल दीपिका बी. एवं अग्रवाल मनीष (2024) द्वारा "नेशनल एजुकेशन पॉलिसी-2020 आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यावसायिक शिक्षा में युगांतकारी बदलाव" विषय पर लिखित आलेख में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारत में व्यावसायिक शिक्षा को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है लचीलेपन, उद्योग के साथ जुड़ाव और समग्र कौशल विकास पर जोर देकर एन.ई.पी.-2020 एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करती है जो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देती है। एन.ई.पी.-2020 ने वर्तमान सदी की आवश्यकताओं

को ध्यान में रखते हुए और एक कुशल कार्यबल के माध्यम से "आत्मनिर्भर भारत" बनाने की दृष्टि से कक्षा छठी से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की वकालत की है

शोध के उद्देश्य

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का अध्ययन करना।
2. आत्मनिर्भर भारत संकल्पना के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के समन्वय का अध्ययन करना।

शोध विधि

यह गुणात्मक अध्ययन है जो शोध के द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। यह शोध संबंधित साहित्य के अवलोकन और विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, बेवसाइट्स से एकत्रित की गई विषयवस्तु के गहन विश्लेषण पर आधारित है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत सरकार द्वारा मई 2020 में प्रारम्भ किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और विदेशी आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना है। इस पहल का लक्ष्य भारत को कृषि, रक्षा और विनिर्माण सहित सभी क्षेत्रों में एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। यह पहल ऐसे समय में प्रारंभ की गई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी और उसके बाद के प्रभावों के कारण अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है। इसका उद्देश्य देश में विकास और प्रगति के लिए नए अवसर पैदा करना है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान पाँच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है जो इस प्रकार हैं:-

1. अर्थव्यवस्था:- प्रथम स्तंभ व्यवसायों को, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (डैडमे) को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
2. बुनियादी ढाँचा:- दूसरा स्तंभ देश में विश्व-स्तरीय बुनियादी ढाँचा विकसित करने

- का लक्ष्य रखता है, जो आर्थिक विकास और प्रगति के लिए अनिवार्य है।
3. प्रणाली:— तीसरा स्तम्भ शासन और प्रशासन की एक सुदृढ़ प्रणाली बनाने पर केन्द्रित है, जो कुशल, पारदर्शी और जबाबदेह हो।
 4. जनसांख्यिकी:— चौथा स्तम्भ देश के जनसांख्यिकीय लाभांश यानी युवा और शिक्षित कार्यबल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
 5. माँग:— पाँचवाँ स्तम्भ देश में वस्तुओं और सेवाओं की माँग पैदा करने पर लक्षित है, जो आर्थिक विकास और प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है।
 2. समानता— दूसरा स्तम्भ शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने पर केन्द्रित है, जो सामाजिक न्याय और समावेशन के लिए अनिवार्य है।
 3. गुणवत्ता— तीसरा स्तम्भ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का लक्ष्य रखता है, जो देश में मानव पूंजी के विकास के लिए आवश्यक है।
 4. वहनीयता— चौथा स्तम्भ शिक्षा को सभी के लिए, विशेषतः गरीबों और वंचितों के लिए, वहनीय बनाने का उद्देश्य रखता है।
 5. जवाबदेही— पाँचवाँ स्तम्भ शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही को बढ़ावा देने पर केन्द्रित है जो पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।

इन स्तम्भों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के विकास के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक व्यापक ढाँचा है, जिसकी घोषणा जुलाई-2020 में की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक अधिक समावेशी, न्यायसंगत और उच्च गुणवत्ता वाली व्यवस्था में परिवर्तित करना है, जो 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को हितधारकों—जिनमें शिक्षक, नीति निर्माता, छात्र और अभिभावक शामिल हैं, के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पाँच स्तम्भों पर केन्द्रित है, जो निम्न हैं:—

1. पहुँच— पहला स्तम्भ सभी बच्चों, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने पर केन्द्रित है।

इन स्तम्भों का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में आत्मनिर्भरता हेतु उच्च शिक्षा में कौशल विकास के उपबंध

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के ड्रॉफ्ट के भाग-द्वितीय “उच्चतर शिक्षा” के अध्याय-11 “समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर” शीर्षक के बिन्दु 11.1 में प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे बाणभट्ट की कादम्बरी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में वर्णित करती है जिसमें व्यावसायिक शिक्षा जैसे बढ़ई का काम और कपड़े सिलने का कार्य, व्यावसायिक कार्य जैसे औषधि तथा अभियांत्रिकी और साथ ही साथ सम्प्रेषण, चर्चा और वाद-संवाद करने के व्यावहारिक कौशल (सॉफ्ट स्किल्स) भी शामिल है। मानवीय सृजन के सभी क्षेत्र यथा व्यावसायिक और व्यावहारिक कौशल को कलाओं के रूप में देखना चाहिए, का उल्लेख किया गया है।

बिन्दु 11.8, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में न केवल व्यावसायिक कौशलों को शामिल किया गया है बल्कि जीवन-कौशल जिसमें मूल्य आधारित शिक्षा की बात कही गई है सेवा तथा सामुदायिक

कार्यक्रमों में सहभागिता को समग्र शिक्षा का अभिन्न अंग बताया है इसके अतिरिक्त कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में इंटरनशिप का उपबंध भी किया है जिसमें बालक स्थानीय उद्योग, व्यवसाय, कलाकार, शिल्पकार आदि के साथ इंटरनशिप करेगा जिससे सक्रिय सीखने के व्यावहारिक पक्ष के साथ एक कौशल विकसित हो और आत्मनिर्भरता की संभावनाओं को भी बढ़ा सकें।

बिन्दु 12.8, वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भरता को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर का उल्लेख है जिससे भारतीय छात्र उच्च शिक्षा में वैदेशिक कौशलों को सीख कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे।

बिन्दु 16.4, में उपबंधित है कि व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने से यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे और अन्य कई व्यवसायों से इस प्रकार परिचित हो। ऐसा करने के परिणामस्वरूप वो श्रम की महत्ता और भारतीय कलाओं और कारीगरी सहित अन्य विभिन्न व्यवसायों के महत्त्व से परिचित होगा जो उसे आत्मनिर्भर बनने में उपयोगी सिद्ध होगा।

इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में बहुत से उपबंध किये गये हैं जो शिक्षा को एकीकृत करते हुए कौशल विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करते प्रतीत होते हैं यह प्रयास निश्चित रूप से भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सार्थक साबित होंगे।

आत्मनिर्भर भारत अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मध्य समन्वय

आत्मनिर्भर भारत अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 दोनों एक-दूसरे के साथ समन्वय रखते हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य देश में आत्मनिर्भरता, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा

देना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य विदेशी आयात पर भारत की निर्भरता को कम करके और घरेलू विनिर्माण तथा नवाचार को बढ़ावा देकर आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उद्देश्य एक ऐसे ज्ञान-आधारित समाज को बढ़ावा देना है जो नवाचारी, रचनात्मक और उद्यमी हो। इसलिए ये दोनों पहले एक-दूसरे की पूरक हैं, क्योंकि दोनों का अंतिम उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा देना है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मध्य प्रमुख आपसी समन्वय में से एक देश में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य कृषि, रक्षा और विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है, जिसके लिए छात्रों को नवप्रवर्तक और उद्यमी बनने हेतु आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान किया जाता है। अतः इन दोनों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना है।

इन दोनों के मध्य एक और प्रमुख समन्वय देश में कौशल विकास को बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य कृषि, रक्षा और विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता को बढ़ावा देना है। वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देना है, जिसके लिए छात्रों का समाज के उत्पादक सदस्य बनने हेतु आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसलिए यह दोनों अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने पर केन्द्रित है।

इनके अतिरिक्त इनका उद्देश्य देश में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भर भारत

अभियान का उद्देश्य कृषि, रक्षा और विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। वही दूसरी ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है, जिसके लिए छात्रों को आधुनिक प्रौद्योगिकी और डिजिटल शिक्षण उपकरणों तक पहुँच प्रदान की जाती है। अतः ये दोनों अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करती है।

चुनौतियाँ और अवसर:-

आत्मनिर्भर भारत अभियान और नई शिक्षा नीति-2020 को लागू करने में चुनौतियाँ भी हैं। इन दोनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में एक मुख्य चुनौती पर्याप्त बुनियादी ढाँचे और संसाधनों की कमी है। इनके लिए बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधनों में भारी निवेश की आवश्यकता है, जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक चुनौती हो सकती है। इसके अलावा इन पहलों की सफलता विभिन्न हितधारकों जिनमें सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज शामिल हैं, के मध्य प्रभावी समन्वय और सहयोग पर निर्भर करती है। इन दोनों को लागू करने से भारत के

लिए कई अवसर भी पैदा होते हैं। इनमें देश के आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और सतत विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है। इनका उद्देश्य आत्मनिर्भरता, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जो ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष

आत्मनिर्भर भारत अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारत में आर्थिक आत्मनिर्भरता, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई दो प्रमुख परिवर्तनकारी पहलें हैं। इनमें भारतीय अर्थव्यवस्था और शिक्षा प्रणाली को एक अधिक समावेशी, न्यायसंगत और मजबूत प्रणाली में बदलने की क्षमता है, जो 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इनके प्रभावी और सुदृढ़ कार्यान्वयन के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिकों सहित विभिन्न हितधारकों के मध्य एक सार्थक प्रयास और सहयोग की आवश्यकता है। इनकी सफलता सुनिश्चित करने तथा भारत के सुदृढ़ विकास हेतु सार्थक पुरुषार्थ की आवश्यकता है।

“उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेः।

न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।।”

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- कौशिक, अनुराग एवं मिश्रा, डॉ. महीप (2023), नई शिक्षा नीति-2020 और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना: एक आंकलन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च इन मल्टीडिसीप्लीनरी, वो.-1,(2) पृ.स. 363-366.
- प्रधान धर्मेन्द्र, (2023), *अमृतकाल और राष्ट्रीय शिक्षा नीति*, शैक्षिक मंथन 25(1), पृ. 25-26.
- पांडे, जय प्रकाश, (2025), कॅरिअर बनाने की दिशा में बहु-विषयक पहल, योजना, अंक-10, पृ. 6-9
- सिंह, डॉ. सुनील कुमार (2020), *आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भूमिका: विश्लेषण, आवश्यकता, एवं भविष्य*, विज्ञान गरिमा सिंधु, त्रैमासिक विज्ञान पत्रिका, अंक-113, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली.
- Asija, Dr. A., and Mathur, Dr. S., (2025), NEP 2020's Role In Realizing Self-Reliant Bharat's Vision For 2047, IJCRT International Peer-reviewed Journal, Vol.-13(2), 293-301.

- Dipika, B. Patel and Agrawal, M., (2024), National Education Policy 2020: Paradigm Shift in Vocational Education for Aatmanirbhar Bharat, Asian Journal of Education and Social Studies, vol.-50(6), 93-99.
 - Kaur, Karamdeep, (2023), Atmanirbhar Bharat Abhiyan and National Education Policy-2020: Opportunities and Challenges for India's Sustainable Development, Indian Journal of Social Science and Literature, Vol.-2(4).
 - Chandrakar, A., Rajak, N., Kumar, S., & Saha, S., (2021), Policy Recommendations for Effective Implementation of Atmanirbhar Bharat Abhiyan and National Education Policy in India. International Journal of Applied Research, 7(2), 1076-1079.
- Websites-**
- www.ijssl.latticescipub.com
 - www.ijcrt.org
 - www.sdiarticle5.com
 - www.researchgate.net
 - www.scholar.google.com

भारत में युवा सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका

डॉ. नीरज कुमार तिवारी

सहायक आचार्य, महात्मा गाँधी टी.टी. कॉलेज, महवा, दौसा, राजस्थान

सारांश

युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति और शक्ति होते हैं, और उनकी गुणवत्ता ही राष्ट्र के भविष्य का निर्धारण करती है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के अनुसार, “युवा अक्सर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले लोग होते हैं। युवा परिवर्तन की शक्ति हैं।” अगले 4-5 वर्षों में, यदि हम अपने देश को विकासशील से विकसित करना चाहते हैं और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो युवा सशक्तिकरण हमारी सरकार की हर योजना, बजट, कार्यक्रम और नीति का मुख्य एजेंडा होना चाहिए। निःसंदेह, हम कह सकते हैं कि आज के युवा कल के नवप्रवर्तक, निर्माता, नेता और राष्ट्र को बदलने की शक्ति हैं। इसलिए, युवाओं में न केवल एक देश का भविष्य तय करने और उसे आकार देने की शक्ति है वे विश्व के भविष्य को भी परिभाषित और आकार दे सकते हैं। युवा अविश्वसनीय और अकल्पनीय कार्य करने में सक्षम हैं। जब युवाओं को प्रेरित किया जाता है, शिक्षित किया जाता है और ऐसे वातावरण में पाला-पोसा जाता है जहां अन्य लोग विभिन्न मुद्दों पर उनके विचारों और राय को खुले तौर पर प्रोत्साहित और महत्व देते हैं, तो हमारे समाज को आकार देना

और विकसित करना कहीं अधिक बेहतर और आसान हो जाता है। शिक्षा असमानता को कम करने, महिलाओं को सशक्त बनाने, आतंकवाद को कम करने, पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने, हिंसा को कम करने और समाज एवं राष्ट्र की किसी भी समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए, शिक्षा युवाओं को सशक्त बनाने का सर्वोत्तम साधन है। क्योंकि शिक्षा बेहतर नौकरियों, उच्च वेतन और सकारात्मक सोच एवं मूल्यों के साथ उच्च जीवन स्तर तक पहुंच प्रदान करती है। शिक्षा व्यक्तिगत क्षमता, अंतर्निहित गुणों को विकसित करने, सामाजिक एवं आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा देने और असमानता को कम करने का सर्वोत्तम साधन है। इस शोधपत्र में, शोधकर्ता इस बात का अध्ययन करते हैं कि शिक्षा किस प्रकार सहायक हो सकती है और युवाओं को सशक्त बनाने में क्या मुद्दे और चुनौतियाँ हैं।

मुख्य शब्द – युवा सशक्तिकरण, शिक्षा, व्यक्तिगत क्षमता, सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा देना।

परिचय

युवा सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों और युवाओं को अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वे अपनी परिस्थितियों का सामना करके और संसाधनों तक अपनी पहुँच को बेहतर बनाने तथा अपने विश्वासों, मूल्यों और दृष्टिकोणों के माध्यम से अपनी चेतना को रूपांतरित करने के लिए

कदम उठाते हैं। युवा सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लाभकारी परिणाम बेहतर सामाजिक कौशल, बेहतर व्यवहार, शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि, आत्म-दक्षता और आत्म-सम्मान में वृद्धि हैं। जब युवा सशक्त महसूस करते हैं, तो वे घर, विद्यालय, समाज और उससे परे सक्रिय योगदानकर्ता और सहयोगी बन जाते हैं। एक सशक्त युवा अपनी क्षमताओं, आत्म-निर्णय और मूल्य को पहचानता

है। वे नई चीजें बनाने का प्रयास करते हैं। उनमें जोखिम उठाने का अधिक आत्मविश्वास होता है और वे जानते हैं कि असफलता प्रगति की ओर एक कदम है, न कि हार मानने का संकेत। और वे जानते हैं कि उन्होंने आत्म-सशक्तिकरण की एक मजबूत नींव बनाई है जिस पर वे संघर्ष के समय या जब वे भटक जाते हैं और उन्हें पुनर्संतुलन की आवश्यकता होती है, तब भरोसा कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से अगली पीढ़ी को सशक्त बनाकर, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे कल की चुनौतियों का सामना करने और अधिक समृद्ध और न्यायसंगत दुनिया बनाने के लिए तैयार हों।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने कहा कि दुनिया भर के युवाओं को सूचना प्राप्त करने, जुड़ने और न्याय, समानता और अवसर जैसे महत्वपूर्ण सवालों को पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। हमारा काम युवाओं की बात सुनना और उनकी मांगों को पूरा करना है। इसके लिए शिक्षा सबसे अच्छा विकल्प है। शिक्षा युवाओं के अंतर्निहित गुणों को निखारने की प्रमुख कुंजी है। शिक्षा न केवल व्यक्तियों को जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से समृद्ध करती है, बल्कि उन्हें अपने समुदायों में सार्थक योगदान देने में भी सक्षम बनाती है। युवाओं को शिक्षित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमारे समाज का भविष्य हैं। शिक्षा हमें अच्छे शिष्टाचार, मूल्य, संस्कृति, सकारात्मक सोच, दूसरों के प्रति सम्मान और आत्मसम्मान सिखाती है, जो युवाओं को सशक्त बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

युवाओं को सशक्त बनाने में आने वाली चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

1. **सामुदायिक कार्यक्रमों में भागीदारी की कमी** – सामुदायिक कार्यक्रमों में भागीदारी से समाज के प्रति संवेदनशीलता, सामुदायिक उत्तरदायित्व, सामाजिक मूल्यों और

आत्मसम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ती है, लेकिन आज के युवा सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं।

2. **आदर्शों और मार्गदर्शकों का अभाव**— आज की शिक्षा प्रणाली आदर्श या मार्गदर्शक बनाने में पूरी तरह विफल रही है, यही कारण है कि युवा केवल शिक्षा के लिए ही शिक्षा प्राप्त करते हैं।
3. **उचित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव**— शिक्षा हर समस्या का समाधान है, फिर भी आज के युवा शिक्षा से मुंह मोड़ लेते हैं।
4. **आत्मविश्वास की कमी**— वे स्वयं को सशक्त बनाने में असमर्थ हैं।
5. **उचित मार्गदर्शन और परामर्श सुविधाओं का अभाव**— उचित मार्गदर्शन और परामर्श सुविधाओं के अभाव के कारण युवा सही दिशा में जाने के बजाय असामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।
6. **सरकारी नीतियों का उचित उपयोग और क्रियान्वयन न होना**— सरकार युवाओं के लिए कई योजनाएं लागू करती है, जैसे—
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY)
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PRPY)
राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना (NCSP)
MGNREGA, ग्रामीण स्वरोजगार और संस्थान (RSETI)
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM & SWANIDHI)
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) लेकिन युवाओं में जागरूकता की कमी के कारण इनका उचित उपयोग और क्रियान्वयन नहीं हो पाता है।
7. **उपयुक्त कौशल का अभाव**—
8. आज के युवा अपने कौशल और गुणों को अद्यतन या बेहतर बनाने के इच्छुक नहीं हैं, जो युवा विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण

- हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली इस पर ध्यान नहीं देती।
9. अवसरों के प्रति जागरूकता का अभाव।
 10. आज के युवा उन अवसरों से अवगत नहीं हैं जो उन्हें सफल होने में मदद कर सकते हैं। उचित मार्गदर्शन और सलाह का अभाव भी जागरूकता की कमी का कारण बनता है। इसी वजह से वे अपने कौशल को उन्नत करने में असमर्थ हैं।
 11. असामाजिक गतिविधियों में भागीदारी।
- सामाजिक चुनौतियाँ**
- आर्थिक असमानताएँ, लैंगिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव और तकनीकी बाधाएँ युवाओं के समग्र विकास को प्रभावित करती हैं। आज के युवा नैतिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं। इसका कारण यह है कि हम कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- बेरोजगारी संकट, आर्थिक संकट, युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उचित बुनियादी ढांचे की कमी और आवश्यक कौशल की कमी जैसे संकटों का सामना कर रहे युवाओं को आसानी से असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए गुमराह किया जा सकता है।
- युवाओं के सशक्तिकरण में चुनौतियाँ**
- युवाओं के सशक्तिकरण में निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं:
1. सामुदायिक सहभागिता के लिए विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना।
 2. शिक्षा किस प्रकार युवाओं के मार्गदर्शन और परामर्श के लिए मार्गदर्शक और आदर्श तैयार करने में सहायक होगी।
 3. युवाओं में सरकारी नीतियों के उपयोग और कार्यान्वयन के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए।
 4. शिक्षा किस प्रकार छात्रों में विभिन्न कौशल और मूल्यों को अद्यतन करने में सहायक होगी।
 5. समाज में उपलब्ध अवसरों की जानकारी कैसे बढ़ाई जाए।
 6. आर्थिक असमानता, लिंगभेद, जातिगत भेदभाव और तकनीकी बाधाओं को कैसे दूर किया जाए जो युवाओं के समग्र विकास को प्रभावित करती हैं।
 7. युवाओं को नैतिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सशक्त कैसे बनाया जाए जिससे असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों में कमी आए।
 8. प्रौद्योगिकी किस प्रकार युवा सशक्तिकरण में सहायक होगी।
- सिफारिशें**
- युवाओं को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें हैं:
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सामुदायिक सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना।
- मार्गदर्शक और आदर्श युवाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शिक्षा सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक और आदर्श बनाने का सबसे अच्छा साधन है, इसलिए शिक्षा और युवा सशक्तिकरण साथ-साथ चलने चाहिए।
- युवाओं में सरकार की विभिन्न नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए और इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहायक होगी।
- युवा नेतृत्व और समाज के साथ सहभागिता को बढ़ावा देना।
- नेतृत्व क्षमता के मामले में उन पर भरोसा करना।
- उन्हें स्थानीय सामाजिक गतिविधियों में शामिल करना।

सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिनका उद्देश्य उनकी क्षमताओं और कौशल का उचित उपयोग करना हो।

स्थानीय सामुदायिक परियोजनाओं और विकास को बढ़ावा देने वाली अन्य स्थानीय पहलों में युवाओं को शामिल करके उन्हें प्रोत्साहित करना। उन्हें अवसर देना और खुद पर भरोसा करना सिखाना। उनकी रुचियों और क्षमताओं को जानने के लिए उचित शिक्षा प्रदान करना।

उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें।

युवाओं को शिक्षा और व्यक्तिगत कौशल विकास के लिए सशक्त बनाना व्यक्तिगत परिवर्तन और सामुदायिक विकास का उत्प्रेरक है। उनकी शिक्षा में निवेश करके, व्यावसायिक प्रशिक्षण और समावेशी सहायता प्रणाली प्रदान करके, हम सभी के लिए अधिक न्यायसंगत और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं।

निष्कर्ष

आज का युग युवाओं का युग है। उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है जो उन्हें लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक, तार्किक, खुले विचारों वाला, आत्मसम्मानित, जिम्मेदार, ईमानदार, सम्मानजनक और देशभक्त बनाए। इन गुणों के विकास के बिना हमारे युवा अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। देश में बढ़ती बेरोजगारी हमारे

युवाओं को सत्ता, धन और प्रतिष्ठा की लालसा में गलत दिशा में धकेल रही है। युवाओं को बेहतर विकल्प प्रदान करके, उन्हें सशक्त बनाकर और उन्हें सशक्त बनाकर हिंसक गतिविधियों और आतंकवाद से बचाना अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्र के विकास के लिए युवाओं की शक्ति का रचनात्मक उपयोग करने और सशक्तिकरण को लक्षित करने वाली नीतियां बनाने से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर भविष्य और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- शांतिपूर्ण विश्व। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टेक्निकल रिसर्च एंड साइंस, 2(12), 1-5
- इंदरीसा, एफ. जेड., हसन, जेड., गिल, एस. के., और अब्बल, एन. ए. एम. (2012). युवाओं की राष्ट्रीय पहचान को आकार देने में शिक्षा की भूमिका।
- प्रोसीडिया-सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज, 443-450- <https://doi-org/10-1016/j-sbspro-2012-09-296>
- जैसवाल, बी., भासिन, एस., और शर्मा, ए. (2015). युवाओं का सशक्तिकरण: 21वीं सदी की एक चुनौती।
- इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल रिलेवेंस एंड कंसर्न, '3'(8), 1-4

भारत में कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण

डॉ. बृजलता चौधरी

प्राचार्य

रतनी देवी गर्ल्स टी.टी. कालेज, हिंडौन सिटी, करौली, राजस्थान

सारांश

भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास शौर्य है, वीरता है, धैर्य है, समर्पण है व ज्ञान का अगाध भंडार है। जिसके युवाओं में सूर्य जैसा तेज तो पृथ्वी जैसी शीतलता है। पिछले कुछ दिनों में युवा शक्ति के कारण ही हमारे लोकतंत्र की शक्ति का परिचय पूरे विश्व के लिए उदाहरण बन गया है। बीता इतिहास ऐसे अनेकों प्रमाण प्रस्तुत करता है और आने वाले भविष्य की उज्ज्वलता का शंघनाद कर रहा है। यह युवा शक्ति के कारण ही संभव है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, कई विकसित देशों में उनकी आर्थिक स्थिति तथा मानसिक विकास को पर्याप्त संसाधनों और कौशल प्रशिक्षणों कारण वे सभी आत्मनिर्भरता की ओर समय रहते अग्रसर हो जाते हैं। हमारे देश में भी केंद्र व राज्य स्तर पर युवाओं के कुशलता के लिए अनेक ऐसे कोर्स एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गए

हैं जिनसे युवा शक्ति को उचित समय पर प्रशिक्षित कर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। इनमें से चड्झटल योजना है जिसके बारे में हम संक्षिप्त रूप में यहां चर्चा करने जा रहे हैं। यह कौशल विकास योजना शिक्षित लोगों के लिए भी वरदान से कम नहीं है। इसमें कम खर्च में युवाओं को आर्थिक व मानसिक रूप से अधिक सक्षम बनाया जा सकता है। यह कौशल प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाता है। इसके अंतर्गत कई प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं जिसमें डिजिटल (AI कोडिंग), तकनीकी, प्लंबर, सेवा (हेल्थकेयर, ब्यूटीशियन), सिलाई एवं ड्रोन तकनीक व प्रिंटिंग आदि शामिल है।

मुख्य शब्द – कौशल, विकास, तकनीकी, रोजगार डिजिटल, आर्थिक, मानसिक सशक्त।

प्रस्तावना

कौशल विकास कार्यक्रम – भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एम. एस. डी. ई.) की प्रमुख योजना है। इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई। यह मिशन युवा कौशल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया जिसका उद्देश्य 2022 तक भारतीय युवाओं को विभिन्न उद्योगों से संबंधित कौशल में प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर और रोजगार के योग्य बनाना था। इस मिशन के तहत शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में युवाओं को दीर्घकालिक या अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना है।

भारत में कौशल विकास युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण –

राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी किसी एक क्षेत्र में न होकर इससे कहीं अधिक होती है। जो नेतृत्व, नवाचार, कठोर परिश्रम और समय के अनुसार परिवर्तन की मांग करती है। भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में युवा पीढ़ी को अग्रसर करना होगा। आज के युवाओं को कौशल विकास की महती आवश्यकता है। जिससे यह अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं और क्षमताओं को निखारकर सभी प्रकार की सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर सकें।

कौशल विकास — कौशल विकास के तीन प्रमुख प्रकार माने गए हैं। जिसमें तकनीकी कौशल, सॉफ्ट स्किल और नेतृत्व कौशल शामिल हैं। जिसमें तकनीकी कौशल का तात्पर्य तकनीकी संसाधनों का विशिष्ट ज्ञान और क्षमताओं से है। यह कौशल नौकरी से संबंधित कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं।

सॉफ्ट स्किल में पारस्परिक क्षमताएं हैं जो टीम के कार्य को करने में टीम के सदस्यों के बीच सहयोग और संचार को बढ़ाते हैं तथा नेतृत्व कौशल दूसरों के मार्गदर्शन और उन्हें प्रभावित करने की क्षमता को विकसित करने पर केंद्रित होते हैं। जिनके व्यक्तित्व में रणनीतिक क्षमता, सोच निर्णय लेना और सलाह देना शामिल है।

उद्देश्य— कौशल विकास का मुख्य उद्देश्य देश में युवा शक्ति को संगठित करके उनके कौशल को निखारकर उन्हें उनकी योग्यता अनुसार रोजगार देना है।

सिद्धांत— युवा विकास के मुख्य सिद्धांत निम्न है।

एक संगठनात्मक संरचना जो युवा विकास को सहयोग प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त सुरक्षित भौतिक वातावरण जो युवाओं को समझने व आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सहायक प्रबंध।

इसका लक्ष्य 2022 तक 40 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करना है।

पात्रता— वैध आधार कार्ड धारक और संबंधित नौकरी के लिए आवश्यक मापदंडों को पूरा करने वाले भारतीय नागरिक। इसके लिए आयु 15 से 28 वर्ष है। इस योजना में कोर्स 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन द्वारा होता है। कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होता है।

युवा सशक्तिकरण— युवा सशक्तिकरण का अर्थ है युवाओं को कौशल, आत्मविश्वास और समर्थन प्रदान करना, जिनकी उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण रखने और सकारात्मक बदलाव के लिए आवश्यकता होती है। जब युवा सशक्त होंगे तो

वह अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। मूल रूप से सशक्तिकरण का अर्थ सक्रियता, अपने परिवेश व समाज में सार्थक परिवर्तन लाने, कार्य करने विकल्प चुनने और प्रयास करने की क्षमता है।

भारत के विकास में युवा शक्ति की भूमिका—

प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में भारत में वर्ष 2030 तक 1.04 बिलियन कार्यशील आयु वर्ग के लोग होंगे। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण 2018 – 2019 के अनुसार जनसांख्यिकी लाभांश 2041 के आसपास अपने उच्चतम स्तर पर होगा।

युवा शक्ति के समक्ष विद्वान चुनौतियां— रोजगार की अस्थिरता

कई बार प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद भी कोई निश्चित रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाती है।

कई बार अपने क्षेत्र से दूर रोजगार मिलने की वजह से भी युवा कार्य से नहीं जोड़ पाते।

सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं का अभाव—

विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के इंतजाम प्रभावी किया जाए केवल कौशल की उपलब्धता व्यवसाय के लिए निश्चित नहीं हो सकती। इसके लिए अनुकूल व्यवस्थाएं की जाएं जैसे कार्य क्षेत्र दूरी पर स्थित है तो पर्याप्त वेतन व आवासीय व्यवस्था की जाए।

रोजगार पूरक कौशल एवं प्रशिक्षण का अभाव—

कई बार समय की अवधि कम रहने से उचित प्रशिक्षण नहीं लेने के कारण कौशल प्रभावी नहीं हो पाते हैं। उचित मार्गदर्शन, जागरूकता एवं पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता भी आवश्यक है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास क्रियान्वयन— यह कौशल विकास कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यहां केंद्र व राज्य से जुड़े कार्यक्रम चलाए जाते हैं। PMKVY के साथ नए कौशल प्राप्त करने के अलावा आप आगे की शिक्षा, बिजनेस/उद्यमों को

चलाने के लिए अपनी मौजूदा प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अनलॉक कर सकते हैं, बजाज फाइनेंस की प्रॉपर्टी के साथ लोन ले सकते हैं। यह आपकी बचत को बढ़ाए बिना अपने भविष्य में निवेश का स्मार्ट तरीका है। इसमें लघु अवधि प्रशिक्षण, विशेष कौशल और रोजगार मेला के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। जिसके प्रभाव से देश भर में रोजगार क्षमता और कार्यबल प्रबल हो जाता है।

PMKVY 2.0 – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016–20 का विस्तार बड़े पैमाने पर किया गया। जिसमें अधिक भौगोलिक क्षेत्र को शामिल किया गया। जबकि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसे प्रमुख राष्ट्रीय मिशन के साथ नजदीकी से मेल अकाउंट था।

बजट – कुल बजट आवंटन 12000 करोड़ था।

कार्यान्वयन संरचना – केंद्रीय प्रायोजित राज्य प्रबंध CSSM राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित राज्य कौशल विकास मिशन (SSDM) के माध्यम से लागू किया गया। यह घातक बाकी 25 : को लागू किया।

केंद्रीय रूप में प्रायोजित केंद्रीय प्रबंधन – राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित राज्य कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा लागू इस घटक को 75 : फंड और प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त हुए।

व्हाट्सएप 3.0 कवरेज – यह 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 717 जिलों में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करना है। जिसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में बेहतर जिम्मेदारियां और सहायता मिलेगी। राज्य कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित जिला कौशल समितियां और स्थानीय मांगों का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

युवा शक्ति के कौशल विकास की गतिविधियों में निम्न विचारों को शामिल किया जा सकता है –

1. **भविष्य के लिए परामर्श सत्र** – विभिन्न क्षेत्रों में रुचि लेने वालों को उचित परामर्श के लिए

आवश्यक कौशल परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाए।

2. **कार्यशाला और सेमिनार** – व्यावसायिक कौशल, डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता का विकास करने वाली कार्यशाला व सेमिनारों को समय-समय पर करवाया जाते रहना चाहिए।

3. **ऑनलाइन व ऑफलाइन अभियान** – युवाओं के कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए लोगों में सकारात्मकता व जागरूकता के लिए इस प्रकार के अभियान चलाए जाए। सोशल मीडिया पर व्यापक प्रसार-प्रचार के साथ-साथ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैंप या शिविरों का क्रियान्वयन किया जाए ताकि लोगों की पहुंच तक उचित जानकारी व लाभ प्रदान कराया जा सके।

युवा विकास के लिए महत्वपूर्ण कौशलों में निम्न शामिल है –

व्यवहारिक व मानसिक कौशल – इन्हें आमतौर पर सॉफ्ट स्किल के रूप में जाना जाता है। इन आवश्यक दक्षता में संचार, टीमवर्क, समस्या समाधान और भावात्मक बुद्धिमत्ता शामिल है।

डिजिटल साक्षरता – आज के डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी को समझना आवश्यक है। आप तकनीकी उद्योग में रुचि नहीं रखते हो परंतु तकनीकी को समझना दूसरों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने एवं उनके विश्लेषण के लिए आवश्यक है।

उद्यमिता – यह नवाचार रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

नेतृत्व – यह युवाओं को प्रभावित करने, प्रेरित करने और परिवर्तन लाने की क्षमता प्रदान करता है।

सांख्यिकी और डेटा – भारत की युवा आबादी इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन साथ ही साथ कई चुनौतियों का भी सामना करती है।

हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश में बड़ी संख्या में अल्प रोजगार प्राप्त युवा हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि कौशल विकास से युवक बेरोजगारों को रोजगार मिला है। वहीं जेनरेशन इंडिया फाउंडेशन के आकलन से पता चला है कि उनके कार्यक्रमों में 91: से अधिक स्नातक प्रशिक्षण प्राप्त करने के 3 महीने के अंतर ही स्थाई रोजगार प्राप्त कर लेते हैं।

निष्कर्ष— भारत में युवा कौशल विकास कार्यक्रम से युवा शक्ति की आत्मनिर्भरता प्रभावित हो रही है। इच योजना के तहत युवाओं को सरकारी गैर सरकारी संगठनों से वित्तीय सहायता में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जिससे राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिकता का विकास होता है। युवाओं को विकास एवं सशक्तिकरण, तकनीकी संसाधनों का कुशलता से प्रयोग करना सिखाना व अन्य विभिन्न प्रकार के मार्गदर्शन प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम युवाओं की केवल आर्थिक स्थिति ही नहीं अपितु मानसिक स्वास्थ्य विकास को भी पनपाती है, जिससे युवा शक्ति का पूर्ण सदुपयोग किया जा सकता है। युवा स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ मन मस्तिष्क में ही अच्छे भाव विचार पनपते हैं, जिनसे युवा पूर्ण शक्ति और एकाग्रता के साथ अपने रोजगार पर ध्यान देकर अपने संबंधित कार्य की शक्ति से देश के भविष्य को रोशन करने की जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा से उठा पाएगा तथा आत्मनिर्भर भारत के विकास में अपना योगदान दे पाएगा।

युवा कौशल विकास कार्यक्रम का भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्व—

प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम युवाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर युवा – आत्मनिर्भर

भारत का निर्माण कर रही है। यह योजना कौशल प्रदान करके उत्पादकता को बढ़ाकर और जन सांख्यिकीय लाभ को बढ़ावा देकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

राष्ट्र निर्माण के महत्व –

1. आत्मनिर्भर भारत का निर्माण युवाओं को केवल डिग्री धारक न बनाकर स्वरोजगार व उद्यमिता बढ़ाना।
2. रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन।
3. बेरोजगारी को काम करके आय के साधन बढ़ाना।

महिला सशक्तिकरण महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर देश की आधी आबादी को मजबूती देना है।

पूर्व अनुभवों का लाभ उठाकर नवीन प्रशिक्षण व विभिन्न कौशलों में निपुण करना।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. पटेल धीरज शिक्षक प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी, कौशल और प्रथाएं।
2. शर्मा रामचंद्र भारत में कौशल विकास के विभिन्न पहलू।
3. Government Welfare schemes And policies (Disha T)
4. PMKVY योजना के तहत कौशल विकास के महत्व और परिणामों का विश्लेषण (अश्विनी कुमार जोशी)
5. विकसित भारत, युवा रोजगार और कौशल विकास (विकसितभारत/47 – 02 अगस्त 2025)

आत्मनिर्भर भारत: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपेक्ष्य में

नलिनी – शोधार्थी

डॉ. गौरव सिंह – सह आचार्य

कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान

सारांश

आदिकाल से ही सम्पूर्ण संसार में शिक्षा ही एक ऐसा पहलू रहा है जिसने मानव जाति को संसार में सभ्यक तरीके से रहना सिखाया। विभिन्न आपदाओं, मुसीबतों, विभिन्न सांसारिक उतार-चढ़ाव के बावजूद भी शिक्षा के कारण ही मानवीय जाति स्वयं अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब रही है। इसलिए मानवीय समाज में शिक्षा को अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत एक युवा देश है जहाँ 50 प्रतिशत से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों की है। इस युवा शक्ति का उपयोग देश के विकास के लिए करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी दिशा में एक बेहतरीन कदम है जो शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाने का प्रयास करती है। इसी के साथ ही नई शिक्षा नीति 2020 भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जो भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखती है। यह नीति शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने का प्रयास करती है जिसमें छात्रों के 21 वीं सदी के कौशल से लाया जा सके।

यह नीति आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाती है, जो शिक्षा को

कौशल-आधारित, बहुविषयक और स्थानीय ज्ञान को मातृभाषा से जोड़ती है। यह नीति कौशल विकास, उद्यमशीलता, तकनीकी एकीकरण और रटने के बजाय वैचारिक समझ पर जोर देकर युवाओं को आत्मनिर्भर व रोजगार योग्य बनाने का लक्ष्य रखती है। इस नीति के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य है कि देश के युवा आत्मनिर्भर बनें और देश की आर्थिक विकास में योगदान करें। प्रस्तुत शोधपत्र में हम विद्यालयी स्तर पर अधिगम संवर्धन का अर्थ तथा आज के बदलते वैश्विक परिवेश में सूचना और संचार तकनीक विद्यालयी बच्चों के लिए सीखने-सिखाने में किस प्रकार सहायक हैं और इसके साथ ही यह शिक्षा उन्हें उनके रोजगार में किस प्रकार सहायी होगी इस विषय पर चर्चा करेंगे जो वर्तमान परिपेक्ष्य के अनुसार विद्यालयों में अधिगम संवर्धन के लिए प्रयोग किये जा रहे हैं, इन उपकरणों का लाभ तथा इनके प्रयोग में आने वाली चुनौतियों के साथ-साथ सुझाव के साथ-साथ सुझाव पर भी प्रस्तुत लेख में चर्चा करेंगे।

मूल शब्द – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आई.सी.टी, विद्यालयी शिक्षा, डिजिटल अधिगम, जीवन कौशल, हस्त कौशल, भूमण्डलीकरण।

प्रस्तावना

शिक्षा मानवीय सभ्यता का अटूट व अभिन्न अंग है। वर्तमान समाज के दिन प्रतिदिन बढ़ते काम के दायरों के कारण शिक्षा के उद्देश्य एवं उसके क्षेत्र में भी दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। भावार्थ यह कि शिक्षा एवं समाज एक दूसरे के पूरक है।

यदि समाज में बदलाव आता है तो शिक्षा में भी बदलाव आता है और यदि शिक्षा में बदलाव आता है तो समाज में परिवर्तन आना स्वाभाविक ही है। नई शिक्षा नीति 2020 विगत तीन दशकों की सामाजिक दशा में सुधार की ओर अग्रसर होती एक ऐसी नीति है जिसमें भारतीय समाज के सभी

विद्यार्थियों एवं परिजनों को इस प्रकार से तैयार करने की योजना का एक प्रारूप है, जिसे भारत को संसार के सभी देशों की विकास की बढ़ती दौड़ में शामिल होने के मक्सद के मद्देनजर तैयार किया गया है। इसी के साथ ही यह भारतीय समाज के लोगों के कार्यों, बच्चों की मानसिक सेहत, कौशलात्मक विकास, शिक्षा में लचकीलापन एवं भावी समाज की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

शिक्षा और भूमंडलीकरण

मुख्यतः शिक्षा का अर्थ केवल इस बात से ही लिया जाता है कि वह मनुष्य को समाज में उसके पैरों पर खड़े होने में सहायक सिद्ध हो। वह उसे केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करने तक ही सीमित न रखे बल्कि हस्त कला में भी पारंगत करे जो भविष्य में उसे रोजीरोटी कमाने के लायक बना सके। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जब भी शिक्षा नीतियां तैयार हुई हैं। उन्हें समकालीन समाज के वातावरण के अनुसार ही तैयार किया जाता रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय समाज को समग्र रूप से विकसित करने के उद्देश्यहित तैयार की गयी है जो केवल वर्तमान से ही संबंधित नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी साथ लेकर चल रही है। क्योंकि सभी इस बात से सहमत एवं अवगत हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानवीय सर्वांगीण विकास ही है। इसके अभाव में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो प्रत्येक राष्ट्र के लिए यह वांछनीय हो जाता है कि वह अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए कोई ऐसा प्लान निर्धारित करे जिसमें चुनौतियों को साथ लेते हुए सभी सकारात्मक पहलु समाहित हों। 34 वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद यह शिक्षा नीति शिक्षा एवं कौशलात्मक विकास में एक बेहतरीन भूमिका निभाने के लिए तैयार है। क्योंकि इतने लम्बे अरसे के बाद स्वाभाविक ही है कि समाज में बहुत कुछ बदलाव आया है। भूमंडलीकरण के बाद सम्पूर्ण संसार में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणिक इत्यादि बहुत बड़े स्तर पर बदलाव आया है। इस बदलाव ने पूरी दुनिया को बदल

कर रख दिया है। प्रत्येक देश इस दौड़ में स्वयं को अग्रणी सिद्ध करने की फिराक में लगा हुआ है। आगे बढ़ने की दौड़ ने मनुष्य को बहुत कुछ सीखने व करने के लिए बाध्य कर दिया है। दिनों-दिन बढ़ती टेक्नॉलोजी की रफतार ने कार्यों में गुणवत्ता के साथ-साथ स्पीड को भी अहम रखा हुआ है, जिससे दिनों के कार्य घण्टों में हो जाते हैं। इंटरनेट ने इसमें विशेष योगदान दिया है जो सूचना प्रसारण में अहम भूमिका निभा रहा है। भूमंडलीकरण के दौर के ऐसे ही ओर भी बहुत से कारण रहे हैं जिन्होंने वर्तमान समय को एक प्रकार से नया रूप प्रदान कर दिया है। ऐसे में ही भारत भी अपनी छवि को सुधारने के लिए ऐढ़ी चोटी का जोर लगा रहा है। किन्तु हमें पता ही है कि बदलाव की इस आंधी में शिक्षा ही वह शस्त्र है जो भारतीय युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है।

आत्मनिर्भर भारत

आत्मनिर्भर भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है कि यहाँ की युवा पीढ़ी बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, कौशलात्मक रूप से सक्षम हो। इसके लिए जरूरी है कि बच्चे के जन्म से ही शिक्षा व पालन-पोषण का स्तर उच्च होना चाहिए। पुरातन शिक्षा नीति में 10+2 के अनुसार शिक्षा का प्रावधान था। किन्तु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्तमान स्थान पर 5+3+3+4 के शैक्षिक ढांचे को अपनाते हुए विद्यालयी शिक्षा में नवोन्मेषी परिवर्तन लाया गया है। इससे बच्चों की शैशवावस्था से ही विकास की एक सुदृढ़ नींव का निर्माण होना तय है जो उसकी युवावस्था तक निरंतर चलती है। शिक्षा का अर्थ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों के साथ शिक्षा द्वारा ज्ञानार्जन एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य एवं कुशल मनुष्य बनाने की पहल है।

स्किल इंडिया मिशन

भारत सरकार ने 2015 में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कर इसकी पहल की थी। जिसका

उद्देश्य युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना था। इसी क्रम में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का ऐसा मंत्र दिया जिसने युवाओं के आत्मविश्वास को गति प्रदान की। मूल्य आधारित शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, शिक्षा की स्वायत्तता और भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देना ही वर्तमान समय की मांग है और इस दिशा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भगीरथ प्रयास करती हुई नज़र आती है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य एक छात्र को कुशल बनाने के साथ-साथ उसी क्षेत्र में उसे प्रशिक्षित करना है जिस क्षेत्र में छात्र रुचि रखता हो। इस प्रकार सीखने वाले अपने उद्देश्य और अपनी क्षमताओं का पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं।

बुनियादी शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इक्कसवीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। वर्ष 1968 और 1986 के बाद यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुँच, क्षमता, गुणवत्ता, वहनता और उत्तरदायित्व पर विशेष बल दिया गया है। इसमें गुणवत्ता पूर्ण व समावेशी शिक्षा का विचार बुनियादी शिक्षा से लिया गया है। बुनियादी शिक्षा का विचार 1937 में महात्मा गांधी द्वारा वर्धा शिक्षा परिषद में देश व दुनिया के सम्मुख रखा गया था यह विचार अनायास ही गांधी जी के द्वारा प्रकट नहीं हुआ था। 1896 से स्वयं के बच्चों की शिक्षा व उनके शैक्षणिक प्रयोगों के प्रारम्भ हुआ। बाद में विविध विद्यालयों में 40 वर्षों के स्तु शैक्षणिक प्रयोगों से प्राप्त अनुभवों तथा देश की जरूरतों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1937 में बुनियादी शिक्षा के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था।

सतत विकास के उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यह नीति भारत

की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों का आधार लेते हुए, 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें सतत विकास के उद्देश्य भी शामिल हैं, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष बल देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं का विकास हो, अपितु उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का भी विकास होना चाहिए। चूंकि 34 वर्षों के एक लम्बे अंतराल के बाद देश में यह शिक्षा नीति लागू हुई है जिसका उद्देश्य नवोन्मेषी, लोकतांत्रिक एवं विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को प्रमुखता देना है। वर्तमान समय में भारतीय समाज को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है और यह रास्ता कहीं न कहीं नई शिक्षा व्यवस्था से होकर आगे बढ़ सकता है। वर्तमान समय में ज्ञान के परिदृश्य से पूरा विश्व तीव्र गति से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धि जैसे क्षेत्रों में ही रहे अनेक वैज्ञानिक-तकनीकी विकास के चलते एक और विश्वभर में अकुशल कामगारों के स्थान पर मशीनें कार्य करने लगी हैं। दूसरी ओर डेटा साइंस, कम्प्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की आवश्यकता तथा मांग बढ़ रही है जो विज्ञान, सामाजिक-विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में भी दक्ष हों।

जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों के कारण हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वाच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नये-नये आयामों पर विचार-विमर्श करने की महती जरूरत है और इस कारण जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में नये कुशल और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में नये

कुशल कामगारों की आवश्यकता होगी। महामारी और इसके बढ़ते हुए संक्रमण, रोग प्रबंध और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक पहलू बहु-विषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी। क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ-साथ दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है इसलिए रोजगार और वैश्विक परिस्थिति में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों के कारण यह आवश्यक हो गया कि छात्रों को जो कुछ नूतन परिदृश्य में सिखाया जाये, उसे तो वे सीखें ही, साथ में वे सतत सीखते रहने की कला में भी निपुणता परिलक्षित करें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से आत्मनिर्भर भारत की आस को मजबूती मिलने की भरपूर आस है। क्योंकि इस नीति का एक अहम पहलू इसका बहु विषयक दृष्टिकोण है, जिसकी प्रासंगिकता इस बात पर केंद्रित है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। जबकि पहले की शिक्षा प्रणाली मूल रूप से सीखने और परिणाम देने पर केंद्रित थी। विद्यार्थियों का आकलन प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता था और यह विकास के लिए एकल दिशा वाला दृष्टिकोण था। भारत सरकार के संकल्प 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान का यह स्वप्न है कि आगे आने वाले काल में हर भारतीय को आत्मनिर्भर बनाना है और यह तभी संभव हो सकता है जब भारत देश अपना पुरातन गौरव पुनः हासिल कर लेगा। यह किसी से छिपा नहीं है कि हमारी पुरातन परंपरा और मूल्य कितने उच्च कोटि के थे। कुटीर उद्योग औ हस्तशिल्प कला की बदौलत एक समय हमारा डंका वैश्विक परिदृश्य पर बजता था। ऐसे में अंततोगत्वा हमें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परिष्कृत होते हुए अपने मूल्यों को पुनः आत्मसात करने की आवश्यकता है। कुटीर उद्योगों की पुनर्स्थापना, हस्तशिल्प कला तथा आयुर्वेदिक उत्पादों को बढ़ावा देना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। इससे

होगा यह कि हमारा ग्रामीण अंचल आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा और यही रास्ता है देश की समृद्धि का। जब लोकल फॉर वोकल की मुहिम को हम गति प्रदान करेंगे, तो निश्चित ही ये एक दिन ग्लोबल विलेज का हिस्सा बनेंगे। भारत सरकार की ओर से जब खादी खरीदने का आग्रह किया गया है, तभी से खादी एवं हैंडलूम की बिक्री देश में रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है और अब उसे ग्लोबल बनाने का कार्य हम लोगों का है।

आत्मनिर्भरता और नवाचार

आत्मनिर्भर भारत अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बीच आपसी जुड़ाव: आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। क्योंकि दोनों ही पहलुओं का उद्देश्य देश में आत्मनिर्भरता, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत की आयात पर निर्भरता को कम करके और धरेलु विनिर्माण तथा नवाचार को बढ़ावा देकर आर्थिक निर्भरता को बढ़ावा देना है। दूसरी ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य एक ऐसे ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देना है जो नवाचार, रचनात्मक और उद्यमी हो। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि दोनों का एक ही उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और नवाचार को प्रसारित करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य कृषि, रक्षा और उद्यमिता की संस्कृति देना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बीच एक और प्रमुख आपसी जुड़ाव देश में कौशल विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी विशेषज्ञता को बढ़ावा देना है जिसके लिए छात्रों को ऐसे आवश्यक कौशल और ज्ञान से सुसज्जित किया जाता है जिससे वे समाज के उत्पादक सदस्य बन सकें। इसके अलावा यह दोनों अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने को केंद्रित हैं। दूसरी ओर इनका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में

प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है जिसके लिए छात्रों को आधुनिक प्रौद्योगिकी और डिजिटल शिक्षण उपकरणों तक पहुँच प्रदान की जाती है।

आत्मनिर्भरता तथा वोकल फॉर लोकल दोनों मंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत युवाओं तक पहुँचाना है। ऐसे में 'ज्ञानोत्सव' जैसे आयोजन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से न सिर्फ शिक्षा किस पहलू को दृष्टिगत रखते हुए दी जाय। यह निर्णय करने में सहायक होगा, अपितु जब विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक मंच पर होंगे। फिर शिक्षा किस तरीके से दी जाए और कैसे दी जाए, जो आत्मनिर्भर भारत का खाका खींच सके। यह निर्णय लेने में भी आसानी होगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी और टिकाऊ क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित हैं। इन पहलुओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज सहित विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय और सहयोग को मजबूत करें। इन पहलुओं के क्रियान्वयन में सहायता के लिए बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधनों में निवेश बढ़ायें। आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जिनमें कृषि, रक्षा, विनिर्माण और शिक्षा शामिल हैं, में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करें। ज्ञान साझाकरण और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों और

अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी और सहयोग विकसित करें। वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए कार्यबल के निरंतर कौशल विकास और कौशल उन्नयन को बढ़ावा देकर 'आजीवन सीखने की संस्कृति' को विकसित करें।

निष्कर्ष

आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दो ऐसे परिवर्तनकारी कदम हैं जिनका उद्देश्य भारत में आर्थिक आत्मनिर्भरता, नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा देना है। इन पहलुओं में भारतीय अर्थव्यवस्था और शिक्षा प्रणाली को एक अधिक समावेशी, न्यायसंगत और टिकाऊ प्रणाली में बदलने की क्षमता है, जो इक्कसवीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। हालांकि इन पहलुओं के व्यावहारिक और टिकाऊ क्रियान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों जिनमें सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज शामिल हैं। इनके बीच एक समन्वित प्रयास और सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए इन पहलुओं की सफलता सुनिश्चित करने और भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है। सारांश के रूप में इतना तो वांछनीय है कि वर्तमान समाज के परिपेक्ष्य में आ रही चुनौतियों का मुकाबला करने के साथ-साथ उनमें स्वयं को समाहित करने व भावी पीढ़ियों के लिए सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत कर सकें। तभी भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ पायेगा। शिक्षा नीति के साथ-साथ हम सभी का सहयोग भारतीय आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत वांछनीय है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल, जे.सी. (2006). शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबन्ध, नई दिल्ली : विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि.।
2. अग्रवाल, पवल (2009): श्रम बाजार के अनुरूप उच्च शिक्षा, योजना, अंक: 09 सितम्बर, 2009
3. डॉ० शिवदत्त (2012) बुनियादी शिक्षा की अवधारणा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. जोशी, भाम्भू, मिथिलेश (2020) गांधी दृष्टि के विविध आयाम, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।

5. पाठक, आर.पी. एण्ड चौधरी जे. एज्यूकेशनल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली पियर्सन, (2012)
 6. पाठक, पी0डी0 (2008) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं, आगरा विनोद पुस्तक मंदिर।
 7. मिश्र, शि, (2006) समग्र नयी तालीम, वर्धा, नयी तालीम समिति, आश्रम सेवा ग्राम।
 8. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (2005) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।
 9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
 10. सारस्वत, मालती एवं बाजपेयी.बी.एल (1996) भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएं, आलोक प्रकाशन
1. <https://epathsala.nic.in/>
 2. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/National_Education_Policy_2020
 - 4: Puri, Natsaha (30August 2019). A Review of the National Education Policy of the Government of India- The Need for DataAnd Dynamism in the 21st Century. SSRN.
 - 5: (<https://www.iamai.in>)
 - 6: (<https://sdgs.un.org/goals>)

भारत में कौशल विकास, युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण

नरेश कुमार माली

सहायक आचार्य, इतिहास

महात्मा गांधी पीजी कॉलेज महवा, दौसा, राजस्थान

सारांश

भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ जनसंख्या का बड़ा हिस्सा युवाओं का है। यह जनसांख्यिकीय स्थिति भारत को विकास की अपार संभावनाएँ प्रदान करती है, किंतु साथ ही यह चुनौती भी प्रस्तुत करती है कि इस विशाल युवा शक्ति को उचित दिशा, शिक्षा और कौशल से कैसे सशक्त बनाया जाए। वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में केवल पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं को तकनीकी, व्यावसायिक तथा व्यवहारिक कौशल से लैस करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार योग्य बनाया जा सकता है, जिससे बेरोजगारी की समस्या कम होगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

भारत सरकार ने इस दिशा में अनेक योजनाएँ प्रारंभ की हैं, जैसे स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया आदि। इन पहलों का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कौशल विकास केवल रोजगार का साधन ही नहीं है, बल्कि यह युवाओं

में आत्मविश्वास, नवाचार क्षमता और नेतृत्व गुणों का विकास भी करता है। इससे युवा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने लगते हैं, जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत बनाता है।

यह शोध पत्र भारत में कौशल विकास की अवधारणा, युवा सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। साथ ही इसमें कौशल विकास कार्यक्रमों के समक्ष उपस्थित चुनौतियों, जैसे शिक्षा और उद्योग के बीच अंतर, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी तथा जागरूकता के अभाव, पर भी चर्चा की गई है। अंततः शोध पत्र यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि यदि कौशल आधारित शिक्षा को व्यापक स्तर पर लागू किया जाए और युवाओं को उचित अवसर प्रदान किए जाएँ, तो वे न केवल स्वयं सशक्त होंगे बल्कि भारत को आत्मनिर्भर, समावेशी और विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

मुख्य शब्द – कौशल विकास, युवा सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, रोजगार, राष्ट्र निर्माण।

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र की प्रगति और विकास में युवा वर्ग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। युवा ऊर्जा, नवाचार, परिवर्तन और विकास के वाहक होते हैं। भारत विश्व के उन देशों में से एक है जहाँ युवाओं की संख्या अत्यधिक है, जो देश के लिए एक बड़ी जनसांख्यिकीय संपदा का

प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान समय में भारत की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या युवा वर्ग की है, जो देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। यदि इस युवा शक्ति को उचित दिशा, शिक्षा, प्रशिक्षण और अवसर प्रदान किए जाएँ, तो यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

आज के वैश्वीकरण और तकनीकी क्रांति के दौर में रोजगार की प्रकृति तेजी से बदल रही है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली युवाओं को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो पा रही है। परिणामस्वरूप शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। इस स्थिति में कौशल आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। कौशल विकास का उद्देश्य युवाओं को ऐसे व्यावहारिक और तकनीकी कौशल प्रदान करना है, जिससे वे रोजगार के योग्य बन सकें और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें।

भारत सरकार ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जिनका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करना तथा उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। कौशल विकास के माध्यम से न केवल बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है, बल्कि उद्यमिता को भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इससे युवाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और नवाचार की भावना विकसित होती है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है।

युवा सशक्तिकरण केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सशक्त युवा समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सकते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं। जब युवा शिक्षित, कुशल और आत्मनिर्भर होते हैं, तो वे राष्ट्र की उत्पादक शक्ति बन जाते हैं और देश के समग्र विकास को गति प्रदान करते हैं।

इस संदर्भ में कौशल विकास, युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण के बीच गहरा संबंध स्थापित होता है। कौशल विकास युवाओं को सशक्त बनाता है, सशक्त युवा राष्ट्र के विकास में योगदान देते हैं, और इस प्रकार राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया

मजबूत होती है। वर्तमान शोध पत्र इसी संबंध का विश्लेषण करने का प्रयास करता है तथा यह समझने का प्रयास करता है कि भारत में कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाकर राष्ट्र निर्माण को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है।

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य भारत में कौशल विकास, युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण के मध्य संबंध का व्यापक अध्ययन करना है। इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार कौशल आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण युवाओं को सशक्त बनाकर राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान दे सकते हैं। इस संदर्भ में शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

भारत में कौशल विकास की आवश्यकता और महत्व का अध्ययन करना।

इस उद्देश्य के अंतर्गत यह विश्लेषण किया जाएगा कि वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में कौशल आधारित शिक्षा क्यों आवश्यक है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की सीमाएँ क्या हैं और कौशल विकास किस प्रकार रोजगार की संभावनाओं को बढ़ा सकता है।

युवा सशक्तिकरण की अवधारणा और उसके विभिन्न आयामों का विश्लेषण करना।

इस उद्देश्य के अंतर्गत युवा सशक्तिकरण के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आयामों का अध्ययन किया जाएगा। इसके माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि सशक्त युवा किस प्रकार समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।

कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण के बीच संबंध को स्पष्ट करना।

इस उद्देश्य के अंतर्गत यह देखा जाएगा कि कौशल आधारित प्रशिक्षण युवाओं में आत्मनिर्भरता,

आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता कैसे विकसित करता है। साथ ही यह भी अध्ययन किया जाएगा कि कौशल विकास युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में किस प्रकार सहायक है।

राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका का मूल्यांकन करना।

इस उद्देश्य के अंतर्गत यह विश्लेषण किया जाएगा कि सशक्त और कुशल युवा देश के आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार, तकनीकी नवाचार तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं।

भारत में कौशल विकास कार्यक्रमों के समक्ष उपस्थित चुनौतियों की पहचान करना।

इस उद्देश्य के अंतर्गत कौशल विकास से संबंधित प्रमुख समस्याओं जैसे प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी, उद्योग और शिक्षा के बीच अंतर, तथा जागरूकता के अभाव का अध्ययन किया जाएगा।

कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

इस उद्देश्य के अंतर्गत ऐसे उपायों पर विचार किया जाएगा, जिनके माध्यम से कौशल आधारित शिक्षा को मजबूत किया जा सके और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

इन उद्देश्यों के माध्यम से यह शोध पत्र कौशल विकास, युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण के बीच संबंध को स्पष्ट करने तथा भारत के समग्र विकास के लिए उनकी उपयोगिता को स्थापित करने का प्रयास करता है।

शोध पद्धति

इस अध्ययन में गुणात्मक (Qualitative) दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जिसके माध्यम से विषय से संबंधित विचारों, नीतियों और कार्यक्रमों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। साथ ही आवश्यकतानुसार कुछ सांख्यिकीय तथ्यों का भी

संदर्भ लिया गया है, जिससे अध्ययन अधिक प्रमाणिक और तार्किक बन सके।

कौशल विकास की अवधारणा

कौशल विकास का अर्थ व्यक्तियों को ऐसे व्यावहारिक, तकनीकी तथा व्यावसायिक ज्ञान और दक्षताओं से सुसज्जित करना है, जिनकी सहायता से वे किसी कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकें तथा रोजगार या स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। वर्तमान समय में केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि कार्य करने की क्षमता, तकनीकी दक्षता और व्यवहारिक समझ को भी समान रूप से आवश्यक माना जाता है। इसी कारण कौशल विकास की अवधारणा शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है।

कौशल विकास का उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य बनाना, उनकी उत्पादकता बढ़ाना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके माध्यम से युवाओं में तकनीकी ज्ञान, समस्या समाधान क्षमता, नेतृत्व कौशल, संचार कौशल तथा उद्यमिता की भावना विकसित होती है। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक वृद्धि और सामाजिक प्रगति को भी गति प्रदान करता है।

कौशल विकास को व्यापक रूप से दो भागों में समझा जा सकता है कृ तकनीकी कौशल और सॉफ्ट स्किल्स। तकनीकी कौशल में मशीन संचालन, कंप्यूटर ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण कार्य, कृषि तकनीक, डिजिटल तकनीक आदि शामिल हैं। दूसरी ओर सॉफ्ट स्किल्स में संचार क्षमता, टीम वर्क, नेतृत्व, समय प्रबंधन और निर्णय लेने की क्षमता शामिल होती है। दोनों प्रकार के कौशल युवाओं को कार्यक्षेत्र में सफल बनाने के लिए आवश्यक हैं।

भारत जैसे विकासशील देश में कौशल विकास की आवश्यकता इसलिए भी अधिक है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में युवा श्रम शक्ति उपलब्ध है, लेकिन उनमें से कई युवाओं के पास आवश्यक कौशल का अभाव होता है। परिणामस्वरूप शिक्षित

बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। कौशल विकास इस अंतर को दूर करने का माध्यम बनता है। यह शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच समन्वय स्थापित करता है तथा युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करता है।

भारत सरकार ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएँ प्रारंभ की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करना तथा उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में भी प्रेरित किया जा रहा है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है।

युवा सशक्तिकरण का महत्व

किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास में युवा वर्ग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। युवा शक्ति ऊर्जा, उत्साह, नवाचार और परिवर्तन का प्रतीक होती है। यदि युवाओं को उचित शिक्षा, कौशल, संसाधन और अवसर प्रदान किए जाएँ, तो वे राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को गति प्रदान कर सकते हैं। इसी संदर्भ में युवा सशक्तिकरण की अवधारणा विशेष महत्व रखती है। युवा सशक्तिकरण का अर्थ युवाओं को ऐसी क्षमताओं से सुसज्जित करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों तथा समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी निभा सकें।

युवा सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा युवाओं को ज्ञान प्रदान करती है और उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। शिक्षा के माध्यम से युवाओं में तार्किक सोच, समस्या समाधान क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता विकसित होती है। जब शिक्षा के साथ कौशल प्रशिक्षण को जोड़ा जाता है, तो युवा रोजगार योग्य बनते हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा और कौशल विकास मिलकर युवा सशक्तिकरण का आधार बनते हैं।

युवा सशक्तिकरण का आर्थिक महत्व भी अत्यधिक है। सशक्त युवा राष्ट्र की उत्पादक शक्ति बनते हैं। जब युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, तो वे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, सशक्त युवा उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं, जिससे नए उद्योगों और रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। इससे बेरोजगारी की समस्या में कमी आती है और आर्थिक विकास को गति मिलती है।

सामाजिक दृष्टि से भी युवा सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। सशक्त युवा समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। वे सामाजिक कुरीतियों जैसे अशिक्षा, बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव और अन्य सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युवा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समानता और समावेशिता को बढ़ावा देते हैं, जिससे सामाजिक विकास को मजबूती मिलती है।

राजनीतिक दृष्टि से युवा सशक्तिकरण लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाता है। जागरूक और शिक्षित युवा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। वे मतदान, नीति निर्माण में सहभागिता और सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से शासन व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी बनाने में योगदान देते हैं। इस प्रकार युवा सशक्तिकरण राष्ट्र के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करता है।

इसके अतिरिक्त, युवा सशक्तिकरण राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक नवाचार और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा देता है। सशक्त युवा नई तकनीकों को अपनाने में अग्रणी होते हैं और वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति में योगदान देते हैं। यह देश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाता है और वैश्विक स्तर पर राष्ट्र को मजबूत बनाता है।

कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण का संबंध

कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण के बीच अत्यंत घनिष्ठ और परस्पर पूरक संबंध है। कौशल विकास वह माध्यम है जिसके द्वारा युवाओं को व्यावहारिक ज्ञान, तकनीकी दक्षता तथा

रोजगारोन्मुख क्षमताएँ प्रदान की जाती हैं, जबकि युवा सशक्तिकरण का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर, सक्षम और आत्मविश्वासी बनाना है। इस दृष्टि से कौशल विकास युवा सशक्तिकरण की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। जब युवाओं को उचित कौशल प्राप्त होते हैं, तो वे न केवल रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, बल्कि वे समाज और राष्ट्र के विकास में भी सक्रिय योगदान देने लगते हैं।

कौशल विकास युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। वर्तमान समय में बेरोजगारी की समस्या युवाओं के सामने एक बड़ी चुनौती है। केवल सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जबकि कौशल आधारित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। इस प्रकार कौशल विकास युवाओं को रोजगार योग्य बनाता है और उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। आर्थिक रूप से सशक्त युवा समाज में सम्मानजनक जीवन जीते हैं और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं।

कौशल विकास युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना को भी विकसित करता है। जब युवा किसी विशेष कौशल में दक्षता प्राप्त करते हैं, तो उनमें अपने कार्य के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। यह आत्मविश्वास उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने और नवाचार करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार कौशल विकास युवाओं के व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इसके अतिरिक्त कौशल विकास उद्यमिता को बढ़ावा देता है, जो युवा सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कौशल प्राप्त करने के बाद युवा स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम होते हैं। इससे न केवल वे स्वयं रोजगार प्राप्त करते हैं, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार कौशल

विकास युवाओं को नौकरी खोजने वाला ही नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला भी बनाता है।

अतः यह स्पष्ट है कि कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण एक-दूसरे के पूरक हैं। कौशल विकास के बिना युवा सशक्तिकरण अधूरा है, और सशक्त युवा ही राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए दोनों के बीच संबंध को समझना और उन्हें एकीकृत रूप से लागू करना राष्ट्र के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका

किसी भी राष्ट्र के विकास में युवा वर्ग को परिवर्तन का प्रमुख वाहक माना जाता है। युवा ऊर्जा, उत्साह, रचनात्मकता और नवाचार से परिपूर्ण होते हैं, जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ युवा जनसंख्या का अनुपात अधिक है, वहाँ युवाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि इस युवा शक्ति को उचित दिशा, कौशल और अवसर प्रदान किए जाएँ।

आर्थिक दृष्टि से युवा राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार हैं। कुशल और शिक्षित युवा देश की उत्पादक शक्ति को बढ़ाते हैं। वे उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र तथा उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देते हैं। युवा वर्ग नए व्यवसायों की स्थापना कर रोजगार के अवसरों का सृजन करता है, जिससे बेरोजगारी की समस्या में कमी आती है। इसके अतिरिक्त, युवा नई तकनीकों को अपनाने में अग्रणी होते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता और दक्षता में वृद्धि होती है। इस प्रकार युवा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सामाजिक दृष्टि से भी युवाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सशक्त और जागरूक युवा समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। वे सामाजिक कुरीतियों जैसे अशिक्षा, लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि के विरुद्ध जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। युवा समाज

में समानता, न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त, युवा सामाजिक सेवा और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करते हैं, जिससे सामाजिक विकास को मजबूती मिलती है।

राजनीतिक दृष्टि से युवा लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जागरूक और शिक्षित युवा मतदान, जनजागरूकता और नीति निर्माण की प्रक्रियाओं में भाग लेकर शासन व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी बनाते हैं। युवा नेतृत्व के माध्यम से नई सोच और नए दृष्टिकोण को राजनीति में स्थान मिलता है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाएँ मजबूत होती हैं। इस प्रकार युवा राष्ट्र के राजनीतिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

तकनीकी और वैज्ञानिक विकास में भी युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवा वर्ग नई तकनीकों को अपनाने और नवाचार करने में अग्रणी होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं के योगदान से देश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ती है। डिजिटल तकनीक, स्टार्टअप संस्कृति और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था में युवाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इससे देश वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर सकता है।

सांस्कृतिक दृष्टि से भी युवा राष्ट्र की पहचान और परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान देते हैं। युवा आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित करते हुए सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। वे कला, साहित्य, खेल और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि युवा राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक प्रगति, सामाजिक सुधार, राजनीतिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षणकृद्इन सभी क्षेत्रों में युवाओं का योगदान अनिवार्य है। इसलिए युवाओं को उचित शिक्षा, कौशल और अवसर प्रदान करना आवश्यक है, जिससे वे राष्ट्र

निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभा सकें और देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकें।

9. कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण की चुनौतियाँ

भारत में कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, फिर भी इनके प्रभावी क्रियान्वयन के सामने कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं। ये चुनौतियाँ न केवल कौशल विकास कार्यक्रमों की सफलता को प्रभावित करती हैं, बल्कि युवाओं के समुचित सशक्तिकरण में भी बाधा उत्पन्न करती हैं। इन प्रमुख चुनौतियों का विवरण निम्नलिखित है:

सबसे पहली चुनौती शिक्षा और उद्योग के बीच असंतुलन की है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि उद्योगों को व्यावहारिक और तकनीकी कौशल वाले युवाओं की आवश्यकता होती है। इस कारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अनेक युवा रोजगार प्राप्त करने में असफल रहते हैं। शिक्षा और उद्योग के बीच यह अंतर कौशल विकास के उद्देश्य को कमजोर करता है।

दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती प्रशिक्षण संस्थानों की कमी है, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में। बड़े शहरों में प्रशिक्षण सुविधाएँ अपेक्षाकृत अधिक उपलब्ध हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर सीमित हैं। इससे ग्रामीण युवाओं का समुचित सशक्तिकरण नहीं हो पाता और वे रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर होते हैं।

तीसरी चुनौती जागरूकता का अभाव है। कई युवा कौशल विकास कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते। इसके परिणामस्वरूप वे इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी के अभाव के कारण कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रभाव सीमित रह जाता है।

चौथी चुनौती गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की कमी है। कई प्रशिक्षण केंद्रों में आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित प्रशिक्षकों का अभाव होता है। इससे युवाओं को अपेक्षित स्तर का प्रशिक्षण नहीं मिल पाता और वे रोजगार बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में कमी कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को कम कर देती है।

पाँचवीं चुनौती रोजगार के पर्याप्त अवसरों की कमी है। कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी कई युवाओं को उपयुक्त रोजगार नहीं मिल पाता। इससे युवाओं में निराशा उत्पन्न होती है और कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रति विश्वास कम होता है। इसलिए कौशल विकास के साथ-साथ रोजगार सृजन पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

छठी चुनौती आर्थिक संसाधनों की कमी है। कई युवाओं के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना आर्थिक रूप से कठिन होता है। विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के युवाओं के पास प्रशिक्षण शुल्क, यात्रा और अन्य खर्च वहन करने की क्षमता नहीं होती। इससे वे कौशल विकास कार्यक्रमों से वंचित रह जाते हैं।

सातवीं चुनौती सामाजिक और लैंगिक असमानता भी है। कई क्षेत्रों में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर सीमित होते हैं। सामाजिक परंपराएँ और पारिवारिक प्रतिबंध भी युवतियों के सशक्तिकरण में बाधा बनते हैं। इससे समाज की आधी आबादी कौशल विकास के लाभ से पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो पाती।

आठवीं चुनौती तकनीकी परिवर्तन की गति है। आज के डिजिटल युग में तकनीक तेजी से बदल रही है। यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम समय के अनुरूप अद्यतन नहीं होते, तो युवाओं के कौशल अप्रासंगिक हो जाते हैं। इसलिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को समय-समय पर अद्यतन करना आवश्यक है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण के समक्ष अनेक चुनौतियाँ मौजूद हैं।

इन चुनौतियों का समाधान किए बिना कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रभावी बनाना संभव नहीं है। अतः शिक्षा प्रणाली में सुधार, प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार, जागरूकता बढ़ाने और रोजगार सृजन जैसे उपायों को अपनाकर इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, जिससे युवाओं को सशक्त बनाकर राष्ट्र निर्माण को गति दी जा सके।

सुझाव

भारत में कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने के लिए ठोस और व्यावहारिक कदम उठाना आवश्यक है। इन उपायों के माध्यम से युवाओं को रोजगार योग्य बनाया जा सकता है तथा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत किया जा सकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

सबसे पहले शिक्षा प्रणाली में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को शामिल करना आवश्यक है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि व्यावहारिक प्रशिक्षण की कमी है। विद्यालय और उच्च शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण तथा इंटरनशिप को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही रोजगारोन्मुख शिक्षा प्राप्त होगी और वे भविष्य में कार्यक्षेत्र के लिए बेहतर रूप से तैयार होंगे।

दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना है। वर्तमान समय में अधिकांश प्रशिक्षण संस्थान शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जिसके कारण ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण के लिए शहरों की ओर जाना पड़ता है। यदि ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएँ, तो स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में ही कौशल प्रशिक्षण प्राप्त होगा और पलायन की समस्या में भी कमी आएगी।

तीसरा सुझाव उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाने का है। उद्योगों की

आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग स्थापित किया जाना चाहिए। इंटरनशिप, अप्रेंटिसशिप और ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देकर युवाओं को व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जा सकता है।

चौथा सुझाव उद्यमिता को प्रोत्साहन देने का है। कौशल विकास का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित करना होना चाहिए। इसके लिए युवाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

पाँचवाँ सुझाव जागरूकता अभियान चलाने का है। अनेक युवा कौशल विकास योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी के अभाव में उनका लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए सरकार और शैक्षणिक संस्थानों को जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को इन योजनाओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए। विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सूचना प्रसार पर ध्यान देना आवश्यक है।

छठा सुझाव प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रशिक्षण केंद्रों में आधुनिक उपकरण, योग्य प्रशिक्षक और अद्यतन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इससे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त होगा और वे रोजगार बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे।

सातवाँ सुझाव महिला युवाओं की भागीदारी बढ़ाने का है। कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजनाएँ चलाई जानी चाहिए। महिलाओं को सुरक्षित प्रशिक्षण वातावरण, वित्तीय सहायता और सामाजिक समर्थन प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। इससे समाज के समग्र विकास को गति मिलेगी।

आठवाँ सुझाव डिजिटल कौशल और नई तकनीकों पर विशेष ध्यान देने का है। आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर, इंटरनेट और नई तकनीकों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने से वे आधुनिक कार्यक्षेत्र में सफल हो सकते हैं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सुझावों के माध्यम से कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण को प्रभावी बनाया जा सकता है। यदि इन उपायों को समुचित रूप से लागू किया जाए, तो युवा वर्ग राष्ट्र निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेगा और भारत के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि कौशल विकास, युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण परस्पर जुड़े हुए तत्व हैं, जो किसी भी देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ युवा जनसंख्या का अनुपात अत्यधिक है, वहाँ युवाओं को सही दिशा और अवसर प्रदान करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि इस विशाल युवा शक्ति को उचित शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल प्रदान किया जाए, तो यह राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक स्थिरता और तकनीकी उन्नति का आधार बन सकती है।

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के साथ कौशल आधारित प्रशिक्षण को जोड़ना समय की आवश्यकता है। केवल सैद्धांतिक ज्ञान युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में पर्याप्त नहीं है, जबकि कौशल विकास उन्हें रोजगार योग्य बनाता है और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करता है। इससे न केवल बेरोजगारी की समस्या में कमी आती है, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलता है। आर्थिक रूप से सशक्त युवा राष्ट्र की उत्पादक शक्ति को बढ़ाते हैं और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

शोध के दौरान यह भी पाया गया कि युवा सशक्तिकरण केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक विकास से भी जुड़ा हुआ है। सशक्त युवा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। वे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने, समानता को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने में योगदान देते हैं। इस प्रकार युवा सशक्तिकरण राष्ट्र के समग्र विकास की प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है।

हालाँकि, कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण के समक्ष कई चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं, जैसे शिक्षा और उद्योग के बीच अंतर, प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी, जागरूकता का अभाव तथा रोजगार के सीमित अवसर। इन चुनौतियों का समाधान किए बिना कौशल विकास कार्यक्रमों को पूर्ण सफलता

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Abdul Kalam]A-P-J- (2002)- India 2020:A Vision for the New Millennium- New Delhi: Penguin Books-
2. Sen, Amartya- (1999)- DevelopmentAs Freedom- OÜford University Press-
3. Government of India- (2015)- Skill India Mission Document- Ministry of Skill Development and Entrepreneurship] New Delhi-
4. National Skill Development Corporation (NSDC)- (2020)- Skill Gap Report- New Delhi-
5. Ministry of Skill DevelopmentAnd Entrepreneurship- (2022)-Annual Report- Government of India-
6. NITIAayog- (2018)- Strategy for New India @75- Government of India-
7. Tilak] J-B-G- (2015)- Education] SkillsAnd Economic Development- New Delhi: Sage Publications-
8. Planning Commission of India- ¼2013½- Twelfth Five Year Plan (2012–2017)- Government of India-
9. World Bank- (2019)- World Development Report: The Changing Nature of Work- Washington] DC-
10. UNESCO- (2016)- Strategy for TechnicalAnd Vocational EducationAnd Training (TVET)- Paris-
11. Ministry of YouthAffairsAnd Sports- (2014)- National Youth Policy- Government of India-
12. Sharma] R-C- (2017)- Skill Development in India: Challenges and Opportunities- New Delhi:Atlantic Publishers-
13. Mehrotra] Santosh- (2014)- India*s Skills Challenge: Reforming Vocational EducationAnd Training- OÜford University Press-
14. Government of India- (2016)- Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana Guidelines- Ministry of Skill Development-
15. Economic Survey of India- (2022–23)- Ministry of Finance] Government of India-

शिक्षकों के व्यवहार का विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन

नवरत्न सिंह

प्राध्यापक, राजकीय महात्मा गाँधी विद्यालय बनोखर, कठूमर, अलवर, राजस्थान

सारांश

शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करती है, उसी प्रकार शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी एक आवश्यक तथा शक्तिशाली साधन है। शिक्षा के द्वारा समाज भावी पीढ़ी को उच्च आदर्श, आशाओं, विश्वासों तथा परम्पराओं आदि सांस्कृतिक सम्पत्ति को इस प्रकार से हस्तान्तरित करता है कि उनके हृदय में देश प्रेम तथा त्याग की भावना प्रज्वलित हो जाती है। जब ऐसी भावनाओं तथा आदर्शों से ओत-प्रोत बालक समाज सेवा का व्रत धारण कर तथा अपने जीवन में त्याग से प्रेरित होकर कार्य करेंगे तो समाज भी निरन्तर उन्नति के शिखर पर चढ़ता ही रहेगा। शिक्षकों एवं अभिभावकों का

व्यवहार अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र का ज्ञान रखने वाला शिक्षक कक्षा की स्थिति के साथ-साथ विद्यालय परिसर में क्या करें और क्या न करें से परिचित होता है। ऐसा शिक्षक सभी को पसंद होता है और वह अपने छात्रों के लिए एक आदर्श की तरह होता है, चाहे वे किसी भी उम्र, वर्ग, मानक, लिंग आदि के हों।

मुख्य शब्द — मानसिक स्वास्थ्य, सर्वांगीण विकास, भावनात्मक, किशोरावस्था, समग्र व्यक्तित्व।

प्रस्तावना

सा विद्या या विमुक्तये से लेकर ज्ञान के सृजन की अवधारणा तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करती है। नवजात शिशु असहाय और असामाजिक होता है व न बोल सकता है और न चल फिर सकता है। उसे समाज के रीति-रिवाज और परम्पराओं का ज्ञान भी नहीं होता तथा उसमें किसी प्रकार के मूल्य तथा आदर्शों को प्राप्त करने की जिज्ञासा भी नहीं पायी जाती। परन्तु जैसे-जैसे वह बड़ा होता है उस पर शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों का प्रभाव पड़ता है जिस कारण उसमें शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास होता है साथ ही उसमें सामाजिक भावना भी विकसित होती है। परिणाम स्वरूप बालक, नागरिक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों के निर्वाह के योग्य बन जाता है। इस प्रकार व्यवस्थित शिक्षा द्वारा बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है।

शिक्षा के महत्व के सन्दर्भ में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि शिक्षा माता के समान पालन-पोषण करती है तथा पिता के समान मार्ग-दर्शन। शिक्षा ही हमारी समस्याओं को सुलझाती है एवं हमारे जीवन को सुसंस्कृत बनाती है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पाकर कमल का फूल खिल उठता है तथा सूर्य अस्त होने पर कुम्हला जाता है उसी प्रकार शिक्षा के प्रकाश में प्रत्येक व्यक्ति खिल जाता है तथा शिक्षा के अभाव में दरिद्रता एवं कष्ट के अन्धकार में डूबा रहता है अर्थात् शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। इससे वह समाज का एक उत्तरदायी सदस्य एवं राष्ट्र का प्रखर चरित्र सम्पन्न नागरिक बनकर समाज की सर्वांगीण उन्नति में अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रेरित होता है।

मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा

मानसिक स्वास्थ्य मुख्य कारक है जो किसी व्यक्ति के विचार की गुणवत्ता और संतुलित व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। यह व्यक्ति के स्वयं, दूसरों और पर्यावरण के प्रति अनुकूलन पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति के लिए स्वयं को समझने, पूर्ण जीवन जीने और लोगों को कुछ उपयोगी देने में सक्षम होने के लिए इस स्वस्थ दृष्टिकोण को प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। परिवर्तन का अर्थ है बदलाव, इस व्यवहार को पूरी तरह से साकार करने के लिए परिवर्तन होना चाहिए और इसमें सुधार होना चाहिए। यदि व्यक्ति परिवर्तित पर्यावरण में जीवित नहीं रह सकता है, तो यह कई समस्याओं का कारण बन सकता है। ये समस्याएं इंसान के दिमाग पर असर डाल सकती हैं। मनोविज्ञान की अवधारणा बहुत पुरानी है, उतनी ही पुरानी जितना मनुष्य। यह स्वास्थ्य की एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं से अवगत होता है, जीवन में सामान्य समस्याओं और तनाव का सामना कर सकता है, प्रभावी ढंग से काम कर सकता है और समाज में योगदान दे सकता है या इसमें एक व्यक्ति का स्वयं और दूसरों के प्रति दृष्टिकोण शामिल है।

मानसिक स्वास्थ्य

मानसिक स्थिति एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। इस स्थिति में व्यक्ति दूसरों के साथ सकारात्मक तरीके से बातचीत कर सकता है। साथ ही तनाव की समस्या से निपटने की क्षमता भी रखता है। किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का संबंध उसकी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्थिति से जुड़ा होता है। मानसिक स्वास्थ्य से व्यक्ति के सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसका असर व्यक्ति के तनाव को संभालने और जीवन से जुड़े जरूरी विकल्प के चयन पर भी पड़ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य जीवन के प्रत्येक चरण अर्थात्

बचपन, किशोरावस्था, प्रौढ़ अवस्था एवं वृद्ध अवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य “व्यक्ति के मन की उस उत्तम अवस्था से है जो उसे एक सम्पूर्ण एवं समग्र व्यक्तित्व के रूप में संतुलित एवं संभावित व्यवहार कर अपने आप से तथा अपने वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायता करती है।”

कुल्हन के अनुसार – मानसिक स्वास्थ्य कार्य की ऐसी आदतों, व्यक्तियों तथा वस्तुओं के प्रति ऐसे दृष्टिकोणों को व्यक्त करता है, जिनसे व्यक्ति को अधिकतम संतोष और आनन्द प्राप्त होता है। मानसिक स्वास्थ्य सम्पूर्ण स्वास्थ्य का एक पहलू है इसके लिये आंतरिक कारकों तथा बाहरी वातावरण के मध्य संतुलन होना अति आवश्यक है। यह वह योग्यता है जो व्यक्ति को सामाजिक व व्यक्तिगत संतुलन स्थापित करना सिखाता है।

इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने के बाद मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में हमें कुछ प्रमुख विशिष्ट तथ्य मिलते हैं जो निम्नांकित हैं—

- मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मूलतः एक शैक्षिक कार्यक्रम है।
- मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान यथा सम्भव जल्द से जल्द मानसिक बीमारियों को पहचान कर उसे दूर करने के उपायों पर बल डालता है।
- मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से मानसिक सावैंगिक कठिनाईयों को प्रारम्भिक अवस्था में ही पता लगा लेने की कोशिश की जाती है।
- मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में मानसिक रोगियों के प्रति आम लोगों की वस्तुनिष्ठ एवं सहानुभूतिपूर्ण मनोवृत्ति विकसित करने का भरसक प्रयास किया जाता है।
- मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में व्यक्तियों को आधुनिक समाज के एक स्वस्थ सदस्य के रूप में जीवन व्यतीत करने पर अधिक बल डाला जाता है। सचमुच यह विज्ञान व्यक्ति

को इस योग्य बना देना चाहता है कि वह अपने जीवन में अधिक से अधिक कुशलता प्राप्त करके अपने आप को अपने लिए एवं अपने समाज के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बना सके।

मानसिक स्वास्थ्य की प्रकृति

संघर्ष रहित चिन्तन – प्रत्येक उस व्यक्ति में जो मानसिक रूप से स्वस्थ है उसको जीवन में चिन्ता व तनाव नहीं होते उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में मानसिक दण्ड, मानसिक परेशानी की दृष्टि से कमजोरी नहीं पायी जाती है।

पूर्णतया समायोजित व्यक्तित्व – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में यह विशेषता पायी जाती है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह से समायोजित होता है।

आत्म नियंत्रण और व्यक्तित्व – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का उसकी इन्द्रियों, संवेगों, भावनाओं पर अपना नियंत्रण होता है। जिससे वह पथ भ्रष्ट नहीं होता है।

सांवेगिक स्थिरता – संवेगों का उचित संतुलन हमें आगे बढ़ने में मदद करता है जिससे व्यक्ति कभी अपने कार्य क्षेत्र में पिछड़ता नहीं है।

उच्च नैतिकता – उच्च नैतिकता मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। उच्च नैतिक मूल्यों वाला व्यक्ति चरित्रवान, ईमानदार व पूर्वाग्रह रहित सामाजिक मूल्यों वाला होता है। व्यक्ति के जीवन में उत्तम चरित्र का होना एक बहुआयामी पक्ष है।

मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएँ

आत्म-ज्ञान – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उसे अपनी प्रेरणा, इच्छा, भाव, आकांक्षाओं आदि का पूर्ण ज्ञान होता है। वह यह पूर्णतः समझता है कि वह क्या कर रहा है, क्यों उसमें इस ढंग का भाव उत्पन्न हो रहा है, उसकी आकांक्षाएँ क्या हैं।

आत्म-मूल्यांकन – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति आसानी से अपने गुण-दोष की परख कर लेता है। वह अपने प्रत्येक व्यवहार का तटस्थ होकर

अध्ययन करता है तथा अपने व्यवहार की परिसीमाओं की परख करता है।

आत्म-श्रद्धा – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में आत्म-श्रद्धा काफी होती है जिसके कारण उसमें आत्मविश्वास, आत्म-बल तथा अपने भावों को स्वीकार करते हुए कार्य करने की क्षमता होती है।

सुरक्षा का भाव – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में यह भावना तीव्र होती है कि वह समाज का स्वीकृत सदस्य है तथा लोग उसके भाव का आदर करते हैं। वह दूसरों के साथ निडर होकर अन्तः क्रिया करता है तथा खुलकर हँसी-मजाक में भाग लेता है। वह अपने पर समूह के दबाव पड़ने के बावजूद अपनी इच्छाओं को दमित नहीं करने की कोशिश करता है।

संतोषजनक संबंध बनाए रखने की क्षमता – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की एक विशेषता यह है कि वह दूसरों के साथ संतोषजनक संबंध बनाए रखने में सक्षम होता है। वह कभी दूसरों के सामने अवास्तविक माँग नहीं पेश करता। फलस्वरूप, उसका संबंध दूसरों के साथ हमेशा संतोषजनक बना रहता है।

उत्पादी एवं खुशी रहने की क्षमता – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी क्षमता को उत्पादी कार्य में लगाते हैं तथा वे काफी खुश रहते हैं। वह ऐसे कार्य में अच्छा उत्साह एवं मनोबल दिखाते हैं और अपने को खुशमिजाज साबित करते हैं।

तनाव एवं अतिसंवेदनशीलता की अनुपस्थिति – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति या छात्र में मानसिक तनाव उत्पन्न नहीं हो पाता और यदि कभी हुआ भी तो वह तुरंत ही नियंत्रित कर लिया जाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों द्वारा किए गए प्रशंसा या आलोचना का प्रभाव अपने ऊपर अधिक नहीं पड़ने देते। दूसरे शब्दों में, इनमें संवेदनशीलता के गुण की कमी होती है।

अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की एक विशेषता यह भी होती है कि

इनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा एवं आकर्षक होता है। यह विशेषता इस कहावत से जुड़ी हुई है कि 'स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही रहता है।

जिन्दगी का एक स्पष्ट सिद्धान्त – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ठोस सिद्धान्त बना रखते हैं और वे हमेशा उसी सिद्धान्त के अनुकूल कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के सिद्धान्त में मानसिक संघर्ष, विरोधाभास—जैसी चीजों की सर्वथा कमी होती है।

वास्तविक प्रत्यक्षण – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या चीज का प्रत्यक्षण वस्तुनिष्ठ ढंग से करते हैं। वे इन चीजों का प्रत्यक्षण करते समय कुछ काल्पनिक तथ्यों का सहारा नहीं लेते।

विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक

घरेलू प्रभाव – बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर घर का प्रभाव पड़ता है। घर के प्रभाव डालने वाले तत्व ये हैं

- परिवार का विघटन
- माता-पिता का व्यवहार
- निर्धनता
- उच्च आदर्श
- घर का अनुशासन
- परिवार में तनाव

विद्यालय का प्रभाव – विद्यालय के वातावरण का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर निम्न कारकों का प्रभाव पड़ता है

- विद्यालय का वातावरण
- अध्यापक का व्यवहार
- अभिव्यक्ति
- परीक्षा प्रणाली
- अनुचित पाठ्यक्रम
- कक्षा में असमायोजन

सामाजिक प्रभाव – समाज में रीति-रिवाज तथा मान्यताओं का अनुसरण प्रत्येक को करना पड़ता

है। सामाजिक कारकों का बालकों के मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत व अपेक्षित दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है जो कि निम्न है—

- आन्तरिक तनाव
- असुरक्षा
- स्वतंत्रता का अभाव
- भावनात्मक प्रतिक्रिया
- मनोदेहिक बाधाएँ
- समाज विरोधी व्यवहार

अन्य कारक

- हीनता की भावना
- वंशक्रम
- शारीरिक दोष
- मनोवैज्ञानिक कारण

शिक्षकों के द्वारा बाल विकास में व्यावहारिक प्रशिक्षण

स्कूल परामर्शदाताओं को बच्चों और किशोरों के सामने आने वाली व्यवहारिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। वे छात्रों के संघर्षों को समझने के लिए तैयार हैं। शिक्षकों को बाल विकास में व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त होता है। जो छात्र हमारे देश के भावी नागरिक हैं, वे राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाते हैं। केवल अच्छे अंक प्राप्त करना और अच्छा प्रदर्शन करना तथा अच्छे शैक्षणिक अंक प्राप्त करना ही राष्ट्र के सच्चे प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएगा, जब तक कि बच्चा अपने कर्तव्यों को पूरी लगन और निष्ठा से पूरा न करे। इसलिए छात्रों के सर्वांगीण विकास पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। यह तभी संभव है जब बच्चे की मानसिक स्थिति राष्ट्र के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए अच्छी हो, जो बदले में तब संभव है जब बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को संरक्षित

करना सभी यानी माता-पिता, शिक्षकों और समाज द्वारा वांछित हो।

मानसिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व और दूसरों के साथ उसके स्थिर व्यवहार का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो उसके स्वयं के अनुसार, दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार और अपने वातावरण के अनुसार समायोजन की सीमा के आधार पर होता है जहां उसे आसानी से अनुकूलन करना होता है। संतुलित व्यक्तित्व की ऐसी स्थिति प्राप्त करना किसी व्यक्ति के लिए स्वयं को जानने, अपना जीवन पूर्णता से जीने और बदले में समाज, समुदाय और राष्ट्र को कुछ उपयोगी और उत्पादक देने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य परिवर्तनों से बंधा हुआ है, वह लगातार विकास की प्रक्रिया में है। इससे अंततः वह बदलाव आएगा जो राष्ट्रीय विकास के लिए वांछनीय है। एक छोटे बच्चे के लिए ऐसे बदलावों को अनुकूलित करना जो उसके लिए नए हैं, इतना आसान नहीं है जब तक कि उसके आस-पास के लोग उसके प्रति सहायक और सहयोगी न हों। यदि बच्चे को इन परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है तो विभिन्न समस्याएं और जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं। ये समस्याएँ और जटिलताएँ वास्तव में एक बच्चे की मानसिक संरचना को आकार देती हैं।

शिक्षक के व्यवहार की अवधारणा

व्यवहार व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। यह क्रियाशील व्यक्तित्व है। प्रभावी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक के अपने छात्रों के साथ संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शिक्षकों का अपने विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण, दयालु, प्रेमपूर्ण, स्नेहपूर्ण, संवेदनशील और निष्पक्ष व्यवहार अच्छा तालमेल स्थापित करता है और शिक्षक की प्रभावशीलता में एक महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की विशिष्टता की चिंता करते हुए उनके प्रति उचित सम्मान दिखाना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण शिक्षण-अधिगम स्थिति के लिए शिक्षकों का

निरंतर सुदृढ़ और गर्मजोशी भरा रवैया आवश्यक है। छात्रों की रुचियों और योग्यता पर काम करना और छात्रों को सीखने के लिए आरंभ करना और प्रेरित करना उत्तम शिक्षक व्यवहार सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

मानसिक स्वास्थ्य को समग्र शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है और यह केवल बीमारी और बीमारियों की कमी नहीं है। कई वर्षों से इस कहावत को हर कोई आदर्श रूप से अपना रहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है। महान भारतीय संतों ने अचेतनता और अज्ञानता पर अधिक जोर दिया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की अतृप्त इच्छाएं छिपी होती हैं, जो व्यक्ति को दुखों की दुनिया में खोए रखती हैं। मन पर काबू पाकर व्यक्ति स्थिरता और लचीलेपन की सर्वोच्च सीढ़ी हासिल कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बाकी लोगों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध का समतापूर्ण सुधार है। यह केवल एक व्यक्ति और दूसरों के बीच के बंधन की चिंता नहीं है, बल्कि व्यक्ति और उसके समुदाय, उसके समाज और उसकी सामाजिक संस्थाओं के बीच भी बंधन की चिंता है जो उसे एक अच्छा जीवन जीने, अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करने में मदद करती है। अपने खाली समय का उचित प्रबंधन करें और अपनी आय प्राप्त करने के लिए और उन वस्तुओं पर व्यय करें जो आवश्यक हैं और जिस तरह से वह अपनी खुशी, संतुलन और सुरक्षा को देखता और समझता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अस्थाना, विपिन (2001). मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, मेरठ : रस्तोगी पब्लिकेशन।
- अग्रवाल, जे.सी. (2006). शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबन्ध, नई दिल्ली : विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि.।

- गुप्ता, अलका. (2017). उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान – सिद्धांत एवं व्यवहार, शारदा पुस्तक भवन, पृष्ठ (602–604)।
 - मंगल, एस. के. (2015). शिक्षा की आवश्यकता. पी०एच०आई० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली।
 - माथुर, एस.एस. (2011). उभरते हुए भारतीय समाज में शिक्षक, आगरा :अग्रवाल पब्लिकेशन्स, पृ०सं० 05।
 - मिश्रा, के. एस. (2006). इमोशनल इण्टेलीजेन्स, कॉन्सेप्ट, मेजरमेन्ट एण्ड रिसर्च, इलाहाबाद, एसोसिएशन फार एजूकेशन स्टेडीज।
 - सोती, शिवेन्द्र चन्द्र (2015). मानव व्यक्तित्व : अवधारणाएं एवं सिद्धान्त, नई दिल्ली, कनिका पब्लिशर्स।
 - श्रीवास्तव अनिल और माथुर दुर्गस्वरी (2014) विभिन्न वर्ग के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव स्टर्नेशनल जर्नल ऑफ किरिटिव रिसर्च वाट वॉल्यूम .2 इश्यू 2 फरवरी मार्च पृष्ठ संख्या 1–06।
- वेबसाइट्स
- www.shodhganga.inflibnet.ac.in
 - www.shaikshikmanthan.com
 - www.education.nic
 - <http://www.desertation.com>

भारत में कौशल विकास, युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण

मनीष शर्मा

सहायक आचार्य, भूगोल

महात्मा गांधी टी.टी. कॉलेज, महवा, दौसा, राजस्थान

सारांश – भारत में कौशल विकास युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण का प्रमुख आधार है। कौशल विकास विकसित भारत के सपनों को साकार करने का प्रमुख आधार है। हमारी शिक्षा प्रणाली रोजगारोन्मुखी बने तथा प्रत्येक युवा आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हमें भारत में कौशल विकास को अपनाना पड़ेगा जिससे युवा सशक्त होगा। कौशल विकास से महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में भी हमें सहायता मिलेगी महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में कौशल विकास का महत्वपूर्ण योगदान होगा। जिससे हमारे देश के आर्थिक विकास में मदद

मिलेगी और देश का युवा महिला जब सशक्त होंगे तो हम एक विकसित राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। शिक्षा में कौशल विकास को अपने से सृजनात्मकता भी बढ़ती है बालक यदि सृजनात्मक होगा तो वह तकनीक व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ नया करके दिखा पाएगा जिससे देश में नए नवाचार होंगे और हमारे विकसित राष्ट्र निर्माण के सपनों को साकार करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

मुख्य शब्द – सृजनात्मकता, आत्मनिर्भर, सर्वांगीण विकास, तकनीक व प्रौद्योगिकी।

प्रस्तावना— कौशल विकास जिसका तात्पर्य है कार्य की कुशलता या दक्षता। हमारे द्वारा किया गया कार्य कुशलता पूर्ण होना चाहिए क्योंकि आधुनिक विश्व तीव्र गति से प्रतिस्पर्धा वाला विश्व बनता जा रहा है। इस प्रतिस्पर्धा वाले युग में छात्रों के लिए कौशल विकास का महत्व सर्वोपरि है। वर्तमान युग में पारंपरिक अकादमी ज्ञान पर्याप्त नहीं है इस युग में छात्रों को विभिन्न प्रकार के कौशल युक्त ज्ञान की आवश्यकता है जो ज्ञान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के योग्य बना सके। वर्तमान युग में हमें विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखना होगा और यह सर्वांगीण विकास का दृष्टिकोण कौशल विकास से ही संभव हो सकता है।

कौशल विकास का महत्व

रोजगार के क्षेत्र में प्राथमिकता – वर्तमान समय में विभिन्न बड़े-बड़े संस्थान या औद्योगिक क्षेत्र के नियोक्ता ऐसे छात्रों का चयन करते हैं जिनके पास

न केवल शैक्षणिक क्षेत्र की योग्यताएं हो बल्कि विभिन्न प्रकार के कौशल भी प्राप्त हो क्योंकि ऐसे व्यक्ति या छात्र अधिक समायोजित तथा अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम होते हैं।

तकनीकी प्रगति – आधुनिक युग तकनीकी विकास का युग है जिसमें तकनीकी कौशल का विशिष्ट महत्व है। आज का समय परंपरागत शिक्षण से हटकर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला है क्योंकि प्रौद्योगिकी के इस युग में आगे वही सक्षम है जो तकनीकी विकास से जुड़ा हुआ है।

उद्यमशीलता – कौशल विकास छात्रों में उद्यमशीलता की भावना को बढ़ाता है कौशल विकास के माध्यम से छात्र अपना स्टार्टअप करने में प्रभावी होते हैं तथा परंपरागत विचारों में परिवर्तन लाते हैं और नौकरी करने के स्थान पर नौकरी देने की क्षमता का विकास करते हैं।

समस्या समाधान – शिक्षा में कौशल विकास से छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित होगी छात्र चुनौतियों को पहचान उनके समाधान करने रचनात्मक समाधान खोजने और अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं को हल करने जैसी स्थितियों में अपने आप को बेहतर बना पाएंगे।

जब छात्र अपने व्यवहार में समस्या समाधान कौशल को अपनाएंगे तो उसमें अनेक परिवर्तन दृष्टिगत होंगे जैसे प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता का विकास, आलोचनात्मक चिंतन, आत्मविश्वास का विकास, नेतृत्व की क्षमता का विकास।

जीवन कौशल – कौशल विकास छात्रों को जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है तथा उसे घर परिवार समाज कार्य स्थल पर श्रेष्ठ भूमिका के लिए तैयार करता है। जीवन कौशल में प्रभावी संचार, समय प्रबंधन आदि कौशल को शामिल किया जाता है।

कौशल विकास के शैक्षणिक लाभ

जब छात्र कौशल विकास की गतिविधियों में संलग्न होते हैं तो वह अपनी मानसिक क्षमताओं, आलोचनात्मक चिंतन तथा समस्या समाधान की क्षमताओं में वृद्धि करते हैं जो किसी भी परिवेश में बहुत मूल्यवान होते हैं ऐसे छात्र अपनी शिक्षण कार्य में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं

कौशल विकास के शिक्षा में लाभ

जटिल अवधारणाओं को समझने में उपयोगीस विभिन्न गतिविधियों के मध्य संतुलन बनाने में सक्षम।

स्मृति सुधार और सूचना प्रतिधारण की क्षमता में विकास।

सुव्यवस्थित एवं सुविचार शोध पत्र एवं प्रस्तुतियां तैयार होती हैं।

परीक्षा के लिए रन नीतियों तथा शैक्षणिक प्रदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका।

सृजनात्मक कौशल शिक्षा

आधुनिक युग वैज्ञानिक युग है इसलिए मनोवैज्ञानिकों का ध्यान उस अदभुत योग्यता एवं शक्ति के सम्बंध में शोध करने के लिए आकर्षित हुआ जो व्यक्ति को नित्य नये आविष्कार करने, जटिल समस्याओं ढूँढने तथा जीवन को सुख मय बनाने के लिए मानव को सहयोग प्रदान करती है। इस अदभूत एवं मनोहरी योग्यता को ही सृजनात्मकता की संज्ञा दी जाती है।

सृजनात्मकता प्रायः समस्त प्राणियों में पायी जाती है परन्तु किसी में कम पायी जाती है, किसी में अधिक। प्रायः यह माना जाता है की केवल लेखक, कवी चित्रकार, संगितकार, वैज्ञानिक, फिल्म अभिनेता आदि ही सृजनशील व्यक्ति होते हैं। आज यह विचार मान्य नहीं है क्योंकि आधुनिक मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि सृजनात्मकता किसी भी क्षेत्र में अपना सुखद प्रभाव दिखा सकती है। अध्यापक, क्लर्क, श्रमिक, माता, रसोइया, कृषक, आंदोलनकारी आदि अपने अपने क्षेत्र में सृजनात्मक हो सकते हैं। यदि एक माता भली भाँती बच्चे का पालन पोषण करके या एक अध्यापक बच्चे की अच्छी एवं उपयोग शिक्षा देकर या एक रसोइया नयी सन्तुलित एवं पोषण युक्त मानों से खाद्य सामग्री तैयार करे या एक कल्के ऑफिस विकास के लिए नवीन विधियों से कार्य करके समाज एवे देश के लिए लाभकारी कार्य करे तो हम कह सकते हैं कि इन सभी प्राणियों में पर्याप्त मात्रा में सृजनात्मकता विद्यमान है।

कौशल विकाश से जुड़ी केंद्रीय योजनाएं

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)। इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने इस योजना को जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 2020 तक एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) देने की योजना बनाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया

कराना है जो कम पढ़े-लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं।

कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए महिला सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। महिलाओं के संदर्भ में उद्यमिता का अर्थ केवल महिलाओं को रोजगार प्रदान करना नहीं है बल्कि उनके द्वारा किए गए कार्यों से उनके आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को और अधिक बेहतर बनाने से है। महिला उद्यमिता से महिलाओं में रोजगार सृजन की प्रवृत्ति में वृद्धि तो होती है साथ ही उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है, जिससे उनका जीवन आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ सुलभ भी हो जाता है। प्राचीन काल की अपेक्षा भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है किंतु आज भी महिलाएं आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए वर्तमान में भी महिला सशक्तिकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में सफल और सशक्त बनाने के साथ-साथ महिलाओं को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग होने के लिए भी प्रेरित करता है। महिला उद्यमिता से महिलाएं अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में सुधार कर सकती हैं, साथ ही महिला सशक्तिकरण की दशा और दिशा दोनों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में जहां कार्य शक्ति में भागीदारी की निम्न दर और लैंगिक असमानता जैसी समस्याएं आज भी उपस्थित हैं, यह एक बड़ी चिंता का विषय है। महिला उद्यमिता से देश में विद्यमान इन समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। इस शोध पत्र के द्वारा महिला उद्यमिता का महिला सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव होगा इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है तथा साथ ही महिला उद्यमिता से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख और उनका समाधान भी प्रस्तुत किया

महिलाएं और उद्यमिता विकास

देश के आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में महिलाओं की भूमिका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा महत्वपूर्ण रही है। जब महिलाओं को अवसर प्राप्त नहीं होते थे, तो वह घर के समस्त कार्य, बच्चों का पालन पोषण आदि तक ही सीमित रहती थीं। लेकिन जैसे-जैसे देश में शिक्षा का विस्तार, कौशल विकास में और उद्यमिता विकास में वृद्धि होती जा रही है तो महिलाएं घर और बाहर दोनों के कार्यों को कुशलता से संभालने का सफल प्रयास कर रही हैं। किंतु यह भी सत्य है कि अधिकतर महिलाएं अकुशल हैं जिससे उद्यम के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी नहीं है।

अतः कौशल विकास और महिला उद्यमिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह महिलाओं की कार्य में भागीदारी तथा कार्यकुशलता और उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेगा। आज के समय के अनुसार महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित कौशल ज्ञान प्राप्त करना चाहिए

युवा शक्ति और कौशल शिक्षा

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये देश की व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रणाली को सशक्त बनाना होगा। कोरोना ने देशवासियों को ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर अनेक लोगों को कौशल की आवश्यकता है। इस समय हर वर्ग के व्यक्ति को एक सभ्य आजीविका की जरूरत है। कौशल एवं व्यवसायिक शिक्षा की जरूरत केवल वंचित समुदायों के लोगों को ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी जरूरत है जो औपचारिक शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पायें। भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला युवा देश है और यह युवा शक्ति न्यू इंडिया का आधारस्तंभ है। लिहाजा केंद्र सरकार की नीतियों में बजट में, योजनाओं में। युवाओं को लेकर भविष्य के विकास का विजन दिखाई देता है। जैसा कि अमृत काल

के बजट में युवाओं और उनके भविष्य को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप से कैसे युवाओं की तकदीर बदल रही है। सुधारों के साथ शिक्षा क्षेत्र की कैसे तस्वीर बदल रही है। युवा किसी भी देश का भविष्य है, आज, भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। यहाँ प्रत्येक तीसरा व्यक्ति युवा है ऐसे में हमें, इस युवा ऊर्जा का प्रयोग सही दिशा में करने के लिए साधन सोचने होंगे। युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने वाली नीतियां और कार्यक्रम मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी आवश्यकता है। युवाओं को सशक्त बनाने की कुंजी, कौशल विकास के साथ है, जब एक युवा के पास आवश्यक कौशल होता है तो वह उसका उपयोग अपनी आजीविका व दूसरों की सहायता करने के लिए कर सकता है। वह आर्थिक रूप से राष्ट्र का भी समर्थन करता है। युवाओं को शिक्षा के साथ कौशल विकास और उद्यमशीलता से जोड़ना जरूरी है। साथ ही उन्हें स्कूली शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा भी अति आवश्यक है। कोरोना माहमारी के समय अनेक लोगों को अपने रोजगार, व्यवसाय और नौकरी से हाथ धोना पड़ा इसलिये जरूरी है कि हमारे देश के सभी बच्चों को कौशल विकास की शिक्षा प्रदान की जाये ताकि उनमें उद्यमशीलता का गुण विकसित हो।

भारत में कौशल विकास में आने वाली सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां लगभग 93 प्रतिशत लोग अकुशल इसके अतिरिक्त ऐसे बेरोजगार लोगो को शिक्षित करना जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की है या बीच में छोड़ दी है। महिलाओं की घटती भागीदारी भी एक गंभीर समस्या है।

कौशल विकास एवं युवा सशक्तिकरण, भारत की विशाल युवा आबादी (64: कामकाजी उम्र) को जनांकिकीय लाभांश में बदलने के लिए अनिवार्य है। स्किल इंडिया मिशन (2015) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से, यह शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के बीच की खाई को पाटकर रोजगार क्षमता को

सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल गरीबी कम करता है, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेश सुनिश्चित करता है। 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार महिलाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में भागीदारी 33.3 प्रतिशत से घटकर 26.5 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में भागीदारी 17.8 प्रतिशत से घटकर 15.5 प्रतिशत रह गई है। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं औद्योगिक सेक्टरों में भी अकुशल कार्यबल आर्थिक विकास के लिए बाधक बन रहा है जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता प्रभावित हो रही है तथा बड़ी संख्या में बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। अतः युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस दृष्टिकोण से हमें उद्यमिता विकास पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उद्यमिता में भारत की स्थिति 143 देशों में 76वें स्थान पर है। भारत में प्रति 1000 वर्किंग लोगों पर 0.09 कम्पनी रजिस्टर्ड है, जो कि जी-20 देशों में सबसे कम है।

निष्कर्ष

कौशल विकास और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक कार्यकुशलता से जोड़ना है, ताकि युवाओं को रोजगार योग्य और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। यह शिक्षा की पारंपरिक पुस्तकीय पद्धति को कम करके, औद्योगिक मांग के अनुसार तकनीकी व सॉफ्ट स्किल्स (Soft Skills) प्रदान करता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) जैसी पहले इसे बढ़ावा देती हैं।

मौजूदा समय में भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। इस समस्या के लिये एक बड़ी वजह भारत में कौशल विकास की कमजोर स्थिति को माना जा सकता है। भारत में कौशल विकास तथा बेरोजगारी की समस्या के मूल में स्कूली स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की अनुपस्थिति तथा विभिन्न कौशल विकास योजनाओं का अप्रभावी क्रियान्वयन है। भारत

विभिन्न विकसित देशों एवं पूर्वी एशिया के देशों से भारत प्रेरणा ले सकता है, साथ ही भारत स्थानीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर अपनी बड़ी युवा आबादी को जनसांख्यिकीय लाभांश में तब्दील कर सकता है।

कौशल विकास केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों से निपटने की क्षमता को बढ़ाने वाली एक सतत प्रक्रिया है।

कौशल विकास युवाओं को निरंतर बदलते वैश्विक परिदृश्य में सफल जीवन के लिए तैयार करने का एक तरीका है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के उत्पादक और सकारात्मक विकास को बढ़ावा देना है। यह योजना नियोक्ताओं, नीति निर्माताओं और शिक्षकों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही है।

निष्कर्ष के मुख्य बिंदु

1. भावी विकास का आधार: युवाओं को कौशल-आधारित शिक्षा प्रदान करना भारत को 2030 तक एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने की कुंजी है।

2. रोजगार सृजन: यह सिर्फ नौकरी की तलाश करने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले (उद्यमी) बनाने पर जोर देता है।
3. चुनौतियां और अवसर: यद्यपि कुशल कार्यबल की मांग है, लेकिन अभी भी उद्योग-अकादमिक तालमेल में सुधार की आवश्यकता है।
4. समग्र सशक्तीकरण: यह वंचित वर्गों और महिलाओं को मुख्यधारा में शामिल कर सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है।
5. अंततः, कौशल विकास और युवा सशक्तीकरण न केवल व्यक्तिगत उत्थान, बल्कि राष्ट्र की दीर्घकालिक, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं

संदर्भ ग्रंथ सूची

वेबसाइट्स

- www.shodhganga.inflibnet.ac.in
- www.shaikshikmanthan.com
- www.education.nic
- <http://www.desertation.com>

शिक्षक शिक्षा एवं कौशल विकास : एक समग्र सिद्धांत

पूजा

सहायक आचार्य, रसायन विज्ञान

महात्मा गांधी टी.टी. कॉलेज, महवा, दौसा, राजस्थान

सारांश

शिक्षक शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान देने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया बन चुकी है जिसमें शिक्षक खुद भी सीखने वाला होता है। आज का शिक्षक सिर्फ जानकारी का स्रोत नहीं, बल्कि मार्गदर्शक, नवाचारी और समस्या-समाधानकर्ता है। इसलिए उसकी शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए जो उसे बदलते समय के साथ ढलने की क्षमता दे।

कौशल विकास इस प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। एक प्रभावी शिक्षक में विषय ज्ञान के साथ-साथ संवाद कौशल, भावनात्मक समझ, तकनीकी दक्षता और रचनात्मक सोच का संतुलन होना जरूरी है। उदाहरण के लिए, डिजिटल युग में शिक्षक को केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीखने का अनुभव बनाना भी आना चाहिए।

सबसे खास बात यह है कि शिक्षक शिक्षा को अब “एक बार सीखो और खत्म करो” की बजाय जीवनभर सीखते रहने की सोच से जोड़ा जा रहा है। प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ, और वास्तविक कक्षा अनुभव मिलकर एक शिक्षक को लगातार बेहतर बनाते हैं।

संक्षेप में, शिक्षक शिक्षा और कौशल विकास का उद्देश्य ऐसा शिक्षक तैयार करना है जो न केवल ज्ञान दे, बल्कि छात्रों में जिज्ञासा, आत्मविश्वास और नवाचार की भावना भी जगा सके यही शिक्षा का असली अर्थ है।

मुख्य शब्द – प्रभावी शिक्षक, भावनात्मक समझ, तकनीकी दक्षता, डिजिटल युग।

1. प्रस्तावना

शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता का सीधा संबंध शिक्षक की गुणवत्ता से होता है। एक सक्षम शिक्षक न केवल ज्ञान का प्रसार करता है, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, मूल्यों और सामाजिक चेतना का निर्माण भी करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षा और कौशल विकास आज के समय में शिक्षा सुधार का केंद्रीय बिंदु बन चुके हैं।

2. शिक्षक शिक्षा का अर्थ

शिक्षक शिक्षा वह सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक को ज्ञान, शिक्षण कौशल, व्यवहारिक दक्षता, नैतिक दृष्टिकोण और व्यावसायिक समझ प्रदान की जाती है। यह केवल प्रशिक्षण नहीं बल्कि एक जीवनपर्यंत सीखने की प्रक्रिया है।

मुख्य विशेषताएँ

ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण का समन्वय
सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पहलुओं पर जोर
निरंतर विकास

संदर्भ आधारित शिक्षण

3. कौशल विकास का अर्थ

कौशल विकास का आशय उन क्षमताओं के निर्माण से है जो शिक्षक को प्रभावी, नवाचारी और संवेदनशील बनाती हैं। इसमें केवल विषय ज्ञान ही नहीं बल्कि निम्नलिखित शामिल होते हैं:

संप्रेषण कौशल
समस्या समाधान क्षमता
डिजिटल साक्षरता
भावनात्मक बुद्धिमत्ता

4. शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य:

शिक्षक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं
व्यावसायिक दक्षता का विकास
नैतिक और सामाजिक मूल्यों का निर्माण
नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान
विद्यार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण का विकास
अनुसंधान और नवाचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना

5. शिक्षक शिक्षा के आयाम**(i) शैक्षणिक आयाम**

विषय ज्ञान की गहराई
पाठ्यक्रम की समझ
शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान

(ii) मनोवैज्ञानिक आयाम

बाल विकास की समझ
व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानना
प्रेरणा और अधिगम सिद्धांत
सामाजिक आयाम
समाज और शिक्षा का संबंध
समावेशी शिक्षा
सांस्कृतिक संवेदनशीलता
तकनीकी आयाम
ई-लर्निंग उपकरणों का उपयोग

स्मार्ट क्लासरूम

ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली

6. कौशल विकास के प्रमुख क्षेत्र**1. शिक्षण कौशल**

पाठ योजना बनाना
कक्षा प्रबंधन
प्रभावी प्रस्तुतीकरण

2. संप्रेषण कौशल

स्पष्ट और सरल भाषा

विद्यार्थियों के साथ संवाद

सक्रिय सुनना

3. डिजिटल कौशल

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग
ई-कंटेंट निर्माण
वर्चुअल कक्षा संचालन

4. आलोचनात्मक चिंतन

तार्किक विश्लेषण
रचनात्मक समाधान
निर्णय लेने की क्षमता

5. भावनात्मक एवं सामाजिक कौशल

सहानुभूति
टीमवर्क
संघर्ष प्रबंधन

7. आधुनिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षक शिक्षा

आज के समय में शिक्षक शिक्षा केवल पारंपरिक कक्षा तक सीमित नहीं है। इसके नए आयाम हैं

तकनीकी एकीकरण

AI आधारित शिक्षण

डिजिटल प्लेटफॉर्म

ब्लेंडेड लर्निंग

जीवन कौशल आधारित शिक्षा

नैतिक शिक्षा

नेतृत्व कौशल

आत्म-प्रबंधन

समावेशी शिक्षा

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षण

समान अवसर प्रदान करना

8. शिक्षक शिक्षा में चुनौतियाँ

पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों का प्रभुत्व

व्यावहारिक प्रशिक्षण की कमी
डिजिटल संसाधनों की असमान उपलब्धता
निरंतर प्रशिक्षण का अभाव
मूल्यांकन प्रणाली की सीमाएँ

9. सुधार के उपाय

निरंतर व्यावसायिक विकास कार्यक्रम लागू करना
प्रयोगात्मक प्रशिक्षण को मजबूत बनाना
डिजिटल शिक्षा का विस्तार
शिक्षकों के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहन
फीडबैक आधारित मूल्यांकन प्रणाली

10. निष्कर्ष

शिक्षक शिक्षा और कौशल विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। एक प्रभावी शिक्षक वही है जो निरंतर सीखता है, स्वयं को बदलता है और विद्यार्थियों के

विकास के लिए नए-नए तरीकों को अपनाता है। भविष्य की शिक्षा प्रणाली में वही शिक्षक सफल होंगे जो ज्ञान के साथ-साथ कौशल, तकनीक और मानवीय मूल्यों का संतुलन बनाए रखेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

वेबसाइट्स

- www.shaikshikmanthan-com
- www.education-nic
- <http://www-desertation-com>
- <http://www-indianjournals-com>
- www.shodhganga-inflibnet-ac-in

वर्तमान संदर्भ में भारत के विकास में युवाओं की

भूमिका: विभिन्न आयाम

राजेश देव

सहायक आचार्य, वनस्पति विज्ञान

महात्मा गांधी कॉलेज, महवा, दौसा, राजस्थान

सारांश

भारत के युवा केवल एक जनसांख्यिकीय वर्ग नहीं हैं, बल्कि इसकी आबादी का सबसे गतिशील और परिवर्तनकारी हिस्सा हैं। एक ऐसे देश में जहां लगभग 65 नागरिक 35 वर्ष से कम आयु के हैं, राष्ट्रीय विकास में युवाओं की भूमिका लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक प्रगति के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण हो जाती है। यह शोध पत्र वर्तमान संदर्भ में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी आयामों में भारत के विकास में युवाओं की बहुआयामी भूमिका का विश्लेषण करता है। गुणात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से, यह अध्ययन राष्ट्रीय

परिवर्तन में योगदान देने की भारत के युवाओं की क्षमता, उनके सामने आने वाली बाधाओं और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य के नीतिगत ढांचे की पड़ताल करता है। निष्कर्ष इस बात पर बल देते हैं कि शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, नवाचार और राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से युवा ऊर्जा का उपयोग करके भारत को सतत और समावेशी विकास में वैश्विक अग्रणी बनाया जा सकता है।

मुख्य शब्द— युवा, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, राजनीतिक वैश्वीकरण, भागीदारी, उत्पादकता।

प्रस्तावना

युवाओं की अवधारणा हर राष्ट्र की प्रगति, परिवर्तन और निरंतरता की दृष्टि का केंद्र रही है। युवा न केवल देश की परंपराओं के उत्तराधिकारी हैं, बल्कि उसके भविष्य के निर्माता भी हैं। भारत, विश्व के सबसे युवा राष्ट्रों में से एक होने के नाते, एक ऐसे जनसांख्यिकीय मोड़ पर खड़ा है जहाँ इसकी जनसंख्या का लाभ विकास प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी की प्रभावी क्षमता के आधार पर लाभकारी या प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को युवा माना जाता है। भारत की जनगणना (2011) के अनुसार, भारत की 50 से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है, और 65 से अधिक 35 वर्ष से कम आयु की है। जहाँ अधिकांश विकसित राष्ट्र तेजी से वृद्ध हो रहे हैं। यदि भारत के युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता और

आकांक्षाओं को उचित मार्गदर्शन दिया जाए, तो वे राष्ट्र को नवाचार, उत्पादकता और सांस्कृतिक गतिशीलता का केंद्र बना सकते हैं। हालांकि, वैश्वीकरण, डिजिटलीकरण और आर्थिक परिवर्तन के वर्तमान संदर्भ में, युवाओं के सामने चुनौतियां भी कई गुना बढ़ गई हैं। बेरोजगारी, कौशल की कमी, राजनीतिक, उपभोक्तावाद और सांस्कृतिक अलगाव जैसे मुद्दे उनकी रचनात्मक भागीदारी के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इसलिए, भारत के विकास में युवाओं के अध्ययन को न केवल उनकी जनसांख्यिकीय क्षमता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, बल्कि सामाजिक संरचना, शिक्षा प्रणाली, नीतिगत ढांचे और मूल्य अभिविन्यास के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए। भारत का लक्ष्य 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है, और इस परिवर्तन में युवाओं की भूमिका प्रमुख रहेगी। इसलिए, प्रभावी राष्ट्रीय नीतियां बनाने के लिए

उनकी भूमिका को व्यापक, बहुआयामी और आलोचनात्मक रूप से समझना आवश्यक है। यह शोधपत्र भारत के विकास में युवाओं की भूमिका के विभिन्न आयामों—आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी—का विश्लेषण करता है, साथ ही उनके योगदान को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक चुनौतियों और नीतिगत तंत्रों पर भी प्रकाश डालता है।

भारत के विकास में युवाओं की ऐतिहासिक भूमिका

भारत के विकास का इतिहास युवाओं की ऊर्जा और बलिदान से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक, भारतीय सभ्यता ने युवाओं को ज्ञान, साहस और रचनात्मकता का वाहक मानते हुए उनकी शक्ति को मान्यता दी है। ऋग्वेद और उपनिषद जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में युवा शिक्षा (ब्रह्मचर्य) को जीवन का मूलभूत चरण बताया गया है। युवावस्था में नैतिक, शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने का विचार भारतीय चिंतन का केंद्र था, जो दर्शाता है कि राष्ट्रीय शक्ति युवाओं के चरित्र और अनुशासन से उत्पन्न होती है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, युवाओं ने राष्ट्रीय चेतना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भगत सिंह, चंद्र शेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे नेताओं के नेतृत्व में क्रांतिकारी युवा आंदोलनों का उदय हुआ, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाले युवा भारत की अदम्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व किया। उसी समय, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने युवाओं को अहिंसक जन आंदोलन में शामिल किया, जिससे देश का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। युवा न केवल भागीदार थे, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक अग्रदूत भी थे।

युवा और आर्थिक विकास

आर्थिक विकास उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जहां युवा सक्रिय योगदान देते हैं। भारत की युवा

आबादी श्रम, नवाचार और उद्यमशीलता की अपार क्षमता का भंडार है। अर्थशास्त्रियों द्वारा वर्णित “जनसांख्यिकीय लाभांश” का अर्थ है कि कामकाजी उम्र की आबादी आश्रित आबादी से अधिक है, जो त्वरित आर्थिक विकास का अवसर प्रदान करती है।

युवा राष्ट्र के कार्यबल के रूप में

नीति आयोग के अनुसार, भारत के लगभग 65 श्रम बल की आयु 35 वर्ष से कम है। पर्याप्त रोजगार के अवसर और कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध होने पर यह जनसांख्यिकीय लाभ राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ा सकता है। कौशल भारत मिशन (2015), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और राष्ट्रीय शिक्षता प्रोत्साहन योजना को शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच कौशल अंतर को पाटने के लिए बनाया गया है। हालांकि, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के अनुसार, युवाओं (15–29 वर्ष) में बेरोजगारी दर 17–20 के बीच बनी हुई है, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। इसके कारणों में संस्थानों में सिखाए जाने वाले कौशल और श्रम बाजार की आवश्यकताओं के बीच असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सीमित उपलब्धता और स्वचालन के कारण पारंपरिक रोजगार के अवसरों में कमी शामिल हैं। इसलिए, युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए न केवल कौशल विकास बल्कि शिक्षा और श्रम नीतियों में संरचनात्मक सुधारों की भी आवश्यकता है।

युवा उद्यमिता और नवाचार

हाल के वर्षों में, भारतीय युवाओं में उद्यमिता की भावना आर्थिक गतिशीलता के एक प्रमुख चालक के रूप में उभरी है। स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने युवा उद्यमियों को प्रौद्योगिकी-आधारित उद्यमों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया है। फिनटेक, एडटेक, हेल्थ टेक और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में युवा नेतृत्व वाले स्टार्टअप ने

भारतीय बाजार में क्रांति ला दी है। रितेश अग्रवाल (OYO), बायजू रवींद्रन (BYJU'S) और निखिल कामथ (मतवर्की) जैसे युवा उद्यमियों की सफलता इस बात का उदाहरण है कि कैसे नवाचार और जोखिम लेने की क्षमता भारत की अर्थव्यवस्था को बदल सकती है।

ग्रामीण और कृषि आयाम

जहां शहरी युवा प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्रों में संलग्न हैं, वहीं ग्रामीण युवा कृषि आधुनिकीकरण और ग्रामीण उद्यमिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि उद्यमिता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और ग्रामीण पर्यटन के विकास ने आय सृजन के नए अवसर पैदा किए हैं। हालांकि, ग्रामीण युवाओं को अभी भी भूमि विखंडन, अपर्याप्त ऋण उपलब्धता और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि शिक्षा, सूक्ष्म वित्त और सहकारी विकास के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाना समावेशी आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था और युवा रोजगार

डिजिटल क्रांति ने सूचना प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर खोले हैं। भारत का युवा कार्यबल वैश्विक आउटसोर्सिंग और आईटी-आधारित सेवा क्षेत्र की रीढ़ बनता जा रहा है। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों और ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्मों ने आर्थिक अवसरों तक पहुंच को और अधिक लोकतांत्रिक बना दिया है। फिर भी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल असमानता पूर्ण भागीदारी को सीमित करती रहती है। समान आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए इस डिजिटल विभाजन को पाटना आवश्यक है।

युवा और राजनीतिक भागीदारी

युवाओं की राजनीतिक भागीदारी एक जीवंत लोकतंत्र की नींव है। विश्व में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली होने के नाते, भारत की

लोकतांत्रिक प्रणाली निर्णय लेने और शासन प्रक्रियाओं में अपने युवा नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर बहुत अधिक निर्भर करती है।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवा

भारत का संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, जिससे 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का अधिकार मिलता है। इसने युवाओं को एक निर्णायक चुनावी शक्ति बना दिया है। हाल के चुनावों में, युवा मतदाताओं ने कुल मतदाताओं का लगभग 45 हिस्सा बनाया। सोशल मीडिया, शिक्षा और मुद्दे-आधारित आंदोलनों के कारण युवाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। हालांकि, राजनीतिक भागीदारी केवल मतदान तक ही सीमित नहीं है। छात्र संगठनों, नीतिगत वकालत, सामाजिक आंदोलनों और नेतृत्व प्रशिक्षण में युवाओं की भागीदारी ने देश के लोकतांत्रिक आधार को व्यापक बनाया है। युवा संसद कार्यक्रम, राष्ट्रीय युवा नीति और नागरिक समाज की पहल युवाओं को राजनीतिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

युवा आंदोलन और राजनीतिक जागृति

ऐतिहासिक रूप से, युवा आंदोलनों ने बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों को गति प्रदान की है। भारत छोड़ो आंदोलन (1942) से लेकर जेपी आंदोलन (1974) और अन्ना हजारे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन (2011) तक, युवाओं ने जवाबदेही और सुधार की मांग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रतिनिधित्व और चुनौतियाँ

जनसंख्यात्मक रूप से मजबूत होने के बावजूद, विधायी निकायों में युवाओं का प्रतिनिधित्व सीमित बना हुआ है। भारत में संसद सदस्यों की औसत आयु 55 वर्ष से अधिक है, जो युवा मतदाताओं और वरिष्ठ नीति निर्माताओं के बीच के अंतर को उजागर करती है। संरचनात्मक बाधाएँ,

राजनीतिक मार्गदर्शन की कमी और धन एवं बाहुबल का वर्चस्व युवाओं को राजनीति में आने से रोकता है। पार्टी सुधारों, नेतृत्व विकास और राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से युवा प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करना अधिक सहभागी लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

युवा और सामाजिक परिवर्तन

राजनीति और अर्थशास्त्र से परे, भारत में युवा ऐतिहासिक रूप से सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक नवीनीकरण के अगुआ रहे हैं। शिक्षा, लैंगिक समानता, पर्यावरण स्थिरता और मानवाधिकार आंदोलनों में उनकी भागीदारी आधुनिक भारतीय समाज को आकार देना जारी रखे हुए है।

शिक्षा और ज्ञानोदय

शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन बनी हुई है। शिक्षित युवा पुरानी परंपराओं, जातिगत पदानुक्रम और लैंगिक भेदभाव को चुनौती देकर आधुनिकीकरण के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) और नई शिक्षा नीति (2020) जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को आलोचनात्मक सोच और बहुविषयक ज्ञान से सशक्त बनाना है। हालांकि, शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच, विशेष रूप से हाशिए पर स्थित क्षेत्रों में, प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है।

लैंगिक समानता और सशक्तिकरण

लैंगिक न्याय के संघर्ष में युवाओं, विशेषकर युवा महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय रहा है। लैंगिक हिंसा के विरुद्ध आंदोलनों से लेकर महिलाओं की शिक्षा और प्रतिनिधित्व के अभियानों तक, युवा सक्रियता ने सामाजिक दृष्टिकोण को बदल दिया है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स का उदय और युवा महिला नेताओं की राजनीतिक भागीदारी समावेशिता की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव को दर्शाती है।

पर्यावरण जागरूकता

हाल के दशकों में भारतीय युवाओं में पर्यावरण चेतना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर जैसे वैश्विक आंदोलनों से प्रेरित होकर, भारतीय युवाओं ने जलवायु परिवर्तन, वृक्षारोपण और टिकाऊ जीवनशैली के लिए स्थानीय अभियान शुरू किए हैं। शैक्षणिक संस्थान और गैर-सरकारी संगठन युवा नेतृत्व वाले पर्यावरण कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के भविष्य के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका को पहचानते हैं।

सोशल मीडिया और सांस्कृतिक परिवर्तन

सोशल मीडिया एक ऐसा मंच बन गया है जहाँ युवा जनमत और सांस्कृतिक विचारों को आकार देते हैं। यह आत्म-अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और सामाजिक कार्यों के लिए लामबंदी के अवसर प्रदान करता है। हालांकि, यह युवाओं को सांस्कृतिक एकरूपता, गलत सूचना और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के प्रति भी संवेदनशील बनाता है। इसलिए, डिजिटल स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाए रखना युवा सामाजिक भागीदारी का एक अनिवार्य पहलू है।

युवा और तकनीकी नवाचार

आधुनिक भारत में युवाओं के योगदान के सबसे गतिशील क्षेत्रों में से एक तकनीकी नवाचार है। 21वीं सदी को अक्सर "डिजिटल युग" कहा जाता है, और भारत के युवा इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। वे न केवल प्रौद्योगिकी के उपभोक्ता हैं, बल्कि देश के विकास पथ को पुनर्परिभाषित करने वाले निर्माता, नवप्रवर्तक और सुधारक भी हैं।

नवप्रवर्तक और डिजिटल मूल निवासी के रूप में युवा

डिजिटल मूल निवासी होने के नाते, भारत के युवाओं में तकनीकी प्रगति को गति देने के लिए आवश्यक रचनात्मकता और अनुकूलन क्षमता है। स्मार्टफोन, हाई-स्पीड इंटरनेट और डिजिटल

साक्षरता कार्यक्रमों के प्रसार ने युवा भारतीयों को ज्ञान प्राप्त करने, वैश्विक स्तर पर जुड़ने और स्थानीय स्तर पर नवाचार करने में सक्षम बनाया है। अटल टिकरिंग लैब्स, हैकाथॉन और स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक जैसे प्लेटफॉर्म छात्रों और युवा पेशेवरों के बीच प्रयोग की भावना को बढ़ावा देते हैं। इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों में युवाओं की बड़ी भागीदारी के साथ भारत का वैश्विक आईटी हब के रूप में उभरना कुशल डिजिटल कार्यबल की मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा, भारतीय युवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, फिनटेक, ब्लॉकचेन और जैव प्रौद्योगिकी में तेजी से सक्रिय हो रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों के समाधान विकसित हो रहे हैं।

स्टार्टअप और ज्ञान अर्थव्यवस्था

भारत में ज्ञान अर्थव्यवस्था के उदय का श्रेय युवा नवोन्मेषकों को जाता है। 2024 तक, भारत में 110 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, जो विश्व में तीसरे सबसे बड़े हैं। इनमें से अधिकांश युवा नेतृत्व वाले उद्यम हैं जो डिजिटल समाधानों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक्स और वित्त के क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करते हैं। अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) और राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन (एनआईएफ) जैसे कार्यक्रम जमीनी स्तर पर रचनात्मकता को पोषित करने के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करते हैं। सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था से ज्ञान-आधारित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन ने भारत के तकनीकी पुनर्जागरण के केंद्र में युवाओं को ला खड़ा किया है। विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान स्टार्टअप्स के साथ सहयोग बढ़ा रहे हैं और छात्रों को उनके शैक्षणिक सफर के दौरान प्रोटोटाइप और उद्यमशीलता के विचार विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

सामाजिक समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी

युवा सामाजिक समावेशन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर

रहे हैं। साक्षरता, ग्रामीण संपर्क, महिलाओं की सुरक्षा और सरकारी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। टेलीमेडिसिन, ई-लर्निंग और ई-गवर्नेंस के लिए मोबाइल-आधारित ऐप्स ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की खाई को पाट रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि दूरदराज के क्षेत्रों के युवा देश की तकनीकी क्रांति में भाग ले सकें।

जोखिम और नैतिक आयाम

हालांकि, तकनीकी क्षेत्र नई नैतिक चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। साइबरबुलिंग, गलत सूचना, डेटा गोपनीयता और डिजिटल लत जैसे मुद्दे युवा मन को काफी प्रभावित करते हैं। इसलिए, तकनीकी नवाचार को नैतिक जागरूकता, सामाजिक जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण डिजिटल साक्षरता द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। विकास में युवाओं की डिजिटल भूमिका को आकार देने में प्रगति और नैतिकता के बीच संतुलन एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है।

भारतीय युवाओं के सामने चुनौतियां

देश की प्रगति की रीढ़ होने के बावजूद, भारतीय युवाओं को कई परस्पर संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो विकास में प्रभावी योगदान देने की उनकी क्षमता को सीमित करती हैं।

बेरोजगारी और अल्प-रोजगार

युवा बेरोजगारी सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, स्वचालन और शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों के बीच असंतुलन ने बेरोजगारी को और भी गंभीर बना दिया है। हालांकि हर साल लाखों लोग स्नातक होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों को उपयुक्त नौकरियां मिल पाती हैं, जिससे अल्प-रोजगार और आर्थिक हताशा उत्पन्न होती है। स्थिर रोजगार का अभाव न केवल व्यक्तिगत कल्याण को

प्रभावित करता है, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादकता को भी धीमा कर देता है।

शिक्षा और कौशल असंतुलन

भारत की शिक्षा प्रणाली, हालांकि विस्तारित हो रही है, अक्सर उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रदान करने में विफल रहती है। पुराने पाठ्यक्रम, अपर्याप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण और आलोचनात्मक सोच पर अपर्याप्त ध्यान कई युवाओं को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं। अकादमिक शिक्षा और बाजार की आवश्यकताओं के बीच का अंतर एक "कौशल विरोधाभास" को जन्म देता है जहाँ डिग्री तो मौजूद है, लेकिन रोजगार योग्यता नहीं।

राजनीतिक अलगाव

यद्यपि युवा मतदाताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, फिर भी उनमें से कई राजनीतिक रूप से निराश हैं। भ्रष्टाचार की व्यापकता, पारदर्शिता की कमी और वंशवादी राजनीति का प्रभुत्व सार्थक भागीदारी को हतोत्साहित करता है। इसके अलावा, सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी अक्सर सतही ही रहती है, न कि सक्रिय नीति निर्माण या शासन में परिवर्तित होती है।

मानसिक स्वास्थ्य और पहचान का संकट

प्रतिस्पर्धा, उपभोक्तावाद और सामाजिक अपेक्षाओं के दबाव के कारण युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ बढ़ रही हैं। सामाजिक अपेक्षाओं, बेरोजगारी और तीव्र परिवर्तन के तनाव के चलते चिंता, अवसाद और पहचान का संकट आम होता जा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सीमित है, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।

सामाजिक असमानता और बहिष्कार

जाति, लिंग और आर्थिक असमानता भारतीय युवाओं के बड़े वर्गों को हाशिए पर धकेलती रहती है। ग्रामीण युवा, महिलाएँ और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लोग शिक्षा, रोजगार और

प्रतिनिधित्व में व्यवस्थागत बाधाओं का सामना करते हैं। इन संरचनात्मक असमानताओं को दूर किए बिना, समावेशी युवा विकास का दृष्टिकोण अधूरा रह जाता है।

पर्यावरणीय और नैतिक चुनौतियाँ

जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और पारिस्थितिक असंतुलन आज के युवाओं के भविष्य को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभरे हैं। कई युवा पर्यावरणीय न्याय के लिए सक्रिय हो रहे हैं, फिर भी उन्हें सरकारी नीतियों और युवा सशक्तिकरण योजनाओं का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार युवाओं को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन मानती है। उनके विकास की क्षमता का उपयोग करने के लिए कई नीतियाँ और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

राष्ट्रीय युवा नीति (2014)

राष्ट्रीय युवा नीति (एनवाईपी) 2014 युवाओं को 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करती है। यह पांच प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:

1. शिक्षा – पहुँच और गुणवत्ता में सुधार;
2. रोजगार और उद्यमिता – कौशल-आधारित अवसरों का सृजन;
3. स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवनशैली – शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देना;
4. सहभागिता – नेतृत्व और शासन भूमिकाओं को प्रोत्साहित करना;
5. सामाजिक न्याय – समानता और समावेश सुनिश्चित करना।

इस नीति का उद्देश्य युवाओं को उनकी पूर्ण क्षमता हासिल करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाना है।

कौशल और रोजगार पहल

स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), राष्ट्रीय शिक्षुता योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का

उद्देश्य युवाओं में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। सरकार का डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया पर जोर युवाओं को वैश्विक डिजिटल और विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं में एकीकृत करके इन पहलों को और मजबूत बनाता है।

शिक्षा और अनुसंधान

नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 समग्र, बहुविषयक और कौशल-आधारित शिक्षा पर केंद्रित है। यह शिक्षा के सभी स्तरों पर नवाचार, अनुसंधान और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ) और विश्वविद्यालयों में नवाचार प्रकोष्ठ जैसी पहलें युवा अनुसंधान और रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं।

शासन और सामाजिक सेवा में युवा

नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) जैसे संगठन लाखों युवाओं को सामुदायिक विकास, नेतृत्व प्रशिक्षण और आपदा राहत कार्यों में शामिल करते हैं। ये कार्यक्रम अनुशासन, देशभक्ति और नागरिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देते हैं।

स्वास्थ्य और कल्याण

फिट इंडिया मूवमेंट, आयुष्मान भारत और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों जैसी योजनाओं का उद्देश्य युवा नागरिकों में शारीरिक फिटनेस और मानसिक लचीलेपन को बढ़ावा देना है। खेलो इंडिया के माध्यम से खेल विकास पर सरकार के फोकस ने एथलेटिक्स और खेल प्रबंधन में युवाओं की भागीदारी के अवसरों को और भी बढ़ाया है।

भारत के युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी आशा और सबसे शक्तिशाली संपत्ति हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में, 21वीं सदी में भारत का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपनी युवा आबादी की क्षमता का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग करता है। युवा एक

समरूप वर्ग नहीं हैं, बल्कि एक विविधतापूर्ण समूह हैं जो भारत की सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक विविधता को दर्शाते हैं। इसलिए विकास में उनकी भागीदारी समावेशी, न्यायसंगत और सतत होनी चाहिए। युवाओं की भूमिका कई आयामों तक फैली हुई है—आर्थिक उत्पादकता, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक परिवर्तन और तकनीकी नवाचार। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र एक मजबूत, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण के व्यापक दृष्टिकोण में योगदान देता है। युवाओं को सशक्त, सक्रिय और शामिल करके ही भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभ को जनसांख्यिकीय लाभांश में बदल सकता है। आज भारत के युवाओं का जोश स्वामी विवेकानंद के शब्दों से मेल खाता है, जिन्होंने कहा था: “मेरी आस्था युवा पीढ़ी में है, आधुनिक पीढ़ी में है, इन्हीं में से मेरे कार्यकर्ता निकलेंगे! ये शेरों की तरह सारी समस्या का समाधान निकालेंगे।” यह आस्था भारत की विकास यात्रा के सार को परिभाषित करती रहती है। युवा ऊर्जा और दूरदर्शी नीति के बीच तालमेल ही अंततः यह निर्धारित करेगा कि क्या भारत 2047 तक एक विकसित, न्यायसंगत और प्रबुद्ध राष्ट्र के रूप में उभरने की अपनी आकांक्षा को पूरा कर पाएगा।

References & Bibliography

- Government of India- (2014)- National Youth Policy 2014- Ministry of YouthAffairsAnd Sports-
- NITI Aayog- (2023)- India @100% Strategy for New India-
- United Nations Development Programme (UNDP)- (2022)- Human Development Report-
- Ministry of Skill DevelopmentAnd Entrepreneurship- (2022)- Skill IndiaAnnual Report-
- National Statistical Office (NSO)- (2023)- Youth EmploymentAnd Education Trends in India-

- Sharma] R- (2021)- YouthAnd Nation&Building in India- New Delhi% Sage Publications-
- Desai] M- (2019)- Indian YouthAnd the Challenges of Modernization- OÔford University Press-
- Basu] K-] & Nayyar] D- (2020) - The Economic Role of Youth in Emerging Economies-
- World Bank- (2021)- World Development Indicators-
- Vivekananda] Swami- (1893)- The Complete Works-AdvaitaAshrama Publications.

आत्मनिर्भर भारत में महिला उद्यमिता का योगदान एवं प्रासंगिकता

मुकलेश माली

सहायक आचार्य, हिन्दी

महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महवा, दौसा, राजस्थान

सारांश

आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना केवल एक आर्थिक अभियान नहीं है, अपितु यह एक सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन का आह्वान भी है। इस परिवर्तन में महिला उद्यमिता एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जब हम यह बात करते हैं कि भारत को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना है, तो इसमें महिलाओं की आर्थिक भागीदारी से अलग नहीं किया जा सकता। भारत में महिलाओं की जनसंख्या लगभग 50 प्रतिशत है और यदि इस शक्ति को उद्यमिता की दिशा में मोड़ा जाये, तो भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है।

प्रस्तुत शोध-पत्र 'आत्मनिर्भर भारत में महिला उद्यमिता का योगदान एवं प्रासंगिकता' विषय पर केंद्रित है, जिसमें यह विश्लेषण किया गया है कि महिला उद्यमिता क्या है, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, सरकार की कौन-सी योजनाएँ महिला उद्यमियों को सहयोग दे रही हैं, तथा इस क्षेत्र में क्या चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ हैं। शोध में गुणात्मक अध्ययन पद्धति का उपयोग करते हुए द्वितीयक स्रोतों, सरकारी आँकड़ों एवं संबंधित साहित्य का विश्लेषण किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना केवल आर्थिक स्वावलंबन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह

सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय विकास का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस परिप्रेक्ष्य में महिला उद्यमिता का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुआयामी है। महिलाएँ न केवल आर्थिक उत्पादन में योगदान देती हैं, बल्कि सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र में महिला उद्यमिता के स्वरूप, उसके विकास, चुनौतियों तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उसकी प्रासंगिकता का विश्लेषण किया गया है।

इस शोध का निष्कर्ष यह है कि महिला उद्यमिता न केवल आर्थिक विकास का माध्यम है, बल्कि यह सामाजिक समता, गृहिणी की आर्थिक स्वतंत्रता और भारत के भौगोलिक एवं सामाजिक विकास का आधार स्तम्भ भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, 'स्टार्टअप इंडिया', 'मुद्रा योजना' और 'स्टैंड अप इंडिया' जैसी सरकारी पहल महिला उद्यमियों के लिए नए द्वार खोलती हैं। यदि इन अवसरों का समुचित दोहन हो, तो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में महिला उद्यमिता सबसे चमकता आयाम बन सकती है।

मुख्य शब्द: महिला उद्यमिता, सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, मुद्रा योजना, डिजिटल उद्यमिता, स्वयं-सहायता समूह, सूक्ष्म वित्त।

1. प्रस्तावना

भारत एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। "आत्मनिर्भर भारत" का स्वप्न केवल पुरुषों की भागीदारी से पूर्ण नहीं हो सकता, अपितु इसमें महिलाओं की सक्रिय सहभागिता अनिवार्य है। भारतीय समाज में सदियों से महिलाएँ गृहस्थ जीवन की धुरी रही हैं, किंतु आधुनिक युग में उन्होंने आर्थिक गतिविधियों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

आज की भारतीय महिला केवल गृहिणी नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी, नवप्रवर्तक और नेतृत्वकर्ता भी है। यह परिवर्तन न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है।

भारतीय सभ्यता में नारी को 'शक्ति' का स्वरूप माना गया है। वैदिक काल से लेकर आज तक, नारी ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। किन्तु सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारणों से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सीमित रही है। आज जब भारत 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना को साकार कर रहा है, तो इस यात्रा में महिला उद्यमिता एक अनिवार्य और परिवर्तनकारी अध्याय बनने जारी है।

महिला उद्यमिता (Women Entrepreneurship) से तात्पर्य उन महिलाओं से है जो अपनी व्यावसायिक प्रज्ञा, सृजनात्मकता और साहस के बल पर नये उद्योगों, व्यवसायों और सेवाओं का सृजन करती हैं। ये महिलाएँ न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारती हैं, बल्कि अन्य महिलाओं एवं पुरुषों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करती हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में, ये 'अर्थव्यवस्था की आगे चालने वाली शक्ति' (Engine of Economic Growth) हैं।

आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है एक ऐसा भारत जो अपने प्राकृतिक संसाधनों, मानवीय शक्ति और तकनीकी क्षमता के बल पर आत्मनिश्चित हो। इस संकल्पना को साकार करने में महिलाओं की भूमिका केंद्रीय है। McKinsey Global

Institute के अनुसार यदि भारत की लगभग 66 करोड़ महिलाओं की शक्ति को उद्यमिता की दिशा में मोड़ा जाये, तो देश की ळव्च में 27 प्रतिशत तक की वृद्धि संभव है। इस शोध-पत्र में इसी महत्वपूर्ण विषय का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

2. महिला उद्यमिता : अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप

महिला उद्यमिता से आशय उन महिलाओं से है जो स्वयं के व्यवसाय का संचालन करती हैं, जोखिम उठाती हैं और आर्थिक निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।

महिला उद्यमिता के प्रमुख स्वरूप निम्नलिखित हैं— लघु एवं कुटीर उद्योग, स्वरोजगार आधारित व्यवसाय, स्टार्टअप एवं नवाचार आधारित उद्यम, सामाजिक उद्यमिता, महिलाएँ आज कृषि, हस्तशिल्प, आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सेवा क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना रही हैं।

महिला उद्यमिता एक बहुआयामी अभिव्यक्ति है। इसे केवल एक महिला द्वारा व्यवसाय शुरू करने तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत आती है कृ एक दृष्टि (Vision), जोखिम उठाने की इच्छाशक्ति (Risk&takingAbility), संसाधनों का संगठन करने की क्षमता, और सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध। संयुक्त राष्ट्र उद्योग एवं विकास संगठन (UNIDO) के अनुसार महिला उद्यमिता से अभिप्राय उन महिलाओं से है जो सांसारिक संसाधनों का नियंत्रण करती हैं, विशेष समाज को लाभ पहुँचाती हैं, और समानता एवं समावेश को सुनिश्चित करती हैं।

भारत में महिला उद्यमिता के विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। पहला स्वरूप है गृह उद्योग (Cottage Industry) जिसमें महिलाएँ अचार, पापड़, शिल्पकारी, कढ़ाई-बुनाई आदि के माध्यम से आय अर्जित करती हैं। दूसरा स्वरूप है सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में भागीदारी जिसमें महिलाएँ खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र निर्माण और हस्तशिल्प में संलग्न हैं। तीसरा और सबसे नवीन स्वरूप है डिजिटल

एवं तकनीकी उद्यमिता (Tech Entrepreneurship) जिसमें महिलाएँ App] E & Commerce और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उद्योगों को विश्व स्तर पर पहुँचा रही हैं।

3. भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमिता का योगदान

आत्मनिर्भर भारत" का उद्देश्य देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाना है।

इस मिशन के पाँच प्रमुख स्तंभ हैं—

अर्थव्यवस्था

अवसंरचना

प्रणाली

जनसांख्यिकी

मांग

इन सभी स्तंभों में महिला उद्यमिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

3.1 आर्थिक योगदान

भारत में लगभग 1.35 करोड़ से अधिक महिला उद्यमियों के व्यवसाय हैं जो देश के कुल उद्योगों का लगभग 20–21 प्रतिशत हैं। ये उद्यमिताएँ लगभग 2.25 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार देती हैं। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में महिला उद्यमियों का योगदान लगभग 3–4 प्रतिशत है, जो आगामी दशक में 9 प्रतिशत तक बढ़ने की क्षमता रखता है। छेबवउ और ब्लैप्स के आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप अधिक स्थायी और समावेशी होते हैं।

3.2 सामाजिक योगदान

महिला उद्यमिता का सामाजिक योगदान आर्थिक योगदान से भी अधिक गहरा है। जब एक महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है तो परिवार में उसकी निर्णय-क्षमता बढ़ती है। वह अपनी बेटी को स्कूल भेजती है, बेटे को कौशल सिखाती है, और समाज में अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है। एक अध्ययन के अनुसार महिला की आमदनी

का 90 प्रतिशत अपने परिवार पर खर्च होता है जबकि पुरुष के लिए यह आँकड़ा केवल 30–40 प्रतिशत है। अर्थात् महिला उद्यमिता एक 'मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट' है जो न केवल आर्थिक बल्कि मानवीय पूँजी में भी निवेश करती है।

3.3 हस्तशिल्प एवं लोक कला क्षेत्र में महिला उद्यमिता

भारत के खिलौना उद्योग के 90 प्रतिशत कारीगर महिलाएँ हैं (राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में)। कच्छ के रोगन आर्ट, बिहार की मंजूनिशीन, उड़ीसा के पाटुचित्र, राजस्थान की फड़ चित्रकला एवं ब्लू पॉटरी में महिला कारीगरों का अद्वितीय योगदान है। इस क्षेत्र की महिला उद्यमियों ने सामाजिक सीमाएँ तोड़कर अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। E&Commerce मंच जैसे। mazon Karigar और Flipkart Samarth ने इन्हें वैश्विक बाज़ार से जोड़ा है।

4. आत्मनिर्भर भारत अभियान और महिला उद्यमिता

आत्मनिर्भर भारत अभियान को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को घोषित किया था। इस अभियान का लक्ष्य है एक ऐसा भारत जिसमें 'लोकल वोकल' (Local Vocal) को पहचान मिले और देश अपनी क्षमताओं के बल पर विश्व-स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। इस संकल्पना में महिला उद्यमिता की भूमिका केंद्रीय है।

आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तम्भ हैं कृ अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, तकनीक, लोग और माँग व्यवस्था। इन सभी स्तम्भों में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है। अर्थव्यवस्था में वह उत्पादक हैं, आधारभूत संरचना में वह उपभोक्ता और निर्माता हैं, तकनीक में वह नवाचारक (Innovator) हैं, लोगों की शक्ति में वह आगे चालने वाली शक्ति हैं, और माँग व्यवस्था में वह बाज़ार निर्माता हैं। अर्थात् महिला उद्यमिता आत्मनिर्भर भारत की जीवन-धारा है।

'स्टार्टअप इंडिया' अभियान के अंतर्गत 2016 से 2024 तक देश में 1.25 लाख से अधिक स्टार्टअप

पंजीकृत हुए हैं जिनमें से लगभग 45 प्रतिशत में कम से कम एक महिला सह-संस्थापक (Co&Founder) है। यह आँकड़ा दर्शाता है कि भारतीय महिलाएँ न केवल पारम्परिक व्यवसायों में बल्कि तकनीक और उद्योग के नये क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही हैं।

5. सरकारी नीतियाँ एवं महिला उद्यमिता समर्थन

भारत सरकार ने महिला उद्यमिता को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएँ और नीतियाँ लागू की हैं जो इस क्षेत्र का सम्पूर्ण चश्मा बदल रही हैं।

मुद्रा योजना (MUDRA & Micro Units Development and Refinance Agency) इस दिशा में सबसे प्रयोगी पहल है। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक का ऋण बिना गिरवी के उपलब्ध कराया जाता है। 2015 से 2024 तक मुद्रा योजना के अंतर्गत वितरित कुल ऋण का 68 प्रतिशत महिलाओं को मिला है, जो लगभग 22 लाख करोड़ रुपये है। यह एक ऐतिहासिक नीतिगत परिवर्तन है।

‘स्टैंड अप इंडिया’ (Stand Up India) योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपये का ऋण मिलता है। राष्ट्रीय महिला विकास निगम (National Women Development Corporation) महिलाओं को उद्योग प्रशिक्षण, तकनीक सहायता और बाजार सम्पर्क प्रदान करता है। *Women Entrepreneurship Platform (WEP) NITIAayog की एक ऐसी पहल है जो महिला उद्यमियों को एक ही मंच पर समस्त संसाधन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने भी इस क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी भूमिका निभाई है। नीति में महिला-शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता कौशल को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाने की अनुशंसा की गई है। जब बालिकाएँ स्कूल से उचित कौशल शिक्षा लेकर निकलेंगी, तो वे न

केवल रोजगार ढूँढने वाली बल्कि रोजगार देने वाली बनेंगी। यह एक दृष्टिगत परिवर्तन है।

6. सफलता के प्रेरणादायक उदाहरण

भारतीय महिला उद्यमिता के क्षेत्र में अनेक ऐसे प्रेरणादायक नाम हैं जिनके संघर्ष, साहस और सफलता की गाथा न केवल महिलाओं को बल्कि सम्पूर्ण समाज को प्रेरणा देती है।

फालगुनी नय्यर ने 50 वर्ष की आयु में अपना ई-कॉमर्स स्टार्टअप शुरू किया और आज उनकी कम्पनी का बाजार मूल्य हज़ारों करोड़ रुपये है कृ वे भारत की सबसे सफल महिला उद्यमियों में सम्मिलित हैं। फालगुनी देवी (बिहार) ने एक छोटे-से गाँव में पानी के लिए संघर्ष करते हुए सैनिटरी नैपकिन का उद्योग स्थापित किया। आज वे हज़ारों महिलाओं को रोजगार दे रही हैं और ‘Padmas of India’ का खिताब प्राप्त कर चुकी हैं। काथा पाई-वर्वेरी (यूएई) एक आदिवासी महिला हैं जो हस्तनिर्मित गहना बनाकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना चुकी हैं।

राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो ‘सहेलिनियाँ’ और ‘स्वयं-सहायता समूहों’ (SHG) के माध्यम से हज़ारों महिलाओं ने अपने जीविकोपार्जन के नये मार्ग तलाशे हैं। जोधपुर, जयपुर और उदयपुर की महिला उद्यमियों ने हस्तशिल्प, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं। Amazon Karigar एवं स्थानीय हस्तशिल्प मेलों के माध्यम से इन महिलाओं ने न केवल अपनी बल्कि पूरी पीढ़ी की आजीविका बदलकर रख दी। ये उदाहरण सिद्ध करते हैं कि यदि अवसर और प्रशिक्षण मिला तो भारतीय नारी किसी से भी पीछे नहीं है।

7. चुनौतियाँ और बाधाएँ

जब हम महिला उद्यमिता की उज्ज्वल संभावनाओं की बात करते हैं, तो इस सत्य से भी मुँह नहीं मोड़ा जा सकता कि इस क्षेत्र में अनेक गम्भीर चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं जो महिलाओं के उद्यमी बन पाने की राह में रुकावट बन रही हैं।

सबसे बड़ी चुनौती है कृ सामाजिक एवं सांस्कृतिक बंधन (Social And Cultural Barriers)। भारतीय समाज का एक बड़ा तबका अभी भी महिलाओं को घर की चारदीवारी में बाँधकर रखने का आग्रही है। 'व्यवसाय करो' को अक्सर 'घर तोड़ो' से जोड़ दिया जाता है। महिला की आर्थिक स्वतंत्रता को कई बार परिवार के लिए खतरा समझ लिया जाता है, जबकि वास्तविक रूप में यह परिवार को सुदृढ़ करती है।

दूसरी बड़ी चुनौती है वित्त तक सीमित पहुँच (Limited Access to Finance)। गिरवी सम्पत्ति नहीं होती, साख इतिहास (Credit History) नहीं होता कृ ऐसे में बैंक ऋण लेना महिलाओं के लिए आज भी एक कठिन कार्य है। तीसरी चुनौती है डिजिटल साक्षरता का अभाव। ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाएँ आज भी स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग सीमित मौकों पर ही कर पाती हैं। चौथी चुनौती है बाज़ार, नेटवर्क और व्यवसाय सूचनाओं तक पहुँच का अभाव। बिचौलिये (Middlemen) आज भी बाज़ार पर काबिज हैं और महिला उद्यमियों का उचित लाभान्श हड़प लेते हैं।

8. सुझाव एवं आगे की राह

महिला उद्यमिता की संभावनाओं को साकार करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण एवं बहु-स्तरीय प्रयास अनिवार्य है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कृ शिक्षा में परिवर्तन। विद्यालय स्तर से ही बालिकाओं को उद्यमिता कौशल (Entrepreneurship Skills) सिखाना आवश्यक है। पाठ्यक्रम में व्यवसाय प्रबंधन, संवाद कौशल, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल कौशल को अनिवार्यतः शामिल किया जाना चाहिए।

दूसरे, वित्तीय समावेश (Financial Inclusion) को मजबूत करना होगा। मुद्रा योजना की पहुँच और सुविधाओं को और व्यापक बनाया जाये। स्वयं-सहायता समूहों (SHG) को बैंक से और अधिक जुड़ने में सहायता की जाये। महिला

उद्यमियों के लिए ऋण देने में बैंकों पर अतिरिक्त प्रोत्साहन सुनिश्चित किया जाये। डिजिटल पर्यावरण में महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएँ जहाँ वे E&Commerce, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ऑनलाइन व्यवसाय संचालन सीख सकें।

अन्ततः सामाजिक-सांस्कृतिक बंधनों को दूर करने के लिए जनजागृति अभियान आवश्यक है। परिवार और समाज को यह समझाना होगा कि महिला की आर्थिक स्वतंत्रता, परिवार के लिए खतरा नहीं— वरन् यह परिवार की शक्ति है। जब समाज की सोच बदलेगी, तो महिला उद्यमिता का मार्ग स्वयं ही प्रशस्त हो जाएगा।

9. निष्कर्ष

इस सम्पूर्ण विश्लेषण के आलोक में यह निष्कर्ष निकलता है कि महिला उद्यमिता आत्मनिर्भर भारत की न केवल आवश्यकता है, बल्कि यह इस राष्ट्रीय संकल्पना की आधारशिला है। जब हम आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न देखते हैं, तो उसके मूल में एक ऐसा भारत है जहाँ प्रत्येक नागरिक कृ स्त्री हो या पुरुष — अपने संसाधनों, कौशल और वातावरण के बल पर नये आयाम निर्मित करे।

भारतीय महिला की सृजनात्मकता, संघर्षशीलता और सामाजिक दायित्व का बोध उसे एक आदर्श उद्यमी बनाता है। जब एक महिला व्यवसाय करती है तो वह केवल पैसा नहीं कमाती कृ वह समुदाय का निर्माण करती है, अन्य महिलाओं को रोजगार देती है, अपने बच्चों के लिए एक प्रेरणा-शक्ति बन जाती है और समाज में एक नया अध्याय लिखती है। आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न तब साकार होगा जब देश की प्रत्येक महिला आत्मनिर्भर होगी। और यह तब होगा जब हम उन्हें उद्यमिता के अवसर, शिक्षा, वित्त और सम्मान देंगे।

अन्ततः यह कहना अनुचित न होगा कि कृ 'जो राष्ट्र अपने स्वप्नों में अपनी आधी आबादी को शामिल नहीं करता, वह राष्ट्र अपने स्वप्नों की पूर्ति भी नहीं कर सकता।' आत्मनिर्भर भारत की

परिकल्पना में महिला उद्यमिता केवल एक साधन नहीं, बल्कि यह स्वयं एक लक्ष्य है कृ एक दृष्टि है और एक अनिवार्यता है जिसे न तो नजरअंदाज किया जा सकता है और न ही जिसके बिना यह स्वप्न साकार हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भारत सरकार (2020) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. NITIAayog (2022)- Women Entrepreneurship Platform Annual Report 2021&22- Government of India] New Delhi-
3. McKinsey Global Institute (2018)- The Power of Parity% Advancing Women*s Equality inAsia Pacific- McKinsey & Company-
4. MUDRAAnnual Report 2023&24- Micro Units DevelopmentAnd RefinanceAgency] Ministry of Finance] Government of India-
5. NSSO (2022)- Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2021&22- National Statistical Office] Government of India-
6. UNIDO (2020)- Women Entrepreneurs in Developing Countries- United Nations Industrial Development Organization-
7. गुप्ता, सुमन (2021) भारत में महिला उद्यमिता: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ. राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
8. मिश्रा, रंजन कुमार (2020). आत्मनिर्भर भारत: सक्षमता एवं संभावना. साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
9. Stand Up India Scheme Report ¼2024½- Ministry of Finance] Government of India] New Delhi-
10. IFC (2022)- Women Entrepreneurs Finance Initiative (WE&FI) India Report- International Finance Corporation-

शिक्षकों के कौशल विकास का महत्व

भूपेंद्र सिंह गुर्जर

सहायक आचार्य, भूगोल

महात्मा गाँधी कॉलेज, महवा, दौसा, राजस्थान

सारांश

कौशल विकास का अर्थ है गतिशील बाजार की नई मांगों के अनुरूप नए कौशल विकसित करना या मौजूदा कौशलों को बढ़ाना, जिससे पेशेवर दक्षता का स्तर भी बढ़ता है। आज के गतिशील और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वैश्विक श्रम बाजार में कौशल विकास का महत्व बहुत अधिक है। अच्छा कौशल विकास व्यक्तियों को रोजगार योग्यता प्राप्त करने, करियर में उन्नति करने, नौकरी बनाए रखने और व्यक्तिगत विकास में लाभ पहुंचाता है। कंपनियों में कुशल कार्यबल नवाचार, उत्पादकता और प्रभावशीलता के आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए, लोगों और कंपनियों को नई तकनीकी, आर्थिक और अन्य औद्योगिक चुनौतियों के अनुकूल ढलकर प्रतिस्पर्धी बने रहना चाहिए।

कुशल शिक्षक नई शैक्षिक पद्धतियों और पहलों को लागू करने और उनका समर्थन करने में सक्षम होते हैं। व्यावसायिक विकास बेहतर शिक्षण

पद्धतियों को सुनिश्चित करता है, जिससे छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन और सफलता में सुधार होता है। संक्षेप में, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास (Professional Development) एक सतत प्रक्रिया है, जो एक सक्षम, आत्मविश्वासी और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने वाली शिक्षा व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। आज के निरंतर बदलते विश्व में, केवल अकादमिक उत्कृष्टता ही सफलता की गारंटी नहीं दे सकती। कौशल विकास वह सेतु है जो कक्षा में सीखी गई शिक्षा को वास्तविक दुनिया की उपलब्धियों से जोड़ता है। यह विद्यार्थियों को न केवल अंक प्राप्त करने के लिए, बल्कि जीवन में अपनी पहचान बनाने के लिए भी आवश्यक साधन प्रदान करता है।

मुख्य शब्द: कौशल विकास, शैक्षणिक प्रदर्शन, व्यावसायिक विकास, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षण-अधिगम

प्रस्तावना

शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाना महत्वपूर्ण है ताकि आधुनिक शिक्षा की उन्नत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो सके और इस सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल और ज्ञान से युक्त प्रशिक्षक छात्रों को प्रशिक्षित कर सकें। शिक्षकों को तकनीकी प्रगति के अनुरूप ढलना चाहिए और डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए ताकि उन्हें कक्षा में एकीकृत किया जा सके। आभासी शिक्षण वातावरण और शैक्षिक

प्रौद्योगिकी में दक्षता दूरस्थ और हाइब्रिड शिक्षण मॉडल के लिए मूलभूत है। परियोजना-आधारित शिक्षण, फ्लिप क्लासरूम और पूछताछ-आधारित शिक्षण जैसी नई शिक्षण पद्धतियों में प्रशिक्षित शिक्षक छात्रों की सहभागिता और परिणामों में सुधार कर सकते हैं, और छात्रों के अधिगम का अधिक प्रभावी ढंग से मूल्यांकन और समर्थन करने के लिए विविध मूल्यांकन रणनीतियों का ज्ञान होना चाहिए। समावेशी प्रथाओं पर केंद्रित व्यावसायिक विकास यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक विभिन्न अधिगम आवश्यकताओं और

पृष्ठभूमि वाले छात्रों का समर्थन कर सकें, क्योंकि व्यक्तिगत अधिगम के अभ्यास में प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण को अनुकूलित करना बहुत महत्वपूर्ण है।

कौशल विकास से शिक्षकों को पाठ्यक्रम मानकों और विषयवस्तु में होने वाले परिवर्तनों के साथ तालमेल बनाए रखने में मदद मिलती है। विशिष्ट विषयों का उन्नत अध्ययन गहन विषय ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है, जो सफल शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यह न केवल एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए, बल्कि शिक्षकों के स्वयं के करियर में उन्नति के लिए भी आवश्यक है। इससे कार्य-प्रगति के अवसर मिलते हैं, जिनमें नेतृत्व की भूमिकाएँ, विशेषज्ञ पद या प्रशासनिक कार्य शामिल हैं। निरंतर सीखने और विकास से कार्य संतुष्टि और प्रेरणा में वृद्धि होती है। कुशल शिक्षक नई शैक्षिक पद्धतियों और पहलों को लागू करने और उनका समर्थन करने में सक्षम होते हैं। व्यावसायिक विकास बेहतर शिक्षण पद्धतियों को सुनिश्चित करता है, जिससे छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन और सफलता में सुधार होता है।

शिक्षकों के कौशल विकास के लिए रणनीतियाँ

1. व्यावसायिक विकास कार्यक्रम

उच्च शिक्षा में व्यावसायिक विकास कार्यक्रम शिक्षकों को उनकी सर्वोत्तम क्षमता के अनुरूप प्रभावी शिक्षक बनने के लिए सहायता और अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथ ही उच्च शिक्षा समुदायों के भीतर उनके अनुसंधान और व्यावसायिक सफलता को बढ़ावा देते हैं। उच्च शिक्षा में व्यावसायिक विकास की प्रभावी रणनीतियों के लिए सहयोगात्मक नवाचार की आवश्यकता होती है, जिसका निरंतर मूल्यांकन किया जाता है, ताकि शिक्षकों को अपने शैक्षणिक करियर में सफल होने के लिए आवश्यक सहायता और संसाधन मिल सकें। इसके अलावा, *।।।।।, ब्बनतेमतं, न्कमउल आदि जैसे ऑनलाइन

प्लेटफॉर्म आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करते हैं, जिनके माध्यम से पाठ्यक्रमों में नामांकन किया जा सकता है।

2. सहयोगात्मक शिक्षण

शिक्षकों के बीच इस प्रकार का सहयोगात्मक शिक्षण पेशेवर विकास, शिक्षण प्रभावशीलता, अनुसंधान उत्पादकता और संस्थागत विकास के लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। संगठन को सहकर्मी अवलोकन, टीम शिक्षण और पेशेवर शिक्षण समुदायों के माध्यम से सहयोगात्मक शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए और ऐसे मार्गदर्शन कार्यक्रम लागू करने चाहिए जहाँ अनुभवी शिक्षक अपने सहयोगियों का मार्गदर्शन और समर्थन करें।

3. प्रमाणपत्र और उन्नत डिग्रियाँ

प्रमाणन और उच्चतर डिग्रियाँ संकाय सदस्यों के पेशेवर विकास और करियर की प्रगति के लिए सराहनीय निवेश हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें प्राप्त करने से उन्हें अपने कौशल को बढ़ाने और ज्ञान अर्जित करने में मदद मिलती है, साथ ही साथ उनका करियर समृद्ध होता है और वे विद्वत्ता और अकादमिक उत्कृष्टता में नेतृत्व प्रदान करते हैं। प्रमाणन और उच्चतर डिग्रियाँ प्राप्त करने के अन्य महत्वपूर्ण तरीके हैं सहायता प्रदान करना, लचीले कार्यक्रम बनाना, मार्गदर्शकों को मान्यता देना और समीक्षा करना। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संकाय विकास पद्धतियों को प्रभावी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनमें सुधार किया जाए।

4. व्यावहारिक अनुभव

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कक्षा में नए कौशल और तकनीकों का प्रयोग होना चाहिए और शिक्षण-अधिगम की प्रभावशीलता पर इसका प्रभाव दिखना चाहिए। इसलिए, शिक्षकों को नई शिक्षण रणनीतियों और तकनीकों का परीक्षण और उनमें महारत हासिल करने के लिए प्रायोगिक कार्यक्रमों में भाग लेना आवश्यक है। व्यावसायिक विकास के

लिए संस्थागत सहायता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्थानों को शिक्षकों को उनके व्यावसायिक विकास के अवसरों के लिए धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए। साथ ही, उन्हें शैक्षणिक वर्ष में व्यावसायिक विकास के लिए शिक्षकों को समय भी देना चाहिए। संसाधनों की अनुपलब्धता पूरी प्रक्रिया को बाधित कर सकती है, इसलिए नवीनतम शैक्षिक शोध, पुस्तकों और वेब-आधारित संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण प्राप्त हो और वे इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करना जानते हों। एनसीयू शिक्षकों और कर्मचारियों के व्यावसायिक कौशल विकास में सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और संसाधन प्रदान करता है।

सतत व्यावसायिक विकास से शिक्षकों के कौशल में वृद्धि होती है, जिससे वे बेहतर शिक्षण गुणवत्ता प्रदान कर सकें, तकनीकी प्रगति को अपना सकें और छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। सतत व्यावसायिक विकास में निवेश से शिक्षकों को अपने कौशल में सुधार करने और करियर में आगे बढ़ने में शिक्षकों में कौशल विकास (Teacher Skill Development) आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक अनिवार्य अंग है, जो न केवल शिक्षकों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। बदलते समय और तकनीक के साथ शिक्षकों का 'अपस्किल' (Upskill) होना आवश्यक है।

शिक्षकों में कौशल विकास के महत्व के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

शिक्षण प्रभावशीलता में वृद्धि: कौशल विकास कार्यक्रम शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण विधियों, तकनीकों और उपकरणों से परिचित कराते हैं, जिससे शिक्षण अधिक प्रभावी और रोचक बनता है।

छात्र परिणामों में सुधार: जब शिक्षक कुशल होते हैं, तो इसका सीधा असर छात्रों के प्रदर्शन पर पड़ता है। अध्ययन बताते हैं कि प्रशिक्षित शिक्षक

छात्रों की उपलब्धि में 21% तक की वृद्धि कर सकते हैं।

तकनीकी अनुकूलन (Digital Literacy): वर्तमान में डिजिटल कक्षाएं और ऑनलाइन उपकरण अनिवार्य हो गए हैं। कौशल विकास शिक्षकों को स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन टूल और नई तकनीक का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

बेहतर कक्षा प्रबंधन: नए कौशल के माध्यम से शिक्षक कक्षा के अनुशासन, छात्रों के व्यवहार और विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों को समझने में बेहतर होते हैं, जिससे एक सकारात्मक शिक्षण माहौल बनता है।

आत्मविश्वास और प्रेरणा: निरंतर सीखने से शिक्षकों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने पेशे के प्रति अधिक प्रेरित रहते हैं, जिससे नौकरी में संतुष्टि बढ़ती है।

समस्या-समाधान की क्षमता: कौशल विकास कार्यक्रम शिक्षकों को छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं, सीखने की कठिनाइयों और अनुशासनात्मक मुद्दों को रचनात्मक तरीके से हल करने की क्षमता प्रदान करते हैं।

21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयारी: आज के दौर में आलोचनात्मक सोच (Critical Thinking), रचनात्मकता, और सहयोग जैसे कौशल आवश्यक हैं। शिक्षक खुद इन कौशलों को सीखकर छात्रों में इनका विकास कर सकते हैं।

संक्षेप में, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास (Professional Development) एक सतत प्रक्रिया है, जो एक सक्षम, आत्मविश्वासी और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने वाली शिक्षा व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। शिक्षकों में कौशल विकास (Teacher Skill Development) आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो न केवल शिक्षकों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना

करने के लिए शिक्षकों का निरंतर सीखना और अपडेट रहना आवश्यक है।

विकास का महत्व निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं में समझा जा सकता है:

1. आधुनिक शिक्षण विधियों का ज्ञान

नवीनतम तकनीक: कौशल विकास शिक्षकों को डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन टीचिंग और नए शैक्षिक तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

पाठ्यक्रम में बदलाव: यह शिक्षकों को बदलती राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और पाठ्यक्रम के अनुसार खुद को ढालने में मदद करता है।

2. प्रभावी कक्षा प्रबंधन और सहभागिता

बेहतर कक्षा प्रबंधन: कुशल शिक्षक कक्षा में सकारात्मक, अनुशासित और सम्मानजनक माहौल बनाए रखने में सक्षम होते हैं।

छात्र जुड़ाव (Student Engagement): कौशल विकास शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक गतिविधियों और संवादात्मक विधियों का उपयोग करने में मदद करता है, जिससे छात्र सक्रिय रूप से सीखते हैं।

3. छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक

21वीं सदी के कौशल: शिक्षक जब खुद स्किल्ड होते हैं, तो वे छात्रों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच (Critical Thinking), समस्या-समाधान, सहयोग और संवाद जैसे कौशल विकसित कर सकते हैं।

व्यक्तिगत ध्यान: कौशल विकास शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण शैलियों (Learning Styles) वाले छात्रों की जरूरतों को समझने में मदद करता है, जिससे हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है।

3. पेशेवर विकास और आत्मविश्वास

आत्म-प्रतिबिंब (Self&Reflection): शिक्षक अपनी शिक्षण शैली की कमजोरियों को पहचानकर उनमें सुधार कर सकते हैं।

आत्मविश्वास में वृद्धि: नियमित प्रशिक्षण से शिक्षकों का आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वे चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं।

4. शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को आसान बनाना

शिक्षण कौशल: इसमें संचार, पाठ योजना (Lesson Planning), और मूल्यांकन के उन्नत तरीके शामिल हैं, जो सीखने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाते हैं।

भावात्मक समझ: शिक्षक छात्रों के भावनाओं और उनके सीखने की गति के अनुरूप पाठ्य सामग्री को तैयार कर सकते हैं।

सिर्फ अंकों से कहीं ज्यादा: कौशल क्यों मायने रखते हैं

आज की तेज़ रफ़्तार और प्रतिस्पर्धी दुनिया में, केवल अकादमिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिस्थितियों के अनुरूप ढलें, समस्याओं का समाधान करें, प्रभावी ढंग से संवाद करें और पहल करें। यहीं पर कौशल विकास की भूमिका आती है।

कौशल विकास से तात्पर्य उन क्षमताओं को सीखने, अभ्यास करने और उनमें महारत हासिल करने की प्रक्रिया से है जो पाठ्यपुस्तकों से परे हैं। इनमें हार्ड स्किल्स (जैसे डिजिटल साक्षरता, वित्तीय प्रबंधन या कोडिंग) और सॉफ्ट स्किल्स (जैसे टीमवर्क, समय प्रबंधन और संचार) दोनों शामिल हैं।

इन कौशलों को विकसित करने से छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है और साथ ही उन्हें दीर्घकालिक करियर सफलता के लिए तैयार किया जा सकता है।

छात्रों के लिए कौशल विकास क्यों महत्वपूर्ण है?

1. शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाता है

जब छात्र समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण और आलोचनात्मक सोच जैसे कौशल हासिल कर लेते हैं, तो वे बेहतर तरीके से पढ़ाई करना सीख जाते हैं। इन क्षमताओं से जटिल अवधारणाओं को

समझना, असाइनमेंट समय पर पूरा करना और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, कार्यों को प्राथमिकता देना सीखने से परीक्षा का तनाव कम हो सकता है और परिणाम बेहतर हो सकते हैं।

2. संचार और सहयोग में सुधार करता है

समूह चर्चाओं, परियोजनाओं और प्रस्तुतियों के लिए प्रभावी संचार और सहयोग आवश्यक है। इन क्षेत्रों में कौशल विकास से यह सुनिश्चित होता है कि छात्र अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकें, ध्यानपूर्वक सुन सकें और टीम में अच्छा काम कर सकें। ये अनुभव न केवल स्कूल में बल्कि आगे चलकर पेशेवर परिवेश में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3. आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करता है

चाहे सार्वजनिक भाषण देना हो, कार्यक्रमों का आयोजन करना हो या किसी समूह परियोजना में नेतृत्व करना हो, कौशल विकास गतिविधियाँ आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। छात्र जिम्मेदारी लेना, समस्याओं को हल करना और निर्णय लेना सीखते हैंकृये ऐसे गुण हैं जो हर नेता में होने चाहिए।

4. रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है

शैक्षणिक सफलता केवल तथ्यों को रटने तक सीमित नहीं हैकृयह ज्ञान का विश्लेषण करने, उसे समझने और लागू करने के बारे में है। जब छात्रों को रचनात्मक सोच या वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने वाली गतिविधियों में शामिल किया जाता है, तो उनके आलोचनात्मक सोच कौशल में सुधार होता है। इससे उन्हें शैक्षणिक चुनौतियों का सामना अधिक स्पष्टता और नवीनता के साथ करने में मदद मिलती है।

कौशल विकास और कैरियर की तैयारी

विद्यालय में कौशल विकसित करना पेशेवर सफलता की नींव रखता है। आज भर्तीकर्ता और

नियोक्ता ऐसे स्नातकों की तलाश करते हैं जो न केवल अकादमिक रूप से सक्षम हों बल्कि कार्यस्थल के लिए भी तैयार हों।

अनुकूलनशीलता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और टीम वर्क जैसे सॉफ्ट स्किल्स को अक्सर तकनीकी विशेषज्ञता से ऊपर स्थान दिया जाता है।

कंप्यूटर साक्षरता, डेटा विश्लेषण और परियोजना प्रबंधन में कौशल छात्रों को भविष्य की नौकरी की भूमिकाओं के लिए तैयार करते हैं।

बैंगलोर के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों की तरह, जो कॉलेज समग्र विकास पर जोर देते हैं, वे छात्रों को वास्तविक दुनिया के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए अपने पाठ्यक्रम में अकादमिक शिक्षा और कौशल निर्माण दोनों को एकीकृत करते हैं।

कौशल विकास को बढ़ावा देने में कॉलेजों की भूमिका

छात्रों के कौशल विकास में संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इंटरनशिप, कार्यशालाओं, मार्गदर्शन कार्यक्रमों, छात्र क्लबों और कौशल प्रयोगशालाओं के माध्यम से छात्र उन प्रतिभाओं को खोज और निखार सकते हैं जो पारंपरिक कक्षाओं में नहीं सिखाई जाती हैं।

बैंगलोर के कुछ शीर्ष कॉलेजों में, सर्वांगीण प्रतिभाओं को निखारने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है – ऐसे छात्र जो पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करते हैं और अपने कौशल के व्यावहारिक अनुप्रयोग के माध्यम से करियर की क्षमता दिखाते हैं।

कौशल विकास व्यक्तिगत विकास में कैसे सहायक होता है?

भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है

भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईक्यू) छात्रों को अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने, पारस्परिक संबंधों को बुद्धिमानी से निभाने और चुनौतियों का शांत भाव से सामना करने में सक्षम बनाती है। सहानुभूति और लचीलापन जैसे कौशल

छात्रों को बेहतर संबंध बनाने और शैक्षणिक तनाव से निपटने में मदद करते हैं।

विकास की मानसिकता को बढ़ावा देता है

कौशल विकास से विकासोन्मुखी मानसिकता विकसित होती है। यह विश्वास कि बुद्धि और क्षमता को प्रयास से विकसित किया जा सकता है। यह मानसिकता छात्रों को चुनौतियों का सामना करने, असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने और निरंतर सुधार की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

आत्म-अनुशासन को बढ़ावा देता है

समय प्रबंधन और लक्ष्य निर्धारण जैसे कौशल सीखने से छात्र अधिक व्यवस्थित और अनुशासित बनते हैं। वे अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी स्वयं लेने लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में दीर्घकालिक सफलता प्राप्त होती है।

बारहवीं के बाद कौशल विकास: आगे की योजना बनाना

12वीं के बाद सही कोर्स चुनना अक्सर छात्रों द्वारा लिया जाने वाला पहला महत्वपूर्ण निर्णय होता है। कौशल-आधारित करियर योजना यह सुनिश्चित करती है कि छात्र अपनी शैक्षणिक यात्रा को अपनी क्षमताओं और भविष्य के लक्ष्यों के अनुरूप बनाएं। चाहे वह वाणिज्य हो, विज्ञान हो या कला, 12वीं के बाद वाणिज्य और अन्य स्ट्रीम में कई ऐसे कोर्स उपलब्ध हैं जो व्यावहारिक कौशल और रोजगार क्षमता पर केंद्रित हैं।

छात्रों के कौशल विकास के लिए सुझाव

1. पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लें: नेतृत्व और संचार कौशल को बढ़ाने के लिए क्लबों, खेलों या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हों।
2. ऑनलाइन पाठ्यक्रम लें: कौरसेरा, लिक्डइन लर्निंग या यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों में मूल्यवान प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

3. सार्वजनिक भाषण का अभ्यास करें: आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वाद-विवाद, स्कूल सभाओं या ओपन माइक कार्यक्रमों में भाग लें।
4. स्वयंसेवक या प्रशिक्षु: वास्तविक दुनिया का अनुभव सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक है।
5. आत्मचिंतन करें और लक्ष्य निर्धारित करें: आत्म-मूल्यांकन के लिए समय निकालें और व्यक्तिगत सुधार के लिए कार्य योजना बनाएं।

निष्कर्ष

आज के निरंतर बदलते विश्व में, केवल अकादमिक उत्कृष्टता ही सफलता की गारंटी नहीं दे सकती। कौशल विकास वह सेतु है जो कक्षा में सीखी गई शिक्षा को वास्तविक दुनिया की उपलब्धियों से जोड़ता है। यह विद्यार्थियों को न केवल अंक प्राप्त करने के लिए, बल्कि जीवन में अपनी पहचान बनाने के लिए भी आवश्यक साधन प्रदान करता है।

इसलिए, चाहे आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, नौकरी के साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हों, या बस आगे बढ़ना चाहते हों, याद रखें: आज आप जो भी नया कौशल सीखते हैं, वह आपको उज्ज्वल भविष्य के एक कदम और करीब ले जाता है।

शिक्षकों का कौशल विकास सिर्फ एक व्यावसायिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करने वाला एक महत्वपूर्ण निवेश है। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक न केवल ज्ञान प्रदान करें, बल्कि छात्रों को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार भी करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल, जे. सी. (2019) शिक्षण के सिद्धांत, विधियाँ और तकनीकें। विकास प्रकाशन।
2. एनसीईई आरटीओ। (2020) प्रारंभिक स्तर पर सीखने के परिणाम। नई: दिल्ली एनसीईआई आरटीओ।

3. एन.सी.टी.ई. (2018) शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम। नई दिल्ली
4. शर्मा, आर. ए. (2021) गणित शिक्षा और शिक्षाशास्त्र। आर. लाल किताब।
5. अवलोकन। (2021) संख्यात्मकता और कौशल कौशल को बढ़ावा देने में सहायक भूमिका।
6. यादव, एस. (2020) गणित शिक्षण में वैज्ञानिकता का उपयोग: एक व्यावहारिक दृष्टिकोण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, 8(4), 65–72।
7. वर्मा, ए. (2022) गणित का भय और संविधान की भूमिका। एजुकेशन इंडिया जर्नल, 11(1), 33–47।
8. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2020) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।
9. सिंह, पी. (2019) गणित शिक्षण में नवीन अभ्यास। स्कूलर्ली एजुकेशन रिव्यू, 15(2), 89–105।
10. जैन, आर. (2021) गतिविधि—आधारित शिक्षण के माध्यम से छात्र अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ पेडागोगिकल स्टडीज़, 9(3), 57–68।

शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रभाव

डॉ. मीरा कुमारी धाकड़

सहायक आचार्य

महात्मा गाँधी टी.टी., कॉलेज, महवा, दौसा, राजस्थान

सारांश

यह शोधपत्र हमारे समाज में शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रभाव का समकालीन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। विशेषज्ञों से इन क्षेत्रों के विशिष्ट पहलुओं पर प्रौद्योगिकी के वर्तमान और संभावित प्रभाव, कार्यस्थल पर छात्रों की आवश्यकताओं और कौशलों, और इस प्रभाव के परिणामस्वरूप स्कूलों में होने वाले अपेक्षित परिवर्तनों के संबंध में डेटा का अनुरोध किया गया है। यह अध्ययन आधुनिक प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है, जिसमें नई इलेक्ट्रॉनिक, कम्प्यूटरीकृत, सूचनात्मक, डिजिटल या माइक्रोप्रोसेसर-आधारित प्रौद्योगिकी शामिल है। इस प्रकार की नई प्रौद्योगिकी में कम्प्यूटर-नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, सेवाएं और संरचित

सूचना प्रणाली) शामिल है, जिसमें कार्यालय स्वचालन प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। शिक्षक शिक्षा में माइक्रो कम्प्यूटर और माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स विषय ने हाल ही में साहित्य में और शैक्षिक समुदाय में पाठ्यक्रमों और कार्यशालाओं के शीर्षकों के रूप में लोकप्रियता हासिल की है। यह भाष्य पत्र प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण के क्षेत्र में, मौजूदा शिक्षकों को नई तकनीक में प्रशिक्षित करने वाले कार्यक्रमों पर बल देता है। यह पद्धति उपकरण प्रौद्योगिकी में बदलाव से उत्पन्न चुनौतियों के समाधान खोजने में भागीदारी सुनिश्चित करती है।

मुख्य शब्द — शिक्षा, रोजगार, कौशल, प्रौद्योगिकी, शैक्षिक प्रशिक्षण, तकनीकी प्रगति

प्रस्तावना—

शिक्षा का क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र है जहां निरंतर विकसित भौक्षिक तकनीकी ने शिक्षा को प्रौद्योगिकी के रूप में विकसित किया है, और इसी के अनुरूप शिक्षक के द्वारा कक्षा में उपयोग की जाने वाली तकनीक भी विकसित हुई है। वर्तमान में आधुनिक तकनीक ने पूरी दुनिया को जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। आजकल, छात्र आसानी से पाठ्यक्रम, असाइनमेंट, नोट्स और ईमेल में महत्वपूर्ण सूचनाओं जैसी शैक्षिक सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। वे शोध पत्रिकाओं, पुस्तकों और शैक्षिक वेबसाइटों तक भी पहुंच सकते हैं, जहां वे कक्षा की सीमाओं से परे अपनी शिक्षा का विस्तार कर सकते हैं।

आज की पीढ़ी के छात्रों को डिजिटल नेटिव कहा जाता है क्योंकि वे डिजिटल तकनीक के युग में पैदा हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के कार्यान्वयन ने विभिन्न ई-लर्निंग विधियों को पेश करके शिक्षण और अधिगम के वातावरण को बदल दिया है, जो किसी भी समय और किसी भी स्थान पर सभी के लिए सुलभ हैं। यह छात्रों के ज्ञान, उच्च-स्तरीय सोच और शैक्षणिक उपलब्धि को बेहतर बनाने में मदद करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इससे विद्यार्थियों को अधिक सीखने और अपनी रुचि के विषयों के बारे में बेहतर संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। लोग हजारों वर्षों से अपनी शिक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का

उपयोग करते आ रहे हैं। सदियों से, विभिन्न युगों ने अपनी प्रौद्योगिकी के माध्यम से नए-नए आविष्कार किए हैं। शिक्षा में प्रौद्योगिकी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ऐतिहासिक संदर्भ

अर्थव्यवस्था, जनसांख्यिकी और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन शिक्षा और श्रम बाजार संस्थानों को बदल सकते हैं। 1979 से, हमने श्रम बाजार में कौशल के प्रावधान और उनके उपयोग के लिए तीव्र परिवर्तन के निहितार्थों को समझने में तीन प्रकार की प्रगति की है। पहली प्रगति साक्ष्य की सरल पहचान है। श्रम बाजार के कई संस्थान, विशेष रूप से स्कूल और उच्च वेतन वाली नौकरियां, कौशल की बदलती मांग के अनुरूप आसानी से समायोजित नहीं हो पाए हैं। सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा प्रणाली का विकास और शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों का हमारा आधुनिक स्तरीकरण आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसी दुनिया की कल्पना करना कठिन है जिसमें किसी को भी प्राथमिक शिक्षा से अधिक शिक्षा न मिले, क्योंकि यह व्यवस्था बहुत कम समय में ही साकार हो जाती है। हमारे पास माध्यमिक, उच्चतर और स्नातकोत्तर शिक्षा का पूरे जनसमूह के लिए तेजी से विस्तार करने का कोई अनुभव नहीं है, ताकि यह तकनीकी रूप से उन्नत आधुनिक अर्थव्यवस्था के कड़े मानकों को पूरा कर सके।

प्रमुख तकनीकी प्रगति

रोजगार संबंधी प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों पर असर डालने वाली प्रमुख तकनीकी प्रगति अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्रों में हो रही है—इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और पर्यावरण संरक्षण। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी श्रम बाजार के सभी क्षेत्रों को बदल रही है, जिससे श्रमिकों को नए तकनीकी कौशल हासिल करने और उन्हें बनाए रखने की आवश्यकता है। विनिर्माण क्षेत्र में, कंप्यूटर-एडेड डिजाइन/कंप्यूटर-एडेड मैनुफैक्चरिंग (CAD/CAM) क्षमताओं वाली

संख्यात्मक रूप से नियंत्रित मशीनों से युक्त “एकीकृत” उत्पादन प्रणालियाँ शुरू की जा रही हैं। वास्तविक समय प्रक्रिया नियंत्रण तकनीकों के बढ़ते उपयोग के लिए बेहतर शिक्षित और प्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता है। खुदरा और सेवा क्षेत्र में, बार कोड स्कैनर सिस्टम, डेबिट/क्रेडिट प्राधिकरण प्रणाली, स्वचालित टेलर मशीनें और कम्प्यूटरीकृत इन्वेंटरी नियंत्रण और लेखा प्रणाली के लिए नौकरी कौशल स्तर में वृद्धि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, दुनिया “सूचना समाज” की ओर बढ़ रही है, जिसका शिक्षा प्रणाली पर नाटकीय प्रभाव पड़ने की संभावना है।

शिक्षा में तकनीकी उपकरण और संसाधन

आधुनिक तकनीक में शिक्षा प्रणाली के भीतर अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने की अपार क्षमता है। नई तकनीक का सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है। हमें यह देखना होगा कि तकनीकी उपकरणों का उपयोग अधिगम में सहायक के रूप में कैसे किया जा सकता है, न कि शिक्षकों या अधिगम प्रक्रियाओं के विकल्प के रूप में। कंप्यूटर कक्षा शिक्षण के पूरक के रूप में अधिगम को बेहतर बनाने की क्षमता रखते हैं। डिजिटल पुस्तकालय, सीडी और इंटरनेट छात्रों को संसाधनों का एक विशाल डेटाबेस प्रदान कर सकते हैं, जो किसी भी विशेष विषय पर समृद्ध ज्ञान और संदर्भ बिंदु प्रदान करते हैं।

इससे छात्र अनुक्रमणिका खोज, सारांश मुद्रण या रुचि के दस्तावेजों की व्यक्तिगत प्रतियां सुरक्षित करने जैसे कार्य कर सकते हैं। उन्नत तकनीक के साथ, अगला कदम पारंपरिक मुद्रित माध्यमों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में रूपांतरण है। विद्यालय छात्रों को सूचना सुपरहाइवे पर उपलब्ध जानकारी और संसाधनों का उपयोग करना सिखा सकते हैं। टेलीविजन, वीडियो, सीडी-रोम और इंटरनेट जैसी मल्टीमीडिया सुविधाएं उन घरों और विद्यालयों तक जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा

सकती हैं जहां प्रशिक्षित कर्मचारी और कंप्यूटर सिस्टम की कमी है। विशेष रूप से, इंटरनेट छात्रों को बिना किसी समय सीमा के, बहुत कम लागत पर विशाल मात्रा में मल्टीमीडिया जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है। इंटरनेट तकनीक का उपयोग करना अब पहले से कहीं अधिक आसान और सस्ता होता जा रहा है। शिक्षक वेबसाइटों का उपयोग करके ऐसे पाठ्यक्रम प्रोजेक्ट भी तैयार कर सकते हैं जिनमें कई विकल्प हों और जो समस्या-समाधान और उच्च-स्तरीय सोच कौशल को चुनौती दे सकें।

ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म

इंटरनेट पर ऐसे कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो विभिन्न विषयों और व्यवसायों से संबंधित कई तरह के कोर्स उपलब्ध कराते हैं। इनमें से कुछ कोर्स मुफ्त हैं, जबकि कुछ के लिए भुगतान करना पड़ता है। इन कोर्सों की अवधि और मिलने वाले सर्टिफिकेट अलग-अलग होते हैं। इंटरनेट की सुविधा होने पर छात्र इन प्लेटफॉर्म से आसानी से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। हम इंटरनेट की सुविधा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं और कोर्स की सामग्री समझने में आसान है। छात्र अपनी प्रगति पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा, छात्र अपनी सुविधानुसार इन प्रोग्रामों को पूरा कर सकते हैं, यानी वे कोर्स के साथ-साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। मुख्य रूप से, ये प्लेटफॉर्म उन नौकरीपेशा लोगों के लिए उपयोगी हैं जो अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से सीखने वाले समुदाय बने हैं और इन समूहों में समान रुचियां होती हैं। वे किसी विशेष कोर्स पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। ये चर्चाएं बोलकर या लिखकर की जा सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के छात्रों को पढ़ाने की सुविधा देते हैं और छात्रों को संगठन द्वारा नियुक्त स्थानीय शिक्षकों से सीखने का अवसर भी मिलता

है। वर्चुअल संचार संभव है और छात्र शिक्षकों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर सकते हैं।

इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड

इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड को स्मार्ट बोर्ड भी कहा जाता है। इनका उपयोग आजकल शिक्षण संस्थानों में व्यापक रूप से किया जाता है। अधिकांश शिक्षण संस्थान पारंपरिक ब्लैकबोर्ड की जगह इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड को प्राथमिकता देते हैं। इस व्हाइटबोर्ड से एक प्रोजेक्टर जोड़ा जाता है। प्रोजेक्टर की डिजिटल तकनीक की मदद से कंप्यूटर की छवियों या सामग्री को व्हाइटबोर्ड पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इससे शिक्षक का कार्यभार कम हो जाता है। इस व्हाइटबोर्ड की विशेषता यह है कि शिक्षक व्हाइटबोर्ड पर सामग्री दिखाते समय बोल भी सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर साझा की गई सामग्री से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को सहेज कर छात्रों को वितरित किया जा सकता है। इससे छात्रों की सीखने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। इसके अलावा, शिक्षक और छात्र दोनों ही इस स्मार्ट बोर्ड पर सक्रिय रूप से बातचीत कर सकते हैं।

दूसरे शब्दों में, यह एक दृश्य प्रस्तुति और विश्लेषणात्मक उपकरण है, जहां सामग्री को एनिमेटेड और साथ ही हाइलाइट किया जा सकता है और इंटरैक्टिव प्रस्तुतियां बनाई जा सकती हैं। इस व्हाइटबोर्ड का कार्य सिद्धांत यह है कि प्रोजेक्टर कंप्यूटर पर प्रदर्शित छवि को प्रोजेक्ट करता है और कंप्यूटर से छवि को हाथ से नियंत्रित किया जा सकता है। इससे छात्रों की विषयवस्तु के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। साथ ही, इसका सरल संचालन उपयोगकर्ताओं के लिए एक अतिरिक्त लाभ है। इसलिए, जब छात्र इस स्मार्ट बोर्ड की सहायता से विषयवस्तु सीखते हुए अध्ययन करेंगे, तो उनके कौशल का विकास होगा। इस स्मार्ट बोर्ड के अनेक लाभ हैं। इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड शिक्षकों का समय और मेहनत बचाते हैं, जिससे वे सुव्यवस्थित पाठ तैयार

कर पाते हैं। शिक्षक अपने काम को ग्राफिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। विषयवस्तु और टॉपिक के दृश्य निरूपण से छात्रों की जिज्ञासा बढ़ती है। इससे वे अवधारणाओं को सीखते समय अधिक रचनात्मक बनते हैं।

विश्वास और उद्यमशीलता हमारे नागरिक विकास का मार्गदर्शन कर सकते हैं। वह हमें दिखाते हैं कि कैसे पड़ोसियों से साझा करने से स्थानीय चरों के केंद्रीय अक्ष मजबूत होंगे और अविश्वास हमें मित्रता की कुंद कुल्हाड़ी फेंकने से पहले सोचने का समय देगा, जो समाज के वृक्ष-तना संघ को तोड़ सकती है। अविश्वास का खतरा एक चेतावनी है जो हमें जगाएगी, समय पर नियंत्रण और समाज को एक स्मार्ट, अपरिहार्य रूप में बचाने के लिए चिंतन के बीच एक खेल। बॉट्समैन का सुझाव है कि विश्वास हमारे भीतर सर्वश्रेष्ठ को सामने लाता है क्योंकि उद्यमियों का इसे संरक्षित करने में बहुत बड़ा हित होता है। इसके अतिरिक्त, विश्वास के लिए वैश्विक नैतिक तर्क जो इन वर्तमान उदाहरणों को बनाना चाहिए, ट्रांसह्यूमनिज्म के विकास में एक पारलौकिक कथन है।

राजनीति के संदर्भ में, बॉट्समैन की उत्तर-मानव नैतिकता प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से मानव कल्याण को बढ़ाने को संदर्भित करती है। एक ऐसे भविष्य के समाज के उनके संदर्भ के साथ जिसमें आर्थिक विकास और लाभप्रदता के बजाय व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है, प्राथमिकताएं क्या हैं, इस बारे में बॉट्समैन अमर्त्य सेन से सहमत हैं, जिन्होंने निर्णय लेने का अवसर प्राप्त करने के लिए आवश्यक सिद्धांतों और संस्थानों पर चर्चा की।

निष्कर्ष –

निष्कर्षतः, सूचना युग ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार के लिए नए और व्यापक अवसर खोल दिए हैं। जिस प्रकार आधुनिक

बाजारों के बढ़ते वैश्वीकरण के कारण कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच वेतन असमानता बढ़ी है, उसी प्रकार यदि हम सावधानी न बरतें, तो शैक्षिक बाजारों का वैश्वीकरण राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर और बाहर शैक्षिक असमानता को और बढ़ा सकता है।

नई प्रौद्योगिकियां रोमांचक संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं, साथ ही तेजी से बदलते प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, तेजी से जुड़ते हुए विश्व में सरकार की उचित भूमिका के बारे में विचारणीय प्रश्न भी उठाती हैं। सुधार और तकनीकी क्रांति की इस प्रक्रिया में, अंतिम लक्ष्य विभिन्न देशों में उत्पाद की गुणवत्ता, समानता और समरूपता में दक्षता बढ़ाना होना चाहिए। यह लक्ष्य प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए हमारे सर्वोत्तम प्रयासों की आवश्यकता है। निश्चित रूप से, इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच सूचना साझाकरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि आवश्यक होगी। शैक्षिक सुधार एक कठिन प्रक्रिया है, और एक ही समाधान सभी के लिए उपयुक्त नहीं है, जैसा कि विभिन्न देशों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से स्पष्ट होता है, जो नए मॉडल में संक्रमण के विभिन्न चरणों को निर्धारित करेगी। शैक्षिक सुधार के लिए बदलाव आवश्यक है, और कई लोग यथास्थिति को बदलने के लिए अत्यधिक अनिच्छुक होते हैं। शैक्षिक सुधारों में अक्सर एक बहुत पुरानी और गहरी जड़ें जमा चुकी संस्थागत संरचना को संशोधित करना भी अनिवार्य हो जाता है, जिससे अन्य क्षेत्रों की तुलना में तीव्र और साहसिक परिवर्तन संभव नहीं हो पाते। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि प्रमुख योजना एक असफल सुधार का उत्कृष्ट उदाहरण थी।

यह एक ऐसा उदाहरण था जहां खराब डिजाइन ने कई कारकों के संयोजन को बढ़ावा दिया,

जिसके परिणामस्वरूप व्यापक समर्थन में कमी आई, और यह दर्शाता है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों और छात्रों में उत्पन्न निराशा और चिंता की तुलना में वादे किए गए लाभ कितने खोखले थे। एक समतल विश्व को सभी के लिए शैक्षिक

अवसरों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, साथ ही डिजिटल विभाजन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में भी मदद कर सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- मुस्तफा ए. अब्दुल रहमान एम. 21 वीं सदी के कार्यबल में प्रभावी शिक्षण और सीखने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षकों द्वारा आवश्यक रोजगार योग्यता। 2015
- आईसीटी। परिभाषा एवं शब्दावली समिति। 2008।
- मुस्तफा ए. व्यावसायिक और रोजगार योग्यता योग्यताएं। 2015.
- ओवरटूम। 21 वीं सदी के कार्यस्थल में रोजगार कौशल। 2000।
- मैसीज डुजिन्स्की। रोजगारयोग्यता कौशलरूप परिभाषा और उदाहरणों की सूची। 2022।
- कार्नेवाले। रोजगार और करियर में सफलता। Aeseuation-com/blog/whatare21stcentury skillsA 1990A
- लौअर एस.आर., योदानिस सी.एल. अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सर्वेक्षण कार्यक्रम (आईएसएसपी)रूप अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ शिक्षण का एक उपकरण। 2012।
- केनी ब्रायन। इसे एक साथ लानारूप निश्चित रूप से, सहयोग अच्छा है, लेकिन हमें डेटा की आवश्यकता है – और हमें इसकी अभी आवश्यकता है। स्कूल लाइब्रेरी जर्नल। 2007,(53)7:9(1)।
- ट्रिलिंग वार्ड, फदेल ई. 21 वीं सदी का ज्ञान और कौशल बार। 2012।
- रॉबर्ट एआर, जॉन वीडो। अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी में रुझान और मुद्दे। 2012।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं रोजगार सृजन : एक समग्र अध्ययन

रोहित

सहायक आचार्य, रसायन विज्ञान

महात्मा गाँधी कॉलेज, महवा, दौसा, राजस्थान

सारांश

शैक्षिक प्रौद्योगिकी ने सीखने और कमाने के बीच की दूरी को काफी हद तक खत्म कर दिया है। पहले शिक्षा का मतलब केवल डिग्री हासिल करना था, लेकिन अब यह सीधे रोजगार और कौशल से जुड़ चुकी प्रक्रिया बन गई है।

आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल टूल्स और वर्चुअल क्लासरूम ने शिक्षा को सीमाओं से मुक्त कर दिया है। इससे न केवल छात्रों को नई-नई स्किल्स सीखने का मौका मिला है, बल्कि शिक्षकों, कंटेंट क्रिएटर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए भी रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। एक व्यक्ति अब घर बैठे ऑनलाइन ट्यूटर, कोर्स डिजाइनर, ऐप डेवलपर या फ्रीलांसर बन सकता है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लोकल टैलेंट को ग्लोबल मार्केट से जोड़ती है। छोटे शहरों और गांवों के लोग भी अब डिजिटल माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर सकते हैं। इससे आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलता है।

संक्षेप में, Educational Technology केवल पढ़ाई का साधन नहीं रही, बल्कि यह एक ऐसा मंच बन गई है जो ज्ञान को सीधे रोजगार में बदलने की क्षमता रखता है यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।

मुख्य शब्द – तकनीक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्व-अध्ययन, मूल्यांकन तकनीक।

1. प्रस्तावना

21वीं सदी में शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि यह आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का प्रमुख साधन बन चुकी है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी (Educational Technology) ने सीखने की प्रक्रिया को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाते हुए नए प्रकार के रोजगार अवसरों का निर्माण किया है। यह शिक्षा और अर्थव्यवस्था के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करती है।

2. शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अर्थ

शैक्षिक प्रौद्योगिकी का आशय उन तकनीकी साधनों, विधियों और प्रक्रियाओं से है जिनका उपयोग शिक्षा को अधिक प्रभावी, रोचक और परिणामोन्मुख बनाने के लिए किया जाता है।

मुख्य तत्व

हार्डवेयर (जैसे कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड)

सॉफ्टवेयर (ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऐप्स)

शिक्षण विधियाँ (Digital pedagogy)

मूल्यांकन तकनीक

3. शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उद्देश्य

शिक्षा को सुलभ और समावेशी बनाना

सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना

स्व-अध्ययन (Self&learning) को बढ़ावा देना

कौशल आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करना

रोजगार उन्मुख शिक्षा विकसित करना

4. शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रकार

(i) पारंपरिक तकनीक

रेडियो, टेलीविजन

ऑडियो-वीडियो सामग्री

(ii) आधुनिक डिजिटल तकनीक

ऑनलाइन शिक्षा (E&learning)

मोबाइल लर्निंग (M&learning)

वर्चुअल क्लासरूम

(iii) उन्नत तकनीक

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)

वर्चुअल रियलिटी (VR)

लर्निंग एनालिटिक्स

5. रोजगार सृजन में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की भूमिका

शैक्षिक प्रौद्योगिकी केवल शिक्षा का माध्यम नहीं है, बल्कि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करती है।

(i) प्रत्यक्ष रोजगार अवसर

ऑनलाइन शिक्षक (Online Tutor)

कंटेंट डेवलपर (Content Creator)

इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर

ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म मैनेजर

(ii) अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर

तकनीकी सहायता (IT Support)

डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ

वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स डिजाइन

डेटा विश्लेषण

6. कौशल आधारित रोजगार के नए क्षेत्र

1. डिजिटल शिक्षा उद्योग

ऑनलाइन कोर्स निर्माण

यूट्यूब/ई-लर्निंग चैनल

फ्रीलांस टीचिंग

2. तकनीकी कौशल क्षेत्र

प्रोग्रामिंग

वेब डेवलपमेंट

ऐप डेवलपमेंट

3. रचनात्मक क्षेत्र

एनीमेशन

मल्टीमीडिया डिजाइन

शैक्षिक वीडियो निर्माण

4. उद्यमिता (Entrepreneurship)

स्वयं का ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म

स्टार्टअप शुरू करना

डिजिटल कोचिंग

5. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रभाव

ग्रामीण क्षेत्र

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अवसर

डिजिटल साक्षरता में वृद्धि

स्थानीय रोजगार के अवसर

शहरी क्षेत्र

उच्च तकनीकी नौकरियाँ

स्टार्टअप संस्कृति

वैश्विक स्तर पर कार्य करने के अवसर

6. चुनौतियाँ

डिजिटल विभाजन (Digital Divide)

तकनीकी संसाधनों की कमी

प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी

इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या

गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव

7. समाधान एवं सुधार के उपाय

डिजिटल अवसंरचना का विकास

शिक्षकों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण

सस्ती और सुलभ इंटरनेट सेवाएँ

स्थानीय भाषा में सामग्री निर्माण

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP Model)

8. भविष्य की संभावनाएँ

भविष्य में शैक्षिक प्रौद्योगिकी निम्न क्षेत्रों में और अधिक अवसर प्रदान करेगी:

AI आधारित व्यक्तिगत शिक्षा

वैश्विक ऑनलाइन शिक्षा बाजार

वर्चुअल विश्वविद्यालय

कौशल आधारित माइक्रो-कोर्स

9. निष्कर्ष

शैक्षिक प्रौद्योगिकी ने शिक्षा को केवल ज्ञान का साधन नहीं, बल्कि रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम बना दिया है। यह न केवल युवाओं को

आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। यदि इसे सही दिशा और संसाधनों के साथ लागू किया जाए, तो यह बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक कम कर सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

वेबसाइट्स

- www.shaikshikmanthan-com
- www.education-nic
- <http://www-desertation-com>
- <http://www-indianjournals-com>
- www.shodhganga-inflibnet-ac-in

कला जगत में रोजगार सृजन के अवसर

भावेश गर्ग

स्नातकोत्तर विद्यार्थी

महात्मा गाँधी कॉलेज, महवा, दौसा, राजस्थान

सारांश

कला जगत सदैव से मानव सभ्यता की आत्मा रहा है। आज के तकनीकी एवं डिजिटल युग में कला केवल सौंदर्यबोध का माध्यम नहीं रही, अपितु यह रोजगार सृजन का एक विशाल और संभावनाओं से परिपूर्ण क्षेत्र बन चुकी है। प्रस्तुत शोध-पत्र 'कला जगत में रोजगार सृजन के अवसर' विषय पर केंद्रित है, जिसमें यह विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार ललित कला, लोक कला, प्रदर्शनकारी कला, फिल्म, मीडिया, फैशन, डिजाइन, डिजिटल आर्ट एवं सांस्कृतिक उद्योग रोजगार के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं।

भारत जैसे युवा जनसंख्या प्रधान देश में, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों युवा रोजगार की तलाश करते हैं, कला जगत एक अप्रतिम समाधान प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी कला-शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने पर बल देती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ओटीटी, सोशल मीडिया, गेमिंग उद्योग

एवं वैश्विक सांस्कृतिक व्यापार ने कला-आधारित रोजगार की परिभाषा को पूर्णतः बदल दिया है। शोध में यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ, कौशल विकास कार्यक्रम एवं उद्यमिता प्रशिक्षण के माध्यम से कला को आजीविका का सशक्त माध्यम बनाया जा सकता है।

इस शोध में गुणात्मक अध्ययन पद्धति का उपयोग करते हुए द्वितीयक स्रोतों, सरकारी रिपोर्टों एवं संबंधित साहित्य का विश्लेषण किया गया है। निष्कर्षतः यह सिद्ध होता है कि कला जगत न केवल सांस्कृतिक संरक्षण का माध्यम है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मुख्य शब्द — कला जगत, रोजगार सृजन, डिजिटल आर्ट, सांस्कृतिक उद्योग, कौशल विकास, आत्मनिर्भर भारत, ललित कला, लोक कला।

1. प्रस्तावना

मनुष्य और कला का संबंध उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता। भीमबेटका की गुफाओं में उकेरे गए चित्र हों अथवा अजंता-एलोरा की भव्य मूर्तिकला — कला सदैव मानव जीवन की अभिव्यक्ति रही है। किन्तु आज के युग में कला केवल अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं रही। वैश्वीकरण, डिजिटल क्रांति और उपभोक्तावाद के इस दौर में कला एक शक्तिशाली आर्थिक उद्योग का रूप ले चुकी है। सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योग (Creative & Cultural Industries) आज

विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

भारत, जो विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में सम्मिलित है, के लिए यह एक अभूतपूर्व अवसर है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार रचनात्मक उद्योग वैश्विक स्तर पर 2.25 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं और 29.5 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। भारत में कला एवं संस्कृति से जुड़े उद्योगों का ळव्च में योगदान 2.5 से अधिक है, जो आने वाले दशक में और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में 'कला जगत में

रोजगार सृजन के अवसर' विषय का अध्ययन न केवल प्रासंगिक है बल्कि अत्यंत आवश्यक भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने कला-शिक्षा को एक नया आयाम दिया है। नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि ललित कलाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना, स्थानीय लोक कलाओं को संरक्षित करना और कला में उद्यमिता को बढ़ावा देना आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है। इस शोध-पत्र में यह विश्लेषण किया जाएगा कि कला के विभिन्न रूपों में किस प्रकार के रोजगार के अवसर विद्यमान हैं, सरकार की क्या नीतियाँ हैं, और भविष्य में इस क्षेत्र में विकास की क्या संभावनाएँ हैं।

2. कला जगत: अर्थ, परिभाषा एवं व्यापक स्वरूप

'कला जगत' एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें ललित कला (FineArts), प्रदर्शनकारी कला (PerformingArts), दृश्य कला (VisualArts), लोक एवं जनजातीय कला (Folk & TribalArts), व्यावहारिक कला (AppliedArts), डिजिटल कला (DigitalArt) एवं रचनात्मक उद्योग (Creative Industries) सम्मिलित हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था को चार मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है कृ विरासत (Heritage), कला (Arts), मीडिया (Media) और कार्यात्मक सृजन (Functional Creations)।

भारत में कला जगत अत्यंत विविधताओं से परिपूर्ण है। यहाँ एक ओर शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी जैसी परंपराएँ हैं, तो दूसरी ओर राजस्थान की कठपुतली, मधुबनी चित्रकला, वारली आर्ट, पट्टचित्र जैसी लोक कलाएँ हैं। फिल्म उद्योग, जिसे 'बॉलीवुड' के नाम से जाना जाता है, केवल मुंबई में ही सीमित नहीं है कृ क्षेत्रीय सिनेमा जैसे टॉलीवुड, कोलीवुड, सैंडलवुड आदि भी लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञापन उद्योग, फैशन उद्योग, गेमिंग, एनिमेशन,

संगीत उत्पादन, फोटोग्राफी, इंटीरियर डिजाइन, आर्किटेक्चर, हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग कृ ये सभी कला जगत के विस्तृत क्षितिज के अंग हैं।

3. कला जगत में रोजगार के प्रमुख क्षेत्र

3.1 ललित कला एवं दृश्य कला

ललित कला जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, छापाकला (Printmaking) आदि में रोजगार के अनेक अवसर हैं। एक प्रशिक्षित कलाकार न केवल गैलरी में अपनी कृतियाँ बेच सकता है, बल्कि कला शिक्षक, कला निर्देशक, म्यूजियम क्यूरेटर, आर्ट थेरेपिस्ट, इलस्ट्रेटर, ग्राफिक डिजाइनर, मुरलिस्ट और पब्लिक आर्ट स्पेशलिस्ट के रूप में भी कार्य कर सकता है। भारत में कला दीर्घाओं (Art Galleries) की संख्या में वृद्धि और ऑनलाइन आर्ट मार्केटप्लेस जैसे SaatchiArt, Artsy, Singulart आदि के उदय ने कलाकारों के लिए वैश्विक बाजार खोल दिए हैं।

3.2 प्रदर्शनकारी कला

नृत्य, संगीत, नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में रोजगार के विविध रूप उपलब्ध हैं। एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नर्तक अथवा गायक प्रदर्शनों के माध्यम से आय अर्जित करने के साथ-साथ अकादमियों में शिक्षण, फिल्मों में कोरियोग्राफी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और संगीत प्रोडक्शन में कार्य कर सकता है। रंगमंच में न केवल अभिनेता बल्कि निर्देशक, प्रकाश डिजाइनर, ध्वनि इंजीनियर, वेशभूषा डिजाइनर और मंच परिकल्पक (Set Designer) के लिए भी पर्याप्त अवसर हैं।

3.3 फिल्म, टेलीविजन एवं ओटीटी उद्योग

भारतीय फिल्म उद्योग विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है जो प्रतिवर्ष 2000 से अधिक फिल्मों का निर्माण करता है। इस उद्योग में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोग जुड़े हैं। अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक, संपादक,

सिनेमेटोग्राफर, VFX आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, कार्टूनिंग डायरेक्टर, साउंड डिजाइनर, फिल्म आलोचक कृ ये सभी इस उद्योग का अभिन्न अंग हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, डिज़ी+हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के आगमन ने कंटेंट की माँग को कई गुना बढ़ा दिया है, जिससे नए रोजगार के द्वार खुले हैं।

3.4 हस्तशिल्प एवं लोक कला

भारत के हस्तशिल्प उद्योग का वार्षिक निर्यात लगभग 4 बिलियन डॉलर है। यह उद्योग ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 70 लाख से अधिक कारीगरों को रोजगार देता है। बनारसी साड़ी, कश्मीरी पश्मीना, राजस्थानी ब्लॉक प्रिंट, लखनवी चिकनकारी, महेश्वरी हैंडलूम कृ इन सभी में पारंपरिक कौशल और आधुनिक बाजार का संगम देखने को मिलता है।

3.5 फैशन एवं टेक्सटाइल डिज़ाइन

भारतीय फैशन उद्योग एक तेज़ी से उभरता क्षेत्र है जिसका मूल्य 2025 तक 100 बिलियन डॉलर से अधिक होने की संभावना है। इस क्षेत्र में फैशन डिज़ाइनर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, फैशन स्टाइलिस्ट, फैशन फोटोग्राफर, फैशन ब्लॉगर, ट्रेंड फोरकास्टर, पैटर्न मेकर और परिधान तकनीशियन के लिए अनेक अवसर हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) इस दिशा में उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करता है।

4. डिजिटल युग में कला और नवीन रोजगार

21वीं सदी की डिजिटल क्रांति ने कला जगत में रोजगार के नितांत नवीन आयाम सृजित किए हैं। एनिमेशन, VFX (Visual Effects), गेम डिज़ाइन, UI@UX डिज़ाइन, डिजिटल इलस्ट्रेशन, मोशन ग्राफिक्स, 3D मॉडलिंग, Augmented Reality (AR) और Virtual Reality (VR) कला कृ ये सभी नई पीढ़ी के रोजगार क्षेत्र हैं। भारत का एनिमेशन, VFX और गेमिंग (AVG) उद्योग 2024 में 3.8 बिलियन डॉलर का था और 2030 तक यह 9 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

सोशल मीडिया ने 'कंटेंट क्रिएटर' और 'डिजिटल आर्टिस्ट' की एक नई श्रेणी उत्पन्न की है। YouTube, Instagram, Pinterest और Behance जैसे प्लेटफॉर्म पर भारत में लाखों कलाकार अपनी कृतियाँ प्रस्तुत करके आय अर्जित कर रहे हैं। NFT (Non-Fungible Token) आर्ट ने डिजिटल कलाकारों को अपनी डिजिटल कृतियाँ बेचने का एक क्रांतिकारी माध्यम प्रदान किया है। Canva, Adobe Suite, Procreate जैसे टूल्स की सुलभता ने ग्राफिक डिज़ाइन को एक जन-व्यापी कौशल बना दिया है, जिसमें फ्रीलांसिंग के माध्यम से लाखों युवा आय अर्जित कर रहे हैं।

ई-लर्निंग उद्योग ने भी कला शिक्षकों के लिए नए रोजगार के द्वार खोले हैं। Udemy, Skillshare, YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कला कोर्सेज से शिक्षक निष्क्रिय आय (Passive Income) अर्जित कर सकते हैं। आर्ट थेरेपी एक नया उभरता क्षेत्र है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य और कला को जोड़कर रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं।

5. सरकारी नीतियाँ एवं कला-उद्यमिता को प्रोत्साहन

भारत सरकार ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए अनेक महत्वपूर्ण नीतियाँ एवं योजनाएँ प्रारंभ की हैं। 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' (PMKVY) के अंतर्गत कला एवं हस्तशिल्प से संबंधित अनेक पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। संस्कृति मंत्रालय की *Scheme for Strengthening of Cultural Relations* और *Scheme वित्त YoungArtists* ने उभरते हुए कलाकारों को अनुदान एवं प्रशिक्षण प्रदान किया है।

'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) योजना ने स्थानीय हस्तशिल्प और कला उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। GI (Geographical Indication) Tag के माध्यम से पारंपरिक कला उत्पादों की पहचान सुरक्षित की

गई है। 'Startup India' और 'Make in India' योजनाओं ने कला-आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया है। राजस्थान जैसे राज्य जहाँ इस संगोष्ठी का आयोजन है, वहाँ की समृद्ध लोक कला परंपरा कृ मांडना, फड़ चित्रकला, नमदा, ब्लू पॉटरी – के संरक्षण और व्यावसायीकरण के लिए अनेक सरकारी प्रयास हो रहे हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने कला को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया है। नीति में बहु-विषयक शिक्षा, स्थानीय भाषाओं एवं कलाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने और कलाकारों को 'आर्टिस्ट-इन-रेसीडेंस' के रूप में विद्यालयों में आमंत्रित करने की अनुशंसा की गई है। यह नीतिगत परिवर्तन कला शिक्षा को एक गंभीर और व्यावसायिक पेशे के रूप में स्थापित करने में सहायक है।

6. महिलाओं एवं युवाओं के लिए कला क्षेत्र में विशेष अवसर

कला जगत महिलाओं के लिए एक विशेष रूप से अनुकूल उद्यमिता क्षेत्र है। घरेलू बंधनों के मध्य भी महिलाएँ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी कला को व्यावसायिक रूप दे सकती हैं। Instagram पर बिकने वाली हाथ से बनाई ज्वेलरी हो, Etsy पर बेची जाने वाली पेंटिंग हो, या YouTube चैनल पर कला सिखाना – ये सभी महिला कलाकारों के लिए आत्मनिर्भरता के सफल मार्ग हैं। WarliArt की महाराष्ट्रीय आदिवासी महिलाएँ और कच्छ की रोगन आर्ट की महिला कारीगर इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

युवाओं के लिए कला उद्यमिता के अवसर और भी व्यापक हैं। एक युवा कलाकार आज सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन से अपना डिजिटल आर्ट स्टूडियो शुरू कर सकता है। Fiverr, Upwork जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर ग्राफिक डिजाइन, लोगो निर्माण, इलस्ट्रेशन, एनिमेशन के लिए वैश्विक ग्राहक मिलते हैं। भारतीय युवाओं की प्रतिभा की वैश्विक माँग को

देखते हुए यह क्षेत्र विशेष रूप से विदेशी मुद्रा अर्जन का भी सशक्त माध्यम बन सकता है।

7. कला जगत में रोजगार की चुनौतियाँ

यद्यपि कला जगत में रोजगार के अवसर अपार हैं, तथापि कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं जिनका सामना कला-कर्मियों को करना पड़ता है। सबसे प्रमुख चुनौती है – सामाजिक मान्यता का अभाव। हमारे समाज में अभी भी कला को 'सुरक्षित करियर' नहीं माना जाता। अभिभावक अपने बच्चों को इंजीनियरिंग या मेडिकल की ओर प्रेरित करते हैं और कला को मात्र एक शौक के रूप में देखते हैं।

दूसरी बड़ी चुनौती है आय की अनियमितता (Income Irregularity)। अधिकांश कला-कर्मि फ्रीलांस आधार पर कार्य करते हैं जिसमें आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता। सामाजिक सुरक्षा, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं का अभाव कला-कर्मियों के जीवन को अनिश्चित बनाता है। इसके अतिरिक्त, कला की नकल (Plagiarism) और बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के उल्लंघन की समस्या भी एक गंभीर चुनौती है जिससे डिजिटल कलाकार विशेष रूप से पीड़ित हैं।

तीसरी चुनौती है प्रशिक्षण और बाजार के बीच की खाई। परंपरागत कला संस्थान अभी भी आधुनिक डिजिटल कौशल और व्यावसायिक प्रबंधन की शिक्षा देने में पीछे हैं। एक प्रतिभाशाली कलाकार बाजार में अपनी कला को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत और बेचने में असमर्थ होता है। ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का अभाव भी एक बड़ी बाधा है।

8. समाधान एवं सुझाव

कला जगत में रोजगार की संभावनाओं को साकार करने के लिए एक समन्वित एवं बहु-स्तरीय प्रयास की आवश्यकता है। शिक्षा के स्तर पर विद्यालयों में कला को एक गंभीर शैक्षणिक विषय के रूप में स्थापित करना होगा। कला संस्थानों के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक प्रबंधन, डिजिटल

मार्केटिंग, IPR जागरूकता और उद्यमिता कौशल को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए। NEP-2020 की भावना के अनुरूप कला और विज्ञान-वाणिज्य का एकीकरण किया जाना चाहिए।

सरकारी स्तर पर कला-कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। कलाकार पंजीकरण, स्वास्थ्य बीमा, वृद्धावस्था पेंशन और आयकर में विशेष छूट जैसे प्रावधान उनके जीवन को स्थिरता प्रदान करेंगे। हस्तशिल्प कारीगरों के लिए प्रत्यक्ष विपणन (Direct Marketing) की सुविधा और बाजार लिंकेज के प्रयास किए जाने चाहिए। जी.आई. टैग प्राप्त उत्पादों के प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

उद्योग जगत के साथ साझेदारी के अंतर्गत कला स्नातकों के लिए इंटरनशिप और अप्रेंटिसशिप के अवसर सृजित किए जाने चाहिए। कॉर्पोरेट जगत में 'आर्टिस्ट-इन-रेसीडेंस' कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कला का प्रचार-प्रसार करने के लिए सरकारी एवं निजी सहयोग से कला दूतावास (Cultural Diplomacy) का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए।

9. निष्कर्ष

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कला जगत में रोजगार के अवसर न केवल विद्यमान हैं, बल्कि तेजी से विस्तारित हो रहे हैं। यह क्षेत्र

आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जब हम कला को केवल एक सौंदर्यबोधात्मक अनुभव की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में देखते हैं, तब इसकी असीमित संभावनाएँ दृष्टिगोचर होती हैं।

भारत की सांस्कृतिक विविधता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस विविधता को 'सॉफ्ट पावर' और 'इकोनॉमिक पावर' दोनों में परिवर्तित करने की क्षमता हमारे पास है। आवश्यकता है तो केवल उचित नीतिगत ढाँचे, शैक्षणिक सुधारों, डिजिटल कौशल विकास और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन की। जब कला और उद्यमिता का संगम होगा, जब परंपरा और तकनीक का समन्वय होगा तब कला जगत भारत के युवाओं के लिए रोजगार का सबसे समृद्ध और संतोषजनक क्षेत्र बनकर उभरेगा।

अंततः यह कहना उचित होगा कि कला न केवल जीवन को सुंदर बनाती है, अपितु यह जीवन को सार्थक और आर्थिक रूप से समृद्ध भी बनाती है। कला जगत में रोजगार की अपार संभावनाएँ उन युवाओं की प्रतीक्षा कर रही हैं जो रचनात्मकता, साहस और कौशल के साथ इस क्षेत्र में कदम रखने को तत्पर हैं। 'आत्मनिर्भर भारत' का सपना कला के माध्यम से निश्चय ही साकार हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भारत सरकार (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. UNESCO (2022)- ReShaping Policies for Creativity Addressing CultureAsA Global Public Good- Paris% UNESCO Publishing-
3. FICCI&EY (2023). India's Media & Entertainment Industry Report- Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry-
4. NASSCOM (2023)-[Animation] VFX] Gaming & Comics (AVGC) Sector Report- New Delhi-
5. Development Commissioner (Handicrafts) (2023)-Annual Report 2022&23- Ministry of TeÚtiles] Government of India-
6. UNCTAD (2022)- Creative Economy Outlook 2022- United Nations Conference on TradeAnd Development-

7. शर्मा, रमेश कुमार (2021). भारतीय कला और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था. राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
8. वर्मा, सुनीता (2020). लोक कला और ग्रामीण उद्यमिता. साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
9. Throsby] D- (2010)- The Economics of Cultural Policy- Cambridge University Press-
10. Ministry of Culture (2023)- India*s CulturalAnd Creative Industries Report- Government of India] New Delhi-

महिला सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता

श्री संजय कुमार

सहायक आचार्य

महात्मा गाँधी टी.टी. कॉलेज, महवा, दौसा, राजस्थान

सारांश

आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत को आर्थिक सामाजिक एवं तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाना है। इस अभियान में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वे पूरे देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। महिला सशक्तिकरण एवं उद्यमिता के माध्यम से न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है बल्कि राष्ट्रीय विकास को गति मिलती है। आत्मनिर्भर भारत के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिलाओं का योगदान प्राप्त करने का सबसे प्रभावित तरीका उनका आर्थिक विकास करना है। यह शोध-पत्र आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता के अवसरों तथा चुनौतियों का विश्लेषण करता है। इसमें सरकारी नीतियों, डिजिटल क्रांति, स्वयं सहायता

समूहों, स्टार्टअप संस्कृति, ग्रामीण उद्यमिता और सामाजिक उद्यमों के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। साथ ही, सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक बाधाओं की पहचान की गई है। अंत में, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए सुझाव (Suggestions) महिला शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना डिजिटल साक्षरता बढ़ाना सामाजिक जागरूकता अभियान महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।

मुख्य शब्द – आत्मनिर्भर भारत, वैश्विक महामारी, पूंजी निर्माण, सामुदायिक उद्यमिता, अर्थव्यवस्था।

प्रस्तावना: “देश की तरक्की का मुख्य स्तम्भ – शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियां तथा महिला सशक्तिकरण “आज के इस समय में महिला सशक्तिकरण एक चर्चा का विषय है खासतौर से पिछड़े और प्रगतिशील देशों में क्योंकि उन्हें इस बात का काफी बाद में ज्ञान हुआ कि बिना महिलाओं की तरक्की और सशक्तिकरण के देश की तरक्की सम्भव नहीं है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ

महिलाओं की उस क्षमता से है। जिससे उनमें वे योग्यता आ जाती है। जिसमें वे अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय ले सकती हैं। 8 मार्च को पूरे विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सही मायने में महिला दिवस मनाने का

उद्देश्य तभी पुरा होगा जब देश में महिलाओं की तरक्की और वह सशक्त बनेगी। यह वह तरीका है जिसके द्वारा महिलाएं भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर सकें।

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

प्राचीन काल की अपेक्षा मध्य काल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आयी हालांकि आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए और उन्हें बाध्य है उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।

1. शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काफी पिछे हैं। हमारे देश में कई सारी महिलाओं को शिक्षा की सुविधा नहीं उपलब्ध है और अगर वह पढ़ती भी है तो कुछ कक्षाओं के बाद ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देती है।
2. भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का एक दूसरा मुख्य कारण भुगतान में असमानता भी है। भारत में कई सारे कार्य क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम भुगतान किया जाता है।
3. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान समाज है। जहाँ पुरुष का हर क्षेत्र में। दखल है और महिलाएं सिर्फ घर-परिवार की जिम्मेदारी उठाती हैं। साथ ही उन पर कई पाबंदिया भी होती हैं। भारत की लगभग 50 प्रतिशत आबादी केवल महिलाओं की है। मतलब पूरे देश के विकास के लिए आधी आबादी की इजरूरत है जो कि अभी भी सशक्त नहीं है और सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हुई है। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते की भविष्य में बिना हमारी आधी आबादी को मजबूत किये हमारा देश विकसित हो पाएगा। अगर हमें अपने देश को विकसित बनाना है तो ये जरूरी है कि सरकार, पुरुष और खुद महिलाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। महिला सशक्तिकरण की जरूरत/आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्राचीन समय से भारत में लैंगिक असमानता थी। और पुरुष प्रधान समाज था।

महिलाओं के उनके अपने परिवार द्वारा कई कारणों से दबाया गया तथा उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई। परिवार और समाज में भेदभाव भी किया गया। ऐसा केवल भारत में ही नहीं। बल्कि दूसरे देशों में भी दिखाई पड़ता है। महिलाओं के लिए प्राचीन काल से समाज में चले

आ रहे गलत और पुराने चलन को नये रीति रिवाजों और परम्पराओं में ढाल दिया गया था। भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए माँ-बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में महिला देवियों को पूजने की परम्परा है। लेकिन इसका कतई मतलब है कि केवल महिलाओं को पूजने भर से देश के विकास की जरूरत पूरी हो जाएगी। आज जरूरत है कि देश की आधी आबादी यानि महिलाओं के हर क्षेत्र में सशक्तिकरण किया जाए। जो देश के विकास का आधार बनेगी। भारत एक प्रसिद्ध देश है। जिसने विविधता में एकता के मुहावरे को साबित किया है। जहाँ भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। महिलाओं को हर धर्म में एक अलग स्थान दिया गया है। लोगों की आँखों ढके हुए बड़े पर्दे के रूप में कई वर्षों से आर्दश के रूप में महिलाओं के खिलाफ कई सारे गलत कार्यों (शारीरिक और मानसिक) को जारी रखने में मदद कर रहा है।

प्राचीन भारतीय समाज दूसरी भेदभावपूर्ण दस्तूरों के साथ सती प्रथा, नगर वधू, दहेज प्रथा, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, गर्भ में बच्चियों की हत्या, पर्दा प्रथा, कार्य स्थल पर यौन भाषण, बाल विवाह, बाल मजदूरी, देवदासी प्रथा आदि परम्पराएं थी। इस तरह की कुप्रथा का कारण पितृसत्तात्मक समाज और पुरुष श्रेष्ठता मनोग्रन्थि है। महिलाएं ज्यादा खुले दिमाग की होती हैं और सभी आयामों में अपने अधिकारों को पाने के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ रही हैं। हालांकि अपराध इसके साथ-साथ चल रहा है।

भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं

भारतीय समाज एक अलग तरह का समाज है जिसमें कई तरह के रिवाज और परम्पराएं शामिल हैं। कई बार यह पुरानी मान्यताएं और परम्पराएं भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए बाधा सिद्ध होती हैं। महिलाओं के रास्ते में आने वाली इसी

तरह की कई सारी बाधाओं के विषय में नीचे अग्रलिखित बिन्दुओं के द्वारा स्पष्ट किया गया है:-

- 1. सामाजिक मापदंड** — पुरानी और रूढ़िवादी विचारधाराओं के कारण भारत में कई सारे क्षेत्रों में महिलाओं के घर छोड़ने पर पाबन्दी होती है। इस तरह के क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा या फिर रोजगार के लिए घर से बाहर जाने के लिए आजादी नहीं होती है। इस तरह के वातावरण में रहने के कारण महिलाएं खुद को पुरुषों से कमतर समझने लगती हैं। और अपने वर्तमान सामाजिक और आर्थिक दशा को बदलने में साबित होती हैं।
- 2. कार्यक्षेत्र में शारिरिक शोषण** — कार्यक्षेत्र में होने वाला शोषण भी महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी बाधा है। निजी क्षेत्र जैसे कि सेवा उद्योग, साफ्टवेयर उद्योग, भोज्य संस्थाएं और अस्पताल इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। यह समाज में पुरुष प्रधानता के वर्चस्व के कारण महिलाओं के लिए और भी समस्याएं उत्पन्न करता है पिछले कुछ समय में कार्यक्षेत्रों में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़नों में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। और पिछले कुछ दशकों में लगभग 70 प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है।
- 3. लैंगिक भेदभाव** — भारत में अभी भी कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक स्तर पर काफी भेदभाव किया जाता है। कई क्षेत्रों में तो महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाने की भी इजाजत नहीं होती है। इसके साथ ही उन्हें आजादीपूर्वक कार्य करने या परिवार से जुड़े फैसले लेने की भी आजादी नहीं होती है। उन्हें हर कार्य में पुरुषों की अपेक्षा कमतर ही माना जाता है। इस प्रकार के भेदभावों के कारण महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक दशा बिगड़ जाती है।
- 4. भुगतान में असमानता** — भारत में महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों की अपेक्षा कम भुगतान किया जाता है। और असंगठित क्षेत्र में यह समस्या और भी ज्यादा दयनीय है। खासतौर से दिहाड़ी मजदूरी वाले जगहों पर तो यह सबसे बदतर है। समान कार्य को समान समय तक करने के बावजूद भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा काफी कम भुगतान किया जाता है। इस तरह के कार्य महिलाओं और पुरुषों के मध्य के भावित असमानता को प्रदर्शित करते हैं। संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों के तरह समान अनुभव और योग्यता होने के बावजूद पुरुषों के अपेक्षा कम भुगतान किया जाता है।
- 5. अशिक्षा** — महिलाओं में अशिक्षा और बीच में पढ़ाई जैसी समस्याएं भी महिला सशक्तिकरण में काफी बड़ी बाधाएं हैं। वैसे तो बाहरी क्षेत्रों में लड़कियां शिक्षा के मामले में लड़कों के बराबर हैं पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस मामले में वह काफी पीछे हैं। भारत में महिला शिक्षा पर 64.6 प्रतिशत है जबकि पुरुषों की शिक्षा 80.90 प्रतिशत है। काफी सारी ग्रामीण लड़कियां जो स्कूल जाती हैं, उनकी पढ़ाई भी बीच में छूट जाती है और वह दसवीं कक्षा भी पास नहीं कर पाती हैं।
- 6. बाल विवाह** — हालांकि पिछले कुछ दशकों में सरकार द्वारा लिए गए प्रभावी फैसलों द्वारा भारत में बाल विवाह जैसी कुरीति को काफी हद तक कम कर दिया गया है। लेकिन 2018 में युनिसेफ की एक रिपोर्ट द्वारा पता चलता है कि भारत में अब भी हर वर्ष लगभग 15 लाख लड़कियों की भांति 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है, जल्द भांति हो जाने के कारण महिलाओं का विकास रुक जाता है। और वह भारीरक तथा मानसिक रूप से व्यस्क नहीं हो पाती हैं।

7. **महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध** भारतीय महिलाओं के विरुद्ध कई सारे घरेलू हिंसाओं के साथ दहेज, ऑनर किलिंग और तस्करी जैसे गंभीर अपराध देखने को मिलते हैं। हालांकि काफी अजीब है की भाहरी क्षेत्र की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की अपेक्षा अपराधिक हमलों की अधिक शिकार होती हैं। यहां तक की कामकाजी महिलाएं भी देर रात में अपनी सुरक्षा को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग नहीं करती हैं। सही मायनों में महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति तभी की जा सकती है। जब महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और पुरुषों की तरह वह भी बिना भय के स्वच्छंद रूप से कहीं आ जा सके।

8. **कन्या भ्रूण हत्या** – कन्या भ्रूण हत्या या फिर लिंग के आधार पर गर्भपात भारत में महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ लिंग के आधार पर होने वाली भ्रूण हत्या से है जिसके अन्तर्गत कन्या भ्रूण का पता चलने पर बिना माँ की सहमति के ही गर्भपात करा दिया जाता है। कन्या भ्रूण के कारण ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेशों में स्त्री और पुरुष लिंगानुपात में काफी ज्यादा अंतर आ गया है। हमारे महिला सशक्तिकरण के ये दावे तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक हम कन्या भ्रूण हत्या की समस्या को मिटा नहीं पायेंगे।

नारी की स्थिति व महिला सशक्तिकरण :- “स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं – सहधर्मिणी अर्धांगिनी और मित्र है।” – महात्मा गाँधी

जिस समाज में नारी का स्थान सम्मानजनक होता है वह उतना ही प्रगतिशील और विकसित देश है। परिवार और समाज के निर्माण में नारी का सदैव महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जब समाज सशक्त और विकसित होता है। तब राष्ट्र भी मजबूत होता है। इस प्रकार राष्ट्र निर्माण में नारी केन्द्रीय भूमिका

का निर्वाहन करती है। माता के रूप में नारी प्रथम गुरु होती है।

यह सही है कि सरकार द्वारा अपने स्तर पर नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में अनेक प्रयास किए गए हैं किन्तु सरकार के यह पहले तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक धरातल पुरुष मानसिकता या पुरुष प्रधान समाज की सोच में बदलाव नहीं आ जाता। आज भी घटता लिंगानुपात, बालिका भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न, बंधुआ मजदूरी, बाल तस्करी जैसी कुरीतियां हमारे देश के सामने एक विकट समस्या बनी हुई है। वर्तमान समय में जन-जन तक यह संदेश पहुंचाने की आवश्यकता है कि महिला सशक्तिकरण देश के विकास की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है आज महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, भाषाई, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता प्रदान करने की आवश्यकता है। नारी को सशक्त बनाए बगैर हम मानवता को सशक्त नहीं बना सकते। संवेदना, करुणा, वात्सल्य, ममत्व, प्यार, स्नेह, सहनशीलता, विनम्रता आदि नारी के वे गुण हैं जिनसे वह मानवता को और संवार कर उसे सम्पूर्ण एवं सशक्त बना सकती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हर क्षेत्र में महिलाओं की सम्मानजनक एवं पर्याप्त हिस्सेदारी हो, उन्हें साक्षर बनाया जाए। हर क्षेत्र में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका को प्रोत्साहन देते हुए उन्हें सुरक्षा भी दी जाए। उन पर हो रही हिंसा का अंत हो तथा उन्हें भांति के प्रत्येक पहलू एवं सुरक्षा और विकास की अनेकानेक प्रक्रियाओं में सम्मिलित किया जाए। हर देश या राष्ट्र को चाहिए कि आर्थिक सशक्तिकरण एवं राष्ट्रीय विकास की योजनाओं में महिलाओं को केन्द्र में रखा जाए। राष्ट्रों को सालाना बजट में “जेंडर बजटिंग” का प्रावधान करना चाहिए। जिसकी पहल भारत वर्ष में की जा चुकी है।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका – भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इनमें से कई सारी योजनाएं रोजगार, कृषि और स्वास्थ्य जैसी चीजों के लिए चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का गठन भारतीय महिलाओं की परिस्थिति को देखते हुए किया गया है। ताकि समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। इनमें से कुछ मुख्य योजनाएं मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना (मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए चलायी जाने वाली योजना) आदि हैं।

1. **बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना**— यह योजना कन्या भ्रूणहत्या और कन्या शिक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके अन्तर्गत लड़कियों की बेहतरी के लिए योजना बनाकर और उन्हें आर्थिक सहायता देकर लोगों की सोच बदलने का कार्य किया जा रहा है।
2. **महिला हेल्प लाईन योजना** – इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को 24 घंटे इमरजेंसी सहायता सेवा प्रदान की जाती है। महिलाएं अपने विरुद्ध होने वाली किसी भी तरह की हिंसा या अपराध की शिकायत इस नंबर पर कर सकती हैं। इस योजना के तहत पूरे देश में 181 नंबर को डायल करके महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं।
3. **उज्ज्वला योजना** – यह योजना महिलाओं को और यौन भोषण से बचाने के लिए की जाती है। इसके साथ ही इसके अन्तर्गत उनके पुर्नवास और कल्याण के लिए भी कार्य किया जाता है।
4. **महिला शक्ति केन्द्र** – यह योजना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसके अन्तर्गत छात्रों और पेशेवर व्यक्तियों जैसे सामुदायिक स्वयंसेवक ग्रामीण महिलाओं

को उनके अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

5. **स्टेप योजना (सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लायड प्रोग्राम फार वूमेन)** – स्टेप योजना के अन्तर्गत महिलाओं के कौशल को निखारने का कार्य किया जाता है। ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके। इसके अन्तर्गत कई सारे क्षेत्रों के कार्य जैसे कि कृषि, 2018 के

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय – 8 मार्च के दिन के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल एक थीम यानि विषय को चुना जाता है। इस साल के लिए “प्रेस फॉर प्रोग्रेस” विषय का चयन किया गया है। वही नीचे पिछले छः सालों में इस दिन के लिए जिन विषयों का चयन किया जा चुका है। उनके बारे में जानकारी दी गई है, जो कि इस प्रकार है।

भारत का महिला आरक्षण बिल – किसी भी देश को चलाने के लिए सभी महत्वपूर्ण फैसले उसकी संसद में ही लिए जाते हैं। वहीं हमारी संसद में अगर महिला सांसदों की संख्या देखी जाए तो ना के समान ही है। हमारे देश की महिलाओं की भूमिका देश को चलाने में ज्यादा खास नहीं है। वहीं संसद में महिलाओं की इतनी कम संख्या को देखते हुए भारत की सरकार ने साल 2010 में महिला आरक्षण बिल का संसद में सबके सामने प्रस्ताव रखा। इस बिल के मुताबिक संसद की 33 प्रतिशत सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने के नियम का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार केवल राज्य सभा से ही इस बिल को पास करवाने में कामयाब रही थी। लोकसभा में इस बिल को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण इसे पास नहीं किया जा सका था। सही साल 1993 में भारत सरकार ने एक संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था। जिसमें ग्रामीण परिषद स्तर के होने वाले चुनावों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी।

जिसकी वजह से आज हर गांव में होने वाले चुनावों में महिला चुनाव लड़ती है। महिला सशक्तिकरण का महत्व:- महिला सशक्तिकरण के महत्व को अग्रलिखित बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट किया गया है:-

1. **समाज का विकास** – महिला सशक्तिकरण का मुख्य लाभ समाज से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोगों को अपने देश को एक भाक्तिशाली देश बनाना है तो, इसके लिए हम लोगों को समाज की महिला को भी भाक्तिशाली बनाने की जरूरत है। महिलाओं के विकास का मतलब होता है कि आप एक परिवार का विकास का कार्य कर रहे हैं। अगर महिला शिक्षित होगी तो वो अपने परिवार को भी पढ़ा-लिखा बनाने की कोशिश करेगी। जिसके चलते हमारे देश को पढ़े लिखे नौजवान मिलेंगे जो कि देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकेंगे।
2. **घरेलू हिंसा में कमी** – घरेलू हिंसा एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी महिला के साथ हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि घरेलू हिंसा केवल अनपढ़ महिलाओं के साथ ही होती है। शिक्षित महिलाएं भी इस तरह की हिंसा का शिकार होती हैं। बस फर्क इतना होता है कि जहाँ पढ़ी लिखी महिलाएं इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखती हैं। वहीं अनपढ़ महिलाएं ऐसी हिंसा के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने से डरती हैं। वहीं अगर महिलाओं का विकास किया जा सके तो हमारे देश में होने वाली घरेलू हिंसा में ना केवल कमी आएगी बल्कि महिलाएं घरेलू हिंसा करने वाले आदमी को सजा भी दिलवाने के लिए आगे आएंगी।
3. **आत्म निर्भर बनाना** – हमारे देश में लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उन्हें आगे जाकर केवल घर की ही देखभाल करनी है। अभी भी गांव में पढाई करने से

ज्यादा लड़कियों को घर के काम सिखाये जाते हैं। जो ना सिर्फ लड़कियों के भविष्य के लिए गलत है बल्कि देश के लिए नुकसानदेह है। देश में अशिक्षित लड़कियां होने के मतलब है कि देश की करीब 40 प्रतिशत आबादी का अशिक्षित होना। अगर हम अपने देश की लड़कियों को आत्म निर्भर नहीं बनने देंगे तो हमारी देश की महिलाएं केवल रसोई तक ही सीमित रह जाएगी।

4. **गरीबी कम करने** – महिला सशक्तिकरण का जो अगला सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो गरीबी से जुड़ा हुआ है। अक्सर देखा गया है कि इतनी मंहगाई के जमाने में कभी-कभी परिवार के पुरुष सदस्य द्वारा अर्जित धन परिवार की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। वहीं महिलाओं की अतिरिक्त आय परिवार को गरीबी के रास्ते से बाहर आने में मदद करता है। इसलिए गरीबी को कम करने के लिए भी महिलाओं का शिक्षित होने के साथ-साथ कामकाजी होना जरूरी है।
5. **प्रतिभाशाली** – कई ऐसी लड़कियां होती हैं जिनमें कई प्रतिभा होती हैं लेकिन मार्गदर्शन और शिक्षा न मिल पाने के चलते वा अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। इसलिए अगर महिलाओं का सही से सशक्तिकरण कर दिया जाए तो महिला अपने हुनर की पहचान कर सकेंगी। जिससे देश को भी प्रतिभाशाली महिलाएं मिलेंगी जो कि देश के विकास के लिए कार्य करेंगी।
6. **समाज में समानता मिलना** – महिला सशक्तिकरण करने का सबसे बड़ा लक्ष्य है। वो महिलाओं को पुरुष के समान इस समाज में समानता देना है। अभी भी दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के तरह अधिकार नहीं दिए गए हैं। महिलाएं अभी भी केवल गुलामों की तरह कार्य करती

है। उनको ना अपनी बात कहने की और ना खुद निर्णय लेने की आजादी दी गई है। वही महिला सशक्तिकरण के जरिए ऐसी महिलाओं का विकास करने पर ही जोर दिया जाता है। ताकि ये महिलाएं बोलने की आजादी का लाभ उठा सकेंगी तथा अपनी राय खुलकर समाज के सामने रख सकें। निष्कर्ष:- इन सब के साथ साथ यह भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि सभी पहले, कार्यक्रम, योजनाएं तभी अपना रंग दिखा पाएंगी जब नारी खुद के अधिकार के संदर्भ में जागरूक होंगी तभी वे स्वयं को सशक्त बना सकेंगी।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची –

1. Annapurna Nautiyal, Himanshu Bourai (2009). 'Women Empowerment in Garhwal Himalayas: Constraints and Prospects', Kalpaz Publications, Delhi.
2. Brady, Martha (2005). Creating Safe Spaces and Building Social Assets for Young Women in the Developing World : A New Role for Sport. Women's Studies Quarterly 2005, vol. 33, no. 1 & 2.
3. Christabell, P.J., (2009). 'Women Empowerment through Capacity Building the Role of Microfinance', Concept Publishing Company, New Delhi.
4. Dandikar, Hemalata. (1986). Indian Women's Development: Four Lenses, South Asia Bulletin, VI (1), 2-10. Delhi.
5. Dr. Dasarati Bhuyan (2006). "Empowerment of Indian Women: A challenge of 21st Century" Orissa Review.
6. Handy, F., & Kassam, M. (2004). Women's empowerment in rural India. Paper presented At the ISTR conference, Toronto Canada.
7. Harriet B. Presser, Gita Sen, (2003). 'Women's Empowerment And Demographic Processes', Oxford University Press, New York.
8. Kabeer, N. (1995). Targeting women or transforming institutions? Policy lessons from NGO Antipoverty efforts. Development in practice 5(2), 108-116.

आत्मनिर्भर भारत: रोजगार सृजन और कौशल विकास में अवसर और चुनौतियाँ

कुलदीप सिंह

सहायक व्याख्याता, महात्मा गांधी टी.टी. कॉलेज, महवा, दौसा, राजस्थान

सारांश

आत्मनिर्भर भारत पहल भारत सरकार द्वारा आर्थिक स्वावलंबन, स्थानीय उत्पादन, नवाचार तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने हेतु प्रारंभ की गई एक समग्र रणनीति है। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य रोजगार सृजन, कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन तथा आयात-निर्भरता में कमी लाना है। प्रस्तुत शोध-पत्र में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत रोजगार एवं कौशल विकास के उभरते अवसरों तथा उनके समक्ष विद्यमान प्रमुख

चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यह पहल भारत को "नौकरी खोजने वाले" (Job Seeker) से "नौकरी सृजक" (Job Creator) राष्ट्र में रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। तथापि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षा-प्रशिक्षण, उद्योग-शिक्षा सहयोग तथा क्षेत्रीय संतुलन को सुदृढ़ करना अनिवार्य है।

मुख्य शब्द – आत्मनिर्भर भारत, रोजगार सृजन, कौशल विकास, उद्यमिता, डिजिटल अर्थव्यवस्था।

1. प्रस्तावना (Introduction)

भारत विश्व की सर्वाधिक युवा आबादी वाले देशों में से एक है, जो इसे एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभान्वित प्रदान करता है। यह लाभ तभी सार्थक सिद्ध हो सकता है जब युवाओं को पर्याप्त रोजगार अवसर एवं प्रासंगिक कौशल उपलब्ध कराए जाएँ। वैश्वीकरण, तीव्र तकनीकी परिवर्तन तथा कोविड-19 जैसी वैश्विक परिस्थितियों ने आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को और अधिक प्रासंगिक बना दिया है।

आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य केवल आर्थिक स्वावलंबन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उत्पादन, नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं मानव संसाधन विकास के समन्वित माध्यम से समग्र राष्ट्रीय प्रगति सुनिश्चित करने की एक व्यापक विकासात्मक दृष्टि है। यह पहल "वोकल फॉर लोकल", "मेक इन इंडिया", "स्टार्टअप इंडिया" तथा "डिजिटल इंडिया" जैसी प्रमुख योजनाओं के साथ अंतर्संबद्ध है, जो रोजगार सृजन एवं कौशल विकास को नई दिशा प्रदान करती हैं।

2. आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा (Concept of Atmanirbhar Bharat)

आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा का तात्पर्य आत्मकेंद्रित या पृथक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना नहीं है, बल्कि भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम, सशक्त एवं आत्मविश्वासी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना है। यह दृष्टिकोण स्वदेशी क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रभावी भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है।

आत्मनिर्भर भारत पहल पाँच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जो इसके संरचनात्मक एवं कार्यात्मक आधार को निर्धारित करते हैं:

अर्थव्यवस्था (Economy): तीव्र, सतत एवं समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, जो परंपरागत रैखिक वृद्धि से आगे बढ़कर गुणात्मक परिवर्तन (नंदजनन रनउच) पर आधारित हो।

बुनियादी ढाँचा (Infrastructure): विश्वस्तरीय अवसंरचना का विकास, जो आधुनिक भारत की

पहचान को सुदृढ़ करे और औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करे।

प्रणाली (System) : प्रौद्योगिकी-आधारित, पारदर्शी एवं कुशल प्रशासनिक एवं आर्थिक प्रणाली का निर्माण, जो डिजिटल नवाचार को बढ़ावा दे।

जनसांख्यिकी (Demography): भारत की युवा आबादी को उत्पादक मानव संसाधन में परिवर्तित कर जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रभावी उपयोग।

मांग (Demand): घरेलू बाजार की सुदृढ़ मांग को सशक्त बनाते हुए उत्पादन और उपभोग के बीच संतुलन स्थापित करना।

उपरोक्त सभी स्तंभ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन और कौशल विकास से संबंधित हैं। इनका समन्वित क्रियान्वयन न केवल श्रम बाजार की गुणवत्ता में सुधार करता है, बल्कि मानव पूंजी के विकास के माध्यम से दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को भी सुनिश्चित करता है।

3. रोजगार सृजन के अवसर (Employment Generation Opportunities)–

आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएँ उभरकर सामने आई हैं। ये अवसर न केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित हैं, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं सतत विकास के नए आयामों को भी समाहित करते हैं।

3.1 विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector)–

“मेक इन इंडिया” पहल के माध्यम से देश में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा मिला है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन की संभावनाएँ सुदृढ़ हुई हैं। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (डैडम्) क्षेत्र ने बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय उद्योगों के प्रोत्साहन से क्षेत्रीय आर्थिक संतुलन को भी बढ़ावा मिला है।

3.2 कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Agriculture and Rural Economy)–

कृषि आधारित उद्योग, जैसे खाद्य प्रसंस्करण एवं डेयरी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरे हैं। जैविक खेती एवं एग्री-स्टार्टअप्स के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे गैर-कृषि रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो रही है।

3.3 स्टार्टअप एवं उद्यमिता (Startups and Entrepreneurship) –

आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत युवाओं को रोजगार खोजने के बजाय रोजगार सृजक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। “मुद्रा योजना” एवं “स्टार्टअप इंडिया” जैसी सरकारी पहलों ने नवाचार-आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित किया है, जिससे नए रोजगार अवसर उत्पन्न हुए हैं।

3.4 डिजिटल अर्थव्यवस्था (Digital Economy) –

डिजिटल प्रौद्योगिकी के विस्तार ने ई-कॉमर्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार की नई संभावनाएँ उत्पन्न की हैं। गिग इकोनॉमी एवं फ्रीलांसिंग ने लचीले रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, जबकि ऑनलाइन शिक्षा एवं डिजिटल सेवाओं ने ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है।

3.5 हरित ऊर्जा एवं सतत विकास (Green Energy and Sustainable Development) –

सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास ने नए रोजगार क्षेत्रों को जन्म दिया है। इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग एवं पर्यावरण प्रबंधन सेवाएँ सतत विकास आधारित रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

4. कौशल विकास के अवसर (Skill Development Opportunities)

आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कौशल विकास एक केंद्रीय तत्व के रूप में उभरकर सामने आया है।

4.1 कौशल भारत मिशन (Skill India Mission)

कौशल भारत मिशन के माध्यम से उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अल्पकालिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल प्रदान करते हैं।

4.2 तकनीकी एवं डिजिटल कौशल (Technical and Digital Skills)

आधुनिक अर्थव्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा विज्ञान, साइबर सुरक्षा एवं क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में कौशल की मांग तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल साक्षरता को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

4.3 व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education)

ITI पॉलिटेक्निक एवं स्किल सेंटर के माध्यम से कार्य-आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि हो रही है।

4.4 समावेशी कौशल विकास (Inclusive Skill Development)

महिलाओं एवं वंचित वर्गों के सशक्तिकरण हेतु स्वयं सहायता समूह, घरेलू उद्योग एवं हस्तशिल्प को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल रहा है।

4.5 अप्रेंटिसशिप एवं उद्योग-शिक्षा सहयोग (Apprenticeship and Industry&Academia Linkages)

अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों एवं उद्योग-शिक्षा साझेदारी के माध्यम से कार्य-अनुभव आधारित कौशल विकसित किए जा रहे हैं, जिससे रोजगार की संभावनाएँ बढ़ती हैं।

5. प्रमुख चुनौतियाँ (Key Challenges) –

आत्मनिर्भर भारत के सफल क्रियान्वयन में अनेक संरचनात्मक एवं नीतिगत चुनौतियाँ विद्यमान हैं:

5.1 कौशल एवं रोजगार के बीच असंगति (Skill Mismatch) –

शिक्षा प्रणाली एवं उद्योग की आवश्यकताओं के बीच असंतुलन के कारण बड़ी संख्या में शिक्षित युवा कौशल-विहीन रह जाते हैं।

5.2 तकनीकी परिवर्तन (Technological Disruption)

ऑटोमेशन एवं नई तकनीकों के कारण पारंपरिक रोजगार के अवसरों में कमी आई है, जिससे पुनः कौशल विकास की आवश्यकता बढ़ी है।

5.3 MSME क्षेत्र की चुनौतियाँ (MSME Constraints)

वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी अवसंरचना का अभाव एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा MSME क्षेत्र के लिए प्रमुख बाधाएँ हैं।

5.4 ग्रामीण-शहरी असमानता (Rural&Urban Disparity)

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण संस्थानों की कमी एवं डिजिटल विभाजन रोजगार एवं कौशल विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं।

5.5 महिला श्रम भागीदारी (Low Female Labour Participation)

सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक बाधाओं के कारण महिलाओं की श्रम भागीदारी अपेक्षाकृत कम है।

5.6 प्रशासनिक एवं नीतिगत बाधाएँ (Policy and Administrative Constraints)

नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में कमी एवं नौकरशाही जटिलताएँ विकास की गति को प्रभावित करती हैं।

6. समाधान एवं नीतिगत सुझाव (Policy Recommendations) –

शिक्षा प्रणाली को कौशल-आधारित एवं उद्योगोन्मुख बनाया जाए

उद्योग-शिक्षा सहयोग को सुदृढ़ किया जाए

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल एवं प्रशिक्षण अवसंरचना का विस्तार किया जाए

MSME क्षेत्र को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाए

महिला एवं युवाओं के लिए लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएँ

आजीवन अधिगम (Lifelong Learning) को प्रोत्साहित किया जाए

7. भविष्य की संभावनाएँ (Future Prospects) –

यदि आत्मनिर्भर भारत की नीतियों का प्रभावी एवं समन्वित क्रियान्वयन किया जाता है, तो भारत के समक्ष निम्नलिखित संभावनाएँ उभर सकती हैं:

भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित हो सकता है।

बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय कमी संभव है।

नवाचार एवं स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ होगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेगी।

भारत “वैश्विक कौशल केंद्र” (Skill Capital of the World) के रूप में उभर सकता है।

8. निष्कर्ष (Conclusion) –

आत्मनिर्भर भारत पहल भारत के आर्थिक एवं सामाजिक रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल के रूप में उभरकर सामने आई है। यह पहल रोजगार सृजन एवं कौशल विकास के व्यापक अवसर प्रदान करती है, जो देश की मानव पूंजी को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। तथापि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन में विभिन्न संरचनात्मक एवं नीतिगत चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं, जिनका समाधान आवश्यक है।

इस संदर्भ में, सरकार, उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों एवं समाज के मध्य समन्वित एवं सहयोगात्मक प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं। विशेष रूप से, कौशल विकास को रोजगार की वास्तविक मांग से जोड़ना तथा स्थानीय संसाधनों एवं क्षमताओं का प्रभावी

उपयोग करना नीति-निर्माण का केंद्रीय तत्व होना चाहिए।

यदि इन पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया जाए, तो आत्मनिर्भर भारत न केवल आर्थिक स्वावलंबन को सुदृढ़ करेगा, बल्कि समावेशी, सतत एवं संतुलित विकास की दिशा में एक सशक्त मार्ग प्रशस्त करेगा। इस प्रकार, यह पहल भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, सक्षम एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती है।

संदर्भ सूची

1. Government of India- (2020)- Atmanirbhar Bharat Abhiyan% Economic stimulus package- New
2. Delhi% Ministry of Finance-
3. Government of India- (2015)- Skill India Mission Document- New Delhi% Ministry of Skill
4. Development and Entrepreneurship-
5. Government of India- (2014)- Make in India% National manufacturing policy- New Delhi%
6. Ministry of Commerce and Industry-
7. Government of India- (2016)- Startup India Action Plan- New Delhi% Department for Promotion of Industry and Internal Trade-
8. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises- (2021)- Annual Report 2020–21- New
9. Delhi% Government of India-
10. National Skill Development Corporation (NSDC)- (2022)- Human Resource and Skill
11. Requirements in India- New Delhi% NSDC-
12. International Labour Organization- (2020)- India Labour Market Update- Geneva% ILO-
13. World Bank- (2021)- World Development Report 2021% Data for Better Lives- Washington] DC%

उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की भूगोल पाठ्यपुस्तकों में निहित चित्रात्मक सामग्री का विश्लेषणात्मक अध्ययन

सरोज कुमारी – शोधार्थी

डॉ. गौरव सिंह – सह आचार्य

कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय

निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान

सारांश

प्रस्तुत शोध लेख का उद्देश्य उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की भूगोल पाठ्यपुस्तकों में निहित चित्रात्मक सामग्री की शैक्षिक प्रभावशीलता का विश्लेषण करना है। भूगोल विषय मूलतः—श्यात्मक एवं स्थानिक प्रकृति का विषय है, अतः इसके प्रभावी अध्यापन हेतु चित्र, मानचित्र, ग्राफ, तालिकाएँ तथा उपग्रह चित्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। अध्ययन में एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 6 से 10 तक की भूगोल पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया। शोध में विश्लेषणात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया तथा सामग्री विश्लेषण तकनीक के माध्यम से चित्रात्मक सामग्री की उपयोगिता, स्पष्टता, विषयवस्तु से संबंध, शैक्षिक उद्देश्य एवं विद्यार्थियों की अवधारणात्मक स्पष्टता में उसकी भूमिका का अध्ययन किया गया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि उच्च प्राथमिक स्तर पर

चित्रों की संख्या अधिक है, परंतु अनेक चित्र केवल सजावटी स्वरूप के पाए गए। माध्यमिक स्तर पर चित्रात्मक सामग्री अपेक्षाकृत कम किन्तु अधिक जटिल पाई गई। यह भी स्पष्ट हुआ कि विषयवस्तु से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित चित्र, मानचित्र एवं ग्राफ विद्यार्थियों की रुचि, जिज्ञासा तथा विश्लेषणात्मक क्षमता को विकसित करने में सहायक होते हैं। अध्ययन के आधार पर यह सुझाव दिया गया कि भूगोल पाठ्यपुस्तकों में आयु-अनुकूल, उद्देश्यपरक एवं गतिविधि-आधारित चित्रात्मक सामग्री का समावेश किया जाना चाहिए।

मुख्य शब्द – भूगोल शिक्षा, चित्रात्मक सामग्री, मानचित्र, पाठ्यपुस्तक विश्लेषण, शैक्षिक प्रभावशीलता।

प्रस्तावना

शिक्षा मानव विकास का आधारभूत साधन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान अर्जित करने के साथ-साथ अपने सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक परिवेश को समझने की क्षमता विकसित करता है। विद्यालयी शिक्षा में विभिन्न विषयों का अपना विशिष्ट महत्व है, किन्तु भूगोल ऐसा विषय है जो मानव एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, भौतिक संरचनाओं, प्राकृतिक संसाधनों तथा वैश्विक परिस्थितियों का समग्र ज्ञान प्रदान करता

है। भूगोल विषय की प्रकृति मूलतः दृश्यात्मक एवं स्थानिक होती है। पर्वत, नदियाँ, पठार, जलवायु, वनस्पति, जनसंख्या वितरण एवं मानचित्र संबंधी अवधारणाओं को केवल मौखिक अथवा पाठ्य विवरण के माध्यम से स्पष्ट करना कठिन होता है। इस कारण भूगोल शिक्षण में चित्रात्मक सामग्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

चित्रात्मक सामग्री में चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, ग्राफ, तालिकाएँ, चार्ट, उपग्रह चित्र एवं अन्य दृश्य

सामग्री सम्मिलित होती हैं। ये सामग्री विद्यार्थियों की अवधारणात्मक स्पष्टता विकसित करने में सहायता प्रदान करती हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार विद्यार्थी दृश्य अनुभवों को अधिक शीघ्रता एवं स्थायित्व के साथ ग्रहण करते हैं। इसी कारण आधुनिक शिक्षण सिद्धांतों में दृश्य सामग्री को विशेष महत्व प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-2005 तथा नई शिक्षा नीति-2020 में भी अनुभवात्मक एवं दृश्य-आधारित अधिगम पर विशेष बल दिया गया है। इसके बावजूद अनेक भूगोल पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त चित्रात्मक सामग्री केवल सजावटी स्वरूप की दिखाई देती है तथा उसका पाठ्यवस्तु से प्रत्यक्ष संबंध स्पष्ट नहीं होता। कई बार मानचित्र एवं ग्राफ इतने जटिल होते हैं कि विद्यार्थी उन्हें समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति में चित्रात्मक सामग्री का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता।

उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर वह अवस्था है जहाँ विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक सोच एवं अवधारणात्मक विकास तीव्र गति से होता है। यदि इस स्तर पर प्रभावी चित्रात्मक सामग्री का उपयोग किया जाए तो अधिगम अधिक रोचक, स्पष्ट एवं स्थायी बन सकता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन किया गया है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं औचित्य

भूगोल विषय की प्रकृति दृश्यात्मक होने के कारण इसमें चित्रात्मक सामग्री का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा को अधिक प्रभावी, रुचिकर एवं विद्यार्थी-केंद्रित बनाने पर बल दिया जा रहा है। इसके बावजूद विद्यालयी भूगोल पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त चित्रों, मानचित्रों एवं ग्राफों की शैक्षिक गुणवत्ता पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है।

अनेक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि यदि चित्रात्मक सामग्री विषयवस्तु से संबंधित, स्पष्ट एवं आयु-अनुकूल हो तो विद्यार्थियों की अवधारणात्मक

समझ में वृद्धि होती है। दूसरी ओर अस्पष्ट एवं जटिल चित्र विद्यार्थियों में भ्रम उत्पन्न करते हैं। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि भूगोल पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त चित्रात्मक सामग्री की शैक्षिक प्रभावशीलता का विश्लेषण किया जाए।

अध्ययन के उद्देश्य

1. उच्च प्राथमिक स्तर की भूगोल पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त चित्रात्मक सामग्री का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर की भूगोल पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त चित्रात्मक सामग्री का अध्ययन करना।
3. चित्रात्मक सामग्री की स्पष्टता एवं उपयोगिता का अध्ययन करना।
4. चित्रात्मक सामग्री एवं विषयवस्तु के मध्य संबंध का अध्ययन करना।
5. मानचित्रों एवं ग्राफों की शैक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन करना।

शोध प्रश्न

1. क्या भूगोल पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त चित्रात्मक सामग्री विषय को स्पष्ट करने में सहायक है?
2. क्या मानचित्र एवं ग्राफ विद्यार्थियों की स्थानिक समझ विकसित करते हैं?
3. क्या चित्रात्मक सामग्री विद्यार्थियों की रुचि एवं जिज्ञासा को बढ़ाती है?
4. क्या चित्रात्मक सामग्री विद्यार्थियों की आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप है?

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में विश्लेषणात्मक शोध विधि (Analytical Research Method) का प्रयोग किया गया।

न्यादर्श

अध्ययन हेतु एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 6 से 10 तक की भूगोल पाठ्यपुस्तकों का चयन किया गया।

डेटा संग्रहण उपकरण

सामग्री विश्लेषण अनुसूची (Content Analysis Schedule) का उपयोग किया गया।

विश्लेषण की विधि

प्राप्त सामग्री का गुणात्मक एवं तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। चित्रों, मानचित्रों एवं ग्राफों की संख्या, स्पष्टता, उपयोगिता एवं विषयवस्तु से संबंध का अध्ययन किया गया।

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

रेखा शर्मा (2016) ने माध्यमिक स्तर की भूगोल पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त मानचित्रों एवं रेखाचित्रों की शैक्षिक उपयोगिता का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश दृश्य सामग्री सूचना प्रदान करने तक सीमित है तथा विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने में कम सहायक है।

कविता सिंह (2018) ने भूगोल पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त दृश्य सामग्री का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया। अध्ययन में स्पष्ट हुआ कि अधिकांश चित्र निम्न स्तरीय अधिगम उद्देश्यों तक सीमित हैं।

प्रदीप कुमार (2020) ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की भूगोल पाठ्यपुस्तकों का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा पाया कि प्राथमिक स्तर पर चित्रों की संख्या अधिक किन्तु माध्यमिक स्तर पर चित्र अधिक जटिल हैं।

पूजा मिश्रा (2022) ने भूगोल पाठ्यपुस्तकों में दृश्य सामग्री की निरंतरता एवं प्रगतिशीलता का अध्ययन किया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि दोनों स्तरों के मध्य दृश्य सामग्री के विकास में समुचित समन्वय का अभाव है।

विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी 1 : भूगोल पाठ्यपुस्तकों में चित्रात्मक सामग्री का स्वरूप

कक्षा	चित्रों की संख्या	मानचित्र	ग्राफ/चार्ट	स्पष्टता स्तर
6	अधिक	मध्यम	कम	उच्च
7	अधिक	अधिक	कम	उच्च
8	मध्यम	अधिक	मध्यम	अच्छी
9	कम	अधिक	टधिक	मध्यम
10	कम	अधिक	टधिक	जटिल

व्याख्या

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर चित्रों की संख्या अधिक है तथा वे अपेक्षाकृत सरल एवं आकर्षक हैं। माध्यमिक स्तर पर चित्रों की संख्या कम होते हुए भी मानचित्र एवं ग्राफों का प्रयोग अधिक किया गया है। कक्षा 9 एवं 10 में प्रयुक्त अनेक ग्राफ एवं मानचित्र विद्यार्थियों के लिए अपेक्षाकृत जटिल पाए गए।

यह भी पाया गया कि जिन अध्यायों में चित्रात्मक सामग्री विषयवस्तु से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित थी, वहाँ विद्यार्थियों की अवधारणात्मक स्पष्टता अधिक प्रभावी रही।

प्रमुख निष्कर्ष

1. उच्च प्राथमिक स्तर पर चित्रात्मक सामग्री की संख्या अधिक पाई गई।
2. माध्यमिक स्तर पर मानचित्र एवं ग्राफों का प्रयोग अधिक किया गया।
3. अनेक चित्र केवल सजावटी स्वरूप के पाए गए।
4. विषयवस्तु से संबंधित चित्र विद्यार्थियों की समझ विकसित करने में सहायक पाए गए।

5. रंगीन एवं स्पष्ट चित्र विद्यार्थियों की रुचि एवं जिज्ञासा को बढ़ाते हैं।
6. जटिल ग्राफ एवं तकनीकी मानचित्र विद्यार्थियों के लिए कठिन पाए गए।
7. चित्रात्मक सामग्री एवं विषयवस्तु के मध्य समुचित समन्वय आवश्यक है।

सुझाव

1. भूगोल पाठ्यपुस्तकों में उद्देश्यपरक चित्रों का समावेश किया जाए।
2. चित्रात्मक सामग्री विद्यार्थियों की आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए।
3. प्रत्येक मानचित्र एवं ग्राफ के साथ स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए।
4. स्थानीय एवं वास्तविक जीवन से संबंधित चित्रों का प्रयोग बढ़ाया जाए।
5. चित्रों के साथ गतिविधि-आधारित प्रश्नों को सम्मिलित किया जाए।
6. जटिल ग्राफों एवं मानचित्रों को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल, जे.सी. (2007). शैक्षिक तकनीकी तथा प्रबंधन के मूलतत्त्व. आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।
2. कुलश्रेष्ठ, एस.पी. (2005). शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार. आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।
3. शर्मा, आर.ए. (1995). शिक्षा अनुसंधान. मेरठ: सूर्या पब्लिकेशन।
4. श्रीवास्तव, डी.एन. (2006). सांख्यिकी एवं मापन. आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।

उपसंहार

भूगोल शिक्षा में चित्रात्मक सामग्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभावी चित्र, मानचित्र एवं ग्राफ विद्यार्थियों की अवधारणात्मक स्पष्टता, विश्लेषणात्मक क्षमता एवं स्थानिक समझ को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि वर्तमान भूगोल पाठ्यपुस्तकों में चित्रात्मक सामग्री का प्रयोग तो पर्याप्त मात्रा में किया गया है, किन्तु उसकी शैक्षिक प्रभावशीलता में अभी भी सुधार की आवश्यकता है।

यदि चित्रात्मक सामग्री को अधिक उद्देश्यपरक, स्पष्ट, आयु-अनुकूल एवं गतिविधि-आधारित बनाया जाए तो भूगोल शिक्षण अधिक प्रभावी एवं रुचिकर बन सकता है। यह अध्ययन पाठ्यपुस्तक निर्माताओं, शिक्षकों एवं शिक्षा नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी दिशा प्रदान करता है।

5. सिंह, अरुण कुमार (2013). शोध विधियाँ. नई दिल्ली: बनारसी दास।
6. Mishra] P- (2022)- Comparative Study of Visual Content in Geography Teûtbooks- Shodh Pravah] 12(3)] 45&52-
7. Sharma] R- (2016)- Educational Utility of Maps in Geography Teûtbooks- Journal of Educational Studies] 8(2)] 33&40-
8. Singh] K- (2018)- Cognitive Perspective of Visual Learning in Geography Education- Indian Educational Review] 10(1)] 25&31-

शिक्षक शिक्षा एवं कौशल विकास राष्ट्र निर्माण के सशक्त माध्यम

अमित कुमार – शोधार्थी

डॉ. निर्मला सिंह राठौड़, सह आचार्य

मनोविज्ञान विभाग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान निम्स विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य शिक्षक शिक्षा और कौशल विकास के मध्य विद्यमान अपरिहार्य अंतर्संबंधों का अन्वेषण करना है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, जहाँ तकनीकी नवाचार और व्यावहारिक ज्ञान सफलता की कुंजी बन चुके हैं, शिक्षक शिक्षा की भूमिका पारंपरिक ज्ञान के हस्तांतरण से कहीं आगे बढ़ गई है। यह शोध पत्र इस तर्क को पुष्ट करता है कि जब तक शिक्षक स्वयं विभिन्न कौशलों (तकनीकी, क्रियात्मक और

सामाजिक) में दक्ष नहीं होंगे, तब तक वे ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण नहीं कर सकते जो राष्ट्र निर्माण में प्रभावी योगदान दे सके। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के संदर्भ में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

मुख्य शब्द— राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शैक्षिक प्रासंगिकता, कौशल, स्व-रोजगार और उद्यमिता।

1. प्रस्तावना

राष्ट्र निर्माण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका केंद्र बिंदु शिक्षा है। किसी भी राष्ट्र की नियति का निर्धारण उसकी कक्षाओं में होता है, और उन कक्षाओं का सारथी शिक्षक होता है। प्राचीन भारत में गुरु केवल ज्ञान का स्रोत नहीं था, बल्कि वह जीवन जीने की कला और विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षक भी था। कालांतर में शिक्षा पद्धति सैद्धांतिक होती गई, जिससे स्नातक तो तैयार हुए परंतु उनमें कौशल का अभाव रहा। वर्तमान में भारत जनसांख्यिकीय लाभांश के दौर से गुजर रहा है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। इस ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण की शक्ति में बदलने के लिए कौशल विकास एकमात्र मार्ग है। यहाँ शिक्षक शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक शिक्षक ही वह माध्यम है जो विद्यार्थी के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानकर उसे सही दिशा दे सकता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में शिक्षक शिक्षा और कौशल विकास एक ही सिक्के के दो पहलू बन

चुके हैं। आज के शिक्षक की भूमिका केवल कक्षा में व्याख्यान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में विकसित हो रहा है जो छात्रों के भीतर निहित क्षमताओं को पहचानकर उन्हें निखारता है। जैसा कि कहा गया है कि शिक्षण केवल ज्ञान का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि यह सीखने की ललक पैदा करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आगमन के साथ, शिक्षक प्रशिक्षण में व्यावहारिक कौशल को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। एक शिक्षक तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक वह डिजिटल साक्षरता, रचनात्मक सोच और संचार कौशल में दक्ष न हो। विशेष रूप से सूक्ष्म-शिक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा का एकीकरण शिक्षक प्रशिक्षुओं को केवल डिग्री धारक नहीं, बल्कि एक कुशल शिल्पकार बनाता है।

शिक्षण की गुणवत्ता सीधे तौर पर शिक्षक के कौशल उन्नयन पर निर्भर करती है। यदि शिक्षक स्वयं को निरंतर तकनीकी और शैक्षणिक बदलावों के अनुरूप ढालता रहता है, तो वह छात्रों में

जिज्ञासा और नवाचार की प्रवृत्ति विकसित कर सकता है। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू ने ठीक ही कहा था जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, वे उन्हें पैदा करने वालों से अधिक सम्मान के पात्र हैं क्योंकि माता-पिता ने तो केवल जीवन दिया है, पर शिक्षकों ने उसे जीने की कला सिखाई है। अतः, शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कार्यशालाओं, श्री-डी मॉडल्स के प्रयोग और अनुसंधान-परक शिक्षण को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। अंततः, कौशल-युक्त शिक्षक ही एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकता है जो न केवल शिक्षित हो, बल्कि स्वावलंबी और राष्ट्र निर्माण में सक्षम भी हो। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कुशल शिक्षक, विकसित राष्ट्र की नींव है।

2. शिक्षक शिक्षा का बदलता स्वरूप और कौशल विकास

शिक्षक शिक्षा केवल बी.एड. या डी.एल.एड. की डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसे एक व्यावसायिक दक्षता कार्यक्रम के रूप में देखा जाना चाहिए।

2.1. शिक्षक एक कौशल प्रदाता के रूप में :- शिक्षक को अब सूचना प्रदाता के स्थान पर एक सुगमकर्ता और प्रशिक्षक की भूमिका निभानी है। कौशल विकास का अर्थ केवल मशीनों पर काम करना नहीं है, बल्कि इसमें निम्नलिखित कौशल शामिल हैं।

1. संज्ञानात्मक कौशल आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान।

2. तकनीकी कौशल डिजिटल उपकरणों और आधुनिक शिक्षण विधियों का ज्ञान।

3. अंतर्व्यक्तिक कौशल संवाद, नेतृत्व और सहानुभूति।

2.2 शिक्षण में नवाचार 3डी और कार्यकारी मॉडल: शिक्षक शिक्षा में सबसे बड़ा परिवर्तन 'क्रियात्मक शिक्षण' से आना चाहिए। इतिहास जैसे सैद्धांतिक विषयों में भी कौशल विकास संभव है। उदाहरण के लिए - इतिहास हड़प्पा सभ्यता को पढ़ाते समय यदि शिक्षक विद्यार्थियों से मृदभांड या नगर

नियोजन का त्रिविमीय (3डी) मॉडल बनवाता है, तो यह केवल इतिहास की समझ नहीं बढ़ाता, बल्कि विद्यार्थी के भीतर वास्तुशिल्प और कलात्मक कौशल का विकास भी करता है। तकनीकी अनुप्रयोग परशियन व्हील या प्राचीन सिंचाई प्रणालियों के कार्यकारी मॉडल बनाने से विद्यार्थियों को यांत्रिक इंजीनियरिंग के मूल सिद्धांतों की समझ विकसित होती है।

3. कौशल विकास के विविध आयाम और शिक्षक की भूमिका

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन की सफलता पूर्णतः शिक्षकों की दक्षता पर टिकी है।

3.1 डिजिटल साक्षरता और तकनीकी एकीकरण- आज का शिक्षक ब्लैकबोर्ड से स्मार्टबोर्ड के युग में प्रवेश कर चुका है। डिजिटल साक्षरता अब एक विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में कोडिंग, डेटा विश्लेषण और एआई के बुनियादी ज्ञान को शामिल किया जाना चाहिए ताकि शिक्षक विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर सकें।

3.2 व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्पष्ट रूप से कहती है कि कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। इसके लिए शिक्षकों को स्वयं बढ़ईगीरी, बागवानी, बिजली का काम या स्थानीय हस्तशिल्प जैसे कार्यों का सम्मान करना और उनके बुनियादी सिद्धांतों को सिखाना आना चाहिए।

4. राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति और शिक्षक का दायित्व

राष्ट्र निर्माण केवल सीमाओं की रक्षा या आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि यह एक सुदृढ़ समाज के निर्माण की प्रक्रिया है। आत्मनिर्भर भारत जब शिक्षक विद्यार्थियों को स्व-रोजगार और उद्यमिता के लिए प्रेरित करते हैं, तो वे देश की बेरोजगारी की समस्या को जड़ से खत्म करने में योगदान देते हैं। सामाजिक समरसता कौशल विकास युवाओं में आत्मविश्वास भरता है। एक आत्मविश्वासी युवा ही सामाजिक कुरीतियों के

विरुद्ध खड़ा हो सकता है और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकता है। नवाचार और शोध शिक्षक को विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। शोध-उन्मुख शिक्षा ही भारत को वैश्विक स्तर पर नवाचार केंद्र बना सकती है।

5. चुनौतियाँ सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई

भारत में शिक्षक शिक्षा और कौशल विकास के मार्ग में कई बाधाएँ हैं—

1. संसाधनों का अभाव :— विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक प्रयोगशालाओं और इंटरनेट की कमी है।
2. पारंपरिक मानसिकता :— अभी भी समाज में डिग्री को कौशल से अधिक महत्व दिया जाता है।
3. मूल्यांकन पद्धति :— हमारी परीक्षा प्रणाली अभी भी रटने की क्षमता पर आधारित है, जो कौशल विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है।

6. समाधान और भविष्य की राह

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय. (2026). वार्षिक प्रतिवेदन 2025–26. भारत सरकार।
2. कुमार, ए. (2024). आधुनिक भारत में कौशल विकास और उद्यमिता राजकमल प्रकाशन।
3. गुप्त, एस., एवं वर्मा, आर. (2023). शिक्षक प्रशिक्षण में नवाचार और 3डी मॉडल की उपयोगिता. शिक्षण शोध पत्रिका, 15(2), ।
4. पांडेय, एम. (2025). डिजिटल साक्षरता और शिक्षक शिक्षा का भविष्य. हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
5. भारत सरकार. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. शिक्षा मंत्रालय।
6. यशपाल, प्रो. (1993). शिक्षा बिना बोझ के. प्रो. यशपाल समिति की रिपोर्ट. मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
7. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (2023). व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण एक मार्गदर्शिका. प्रकाशन।
8. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (2021). शिक्षक शिक्षा हेतु नवीन पाठ्यचर्या की रूपरेखा. भारत सरकार।
9. वशिष्ठ, के. (2024). आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में शिक्षकों का योगदान. कौशल विकास विमर्श, 8(1)।
10. शर्मा, पी. (2022). भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक शिक्षण विधियाँ. राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।

निरंतर व्यावसायिक विकास शिक्षकों के लिए समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन होना चाहिए जहाँ वे नए कौशलों को सीख सकें। उद्योग-अकादमिक समन्वय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को स्थानीय उद्योगों के साथ समझौता करना चाहिए ताकि प्रशिक्षु शिक्षक वास्तविक कार्य वातावरण को समझ सकें। प्रायोगिक मूल्यांकन परीक्षाओं में 70 प्रतिशत भार क्रियात्मक कार्यों, मॉडल निर्माण और शोध परियोजनाओं को दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

शिक्षक शिक्षा वह नींव है जिस पर राष्ट्र की भव्य इमारत खड़ी होती है। यदि हम शिक्षक को कौशल-संपन्न और नवाचारी बनाते हैं, तो हम स्वतः ही एक ऐसी युवा पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो न केवल आत्मनिर्भर होगी, बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ योगदान देगी। शिक्षक केवल विषय नहीं पढ़ाता, वह भविष्य गढ़ता है। कौशल विकास के माध्यम से शिक्षक शिक्षा को सशक्त बनाना ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने का एकमात्र विकल्प है।

भारत में शिक्षक शिक्षा में कौशल विकास की संभावनाएँ

डॉ. मुकेश कुमार शर्मा

सह आचार्य

शिक्षा विभाग, जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान

सारांश

वर्तमान वैश्विक एवं ज्ञान-आधारित समाज में शिक्षा की गुणवत्ता सीधे शिक्षक की दक्षताओं पर निर्भर करती है। भारत में शिक्षक शिक्षा को कौशल-उन्मुख बनाने की आवश्यकता इसलिए बढ़ी है क्योंकि पारंपरिक, केवल सैद्धांतिक प्रशिक्षण बदलती कक्षा-परिस्थितियों, विविध शिक्षार्थी आवश्यकताओं तथा डिजिटल वातावरण की चुनौतियों का पर्याप्त समाधान नहीं कर पाता। इस शोध पत्र में शिक्षक शिक्षा में कौशल विकास की संभावनाओं का विश्लेषण द्वितीयक स्रोतों—जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सरकारी रिपोर्ट्स तथा समकालीन शोध अध्ययनों के आधार पर किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि डिजिटल साक्षरता, अनुभवात्मक अधिगम, संप्रेषण एवं जीवन कौशल, समावेशी शिक्षण, मूल्यांकन-कौशल तथा अनुसंधान-आधारित दृष्टिकोण को प्रशिक्षण में

समाहित करने से शिक्षण-प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। DIKSHA, SWAYAM और NISHTHA जैसे प्लेटफॉर्म इस दिशा में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं, किंतु अवसंरचना की कमी, प्रशिक्षकों की क्षमता-वृद्धि और ग्रामीण-शहरी अंतर जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। निष्कर्षतः यदि नीति-स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन, सतत व्यावसायिक विकास और संस्थागत-उद्योग सहयोग को सुदृढ़ किया जाए, तो शिक्षक शिक्षा में कौशल विकास के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के लक्ष्यों को अधिक सशक्त ढंग से प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य शब्द — शिक्षक शिक्षा, कौशल विकास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षण-प्रभावशीलता, नवाचार, शिक्षा गुणवत्ता, राष्ट्र निर्माण।

प्रस्तावना

भारत एक युवा एवं उभरती हुई ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था है, जहाँ शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक प्रगति तथा राष्ट्रीय विकास का प्रमुख साधन माना जाता है। इस संदर्भ में शिक्षक की भूमिका अत्यंत केंद्रीय एवं निर्णायक होती है, क्योंकि वह शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का संचालक और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण का प्रमुख मार्गदर्शक होता है। वर्तमान वैश्वीकरण, डिजिटलीकरण एवं ज्ञान-विस्फोट के युग में शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, जिसके कारण पारंपरिक शिक्षण पद्धतियाँ अब पर्याप्त नहीं रह गई हैं। आज शिक्षा केवल विषय-वस्तु के ज्ञान

तक सीमित न रहकर कौशल, मूल्यों, नवाचार और जीवनोपयोगी दक्षताओं के विकास पर केंद्रित हो गई है।

इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षक शिक्षा को भी पुनर्संरचित करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए शिक्षक शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, कौशल-आधारित, बहुआयामी और समावेशी बनाने पर विशेष बल दिया है। नई नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों को केवल विषय विशेषज्ञ ही नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से दक्ष, नवाचारी, संवेदनशील एवं शोध-उन्मुख पेशेवर के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में डिजिटल साक्षरता, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, संप्रेषण कौशल, सहयोगात्मक अधिगम तथा समावेशी शिक्षण जैसी क्षमताओं को समाहित करना अनिवार्य हो गया है।

वर्तमान में भारत में DIKSHA, SWAYAM, NISHTHA जैसे प्लेटफॉर्म शिक्षक शिक्षा में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी माध्यम के रूप में उभर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण, संसाधन एवं नवाचारी शिक्षण विधियों तक पहुँच प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, अनुभवात्मक अधिगम, इंटरनशिप, माइक्रो-टीचिंग तथा विद्यालय आधारित प्रशिक्षण भी शिक्षक कौशल विकास के महत्वपूर्ण साधन हैं। हालाँकि, इन प्रयासों के बावजूद शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जैसे—प्रशिक्षण की गुणवत्ता में असमानता, संसाधनों की कमी, ग्रामीण-शहरी विभाजन तथा तकनीकी अवसंरचना की सीमाएँ। इन चुनौतियों के समाधान के बिना कौशल विकास के लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः शिक्षक शिक्षा में कौशल विकास की संभावनाओं, चुनौतियों एवं सुधारात्मक उपायों का सम्यक अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुत शोध पत्र इन्हीं आयामों का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि किस प्रकार कौशल-आधारित शिक्षक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी, समावेशी और राष्ट्र निर्माण में सहायक बनाया जा सकता है।

शिक्षक शिक्षा में कौशल विकास का अर्थ

शिक्षक शिक्षा में कौशल विकास का तात्पर्य उन व्यावहारिक, पेशेवर एवं जीवनोपयोगी दक्षताओं के विकास से है, जो एक शिक्षक को प्रभावी, नवाचारी एवं शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षण करने में सक्षम बनाती हैं। इसमें केवल विषय-ज्ञान ही नहीं, बल्कि संप्रेषण कौशल, कक्षा-प्रबंधन, मूल्यांकन तकनीक, डिजिटल साक्षरता,

समस्या-समाधान क्षमता तथा समावेशी दृष्टिकोण जैसे बहुआयामी कौशल सम्मिलित होते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक को तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हुए विविध शिक्षण विधियों—जैसे अनुभवात्मक अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम और परियोजना-आधारित अधिगम को अपनाना आवश्यक है। कौशल विकास की यह प्रक्रिया सतत होती है, जो प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव के माध्यम से विकसित होती है। अतः शिक्षक शिक्षा में कौशल विकास का उद्देश्य ऐसे सक्षम, संवेदनशील एवं उत्तरदायी शिक्षकों का निर्माण करना है, जो बदलती शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढाल सकें और विद्यार्थियों के समग्र विकास में प्रभावी योगदान दे सकें।

शिक्षक शिक्षा में कौशल विकास की आवश्यकता:

वर्तमान शैक्षिक परिवेश में शिक्षक शिक्षा में कौशल विकास की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। बदलती शिक्षा प्रणाली, तकनीकी प्रगति तथा विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के कारण शिक्षकों को बहुआयामी दक्षताओं से सुसज्जित होना आवश्यक है। इस आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है—

1. **डिजिटल दक्षता की आवश्यकता**— आधुनिक शिक्षण में ई-लर्निंग, स्मार्ट कक्षाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग के लिए डिजिटल कौशल आवश्यक है।
2. **समावेशी शिक्षण की अनिवार्यता**— विविध सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए समावेशी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।
3. **नवाचारी शिक्षण विधियाँ**— विद्यार्थियों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्या-समाधान क्षमता विकसित करने के लिए नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक है।

4. **प्रभावी संप्रेषण कौशल**— शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सशक्त संवाद स्थापित करने हेतु संप्रेषण कौशल का विकास आवश्यक है।
5. **कक्षा प्रबंधन कौशल**— अनुशासन बनाए रखने तथा सकारात्मक अधिगम वातावरण तैयार करने के लिए कक्षा प्रबंधन कौशल महत्वपूर्ण है।
6. **सतत मूल्यांकन की क्षमता**— विद्यार्थियों की प्रगति का समुचित आकलन करने हेतु विविध मूल्यांकन तकनीकों का ज्ञान आवश्यक है।
7. **नीति आधारित आवश्यकताएँ**— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कौशल-आधारित शिक्षक शिक्षा पर विशेष बल दिया है, जो इसकी आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट करता है।

अतः स्पष्ट है कि शिक्षक शिक्षा में कौशल विकास शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

भारत में कौशल विकास की वर्तमान स्थिति

भारत में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार और पहलें की गई हैं, जिनका उद्देश्य कौशल-आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। वर्तमान स्थिति को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है—

1. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव**— शिक्षक शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, समग्र और कौशल-आधारित बनाने पर विशेष बल दिया गया है।
2. **डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास**— DIKSHA प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षकों को ई-सामग्री, प्रशिक्षण एवं डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
3. **ऑनलाइन शिक्षण पहल**— SWAYAM पोर्टल के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान की जा रही है।

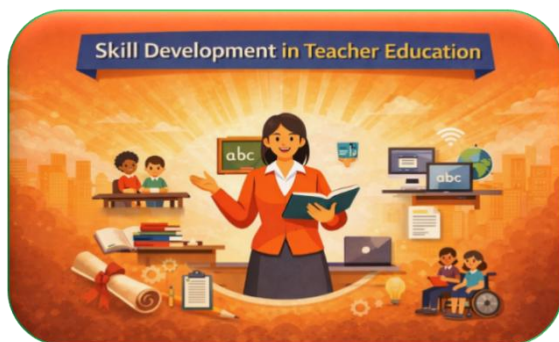
4. **प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन**— NISHTHA कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों के समग्र विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
5. **डिजिटल जागरूकता में वृद्धि**— शिक्षकों में तकनीकी कौशल और डिजिटल उपयोग की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी गई है।

इन पहलों के बावजूद अभी भी कौशल आधारित प्रशिक्षण की कमी, व्यावहारिक अनुभव का अभाव तथा प्रशिक्षण संस्थानों में असमानता जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं।

शिक्षक शिक्षा में कौशल विकास की संभावनाएँ:

भारत में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कौशल विकास की व्यापक संभावनाएँ विद्यमान हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और शिक्षण को अधिक प्रभावी, समावेशी एवं आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बदलते शैक्षिक परिदृश्य, तकनीकी प्रगति तथा नीतिगत समर्थन के कारण इस क्षेत्र में अनेक नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। इन संभावनाओं को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है—

1. **डिजिटल कौशल का विस्तार**— डिजिटल तकनीकों जैसे स्मार्ट बोर्ड, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल कक्षाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से शिक्षकों की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। यह शिक्षण को अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाता है।
2. **अनुभवात्मक अधिगम**— शिक्षक प्रशिक्षण में इंटर्नशिप, माइक्रो-टीचिंग, प्रोजेक्ट वर्क और केस स्टडी के माध्यम से व्यावहारिक कौशल विकसित किए जा सकते हैं, जिससे शिक्षण अधिक वास्तविक और परिणामोन्मुख बनता है।
3. **जीवन कौशल एवं सॉफ्ट स्किल्स**— संप्रेषण कौशल, नेतृत्व, टीमवर्क, समय प्रबंधन और भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे कौशलों का विकास शिक्षक को अधिक प्रभावी बनाता है।



4. **समावेशी शिक्षा की संभावनाएँ**— विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, विविध भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण की नई विधियाँ विकसित की जा सकती हैं।
5. **अनुसंधान और नवाचार**— शिक्षक शिक्षा में शोध को बढ़ावा देकर नवीन शिक्षण विधियों और रणनीतियों का विकास किया जा सकता है, जिससे शिक्षा प्रणाली में निरंतर सुधार संभव है।
6. **नीतिगत समर्थन**— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा अन्य सरकारी योजनाएँ शिक्षक शिक्षा में कौशल विकास को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे संस्थागत स्तर पर सुधार की संभावनाएँ बढ़ती हैं।
7. **सतत व्यावसायिक विकास**— शिक्षकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन कार्यक्रम उनके ज्ञान और दक्षता को अद्यतन बनाए रखते हैं।
8. **उद्योग-शिक्षा समन्वय**— शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग से शिक्षकों को व्यावहारिक और रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान किए जा सकते हैं।

उपर्युक्त संभावनाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि यदि शिक्षक शिक्षा में कौशल विकास को व्यवस्थित रूप से लागू किया जाए, तो यह न केवल शिक्षकों की दक्षता को बढ़ाएगा, बल्कि विद्यार्थियों के समग्र विकास और राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन

संभावनाओं का प्रभावी उपयोग करते हुए शिक्षक शिक्षा को अधिक प्रासंगिक, व्यावहारिक और भविष्य उन्मुख बनाया जाए।

शिक्षक शिक्षा में कौशल विकास की प्रमुख चुनौतियाँ

शिक्षक शिक्षा में कौशल विकास को प्रभावी रूप से लागू करने में कई संरचनात्मक एवं व्यावहारिक चुनौतियाँ सामने आती हैं, जो इसकी गुणवत्ता और पहुँच को प्रभावित करती हैं। प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं—

1. **संसाधनों की कमी**— अनेक प्रशिक्षण संस्थानों में पर्याप्त वित्तीय, तकनीकी एवं भौतिक संसाधनों का अभाव है, जिससे गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्रभावित होता है।
2. **प्रशिक्षित संकाय का अभाव**— कौशल-आधारित प्रशिक्षण देने के लिए सक्षम एवं अद्यतन ज्ञान वाले प्रशिक्षकों की कमी देखी जाती है।
3. **ग्रामीण-शहरी असमानता**— ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट, उपकरणों और प्रशिक्षण सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के कारण अवसरों में अंतर बना रहता है।
4. **पारंपरिक शिक्षण पद्धतियाँ**— कई संस्थानों में अभी भी रटने-आधारित और व्याख्यान-केंद्रित पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जो कौशल विकास में बाधा बनती हैं।
5. **तकनीकी अवसंरचना की सीमाएँ**— डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के लिए आवश्यक अवसंरचना का अभाव कौशल विकास की गति को धीमा करता है।
6. **निरंतर प्रशिक्षण का अभाव**— सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की सीमितता के कारण शिक्षकों का कौशल अद्यतन नहीं हो पाता।

अतः इन चुनौतियों का समाधान नीति-स्तर, संस्थागत प्रयासों तथा संसाधनों के समुचित

प्रबंधन के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, ताकि शिक्षक शिक्षा में कौशल विकास को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकें।

महत्वपूर्ण सुझाव:

शिक्षक शिक्षा में कौशल विकास को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए बहु-स्तरीय और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। निम्नलिखित सुझाव इस दिशा में मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं—

1. **पाठ्यक्रम का पुनर्गठन**— शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यावहारिक, कौशल-आधारित और शिक्षार्थी-केंद्रित तत्वों को समुचित स्थान दिया जाए।
2. **डिजिटल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण**— सभी प्रशिक्षण संस्थानों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, उच्च गुणवत्ता की इंटरनेट सुविधा, उपकरण और ई-लर्निंग संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ।
3. **संकाय विकास कार्यक्रम**— प्रशिक्षकों के लिए नियमित उन्नयन और पुनःप्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएँ, ताकि वे आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से अद्यतन रहें।
4. **अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा**— इंटर्नशिप, माइक्रो-टीचिंग, स्कूल-आधारित प्रशिक्षण और केस-स्टडी को अनिवार्य एवं मूल्यांकन-सम्बद्ध बनाया जाए।
5. **सतत व्यावसायिक विकास**— कार्यरत शिक्षकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण, मेंटरिंग और ऑनलाइन मॉड्यूल उपलब्ध कराए जाएँ, जिससे कौशल अद्यतन बना रहे।
6. **उद्योग-शिक्षा सहयोग**— शैक्षिक संस्थानों और उद्योग/एड-टेक संगठनों के बीच साझेदारी विकसित की जाए, ताकि व्यवहारिक और तकनीकी कौशलों का समावेश हो सके।
7. **प्रभावी क्रियान्वयन और मूल्यांकन**— नीतियों और योजनाओं (जैसे— NEP 2020, NISHTHA, DIKSHA) का समयबद्ध क्रियान्वयन और

परिणाम-आधारित मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाए।

अंततः, इन सुझावों के समन्वित कार्यान्वयन से शिक्षक शिक्षा में कौशल विकास को गति मिलेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में स्थायी सुधार संभव होगा।

निष्कर्ष

भारत में शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में कौशल विकास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक बन चुकी है। वर्तमान युग में शिक्षा केवल ज्ञानार्जन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों के समग्र विकास पर केंद्रित है, जिसमें— बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं व्यावसायिक आयाम शामिल हैं। इस परिवर्तनशील परिदृश्य में शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक, नवाचारी एवं सुगमकर्ता के रूप में विकसित हुई है, जिसके लिए आवश्यक है कि उसे विविध कौशलों से सुसज्जित किया जाए।

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत में शिक्षक शिक्षा को कौशल-आधारित बनाने की दिशा में कई सकारात्मक पहलें की गई हैं, जैसे— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, DIKSHA, SWAYAM और NISHTHA जैसे कार्यक्रम। इन पहलों ने शिक्षकों के प्रशिक्षण को अधिक सुलभ, लचीला और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया है। साथ ही, अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल साक्षरता, समावेशी शिक्षण और सतत व्यावसायिक विकास जैसे आयामों ने शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा प्रदान की है।

हालाँकि, संसाधनों की कमी, ग्रामीण-शहरी असमानता, पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों का प्रभाव तथा प्रशिक्षित संकाय का अभाव जैसी चुनौतियाँ अभी भी इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। इन चुनौतियों के समाधान हेतु आवश्यक है कि नीति-स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन, संस्थागत सुधार तथा आधुनिक तकनीकों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

अंततः यह कहा जा सकता है कि यदि शिक्षक शिक्षा में कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाए और इसे व्यवस्थित रूप से लागू किया जाए, तो यह न केवल शिक्षकों की दक्षता को बढ़ाएगा, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा राष्ट्र

निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस प्रकार, कौशल-आधारित शिक्षक शिक्षा एक सशक्त, समावेशी और प्रगतिशील भारत के निर्माण की आधारशिला सिद्ध हो सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. नई दिल्ली: भारत सरकार।
2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT). (2021). *शिक्षक शिक्षा पर रिपोर्ट*. नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC). (2021). *वार्षिक रिपोर्ट*. नई दिल्ली।
4. विश्व बैंक. (2020). *कौशल और रोजगार पर विश्व विकास रिपोर्ट*. वाशिंगटन डीसी।
5. यूनेस्को. (2019). *शिक्षक शिक्षा और कौशल विकास रिपोर्ट*. पेरिस।
6. योजना आयोग. (2014). *भारत में कौशल विकास पर रिपोर्ट*. नई दिल्ली।
7. DIKSHA. (2021). *डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म रिपोर्ट*. भारत सरकार।
8. SWAYAM. (2020). *ऑनलाइन शिक्षा पहल रिपोर्ट*. भारत सरकार।
9. NISHTHA. (2019). *शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट*. शिक्षा मंत्रालय।
10. शर्मा, आर. (2018). *शिक्षक शिक्षा में नवाचार*. नई दिल्ली: प्रकाशन।
11. सिंह, एम. (2019). *शिक्षा और कौशल विकास*. जयपुर: प्रकाशन।
12. कुमार, ए. (2020). *डिजिटल शिक्षा और शिक्षक*. दिल्ली: प्रकाशन।
13. गुप्ता, पी. (2017). *आधुनिक शिक्षण विधियाँ*. लखनऊ: प्रकाशन।
14. अग्रवाल, एस. (2016). *शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग*. दिल्ली: प्रकाशन।
15. मिश्रा, डी. (2021). *शिक्षक प्रशिक्षण और विकास*. वाराणसी: प्रकाशन।

माध्यमिक स्तर के अध्यापकों में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं दृष्टिकोण का अध्ययन

डॉ. छैलबिहारी

सहायक आचार्य

महात्मा गांधी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, महवा, दौसा, राजस्थान

सारांश

शिक्षा का मानव सभ्यता के उत्कर्ष में सर्वाधिक योगदान है किन्तु सभ्यता के विकास की इस राह में कई बाधाएं और समस्याएं आती हैं और मानव ने विभिन्न प्रकार की विधियों से उनका समाधान किया है। वर्तमान में शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावशाली अनुसंधान एक प्रक्रिया है। जिसमें प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान ज्ञात किया जाता है जिसके द्वारा मानवीय ज्ञान में वृद्धि की जाती है और मानव जीवन को सुगम बनाया जाता है।

शिक्षा के संदर्भ समावेश का अर्थ विद्यालय की ऐसी पुनर्संरचना से है जिसमें विद्यालय सभी समुदायों का एक केन्द्र है और जहाँ सभी प्रकार के बालक शिक्षा ग्रहण कर सकें। एक ऐसा विद्यालय जहाँ शिक्षक, शिक्षार्थी को सीखने के विभिन्न अवसर प्रदान करें। परन्तु समावेशी शिक्षक व समावेशी विद्यालय बनाने का कोई प्रभावीकृत प्रावधान नहीं है। समावेशी शिक्षा के मूल में अच्छा

शिक्षण, अभ्यास, शिक्षक-शिक्षार्थी के मध्य अच्छे संबंध, कक्षा के सभी बालकों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा बालको का विभिन्न प्रकार से सर्वांगीण विकास में सहायता करना है। समावेशी शिक्षा दर्शन में उपर्युक्त गुणों का समावेश है। कक्षा में सभी बालकों का प्रदर्शन तभी अच्छा हो सकता है जब कक्षा समायोजन इस तरह किया गया हो कि सभी प्रकार के बालको की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखा गया हो। सभी को समान अवसर सभी को पूर्ण भागीदारी, समावेशी शिक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक बच्चों की भागीदारी न हो और समान अवसर दिये जायेंगे। समावेशी शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है जिसके अन्तर्गत वे सभी बच्चे आयेंगे जो हाशिए पर होते हैं, जिनको अगर देखभाल न की गई तो वह शिक्षा व्यवस्था से बाहर चले जायेंगे।

मुख्य शब्द – समावेशी शिक्षा, पुनर्संरचना सर्वांगीण विकास, भागीदारी, समान अवसर।

प्रस्तावना

“सा विद्या या विमुक्तये”

– शंकराचार्य

अर्थात् विद्या (शिक्षा) वह है जो मुक्ति दिलाए, मुक्ति अज्ञानता से हृदय की कठोरता से कर्मेन्द्रियों को अकर्मण्यता से इत्यादि। शिक्षा सीखने-सिखाने की प्रक्रिया है। नया ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा है। सदगुणों का विकास शिक्षा है। योग्य नागरिक

बनाना शिक्षा है। मनुष्य को ‘मनुष्य’ बनाना शिक्षा है।

यदि हम सरल शब्दों में कहना चाहें तो शिक्षा का अर्थ है – बालक की जन्मजात शक्तियों या गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करना, न कि उसके मस्तिष्क में ज्ञान को जागृत करना।

‘शिक्षा’ के लिए विद्या एवं ज्ञान शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा ‘शिक्ष’ से बना है जिसका अर्थ सीखना और सिखाना। ‘विद्या’ की अभिप्राय है जानना। ‘ज्ञान’ भी जानने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार नया ज्ञान, कुछ जानना ‘शिक्षा’ है।

फ्रॉबेल के अनुसार – “शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती है।”

अरस्तु के अनुसार – “शिक्षा वह है जो शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है।

समावेशी शिक्षा की पृष्ठभूमि

शिक्षा मानव की समस्त स्वभाविक शक्तियों का पूर्ण प्रगतिशील विकास है। अतः शिक्षा अर्जन करने वाला बालक सामान्य हो या विशेष आवश्यकता वाले, उसको शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त होना न्याय संगत है। इस उद्देश्य की पूर्ति के पूरक कार्यक्रम के रूप में सन् 1975 में समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार ने समेकित शिक्षा योजना (आई.ई.डी.एस.) प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत सामान्य विद्यालय में पढ़ने वालों विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को छात्रवृत्ति व अतिरिक्त सुविधा दी गई तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए अतिरिक्त सुविधा भत्ते का प्रावधान किया गया।

विशेष बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के मद्देनजर विशिष्ट शैक्षिक सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं 18 वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका और फ्रांस के आंदोलनों को अनुसरण करते हुये दृष्टिहीने या श्रवण सम्बन्धी समस्या के बच्चों के लिए शिक्षण के प्रभावी तरीके खोजे गये। 19 वीं शताब्दी के प्रारंभ में पहली बार क्रमबद्ध तरीके से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास किये गये। आंदोलन के पूर्व के युग में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सम्मान के साथ जीवन यापन नहीं कर सकते थे। परंतु जैसे ही लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि के विचार अमेरिका और फ्रांस में जोर पकड़ने लगे, तो इस तरह की प्रवृत्ति

में बदलाव आया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और युवाओं को कुछ विशेष क्षेत्रों व क्षमताओं में राजनीतिक सुधारक और राजनेताओं ने शिक्षा और स्वास्थ्य में कुशल बनाकर उन्हें स्वतंत्र और शिक्षित नागरिक बनाया जा सकता है।

शोध समस्या का अभिकथन

“भरतपुर जिले के माध्यमिक स्तर के अध्यापकों में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं दृष्टिकोण का अध्ययन”।

शोध समस्या में प्रयुक्त शब्दावली का परिभाषीकरण

समावेशन – समावेशन से तात्पर्य है कि विद्यालयों और समुदायों का पुनर्गठन जिसे सभी बच्चे एक समान वातावरण में बिना किसी भेदभाव के सीख पायें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित सभी प्रकार के बच्चों को उनके निवास स्थान के निकट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान केवल पृथक्करण के स्थान पर समावेश के दर्शन को अपनाने से ही संभव हो सकता है। अतः समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक स्कूल अपने छात्रों की सभी प्रकार की सीखने, शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है।

समावेशी शिक्षा – समावेशी स्कूल या सेटअप को एक ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहाँ हर कोई शामिल होता है, स्वीकार किया जाता है, समर्थन करता है और उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के दौरान उसके साथियों और स्कूल समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा सम्मानित किया जाता है।

शोध समस्या से उभरने वाले प्रश्न

- समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों में जागरूकता का स्तर कितना है ?
- समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों का दृष्टिकोण कैसा है?
- सामान्य कक्षा में विविध आवश्यकताओं वाले बच्चों को कैसे समायोजित किया जाए?

- समावेशी शिक्षा का दृष्टिकोण सभी के लिए सर्वांगीण विकासात्मक शिक्षा होना चाहिए?

शोध अध्ययन के उद्देश्य

- माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्यापनरत् अध्यापकों में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्यापनरत् सामान्य अध्यापक एवं विशेष अध्यापकों में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्यापनरत् पुरुष एवं महिला अध्यापकों में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्यापनरत् ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ

प्रस्तुत शोध अध्ययन की निम्न शून्य परिकल्पनाएँ निर्धारित की गयी हैं—

- H01. माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्यापनरत् महिला एवं पुरुष अध्यापकों में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता के स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- H02. माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्यापनरत् महिला एवं पुरुष अध्यापकों में समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- H03. माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्यापनरत् ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता के स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- H04. माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्यापनरत् ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों में समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध समस्या का परिसीमन

प्रस्तुत शोधकार्य का अध्ययन क्षेत्र अधिक विस्तृत किया जा सकता है लेकिन समय एवं श्रम की बचत के लिए अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध अध्ययन में भरतपुर जिले के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का चयन किया गया।

- प्रस्तुत शोध अध्ययन में 400 सामान्य एवं विशेष शिक्षा अध्यापकों का न्यादर्श के रूप में चयन किया गया है।
- प्रस्तुत शोध में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्यापनरत् महिला एवं पुरुष अध्यापकों का चयन किया गया है।
- प्रस्तुत शोध में माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है।
- प्रस्तुत शोध में माध्यमिक स्तर के ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत अध्यापकों का चयन किया गया है।

प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है किसी भी क्षेत्र में जैसे आर्थिक, सामाजिक या शैक्षिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए तत्कालीन परिस्थिति की जानकारी होना अत्यन्त आवश्यक है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के चर

- स्वतंत्र चर— समावेशी माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्यापनरत् अध्यापक सभी स्वतंत्र चर हैं।
- आश्रित चर — प्रस्तुत शोध अध्ययन में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं दृष्टिकोण का अध्ययन करना आश्रित चर हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी

- मध्यमान
- प्रमाप विचलन
- टी (t) परीक्षण

प्रदत्तों का वर्गीकरण, विश्लेषण, परिणाम एवं व्याख्या

H01 माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्यापनरत् महिला एवं पुरुष अध्यापकों में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता के स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या- 1.1

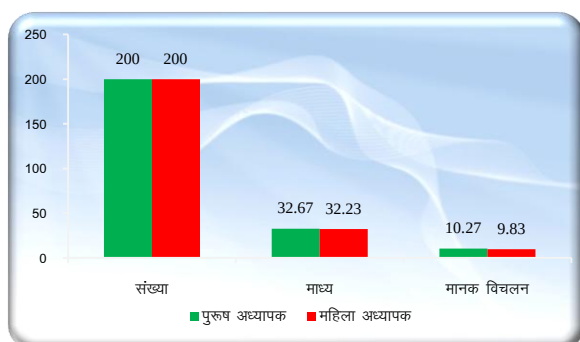
लिंग भेद आधारित माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्यापनरत् महिला एवं पुरुष अध्यापकों में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता को प्रदर्शित करने वाली तालिका का विश्लेषण

लिंग	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	टी-मूल्य	सार्थकता स्तर 0.05	निष्कर्ष
पुरुष अध्यापक	200	32.67	10.27	0.726	0.435	असार्थक	स्वीकृत
महिला अध्यापक	200	32.23	9.83	0.696			

स्वतंत्रता के अंश (df) 398 के लिए सार्थकता स्तर 0.05 पर स्तर पर तालिका मान = 1.96

आरेख संख्या – 1.1

लिंग भेद आधारित माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्यापनरत् महिला एवं पुरुष अध्यापकों में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता के स्तर को प्रदर्शित करने वाला आरेखीय निरूपण



विश्लेषण एवं व्याख्या

प्रस्तुत तालिका एवं आरेख संख्या 1.1 में महिला अध्यापकों एवं पुरुष अध्यापकों में 'समावेशी शिक्षा' के प्रति जागरूकता के स्तर का अध्ययन पर प्राप्तियों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता

है कि पुरुष अध्यापकों के समूह का मध्यमान 32.67 मानक विचलन 10.27, तथा मानक त्रुटि 0.726 पायी गयी है। महिला समूह का मध्यमान 32.23, मानक विचलन 9.83 तथा मानक त्रुटि 0.696 पायी गयी है एवं महिला दोनों समूह का तुलनात्मक टी परीक्षण मूल्य 0.435 पाया गया है जो स्वतंत्रता के अंश 398 के 0.05 सार्थकता स्तर पर टी के अपेक्षित मूल्य 1.96 से बहुत कम है जो अन्तर की सार्थकता की पुष्टि नहीं करता है। अतः परिकल्पना भरतपुर जिले के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्यापनरत् महिला एवं पुरुष अध्यापकों में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता के स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि "समावेशी शिक्षा" के प्रति जागरूकता के स्तर के संबंध में महिला अध्यापकों एवं पुरुष अध्यापकों में "समावेशी शिक्षा" के प्रति जागरूकता का स्तर लगभग समान है दोनों की सकारात्मक विचारधारा एवं आन्तरिक स्वीकृति, अपने शिक्षण के प्रति उत्तरदायित्व, आधारभूत मूल्यों में निष्ठा एवं शिक्षण व्यवसाय के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व में महिला अध्यापकों के समूह की पुरुष विद्यार्थियों की तुलना में न्यून अन्तर पाया गया है। अतः कहा जा सकता है कि "समावेशी शिक्षा" के प्रति जागरूकता के संबंध में दोनों वर्ग के अध्यापक समूह में समान स्तर है क्योंकि समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त और सर्वोत्तम पद्धतियों के बारे में दोनों को समान रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। अध्यापकों में उनका शैक्षणिक स्तर व शैक्षणिक समानता तथा समावेशी शैक्षणिक संसाधनों का समान वितरण, योग्य और अनुभव आधारित उनके प्रशिक्षण में समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की समान गुणवत्ता आधारित समावेशी शिक्षा, नवीनतम संचार प्रौद्योगिकी की समान उपयोगिता के कारण एवं 'समावेशी शिक्षा' के प्रति जागरूकता के प्रति ज्ञान की प्रतिबद्धता के लिए अनिवार्य और महत्वपूर्ण स्थिति है। समावेशी शिक्षा में

अध्यापक की भूमिका बहुआयामी होती है। शिक्षक न केवल शैक्षिक ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि बच्चों की समाजिक – भावनात्मक, शारीरिक और व्यक्तिगत विकास को भी बढ़ावा देते हैं।

शैक्षिक निहितार्थ

शिक्षा की एक सामान्तर प्रणाली की आवश्यकता है। सभी छात्रों को एक शिक्षित किया जा सकता। हालाँकि, पूर्ण समावेशन की समझ को मुख्यधारा की कक्षा के बाहर विशेष प्रावधान की अनुमति देनी चाहिए ताकि समावेशी शिक्षा के अभ्यास में इसे शामिल किया जा सके। हालाँकि, ऐसा प्रावधान जरूरी नहीं है कि मुख्यधारा की कक्षा में हो, लेकिन यह शिक्षा एक व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा का शैक्षिक निहितार्थ यह है कि सभी छात्रों, चाहे उनकी शारीरिक, मानसिक या सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, को समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है। इसका अर्थ है कि एक ऐसा वातावरण बनाना जहाँ हर छात्र को अपनी क्षमता तक पहुँचने का अवसर मिले, जहाँ उनकी विविध आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

प्रस्तुत शोध अध्ययन यह दर्शाता है कि समावेशी शिक्षा के लिए प्रशस्त जागरूकता और दृष्टिकोण के प्रति अभिवृत्ति में सुधार की आवश्यकता है। साथ ही समावेशी शिक्षा की नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध के परिणामों के विश्लेषण से, इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष भारत में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कार्यक्रमों में समावेशी शिक्षा के प्रमुख घटकों, तथ्यों एवं आयामों को शामिल करने के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शैक्षिक निहितार्थों को महत्वपूर्ण बिन्दुओं में प्रदर्शित किया गया है। इस अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि समावेशन के बड़े पैमाने पर व्यावहारिक अभ्यास के लिए अध्यापकों को एक सिंहावलोकन प्रदान करने के लिए समावेशी शिक्षा को प्रभावी तरीके से शामिल किया जाना चाहिए।

समावेशी शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक सुझाव

- स्कूलों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए राज्य या केन्द्र सरकार को अधिक जागरूक अभियान चलाना चाहिए।
- समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति और प्रधानाचार्य को विशेष प्रयास किया जाना चाहिए।
- समावेशी शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को और अधिक प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- शिक्षा से जुड़े प्रत्येक घटक को समावेशी शिक्षा की मूल अवधारणाओं की आवश्यक जानकारी देनी चाहिए।
- सभी विद्यालयों की बनावट इस आधार पर होनी चाहिए कि किसी को भी उसमें आवागमन की परेशानी न हो।
- निःशक्त अधिनियम 1995 की जानकारी सामान्य लोगों को भी होनी चाहिए। और उसका लाभ उठाने के लिए सभी को प्रेरित किया जाना चाहिए।
- समुदायिक स्तर पर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए।
- विद्यार्थियों को भी समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।

उपसंहारात्मक कथन

समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति भारत में, विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए, अभी भी चुनौतीपूर्ण है। जबकि सरकार ने कई नीतियां और कार्यक्रम लागू किए हैं, वास्तविक कार्यान्वयन में कई बाधाएं हैं। फिर भी, नीति निर्माण में अक्सर दिव्यांग बच्चों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे उनकी शिक्षा तक पहुँच सीमित हो जाती है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भाग लेने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। दुनिया भर में ये बच्चे स्कूल से बाहर होने की सबसे

अधिक संभावना वाले बच्चों में से हैं। उन्हें भेदभाव, कलंक और स्कूल सेवाओं में दिव्यांगता को शामिल करने में निर्णय लेने वालों की नियमित विफलता के कारण शिक्षा में लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

समावेशी शिक्षा भारत में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। सरकार, शिक्षकों, माता-पिता और समुदाय को मिलकर काम करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, चाहे उनकी दिव्यांगता कुछ भी हो।

अतः कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन विविधता, समानता और समावेश के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने वाले शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रस्तावित कार्यक्रम हमारे शैक्षणिक संस्थान में दिव्यांग छात्रों की अनूठी जरूरतों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य एक सहायक और समृद्ध वातावरण बनाना है जहाँ सभी छात्र शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से आगे बढ़ सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अस्थाना विपिन (2001), मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ।
- आशा शर्मा (2016), समावेशी शिक्षा, प्रथम संस्करण, अमित प्रकाशन जालन्धर, पृष्ठ संख्या 35-40।
- अग्रवाल जे.सी. (2006), शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबन्ध, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. नई दिल्ली।
- आलतेकर ए.एस. (2008), प्राचीन भारत में शिक्षा, वसुंधरा प्रकाशन गोरखपुर, पृष्ठ संख्या 13-15।
- अग्रवाल, जे. सी. (2010), शिक्षा मनोविज्ञान, शिप्रा पब्लिकेशन न्यू दिल्ली, पृष्ठ संख्या- 273-289।
- कपिल एच. के. (2007), अनुसंधान विधियाँ, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा, पृष्ठ संख्या- 68-75।
- गुप्ता एस.पी. (2005), आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- गर्ग सरिता (2005), "सामान्य व दिव्यांग विद्यार्थियों की समेकित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति" भारतीय आधुनिक शिक्षा एन.सी.ई. आर.टी., नई दिल्ली।
- चुगतई आई बी. (2011), समावेशित शिक्षा क्या, क्यों और कैसे ? निवेदिता पत्रिका बनारस, पृष्ठ संख्या 38-46।
- जुल्का, अनिता एवं कुमार मनोज (2007), "समावेशित शिक्षा और समान अवसरों की भागीदारी" भारतीय आधुनिक शिक्षा एन.सी.ई. आर.टी., नई दिल्ली।

शोध पत्र – पत्रिकाएं

- अनवर (2024), समावेशी शिक्षा की अद्भुत परम्पराएं इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसीप्लिनरी रिसर्च वॉल्यूम 06, अंक 05, पृष्ठ संख्या 01-07, आई.एस.एस.एन. न. 2582-2160।
- कच्छावा प्रति (2020), नई शिक्षा नीति 2020 : समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसीप्लिनरी रिसर्च वॉल्यूम 01, अंक-03 पृ.सं. 85-92 आई.एस.एस.एन. न. 2582-7162।
- देवी कुसुम (2018), समावेशन शिक्षा में अध्यापकों के उत्तरदायित्व एवं भूमिका : एक समीक्षा आई.जे.एस.आर.एस.टी., वॉल्यूम 04, अंक-07 पृ.सं. 242-248 आई.एस.एस.एन. न. 2395-6027।
- पाठक आशीष, सिंह धर्मवीर (2024), विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के संवर्धन में शिक्षकों की भूमिका जर्नल ऑफ इमर्जिंग

टेक्नोलॉजी एंड एनोवेटिव रिसर्च, वॉल्यूम 11, वेबसाइट्स

अंक-02 पृ.सं. 1170-1176, आई.एस.एस.एन.

नं. 2349-5162 |

- www.shaikshikmanthan-com
- <http://www-desertation-com>
- <http://www-ssmrae-com>
- <http://www-oerj-or>

21 वी सदी की शिक्षा प्रणाली में भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता

डॉ० दीपिका शर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग,
जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान

दीपांशु सांवरिया

प्रशिक्षणार्थी, शिक्षा विभाग
जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान

सारांश

शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व और व्यवहार में काल एवं परिस्थिति के अनुसार परिमार्जन कर उनके भीतर अच्छे विचारों का निर्माण करती है तथा जीवन के मार्ग को प्रशस्त करती है। बेहतर समाज के निर्माण में सुशिक्षित नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मानव के विकास की सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान ही है। 'ज्ञान' शब्द देखने में जितना छोटा है अपने आप में उतनी ही व्यापकता लिए हुए है। यह जीवन—पर्यंत चलता है। आज वही देश सबसे कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। यह ज्ञान ही है जो मनुष्य को अन्य जीव-जन्तुओं से श्रेष्ठ बनाता है। भारत की शिक्षा परंपरा विश्व की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध परंपराओं में से एक रही है। वेद, उपनिषद्, दर्शन, गणित, खगोल, आयुर्वेद, ज्योतिष, संगीत, कला योग, व्याकरण और शिल्प जैसी विषयवस्तु में निपुणता भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली की पहचान थी।

ये परंपराएँ न केवल ज्ञान का स्रोत रही हैं, बल्कि नैतिक मूल्यों, जीवन-दर्शन और व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा भी देती हैं। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय इसकी साक्षी हैं। समय के साथ, औपनिवेशिक प्रभाव और वैश्वीकरण के कारण भारतीय शिक्षा प्रणाली ने अपनी मौलिकता खो दी। इसी परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) एक नई आशा लेकर आई है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। यह शोध पत्र समकालीन शिक्षा प्रणाली में भारतीय ज्ञान परंपरा के स्थान, उसकी प्रासंगिकता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उसके समावेश का विश्लेषण करता है।

मुख्य शब्द — समकालीन शिक्षा प्रणाली, भारतीय ज्ञान परंपरा, एन. ई. पी. 2020।

प्रस्तावना

भारतीय सभ्यता का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और इसकी शिक्षा प्रणाली मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को छूने वाली रही है। प्राचीन भारत में शिक्षा केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं थी, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास (शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक) का आधार थी। इसी कारण भारत की प्राचीनकालीन शिक्षा व्यवस्था देश में ही नहीं वरन् समूचे विश्व में भी प्रसिद्ध थी। चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक ज्ञान के

साथ-साथ व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य पर आधारित शिक्षा प्रणाली की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। चीन, जापान, तिब्बत तथा लंका आदि देशों से यहां शिक्षार्थी ज्ञानार्जन हेतु आते थे। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ आचार्यों के कारण नालंदा, तक्षशिला एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्व में सुविख्यात थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा अपने उद्देश्यों एवं व्यावहारिकता के कारण संसार में अनूठी थी। लेकिन औपनिवेशिक काल में थोपे गए शिक्षा मॉडल ने इस परंपरा को काफी हद तक विस्मृत कर दिया। किन्तु यह संतोषजनक है

कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस ओर ध्यान दिया है और महत्वपूर्ण सुधारों की ओर कदम बढ़ाया है। इस नीति का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए शिक्षा के माध्यम से छात्रों को भारतीय जड़ों से जोड़ना है। यह नीति भारतीय संस्कृति, भाषा, और दर्शन को समकालीन शिक्षा में पुनः स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

भारतीय ज्ञान परंपरा

भारत के पास बौद्धिक अनुसंधान एवं मूल ग्रंथों के धरोहर की एक अत्यंत समृद्ध परंपरा रही है जो कि सदियों पुरानी है। भारतीय ज्ञान परंपरा अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है जिसमें ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और पारलौकिक, कर्म और धर्म तथा भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय है। ऋग्वेद के समय से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली जीवन के नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक मूल्यों पर केंद्रित होकर विनम्रता, सत्यता, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सभी के लिए सम्मान जैसे मूल्यों पर जोर देती थी। भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा प्रणाली, ज्ञान, परंपरा और प्रथाएं मानवता को प्रोत्साहित करती थी। भारत के तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लभी, उज्जैन, काशी आदि विश्व प्रसिद्ध शिक्षा एवं शोध के प्रमुख केंद्र थे तथा यहां कई देशों के शिक्षार्थी ज्ञानार्जन के लिए आते थे। प्राचीन काल से ही हमारा भारत उच्च मानवीय मूल्यों एवं विशिष्ट वैज्ञानिक परंपराओं का देश रहा है। भारत की ऐसी संस्कृति रही है कि भारत ने दुनिया को अलग-अलग देश या भूभाग के रूप में माना ही नहीं है।

अयं निजः परो वेति, गणना लघुचेतसाम्।

उदारचरितानां तु, वसुधैव कुटुम्बकम्॥

महाउपनिषद के इस सिद्धांत के आधार पर समस्त दुनिया को एक परिवार के रूप में मान्यता देने वाला एकमात्र देश भारत है।

भारतीय ज्ञान परम्परा, शिक्षा के माध्यम से छात्र को अज्ञानता रूपी अंधकार से दूर करते हुए मुक्ति

का मार्ग प्रशस्त करती है तथा भारत को मूल्य आधारित शिक्षा का केंद्र बना कर भारतीय जनमानस में विश्व बंधुत्व के भाव का विकास कर, राम राज्य का सपना साकार करने का प्रयास करती है। भारत की ज्ञान परंपरा ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को इस अर्थ में गढ़ा कि संसार के अन्य सभी ज्ञान इसके सामने फीके रह गये। अपनी समृद्ध ज्ञान परम्परा के कारण ही भारत अनेको विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण व लूटपाट के तंत्र के सागर को पार करते हुए अपनी संस्कृति, सम्यता एवं मूल्यों को अक्षय बनाये रखने में सफल रहा है। भारत की ज्ञान परंपरा एवं मूल्य यहाँ के कण-कण में विद्यमान है। भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व पर बल देते हुए हिंदू धर्म के पवित्रतम ग्रंथ श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् कृष्ण ने कहा है कि "न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते (4/48)" अर्थात् इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। भारतीय ज्ञान परम्परा शिक्षा के माध्यम से छात्रों में ज्ञान के मूल्य को स्थापित कर उन्हें स्वयं को संयमित रखने और पाश्चिक प्रवृत्तियों से दूर रहने की प्रेरणा देती है। इसी में ज्ञान की सार्थकता है। विश्व में सर्वप्रथम मानव मूल्य से आप्लावित ज्ञान की किरण भारत से प्रस्फुटित हुई एवं यह युगों-युगों तक भारत को ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित करता रहेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा बहुआयामी, समावेशी और सार्वकालिक रही है यह केवल औपचारिक शिक्षा तक सीमित न होकर जीवन के हर क्षेत्र को समाहित करती है। इसके कुछ प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं—

वेद और उपनिषद— ये ज्ञान, दर्शन, और आध्यात्मिकता का स्रोत है। जीवन का उद्देश्य और आत्मा-परमात्मा का संबंध बताने वाले ग्रंथ हैं। "सत्यं वद, धर्मं चर" जैसे उपदेश मूल्यों पर आधारित शिक्षा का उदाहरण हैं।

गणित और विज्ञान— आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त आदि विद्वानों का इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे

वैज्ञानिकों ने दशमलव प्रणाली, शून्य, बीजगणित और खगोल विज्ञान में अमूल्य योगदान दिया।

आयुर्वेद और चिकित्सा प्रणाली— चरक द्वारा रचित चरक संहिता और सुश्रुत द्वारा रचित संहिता चिकित्सा शास्त्र की अद्भुत धरोहरें हैं।

योग और ध्यान— योग के माध्यम से शारीरिक व मानसिक संतुलन की शिक्षा दी जाती रही है। पतंजलि के योगसूत्र आज भी विश्वभर में लोकप्रिय हैं। कला, संगीत और नाट्यशास्त्र भरत मुनि का 'नाट्यशास्त्र' नृत्य, संगीत और रंगमंच का गहनतम अध्ययन है।

दर्शन शास्त्र— न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत जैसे तत्त्वदर्शनों का विकास।

नैतिक शिक्षा— नीति, धर्म, और समाज के प्रति उत्तरदायित्व।

भारतीय परंपरा गुरु व शिष्य के ऐक्य का मार्ग भी सूझाता है— सहनाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै। तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ।। शांतिः शांतिः शांतिः।। (कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरिय उपनिषद् 2.2.2) अर्थात् गुरु और शिष्य दोनों एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दोनों को साथ-साथ विद्या का फल प्राप्त हो, सामर्थ्य प्राप्त हो, हम तेजस्वी बनें और हम परस्पर द्वेष ना करें मिल कर आगे बढ़ें। धर्म भारत की परंपरा का जो मूल आधार है। तैत्तिरिया आरण्यक में कहा गया है "धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा" अर्थात् धर्म संपूर्ण जगत का आधार है। भारतीय परंपरा में जीवन का लक्ष्य धर्म को मूल मानते हुए पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि है। इसलिए महर्षि कणाद अभ्युदय और निरुश्रेयस के साधन को ही धर्म कहते हैं— "यतो अभ्युदयनिरुश्रेयस सिद्धिरु स धर्मस" अर्थात् जिस माध्यम से अभ्युदय अर्थात् भौतिक दृष्टि से तथा निरुश्रेयस अर्थात् आध्यात्मिक दृष्टि से सभी प्रकार की उन्नति प्राप्त होती है उसे धर्म कहते हैं। वैदिक काल में विद्या अध्ययन के केंद्र गुरुकुल थे, जहां गुरु को सर्वोपरि मानकर 'महेश्वर' का दर्जा देकर पूजा की जाती थी। गुरु— शिष्य में

पिता और पुत्र का संबंध होता था। गुरु अपने शिष्य को निस्वार्थ भाव से शिक्षा प्रदान करके उसके सर्वांगीण विकास को अपना परम उद्देश्य समझते थे। गुरु अपने अंदर विद्यमान समस्त परा व अपरा विद्या को शिष्य को प्रदान करते थे तथा शिष्य भी अपने गुरु को सर्वस्व मानकर उनके द्वारा दी हुई शिक्षा को तत्परता और तल्लीनता से ग्रहण करते थे। वैदिक काल में शिक्षा का मूल उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना था। इस प्रकार आध्यात्मिकता भारतीय ज्ञान परम्परा का केन्द्रीय तत्व रहा है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु शिष्य का संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होता था प्राचीन वैदिक काल के गुरुकुलों में मूल्य आधारित शिक्षा पर विशेष जोर बल दिया जाता था, वहाँ वेदों का अध्ययन कराया जाता था, सत्य, दान, तप, यज्ञ छात्रों को दैनिक जीवन में अपनाना होता था। भारतीय ज्ञान परंपरा मातृदेवो भव, पित्रदेवो भव, अतिथि देवो भव की सीख देती है एवं वसुधैव कुटुंबकम्, अनेकता में एकता, कर्म योग आदि को अपनाने पर बल देती है जिससे मनुष्य समाज का एक उत्कृष्ट नागरिक बन उच्च जीवन शैली को प्राप्त कर सके और अपने समाज को उत्तम बनाने में भूमिका निभा सके। भारतीय मूल्यों में परोपकार व करुणा का सदैव उच्च स्थान रहा है, आज भी इन्हीं मूल्यों पर चलकर वास्तविक शांति एवं प्रसन्नता प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक शिक्षाविदों ने भी मूल्य आधारित शिक्षा को अपनाने पर बल दिया है। स्वामी विवेकानंद, गांधी, अरविंद आदि सभी विद्वान भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाने पर ही बल देते हैं। रविंद्र नाथ टैगोर एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त होकर एक शांतिपूर्ण जीवन जी सके, श्री अरविंदो भी मूल्य आधारित शिक्षा पर बल देते हैं, उनके अनुसार— जबसे जीवन मूल्य, शिक्षा से दूर हो गया है तब से देशवासी धर्मभ्रष्ट हो गए हैं। आज के आधुनिक दौर में भारतीय ज्ञान प्रणाली लुप्त होती जा रही है। शिक्षा केवल व्यवसायपरक, अर्थपरक होकर छात्रों को

गला-काट प्रतिस्पर्धा के पीछे भागने पर मजबूर कर रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा में मूल्य आधारित शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से आध्यात्मिकता एवं सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति करा कर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, सामाजिकता, भारतीय परंपरा एवं संस्कृति का संरक्षण एवं ज्ञानवान बनाने पर बल देना, सत्य का आचरण सिखाना, शांतिपूर्ण वातावरण, सुख एवं समन्वय स्थापित करना, विद्या, बुद्धि एवं विवेक का सामान्य ज्ञान व कर्म के मध्य संतुलन स्थापित करना था। सही मायने में भारतीय ज्ञान परंपरा द्वारा शासित शिक्षा नीति अपने आप में पूर्ण है, जो मनुष्य को इस लोक से परलोक तक की यात्रा को सुगमता से पूर्ण करने के योग्य बनाती है। मूल्य आधारित शिक्षा व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करती है। इन मूल्यों से युक्त होकर व्यक्ति विश्व बंधुत्व, सर्वे भवंतू सुखिनरू, वसुधैव कुटुंबकम का व्रत लेकर जीवन पथ पर धर्म एवं सत्य के साथ आगे बढ़ता है। यही हमारे ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है जिसके बल पर आज भी भारत अपने गौरवशाली परम्परा से पूरे संसार में जगमगा रहा है। अतः स्पष्ट है कि—

भारतीय ज्ञान परंपरा एक ऐसे समृद्ध, बहुआयामी एवं प्रगतिशील संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें मानवीय मूल्यों की प्राथमिकता है। इसमें विभिन्न धर्मों का समावेश है, जो सत्य, अहिंसा, न्याय, परोपकार और सदाचार जैसे मूल तत्वों की गंगोत्री प्रदान करते हैं। ये धर्म अपनी प्रकृति और तत्व की दृष्टि से प्राचीन भारतीय वैदिक संस्कृति की उपज प्रतीत होते हैं। भारतीय संस्कृति में एकता का सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, यहाँ धार्मिक और भाषाई विविधता के बावजूद सभी में एकता देखी जाती है। भारतीय संस्कृति में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य संस्कारों का विकास करना है। यह न केवल बौद्धिक ज्ञान का विस्तार करता है, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को भी ऊंचा उठाने हेतु प्रयत्नशील रहती है। इन मूल्यों का उद्देश्य मानव के आचरण, चरित्र और शील की

विवेचना करना है, जो उसके सम्पूर्ण जीवन दर्शन और व्यवहार शैली को परिभाषित करता है। इस प्रकार, भारतीय ज्ञान परंपरा न केवल सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि मानवता, नैतिकता और आध्यात्मिक विकास का मार्गदर्शक भी है।

संस्कार और मूल्य, चरित्र निर्माण की मौलिक आधारशिला हैं, और चरित्र ही जीवन की वास्तविक कुंजी है। ये मूल्य हमारे निर्णय लेने को मार्गदर्शित करते हैं। विद्यालय एवं शिक्षकों की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि उनके आचरण और व्यवहार का बालकों के जीवन पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जिससे उनका व्यक्तित्व और चरित्र विकसित होता है। इस प्रकार, विद्यालय और शिक्षकों का संस्कार और मूल्यों के निर्माण में केंद्रीय स्थान है।

भारतीय परंपरा में शिक्षा का मूल उद्देश्य चरित्र निर्माण था, जो बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है। इसमें गुरु-शिष्य का संबंध आत्मिक रूप से जुड़ा था, छात्रों का कर्तव्य गुरु के आदर्शों का अनुकरण करना था। इस प्रणाली में धर्म, दर्शन, वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान था, जिससे विद्यार्थियों में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना विकसित होती थी।

भारत विश्व गुरु अपनी ज्ञान की समृद्धि और शिक्षा प्रणाली के कारण थी। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास और नैतिक उत्थान था, जिससे मनुष्यता का निर्माण होता था। प्राचीन भारत में गुरु-शिष्य का संबंध पिता-पुत्र जैसा था, गुरु उच्च आदर्शों और आचरण वाले थे, उनके जीवन में त्याग और समर्पण की भावना थी। उनका लक्ष्य शिष्यों में मानवता, आध्यात्मिकता और नैतिकता जैसे गुणों का विकास करना था।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का गहरा संबंध मानवता, नैतिकता और चरित्र निर्माण से है यह न केवल एक सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि आज भी अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाकर अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं।

औपनिवेशिक प्रभाव और समकालीन शिक्षा प्रणाली

समकालीन शिक्षा प्रणाली का ध्यान आर्थिक सम्पन्नता पर है, भौतिक सुख और विलासिता ने शिक्षा के वास्तविक लक्ष्यों से ध्यान भटका दिया है। आज शिक्षा में वेद और पुराणों के तत्वों का अभाव है, जबकि विज्ञान और तकनीकी का प्रभाव बढ़ गया है, जिससे शिक्षा महज जीविकोपार्जन का साधन बनकर रह गई है। फलतः हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। ब्रिटिश काल में लॉर्ड मैकाले की नीति के तहत जो औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली स्थापित हुई, उसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कर्मियों का निर्माण था। यह प्रणाली भारतीय संदर्भ, संस्कृति और भाषाओं की उपेक्षा करती थी। इस नीति ने भारतीय शिक्षा के मूल स्वरूप को ही नकार दिया। इसके कारण भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता मिली और रटत प्रणाली हावी हो गई, व्यावहारिक ज्ञान का अभाव हो गया, नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा लगभग समाप्त हो गई, पश्चिमी चिंतन पर विशेष बल दिया जाने लगा, भारतीय भाषाओं व दर्शन की उपेक्षा हुई। समकालीन शिक्षा प्रणाली भी उसी उपनिवेशी ढांचे का ही एक परिवर्तित रूप है जिसमें भारतीयता गौण हो गई है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण केवल नौकरी केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया जा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार स्तंभों में समन्वय न बनाते हुए केवल अर्थ व काम पर ही ध्यान दिया जा रहा है जिससे कहीं न कहीं हमारे भारत की पहचान और मूल्यों का धीरे-धीरे हास होता जा रहा है। परिणामस्वरूप भारतीय युवाओं का अपनी संस्कृति और ज्ञान परंपरा से संबंध धीरे-धीरे कम होता जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय ज्ञान परंपरा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ समन्वित करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य है कि छात्र केवल 'कर्मचारी' न बनें, बल्कि एक संपूर्ण मानव बनें— जो आत्मनिर्भर, नैतिक और वैश्विक

दृष्टिकोण से युक्त हो। इस हेतु नीति में छात्रों को अपनी जड़ों से जोड़कर उनका सांस्कृतिक पुनरुत्थान, समग्र शिक्षा पद्धति के माध्यम से उनमें रचनात्मकता का विकास, स्थानीय ज्ञान का संरक्षण, पारंपरिक शिल्प, लोक ज्ञान, और कृषि प्रणाली में नवाचार, समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण, छात्रों में भारतीय मूल्यों और संस्कृति के प्रति सम्मान जागृत कर उनमें आत्मगौरव और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करने तथा वैश्विक स्तर पर भारतीय ज्ञान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। चूंकि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में मूल्यरहित शिक्षा प्रणाली के कारण युवाओं में आत्महत्या, लूटपाट, नशा इत्यादि की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस दौर में भारतीयों का अपने ज्ञान परंपरा और मूल्यों को भूलते जाना एक सबसे बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है। आज की शिक्षा व्यवस्था में छात्र एक विद्यार्थी न बनकर प्रशिक्षणार्थी बनकर रह गया है, वह ज्ञानार्जन नहीं वरन जीवन यापन एवं अर्थचरी विद्या हेतु प्रशिक्षण मात्र प्राप्त कर रहा है। परिणामस्वरूप पाश्चात्य जगत की चकाचौंध भरी जिंदगी, युवाओं के लिए आकर्षक बनती जा रही है। वह अपने गौरव को भूलते जा रहे हैं, उनकी जीवनशैली बिल्कुल ही बदल चुकी है। वे व्यवसायिक शिक्षा में पढ़कर खोखले ज्ञान को हासिल करते जा रहे हैं और वास्तविक जीवन के मर्म से दूर होते जा रहे हैं। मनुष्य के चरित्र का निर्माण गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, शैशवावस्था अनुकरण की अवस्था होती है, फिर किशोरावस्था अत्यंत संवेदनशील अवस्था होता है जिसमें बालक का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक व भावनात्मक विकास सबसे अधिक होता है, यही वह अवस्था है जब बालक के भीतर मूल्यों का स्थायी समावेश हो सकता है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा से इस अवस्था के बालको को परिचित कराना अत्यंत ही आवश्यक प्रतीत होता है यहाँ यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि मूल्यों का समावेशन इस प्रकार

से किया जाए कि छात्र को वर्तमान आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में स्वच्छता की ओर ले जाया जा सके और उसे बिना सोच-समझ वाला रेस का घोड़ा बनने से बचाया जा सके। मूल्य आधारित शिक्षा ही छात्र को संवेदनशील व चौतन्त्र मानव बना सकती है। अतः यह अति आवश्यक प्रतीत होता है कि भारतीय जनमानस में मूल्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जाय एवं पवित्र ज्ञान रूपी धारा से छात्रों को अवगत कराया जाए एवं असीम, अद्वितीय और अनंत ज्ञान धारा को छात्रों के मन मस्तिष्क में आरोपित करके उन्हें पाश्चात्य जगत का अंधानुकरण करने से रोका जाय जिससे कि वे अपनी जड़ों को फिर से प्राप्त कर सकें। इस हेतु छात्रों के अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित मूल्य आधारित शिक्षा का समावेश करके उन्हें धैर्यवान, संयमी, परोपकारी, सदाचारी, मानवतावादी, आत्मचिंतन करने वाला बनाया जाय जिससे कि वे अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकें, वे आधुनिकता की चकाचौंध के दलदल से बाहर निकल कर अपने ज्ञान परंपरा की विशिष्टता को समझ सकें और भारत भूमि को एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में सिरमौर बनाएं एवं सर्वे भवतु सुखिनः की अवधारणा का मार्ग प्रशस्त कर पुनः अपनी जड़ों से जुड़ सकें। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय ज्ञान परम्परा को समृद्ध करने के उद्देश्य से यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि— प्रत्येक विद्यार्थी को ज्ञान केन्द्रित भारतीय मूल्यों से विकसित, गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाकर एक जीवंत और न्याय संगत समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करेगी। इस नीति में परिकल्पित किया गया है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि, छात्रों में मौलिक दायित्व और संवैधानिक मूल्यों के विकास के साथ ही देश के साथ गुड़ाव और बदलते विश्व में योग्य नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करेगी। इस

में NEP-2020 एक क्रांतिकारी पहल है जिसका लक्ष्य केवल ज्ञान प्रदान करना है, बल्कि चरित्र निर्माण, रचनात्मकता, और वैश्विक दृष्टिकोण के साथ-साथ भारतीयता को बनाए रखना है। नीति में भारतीय भाषा में शिक्षा को प्राथमिकता तथा भारतीय लिपियों (संस्कृत, पालि, प्राकृत, तमिल जैसी प्राचीन भाषाओं) के संरक्षण को बढ़ावा देने, शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश तथा भारतीय संस्कृति और विरासत की समझ को प्रोत्साहन, शिक्षा में नैतिकता, आध्यात्मिकता, योग और ध्यान का समावेश, शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहन, National Research Foundation (NRF) की स्थापना, पारंपरिक ज्ञान पर आधारित शोध को बढ़ावा देने के साथ ही आदर्श गुरु-शिष्य परंपरा पुनः स्थापित करने की बात की गयी है। स्पष्ट है कि शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान परम्परा का सम्पोषित विकास कर सम्बल प्रदान करते हुए भारत केन्द्रित तथा समाज पोषित होकर भारत को परम वैभव राष्ट्र तथा जगतगुरु बनाने में महती भूमिका का निर्वहन करेगी।

इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसा प्रयास है जो भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ता है। इससे न केवल छात्र अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ेंगे, बल्कि भारत को एक आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने में भी सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष

भारतीय ज्ञान परंपरा केवल एक शैक्षणिक विषय नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। शिक्षण प्रक्रिया में इसका समावेश केवल एक शैक्षणिक सुधार ही नहीं, बल्कि भारत के आत्मिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का माध्यम है। समकालीन शिक्षा प्रणाली में इसके समावेश से न केवल शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि होगी, बल्कि यह भारत को पुनः "विश्वगुरु" बनने की दिशा में अग्रसर करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक

निर्णायक कदम है, जो भारत की आत्मा को शिक्षा के माध्यम से पुनः जागृत करने और

शिक्षा प्रणाली को भारतीय मूल्यों, भाषाओं और दर्शन से समृद्ध करने का प्रयास है। यदि इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो यह भारत को न केवल शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाएगा बल्कि भारतीय युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और सांस्कृतिक नेतृत्व प्रदान करने में भी सहायक होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार - <https://www.education.gov.in>
2. गोखले, बालगंगाधर (2015). भारतीय ज्ञान परंपरा का इतिहास, प्रकाशन : नेशनल बुक ट्रस्ट।
3. शर्मा, रामधारी सिंह (2010). प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, दिल्ली विश्वविद्यालय।
4. IGNOU Study Material & Indian Knowledge Systems, BA Philosophy Course.
5. Vedic Heritage Portal <http://www.vedicheritage.gov.in>
6. Ministry of AYUSH – भारत में आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान, <https://www.ayush.gov.in>
7. UNESCO Report on Indigenous Knowledge Systems, 2018.
8. नीतिशास्त्र और योग दर्शन पर आधारित ग्रंथ: पतंजलि योगसूत्र, भगवद्गीता (अध्याय 2 श्लोक 47)
9. प्रो. शर्मा सरोज, भारतीय ज्ञान परंपरा : विविध आयाम (2023) NIOS शिप्रा पब्लिकेशन पड़पड़गंज, दिल्ली
10. National Curriculum Framework (NCF) 2023 Draft, NCERT
11. Radhakrishnan, Dr. S. (1949). The Philosophy of the Upanishads, Oxford University Press.
12. कृष्ण यजुर्वेद तृतीय उपनिषद्
13. वृहदारण्यक उपनिषद्
14. महाउपनिषद्

Constructive Education as the Backbone of Atmanirbhar Bharat: Rethinking Soft Skill Development in NEP 2020

Rekha Karnath Unny - Research Scholar

Dr. Gaurav Singh - Associate Professor

School of Arts, Humanities & Social Science, Nirwan University, Jaipur, Rajasthan

Abstract

NEP 2020 is built around holistic, competency-based education and connects skill development directly to the national vision of Atmanirbhar Bharat, treating youth as the country's future innovators, entrepreneurs, and citizens.^{1,2} This paper argues that constructive education, drawing on the theories of Piaget and Vygotsky, is the most credible pedagogical path toward these goals because it builds soft skills into the learning process rather than tacking them on as separate modules.^{3,4} Research from Indian classrooms shows that inquiry-based, cooperative, and problem-centred constructivist methods improve science achievement, problem-solving ability, and student attitudes toward learning.^{5,6,7} There is also growing evidence that constructivist teaching improves communication, self-confidence, and collaborative capacity — qualities that NEP 2020

identifies as central to twenty-first-century education.^{8,9} Classrooms organised around these principles can act as small-scale rehearsals for Atmanirbhar Bharat: they produce self-directed learners who can solve real problems, build enterprises, and contribute to their communities.^{10,11} The paper also addresses a serious implementation obstacle. Many teacher education programmes are still lecture-heavy and poorly aligned with the constructivist, experiential, and interdisciplinary approaches that NEP 2020 and the National Professional Standards for Teachers (NPST) require.^{12,13}

Keywords: Constructive Education, Atmanirbhar Bharat, NEP 2020, Soft Skills, Problem-Solving, Science Achievement, Teacher Education

Introduction

NEP 2020 set out to change something fundamental about Indian education: to move a system built on rote memorisation toward one that equips young people with flexible, usable skills for an uncertain future.² The policy connects this goal directly to Atmanirbhar Bharat, treating education not as a social service but as the engine of national self-reliance.^{1,10} In that framing, soft skills such as critical thinking, communication, adaptability, and collaborative problem-solving are not optional extras. They are what self-reliance actually looks like in a person.^{14,15}

India's existing approach to soft skills, however, often contradicts this vision. Workshops, personality development modules, and value-added courses are tacked onto programmes without being woven into them — especially in teacher education.^{8,12} The result is fragmented learning that separates the cognitive from the socio-emotional, the technical from the ethical — the opposite of what NEP 2020 intends.¹⁴

This paper, situated within ongoing doctoral research on constructive education and science learning, proposes that constructivist pedagogy is the more honest route: one where soft skills grow naturally from authentic, problem-centred learning rather than being delivered in a separate session.^{3,4}

The paper is organised in seven sections. Section 2 sets out the theoretical basis of constructive education. Sections 3 and 4 examine how NEP 2020 and Atmanirbhar Bharat align with constructivist pedagogy. Section 5 reviews the evidence from science education. Section 6 looks at the teacher preparation gap — the point where most reform efforts stall. Section 7 draws out implications for policy, research, and practice.

Constructive Education and Constructivist Theory

Constructive education, as used here, means classroom practice grounded in constructivist learning theory. The two foundational figures are Piaget and Vygotsky. Piaget showed that learners build

understanding actively by assimilating new experience into existing mental structures and revising those structures when something does not fit. Vygotsky added the social dimension: learning happens most effectively through dialogue, shared problem-solving, and guided support within what he called the Zone of Proximal Development. In both accounts, knowledge is constructed, not delivered.³

In Indian research, constructivism has been studied as a way to shift classrooms away from teacher-dominated instruction toward environments where tasks are open-ended, problems are rooted in context, and students are expected to question, hypothesise, and justify.^{3,4} When cooperative and project-based learning is organised along these lines, students develop stronger communication skills, a greater sense of responsibility, and deeper conceptual understanding — not as separate goals but as outcomes of the same learning process.¹⁷ This makes constructive education a natural fit for NEP 2020's call for experiential, inquiry-based, and competency-oriented teaching.^{14,12}

One distinction is worth making explicit. This paper is not concerned with constructivism as a philosophical position. It is concerned with pedagogy — with what teachers actually do. Constructivist pedagogy means designing tasks that surface prior knowledge, create productive confusion, invite peer dialogue, and scaffold understanding through graduated challenge.³ These are concrete, teachable practices. And they are exactly what generates the soft skills NEP 2020 is trying to produce.

NEP 2020, Soft Skills, and Nation Building

NEP 2020 treats soft skills not as a curriculum afterthought but as a central policy concern, arguing that creativity, communication, and critical thinking matter as much as content knowledge — and that education must address youth unemployment and social inequality, not just academic achievement.^{1,2} It calls for soft skills and vocational competencies to be integrated across all curricula rather than confined to narrow electives or short-term programmes.^{14,8} This connects directly to Atmanirbhar Bharat, which depends on young people who can create jobs, not just fill them.^{10,18}

Research on the policy notes that NEP 2020's push for multidisciplinary learning, flexibility, and experiential pedagogy can genuinely widen opportunities for

young people, particularly when it works alongside initiatives like the National Youth Policy and Skill India.^{1,19} But realising this requires more than a policy document. Soft skills need to be structurally embedded in how teaching is organised, how students interact, and how learning is assessed — not listed as intended outcomes and then left to chance.^{12,15} Constructive education does this by making collaboration, communication, and reflection part of the method, not the goal.^{3,17}

The National Youth Policy 2021 points in the same direction, identifying capacity building, skill development, and civic participation as interconnected priorities and calling for educational environments that foster agency, resilience, and social responsibility.¹⁹ A constructivist classroom, with its emphasis on self-directed inquiry and joint problem-solving, fits that description. The policy architecture is already aligned. What is missing is pedagogical follow-through.

Soft Skills as Outcomes of Constructivist Pedagogy

Studies from India and elsewhere show that constructivist and active-learning approaches measurably improve students' communication, collaboration, and socio-emotional development.^{9,17} A comparative study of secondary students — one group taught under constructivist methods after NEP 2020, the other under traditional instruction — found that students in constructivist classrooms were more confident, articulated ideas more easily, and communicated more competently.⁹ Research on cooperative learning with a constructivist structure similarly shows gains in teamwork, leadership, and problem-solving alongside improved academic understanding.¹⁷

Constructivist environments also build the less visible qualities that matter: willingness to hear a different perspective, persistence when a task is hard, openness to peer critique, and the habit of evaluating one's own work honestly.^{3,4} These are not soft skills in the sense of being easy. They are exactly what changing labour markets and democratic societies require.^{1,19} From the standpoint of Atmanirbhar Bharat, they underpin something specific: the capacity to see a local problem clearly, work with others across disciplines, and build a solution that fits the context rather than borrowing one from elsewhere.^{11,10}

It is worth being concrete about the mechanism. When a science student frames a research question,

designs an investigation, interprets findings, and presents them to peers, she is not practising one skill at a time. Critical thinking, communication, evidence-based reasoning, and collaborative negotiation are all happening simultaneously, inseparably from the learning itself. That is what embedding soft skills in the architecture of learning actually means. Not a workshop at the end of term. The learning itself, done a particular way.¹⁴

Science Achievement, Problem-Solving, and Constructivism

Science education is the particular focus of the doctoral research that frames this paper, and the evidence here is consistent. Indian studies comparing constructivist and traditional methods at elementary and secondary levels show that students in constructivist classrooms score higher on conceptual understanding tests, handle non-routine problems better, and stay more persistently engaged with difficult material.^{5,6,7,20}

One study of constructivist science learning at the elementary stage found gains not only in test scores but in students' interest and confidence when dealing with scientific phenomena.⁷ A separate study of biology learning found that achievement improved across different intelligence levels — meaning constructivist approaches supported weaker learners rather than only rewarding those already doing well.²⁰ A comprehensive review of Indian research on constructivist science teaching reaches the same conclusion: inquiry-based, student-centred instruction produces stronger outcomes than transmission-based teaching.⁶

This matters for NEP 2020 because the policy specifically asks for science education that develops curiosity, creativity, and problem-solving — not reproduction of textbook content.¹⁴ Constructive science teaching serves both aims at once: it improves disciplinary understanding and builds the cross-cutting skills that Atmanirbhar Bharat requires from its next generation.^{5,18}

One finding deserves particular attention. The gains from constructivist science teaching are not confined to well-resourced urban schools. Studies from semi-urban and rural contexts in India show these approaches work across resource levels when teachers receive adequate preparation and support.^{6,5} This matters because self-reliance cannot be a privilege of

urban youth. If constructive science education can function as a democratising pedagogy when it is adapted to local language and context, it becomes a significant policy

Teacher Education and the Implementation Gap

The conceptual alignment between constructive education, NEP 2020, and Atmanirbhar Bharat is real. The implementation gap is equally real. Teacher education is where the distance between policy and practice is widest.^{21,22} Studies of teacher education programmes in India point to the same problems repeatedly: lecture-dominated delivery, overcrowded syllabi, very little time for micro-teaching of constructivist methods, and weak connections between theoretical coursework and school-based practice.¹² Many teacher educators have not themselves been taught through constructivist methods and find it difficult to model what they have not experienced.²¹

The NPST, developed after NEP 2020, sets out clear expectations: high-quality teaching, twenty-first-century skill sets, and reflective practice. But the NPST cannot work without systemic support — institutional autonomy, mentoring, and ongoing professional development.^{13,23} Without that, teachers face overcrowded classrooms, examination pressure, and resource constraints that make sustained constructivist practice very difficult to maintain.^{22,21}

India has been here before. The National Curriculum Framework 2005 made a similar argument for child-centred, constructivist pedagogy. Without sustained investment in teacher preparation, that framework was absorbed superficially: teachers agreed with it on paper and continued as before. NEP 2020 faces the same risk. The architecture is sound. The implementation vehicle — teacher education — needs to be taken more seriously than it has been.²²

What would serious investment look like? Pre-service programmes need extended school internships where student-teachers design and teach constructivist lessons, then reflect critically on what happened — particularly on how soft skills surfaced or did not during group work and inquiry.²¹ Classroom-based research during this period can help prospective teachers develop the habit of studying the relationship between how they teach and what students actually learn.⁶

In-service development should shift from one-off workshops to school-based learning communities where teachers plan together, observe each other's lessons, and review student work to improve their constructivist practice.^{13,22} NEP 2020's digital platforms can support this across regions.² And assessment needs to change. Project work, portfolios, and performance tasks make soft skill development visible and assessable rather than leaving it as an invisible byproduct that nobody measures and therefore nobody prioritises.^{14,15}

Implications for Policy, Research, and Practice

The argument in this paper is straightforward: constructive education is not just compatible with NEP 2020 and Atmanirbhar Bharat. It is the pedagogical approach that gives both their best chance of working.^{5,2,10} For policymakers, this means treating constructivist pedagogy and teacher education as central priorities, not secondary concerns. Resource allocation, regulatory frameworks, and accountability mechanisms need to reward learner-centred, inquiry-driven practice rather than merely prescribing it.^{1,21,13}

For researchers — particularly doctoral scholars in science education — there is genuine scope for

longitudinal and mixed-methods work tracing how constructivist teaching shapes students' development over time, across different socio-cultural settings.^{6,9} The field needs studies that go beyond achievement scores. How do students grow in confidence? How do they learn to voice disagreement without giving up or giving in? How do they develop persistence? These qualities are harder to measure but they are closer to what Atmanirbhar Bharat actually needs its young people to have.

For teachers, constructive education offers a practical way to teach disciplinary content and soft skills through the same activity rather than in competition with each other. A well-designed science investigation advances conceptual understanding, collaborative problem-solving, and communication at the same time.^{7,17} Teachers who have been taught this way themselves are far better placed to teach this way for others.¹²

To successfully implement NEP 2020's ambitions the system needs sustained commitment to constructivist teacher preparation and school cultures that support inquiry.

References

1. The National Education Policy and Empowerment of Youth. (2025). International Journal of Research and Scientific Innovation. <https://rsisinternational.org/journals/ijrsi/articles/the-national-education-policy-and-empowerment-of-youth/>
2. Ministry of Education, Government of India. (2020). National Education Policy 2020. <https://www.eoibucharest.gov.in/docs/1596447766SalientFeatures.pdf>
2. Constructivist Approach of Vygotsky for Innovative Trends in Education. (n.d.). International Journal of Academic Research and Development. <https://www.allstudyjournal.com/article/662/3-4-44-962.pdf>
3. Constructivist Pedagogy in Indian Secondary Education: Transforming Learning in Social Science Classrooms. (2026). International Journal of Academic Pedagogical Research. <http://ijeais.org/wp-content/uploads/2024/12/IJAPR241216.pdf>
4. A Study on the Effectiveness of the Constructivist Approach on Science Achievement and Attitudes Toward Science. (n.d.). Ganga Institute of Education. <http://www.gangainstituteofeducation.com/wp-content/uploads/2025/09/1.-A-Study-on-the-Effectiveness-of-the-Constructivist-Appro.pdf>
5. Sharma, N. (2025). The impact of constructivist approach on achievement in science education: A comprehensive review. International Journal of FMR. <https://www.ijfmr.com/papers/2025/1/36540.pdf>
6. Bhattacharjee, S. (2014). Effectiveness of constructivist approach in science learning at elementary school stage. Pedagogy of Learning. <http://pedagogyoflearning.com/wp-content/uploads/2015/06/17-April-2014-Effectiveness-of-Constructivist-Approach-in-Science-Learning-at-Elementary-School-Stage->

- by-Shantanu-Bhattacharjee-and-Chitralekha-Mehera.pdf
7. Teaching Soft Skills in India as per the NEP 2020: The Why and the How. (2024). International Journal of All Research Education and Scientific Methods. https://www.academia.edu/121699799/Teaching_Soft_Skills_in_India_as_Per_the_Nep_2020_The_Why_and_the_How
 8. Enhancing Communication Skills and Self-Confidence through NEP-Aligned Pedagogy. (2025). International Journal of Research in Humanities, Arts and Education. <https://www.ijrah.com/index.php/ijrah/article/view/764>
 9. Atmanirbhar Bharat: Entrepreneurial Education and NEP 2020. (2022). International Journal of Research Publication and Reviews. <https://ijrpr.com/uploads/V5ISSUE6/IJRPR30004.pdf>
 10. Role of Youth in Atmanirbhar Bharat. (2022). International Research Journal of Social Sciences. <https://www.isca.me/IJSS/Archive/v12/i2/10.ISCA-IRJSS-2022-063.pdf>
 11. Transforming Teacher Education Through NEP 2020. (2025). International Journal of FMR. <https://www.ijfmr.com/papers/2025/5/58743.pdf>
 12. National Council for Teacher Education. (2023). National Professional Standards for Teachers (NPST): Guiding document. <https://ncte.gov.in/website/PDF/NPST/NPST-Book.pdf>
 13. NEP 2020: Fostering Critical Thinking, Problem Solving and Creativity in Learners. (n.d.). International Journal of All Research Education and Scientific Methods. <https://www.allstudyjournal.com/article/1469/7-5-32-383.pdf>
 14. Pavithra, V. (2024). Assessing the skill sets from the NEP Policy 2020: Scale development and validation. Parikalpana: KIIT Journal of Management, 17(9). <https://www.indianjournalofmanagement.com/index.php/pijom/article/view/173941>
 15. Constructivist Communicative Strategies for Integration of Soft Skills. (n.d.). Peerian Journal of Management and Innovation. <https://peerianjournal.com/index.php/czjmi/article/download/25/16>
 16. Constructivist Communicative Strategies for Integration of Soft Skills — Cooperative Learning Outcomes. (n.d.). Peerian Journal of Management and Innovation. <https://peerianjournal.com/index.php/czjmi/article/download/25/16>
 17. Employment Opportunities and Skill Development under Self-Reliant India (Atmanirbhar Bharat Abhiyaan). (2023). Pacific Business Review International. https://www.pbr.co.in/2023/2023_month/June/5.pdf
 18. National Youth Policy 2021. (2022). Government of India. <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/may/doc20225553401.pdf>
 19. Effect of Constructivist Approach on Academic Achievement in Relation to Intelligence of Elementary School Students in Biology. (2017). International Education and Research Journal, 3(2). <https://ierj.in/journal/index.php/ierj/article/view/670>
 20. Teaching-Learning and Teacher Challenges under NEP 2020. (2025). The Learning Vertex. <https://ndpublisher.in/admin/issues/TLV15I1b.pdf>
 21. NEP-2020 and Teacher Education — Some Issues. (2022). International Journal of Creative Research Thoughts. <https://ijcrt.org/papers/IJCR T2204054.pdf>
 22. National Council for Teacher Education. (2021, November 16). National Professional Standards for Teachers (draft). https://ncte.gov.in/WebAdminFiles/PublicNotice/Hindi_0_17_11_2021_637727482281976435.pdf

Teacher Education and Skill Development

Dr. Meghaben H. Patel

Assistant Professor

The New Progressive College of Teachers' Education

P.G. Department Mehsana, Gujrat

Abstract

Teacher education and skill development are the foundation of a nation's development. To ensure quality education, it is essential to provide teachers with training based on modern technology, innovative teaching methods, and various skills. Competent teachers alone can prepare students to face the challenges of the 21st century by developing curiosity and skills in them, which is a key feature of the Indian education system.

A teacher is the mirror of society. The future of every country is being shaped in its classrooms. As the Kothari Commission stated, "The destiny of India is now being shaped in her classrooms". The more

competent the teacher handling the classroom, the brighter the country's future will be. In this age of world-class technology, teachers should not just be degree holders; there is a need for teachers who possess proficient technological knowledge. Such teachers can provide computer-based education alongside regular teaching. Teacher education and skill development is a process of refining a teacher's capabilities.

Keywords: Teacher education, Skill Development, Communication Skills, Problem Solving, Critical Thinking, Technical Skills, Time Management Soft Skills, Life Skills, Social Skills.

Introduction

What is Teacher Education?

Teacher education is a continuous process. A teacher is a lifelong student. The foundation of teacher education lies in a teacher's constant readiness for self-study, activity, and efforts for improvement through self-evaluation. A teacher's development can be seen in the context of their self-study.

Teacher education does not just provide subject knowledge; it also teaches the art of teaching. It is a planned process through which training is given to make an individual a good, responsible, and effective teacher. In the world of education, a teacher is an individual who provides schooling to others. A person wishing to become a teacher must first obtain the necessary qualifications or eligibility from institutions like universities or colleges.

Skill Development

In teacher education, a teacher should not just have bookish knowledge but should possess all types of capabilities. Beyond the classroom teaching-learning process, a teacher should have mastered administrative work, technological knowledge, and practical dealings.

Skill development is the process of increasing an individual's work capacity. In the current era, teachers are equipped with various skills, such as:

➤ **Communication Skills**

The ability to convey our thoughts, information, or feelings clearly and effectively to others. This includes speaking, listening, reading, and writing. Good communication is essential for professional readiness and building confidence in relationships.

➤ **Problem Solving**

The ability to identify, understand, and find the best solution for any difficulty or challenge. A teacher should first understand the students' problems and think of multiple possible solutions, choosing the most effective and practical one.

➤ **Critical Thinking**

A logical or analytical mindset where a person analyzes information deeply instead of accepting it blindly. This skill helps in reaching decisions by understanding what is right and wrong through logic.

➤ **Technical Skills**

Practical or mathematical knowledge and proficiency required to perform specific tasks. In the digital age, technical skills are necessary for every teacher.

➤ **Time Management**

Organizing and dividing your time effectively so that more quality work can be done in less time. Using time smartly is the key to success.

➤ **Soft Skills**

- **Definition:** Soft skills refer to personality, workplace etiquette, communication, and teamwork.
- **Nature :** These are behavioral and social skills essential for success.
- **Components:** They include problem-solving and emotional intelligence.
- **Importance:** These skills are vital for improving performance in any profession and are distinct from technical knowledge.
- **Collaboration:** Soft skills involve the ability to work effectively with others and cooperate in tasks.
- **Application in Teaching:** Soft skills are crucial for making education effective and vibrant. While a teacher must have subject knowledge, the ability to transmit that knowledge to students depends entirely on soft skills.
- **Empathy:** A teacher should understand the student's personality. If a child is weak in studies, the teacher should identify the reason, encourage them, and provide guidance based on their specific problems.
- **Professional Development:** In B.Ed. and P.T.C. colleges, personality is shaped through practice teaching, seminars, and organized activities, making the educational process more effective.

➤ **Life Skills**

- **Foundation:** Life skills are the foundation of modern teaching methods in teacher education.
- **WHO Definition:** According to the WHO, life skills are abilities that help individuals deal effectively with the demands and challenges of everyday life.
- **Teacher's Role:** A teacher does not just provide subject knowledge but builds society and the nation.

- **Self-Awareness:** Teachers must recognize their own strengths, limitations, and feelings to improve themselves.
- **Positive Environment:** A healthy and aware teacher spreads positive energy in the classroom.
- **Perspective:** Education becomes more effective when a teacher understands a student's difficulties from the student's perspective, building a relationship of trust.
- **Innovation:** Teachers should avoid rote learning ("Gokhan Patti") and instead use new techniques to make students think.
- **Conflict Resolution:** In case of classroom conflicts, a teacher must listen to both sides and remain neutral and impartial.
- **Relationships:** Teachers should maintain close relationships not only with colleagues and students but also with parents.
- **Emotional Control:** Teaching is a responsible and stressful job; a teacher must remain a "team player" and control anger or frustration to maintain a calm classroom environment.
- **Values:** A teacher with life skills can easily instill values like honesty, discipline, and humanity in students.

➤ **Social Skills**

- **Goal of Teacher Education:** It is a process that teaches pedagogical methods, subject knowledge, and the right attitude.
- **Beyond Subjects:** A good teacher must be capable of understanding, inspiring, and guiding students, not just knowing the subject.
- **Social Competence:** Social skills help an individual behave appropriately in society and build good relationships.
- **Key Skills:** These include communication, cooperation, empathy, leadership, tolerance, and conflict resolution.
- **Classroom Impact:** Good communication makes teaching easier and creates a positive atmosphere. An empathetic teacher understands students' feelings and provides proper guidance.
- **Society and Teacher:** The teacher and society are two sides of the same coin. Social skills are essential for interacting with students, parents, and colleagues.

- Role Model: By being a role model, a teacher develops confidence, discipline, and a spirit of cooperation in students.
- Synergy: Teacher education and social skills complement each other.
- Outcome: Their combination makes education more effective, interesting, and full of life values.
- Development: This leads to the holistic development of students, which is crucial for the growth of the society and the nation.
- Modern Context: In today's modern era, bookish knowledge alone is not enough; skill development is essential.
- Future Impact: When teacher education is linked with skill development, education becomes more practical and influential. A skilled teacher develops skilled students, ensuring a bright future for them and contributing to national development.

Conclusion

Through teacher education, teachers are provided with subject knowledge, teaching methodologies, and moral values. While through skill development, teachers develop an understanding of student potential, communication skills, thinking power, and problem-solving abilities. In today's modern era, mere bookish knowledge is not enough; various types of skills are also necessary. Therefore, by linking skill development with teacher education, teaching becomes more effective and practical. If a teacher is

skilled, they will be able to develop good skills in students as well, which will be very useful for their future. In this way, both teacher and student together provide a significant contribution to personality development, social development, and national development.

References

1. Jyoti Deka Bharati Vidyapeeth, R., & Batra, B. (2016). The Scope of Skill Development, Employability of Indian Workforce in Context of Make in India: A Study.
2. Tiwari, P., & Malati, N. (2020). Employability skill evaluation among vocational education , students in India. Journal of Technical Education and Training, 12(1 Special Issue), 218–228.
3. Lok Sabha Unstarred Q.No. 1883, 36th Report of Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development, Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana Data for PMKVY is from 2015-16 to Sept 2022; for DDU-GKY from 2014-15 to 2022-23; for JSS and NAPS from 2018-19 to Sept 2022; for CTS from 2018 to Sept 2022
4. Government of india, Ministry of skill development and entrepreneurship, Lok sabha, Unstarred, question no. 1883, Answered on 19.12.2022 Speed up the skill development programme 1883.
5. https://www.epfindia.gov.in/site_docs/exmpted_est/Payroll_Data_EPFO_Dec_2022.pdf
6. <https://reports.skillindia.gov.in>

Opportunities for Employment Generation in the Field of Arts

Dr. Roshankumar. R. Patel

Assistant Professor

The New Progressive College of Teachers' Education

P.G. Department Mehsana, Gujarat

Abstract

A student has completed class 12th with a concentration in the arts stream. Now what?

If he/she comes to you and asks for guidance, you must be aware of the career opportunities available for the Arts/ Humanities stream students. As far as these streams are concerned, people have the misconception of having only limited career options. However, the real scenario is different.

With the advancement of our education sector, career opportunities have been drastically improved and increased.

Keywords: Content Writing / Blogging , Fashion/ Interior Designing , Corporate Law , Social Work , Event Management.

Introduction

Explore the Best Career Opportunities in Arts Stream Here

❖ Content Writing/ Blogging

Everything is going digital nowadays. From education to business, technology and the internet have become the need of the hour. When it comes to the digital world, people connect through content. Good write-up and well-written ad content play a vital role in successful marketing.

Hence, there's a huge demand for content writers and bloggers. This creative sector is booming and people working in this field have a promising future.

Who can apply?

If your student loves expressing thoughts via words, this profession is an ideal choice. For people who love writing about new things every day, content writing is all they should go for.

Average Initial Salary: 11,500 Rs to 41,800 Rs (Monthly)

❖ Fashion/ Interior Designing

If someone is looking for a glamorous profession in the Arts stream, he/she can go for fashion or interior design. People working in this profession are very creative, & innovative and work towards detailing

with patience. This field asks for a lot of time, good connections, networks, and required skills.

Who can apply?

People who are creative, and innovative and work toward detailing are the ideal candidates for fashion and interior design.

Average Initial Salary: 15,500 Rs to 1.66 Lakh

❖ Corporate Law

One of the highest-paying jobs in the Arts stream is Corporate Law. This is the profile that will be in demand forever. This is an evergreen industry to work in. To make a career in this profession, you need to take an entrance test like CLAT, LSAT, etc. After that, you can go for a 5-years degree and choose a field for your practice.

Who can apply?

People who are good at public speaking, have an interest in studying Indian law, and love fighting for justice can go for this profession.

Average Initial Salary:

The basic starting salary of a corporate lawyer starts from 29,166 Rs (Per Month) and is subject to increment with more experience.

❖ Social Work

Social work is one of the top careers that people pursue in the Arts stream. It is a noble profession that anyone could take up. If you work as a social worker, it will broaden your perception of life and the way to see your life goals. This field offers various career options that teach you life lessons.

Who can apply?

A person who helps nature and who wants to do something for mankind can go for this profession.

Average Initial Salary:

The average salary of a social worker starts from 15000 Rs to 30,000 Rs Per month.

❖ Event Management

Event management is a booming sector. As the name suggests, this profession is related to managing all events whether big or small. The person who manages all the events is called the event manager and takes

care of all the aspects related to the event such as attending guests, catering, venue, and more.

Who can apply?

A creative person who loves managing events is the perfect suitable candidate for this profession.

Average Initial Salary:

The salary of an event manager starts from 33,333 Rs to 50,000 Rs per month.

Conclusion

The above-mentioned are the 5 best career opportunities in the Arts stream. However, this is not it. They have different other options to choose from as per their interests, likes, dislikes, and potential. Each student in the Arts stream can choose career-related course areas keeping in mind their aptitude, interests, and future career opportunities/employment opportunities, etc.

References

1. Adetoro, S. 1987. "Career Opportunities in Arts and Industrial Design". Paper presented during Career week activities of students of Ahmadu Bello University Demonstration School, Zaria.
2. Adetoro S. 1987. "Creativity as a means of Solving Unemployment among Nigerian Youths". A Seminar Paper presented during Ahmadu Bello University, Zaria, Jaycees week.
3. Linton R. 1936. The Study of Man, New York: Appleton – Century.
4. National Planning Commission, Nigeria 2004. National Economic Empowerment and Development Strategy (Needs), Abuja. Spencer, H. 1885, Principles of Sociology, London: Williams & Norgate, Vol. 1.435.
5. Suleiman, S. 1978. "The Arts and Technology in Balanced National Development" Confluence: An Academic Journal of the Kwara State Council for Arts and Culture Vol. 1, No. 1. 6 – 16.

Communication and Classroom Management Skills for Inclusive Teaching

Axina Geo Augustine – Research Scholar

Dr. Gaurav Singh - Associate Professor

School of Arts, Humanities & Social Sciences

Nirwan University, Jaipur, Rajasthan

Abstract

Inclusive education is a progressive educational approach that aims to provide equitable learning opportunities for all students regardless of their abilities, socio-economic backgrounds, or learning differences. It promotes participation, accessibility, and respect for diversity within the classroom. Among the essential competencies required for effective inclusive teaching, communication and classroom management skills play a central role. Effective communication enables teachers to convey information clearly, understand learners' needs, and foster meaningful interactions, while classroom management ensures a structured, supportive, and disciplined learning environment. This paper examines the role of communication and classroom management in inclusive education by analyzing key strategies, challenges, teacher competencies, and the integration of technology. It also highlights collaborative approaches that enhance inclusion and improve learning outcomes. The study emphasizes that adaptive communication methods and proactive classroom management strategies significantly improve student engagement, reduce behavioral challenges, and promote a sense of belonging among learners. The paper concludes by recommending continuous teacher training, institutional support, and the effective use of resources to strengthen inclusive teaching practices.

Keywords: Inclusive Education, Communication Skills, Classroom Management, Differentiated Instruction, Teacher Effectiveness.

1. Introduction

Inclusive education has become a major focus in contemporary educational systems, reflecting the commitment to provide equal learning opportunities for all students. It is based on the principle that diversity should be recognized and accommodated within mainstream classrooms rather than treated as a limitation. Students with different abilities, cultural backgrounds, and learning styles are educated together, fostering both academic achievement and social development. This approach encourages acceptance, cooperation, and mutual respect among learners.

However, inclusion is not limited to the physical integration of students. It requires the use of effective teaching practices that address the diverse needs of learners. Communication and classroom management are two critical components that determine the success of inclusive teaching. Communication facilitates understanding, builds

relationships, and ensures clarity in instruction. Classroom management creates a structured environment that supports learning, reduces disruptions, and promotes active participation.

Teachers must be equipped with the skills to integrate communication and classroom management effectively. This paper aims to analyze the importance of these competencies in inclusive education and explore strategies that can enhance teaching effectiveness and student engagement.

2. Concept of Inclusive Teaching

Inclusive teaching refers to instructional practices that accommodate the diverse needs of learners by adapting curriculum content, teaching methods, and assessment techniques. It ensures that all students have equal opportunities to participate, learn, and succeed. Inclusive teaching is based on the belief

that every learner has the potential to achieve when provided with appropriate support.

2.1 Principles of Inclusive Teaching

The principles guiding inclusive teaching include:

- Equity in access to learning opportunities
- Respect for individual differences
- Active participation of all learners
- Flexibility in instructional approaches and assessments
- Collaboration among educators, parents, and specialists

These principles provide a foundation for creating inclusive classrooms where diversity is valued and supported.

2.2 Importance of Inclusive Teaching

Inclusive teaching contributes significantly to both academic and social development. It enhances students' confidence, encourages collaboration, and promotes empathy. By fostering a sense of belonging, it improves student motivation and engagement. Inclusive education also prepares students to function effectively in diverse social and professional environments, making it an essential component of modern education systems.

3. Role of Communication in Inclusive Teaching

Communication is a fundamental aspect of inclusive education as it enables teachers to interact effectively with students from diverse backgrounds and abilities. It involves not only the delivery of information but also understanding student responses and providing appropriate feedback. Effective communication helps create a supportive learning environment where students feel valued and understood.

3.1 Types of Communication

The main forms of communication used in classrooms include:

- Verbal communication through spoken language
- Non-verbal communication such as gestures, facial expressions, and body language
- Written communication including instructions, assignments, and feedback
- Visual communication through charts, diagrams, and multimedia tools

Each type of communication plays an important role in enhancing understanding and engagement among students.

3.2 Characteristics of Effective Communication

Effective communication in inclusive classrooms is characterized by clarity, empathy, and adaptability. Teachers must use simple and understandable language, provide clear instructions, and ensure that all students can follow the lesson. Active listening is equally important, as it helps teachers understand students' needs and respond appropriately. Cultural sensitivity and awareness are essential to respect the diverse backgrounds of learners.

3.3 Communication Strategies for Inclusion

Teachers can adopt several strategies to enhance communication:

- Using clear and simple language for instruction
- Incorporating visual aids and multimedia tools
- Encouraging student participation and interaction
- Providing continuous feedback and reinforcement
- Utilizing assistive technologies for students with communication difficulties

These strategies help overcome communication barriers and ensure that all learners can actively participate in the learning process.

4. Classroom Management in Inclusive Teaching

Classroom management involves organizing and regulating classroom activities to create a conducive learning environment. In inclusive classrooms, it requires managing diverse student behaviors while ensuring that all learners feel safe, respected, and supported. Effective classroom management is essential for maintaining discipline and promoting active engagement.

4.1 Objectives of Classroom Management

The main objectives include:

- Promoting positive student behavior
- Minimizing disruptions and maintaining discipline
- Creating a safe and inclusive environment
- Encouraging active participation in learning

4.2 Principles of Inclusive Classroom Management

Effective classroom management is based on:

- Consistency and fairness in implementing rules
- Respect for individual differences
- Proactive rather than reactive strategies
- Student involvement in establishing classroom norms

4.3 Classroom Management Strategies

Teachers can implement the following strategies:

- Establishing clear rules and routines
- Using positive reinforcement to encourage appropriate behavior
- Adapting management approaches to individual needs
- Organizing the classroom for accessibility and interaction
- Encouraging cooperative learning and peer support

These strategies help create a structured and inclusive classroom environment.

5. Strategies for Effective Communication and Classroom Management

The integration of communication and classroom management strategies is essential for inclusive teaching. Teachers must adopt a comprehensive approach that addresses both instructional and behavioral aspects of learning.

5.1 Instructional Strategies

- Differentiated instruction to meet diverse learning needs
- Multimodal teaching approaches combining visual, auditory, and kinesthetic methods
- Collaborative learning activities that promote peer interaction and cooperation

5.2 Behavioral Strategies

- Positive reinforcement and motivation
- Clear communication of expectations and classroom rules
- Conflict resolution and problem-solving techniques

These strategies enhance engagement, improve classroom discipline, and support inclusive learning.

6. Relationship Between Communication and Classroom Management

Communication and classroom management are closely interconnected and mutually reinforcing. Clear communication helps reduce misunderstandings, sets expectations, and prevents behavioral issues. At the same time, effective classroom management creates a structured environment that supports interaction and learning. Positive teacher-student relationships strengthen both communication and management, leading to improved academic performance and classroom harmony.

7. Challenges in Inclusive Classrooms

Inclusive education presents several challenges that teachers must address effectively to ensure successful implementation.

7.1 Instructional Challenges

- Diverse learning needs and abilities within a single classroom
- Difficulty in designing flexible lesson plans that suit all learners

7.2 Resource and Training Challenges

- Lack of adequate teaching materials and assistive tools
- Insufficient training in inclusive teaching practices

7.3 Behavioral and Communication Challenges

- Managing diverse student behaviors and attitudes
- Overcoming language barriers and communication difficulties

Addressing these challenges requires continuous professional development, institutional support, and access to resources.

8. Role of Teacher Competencies

Teachers play a central role in implementing inclusive education, and their competencies significantly influence its success.

8.1 Professional Competencies

- Knowledge of inclusive education principles and practices
- Ability to adapt instructional strategies
- Strong classroom management skills

8.2 Interpersonal Competencies

- Empathy and patience in dealing with diverse learners
- Cultural awareness and sensitivity
- Effective communication skills

8.3 Reflective Practice

Teachers must continuously evaluate their teaching practices, identify areas for improvement, and adopt innovative strategies to enhance effectiveness.

9. Use of Technology in Inclusive Teaching

Technology plays a significant role in supporting inclusive education by enhancing communication and classroom management. It provides innovative tools that help teachers address diverse learning needs effectively.

9.1 Assistive Technologies

- Screen readers and speech recognition tools
- Educational software designed for diverse learners

9.2 Digital Learning Tools

- Online platforms for interactive and collaborative learning
- Multimedia resources such as videos and simulations

9.3 Classroom Management Tools

- Applications for tracking student progress and behavior
- Digital tools for lesson planning and organization

Technology enables personalized learning experiences and improves accessibility for all students.

10. Collaborative Approaches

Collaboration among stakeholders is essential for effective inclusive education.

10.1 Teacher Collaboration

- Team teaching and co-teaching models

10.2 Parental Involvement

- Regular communication with parents
- Support for student learning at home

10.3 Professional Support

- Involvement of counselors and special educators

- Interdisciplinary collaboration among professionals

Collaboration ensures comprehensive support for students and enhances learning outcomes.

11. Best Practices for Inclusive Teaching

Adopting best practices improves the effectiveness of inclusive education.

11.1 Teaching Practices

- Student-centered learning approaches
- Peer collaboration and cooperative learning

11.2 Classroom Environment

- Positive and respectful classroom climate
- Inclusive and accessible learning spaces

11.3 Continuous Improvement

- Ongoing assessment and feedback
- Adaptation of teaching strategies

12. Recommendations

To strengthen inclusive education, the following measures are recommended:

12.1 Institutional Measures

- Teacher training programs on inclusive practices
- Availability of adequate resources and support systems

12.2 Policy Measures

- Promotion of inclusive education policies
- Awareness programs on diversity and inclusion

13. Conclusion

Communication and classroom management are essential components of inclusive teaching. They enable teachers to address diverse learner needs, foster positive relationships, and create supportive learning environments. By integrating effective communication strategies with proactive classroom management techniques, educators can ensure meaningful participation for all students. Inclusive education contributes to academic success, social development, and mutual respect. Continuous efforts in training, resource development, and collaboration are necessary for achieving sustainable inclusive practices.

References

1. Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). *Improving schools, developing inclusion*. Routledge.
2. Ainscow, M. (2005). *Developing inclusive education systems*.
3. Booth, T., & Ainscow, M. (2011). *Index for Inclusion*.
4. Avramidis, E., & Norwich, B. (2002). Teachers' attitudes towards integration/inclusion: A review of the literature. *European Journal of Special Needs Education*, 17(2), 129–147.
5. Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
6. Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
7. Friend, M., & Cook, L. (2017). *Interactions: Collaboration skills for school professionals* (8th ed.). Pearson.
8. Gay, G. (2018). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice* (3rd ed.). Teachers College Press.
9. Hattie, J. (2009). *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. Routledge.
10. Florian, L. (2014). *What counts as evidence of inclusive education?* Tomlinson, C. A. (2001). *How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms*. UNESCO. (2017). *A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education*.
11. Kounin, J. S. (1970). *Discipline and group management in classrooms*. Holt, Rinehart & Winston.
12. Marzano, R. J. (2003). *Classroom management that works: Research-based strategies for every teacher*. ASCD.
13. Piaget, J. (1972). *The psychology of the child*. Basic Books.
14. Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. *Harvard Educational Review*, 57(1), 1–22.
15. Skinner, B. F. (1953). *Science and human behavior*. Macmillan.
16. Tomlinson, C. A. (2014). *The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners* (2nd ed.). ASCD.
17. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
18. Weinstein, C. S., Tomlinson-Clarke, S., & Curran, M. (2004). Toward a conception of culturally responsive classroom management. *Journal of Teacher Education*, 55(1), 25–38.

Value-Based Moral Teacher Education as the Foundation of Character Building

Dr. Vinod Kumar H. Pandya

Assistant Professor

The New Progressive College of Teachers' Education

Mehsana, Gujarat

Abstract

This article examines the decline of the Moral Quotient (MQ) and human values in contrast to the emphasis placed solely on Intellectual Development (IQ) in the modern education system. Research suggests that purely informative education increases social conflict, whereas value-based education leads

an individual toward inner peace and social responsibility.

Keywords: Value, Morality (Ethics), Importance of Values in Life, Teacher Education, Classification of Values in Education, Integration of Morality and Intellect.

Introduction

In human history, education is not merely a tool for literacy or livelihood; it is a process of soul-shaping and character building. For this character building, an individual must possess every type of commitment. What is commitment? When you accept a task and stick to completing it regardless of the difficulties that arise, it is called '**commitment**'.

Modern education discusses the decreasing influence of moral values against rising materialism. In Indian culture, 'Vidya' (knowledge) is linked with humility and wisdom. In the current digital and Artificial Intelligence era, technology possesses 'intelligence' but lacks 'wisdom' (discretion). Developing this power of wisdom is the primary goal of moral education. This article highlights various aspects of value-based education, its importance, and the challenges in implementing it.

❖ Value and Morality: Two Complementary Aspects

- **Value:** This is an individual's life compass. It determines what is most important in one's life—money, power, or humanity?
- **Morality (Ethics):** This is the standard of behavior. It explains the difference between 'what can be done' and 'what should be done'.

The original purpose of education is character building, not just earning a living. Character building requires commitment. **Commitment (Pratibaddhata)** refers to loyalty toward any task, idea, person, or goal where you remain firm in your decision despite difficulties and apply your full strength to complete it.

❖ Importance of Values in Education

Life without values is like a ship without a rudder. Its importance is as follows:

- **Ease in Decision Making:** When faced with difficult choices, our values help us choose the right path.
- **Character Building:** Good values create a distinct and prestigious identity for an individual in society.
- **Self-Satisfaction:** Living according to our values brings a sense of inner peace and satisfaction.
- **Sweetness in Relationships:** Values like love, trust, and respect strengthen relationships.
- **Social Welfare:** If everyone follows human values, crime decreases and peace is established in society.

❖ Classification of Values in Teacher Education

According to research, it is essential to instill values at the following four levels:

1. **Individual Level:** Self-discipline, honesty, and patience.
2. **Social Level:** Empathy, altruism, and acceptance of diversity.
3. **Professional Level:** Work ethics, loyalty, and commitment.
4. **Global Level:** Environmental sensitivity and peaceful co-existence.

❖ Why is Morality Necessary?

The need for moral education has increased in today's competitive era:

- **Events:** The increase in crime, chaos, corruption, and mental stress is primarily due to a lack of morality in education.
- **Trust:** People quickly trust a moral person.
- **Inner Peace:** A person doing wrong may achieve success, but they will not find peace of mind. Morality gives us the strength to live with pride.
- **Decision-making Power:** Moral education provides the ability to make the right decisions in difficult situations and makes future leaders responsible.
- **Social Unity:** Social unity—where people of different religions, castes, and cultures live together in brotherhood—is the foundation of a nation's progress.
- **Stability:** Morality makes a person firm during failure and humble during success. It balances every turn of life.

"The best morality is to behave with others as we expect them to behave with us."

❖ What is Moral Education?

Moral education is the education that teaches a human to distinguish between 'good' and 'bad' (right and wrong). It is not limited to reading books; it is a process to purify an individual's behavior, thoughts, and character. In short, education that teaches us to become a "good person" is moral education.

Key Objectives:

- **Character Building:** Developing qualities like honesty, patience, and courage.

- **Social Responsibility:** Understanding duties toward society and raising a voice against injustice.
- **Tolerance:** Respecting the thoughts, religions, and beliefs of others.
- **Self-confidence:** Gaining the strength to remain firm on one's ideals.

Core Elements:

1. **Integrity:** Being one in mind, word, and deed; doing what you say.
2. **Non-violence:** Not causing physical or mental pain to anyone.
3. **Altruism:** Helping others without selfishness.
4. **Humility:** Not being arrogant even when successful and treating everyone with love.

❖ Integration of Morality and Intellect

A purely intelligent person who is not moral can pose a risk to society (e.g., cybercrime, corruption). Moral education gives the right direction to intelligence.

The Role of the Teacher: Values are taught in institutions not through books, but through the teacher's 'conduct'. The teacher is a living role model for students. This is supported by the **National Education Policy (NEP 2020)**, which recommends weaving Indian moral values and culture into the curriculum.

❖ Challenges and Obstacles

23. **Race for Marks:** Education has become merely a tool for obtaining degrees.
24. **Lack of Role Models:** Ideals with moral values are decreasing in society and social media.
25. **Mechanical Life:** Physical comforts are given more importance than human sensitivities.

Conclusion

The ultimate goal of education is to prepare humans who are not only intelligent but also compassionate. Without the support of morality, science and technology can become destructive. For the holistic development of a nation, morality must be accepted as a 'lifestyle' rather than just a subject.

References

1. Aarya, K. Concept of Value Education according to Swami Vivekananda and Gandhi.

Multidisciplinary Higher Education, Research, Dynamics and Concepts: Opportunities and Challenges for Sustainable Development. 2018: 296-299.

2. Cairns, J., Gardner, R., and Lawton, D. Education for Values: Morals, Ethics and Citizenship in Contemporary Teaching. London: Kogan Page. 2003
3. Cubukcu, Z. The effect of Hidden Curriculum on Character Education Process of Primary School Students. Educational Science; Theory and Practice. 2012; 12(2):1526-1534.
4. Gulati, S., and Pant, D. Education for Values in Schools - A Framework. National Council of Educational Research and Training. 2014
5. Muijen, H. Integrating Value Education and Sustainable Development into a Dutch University Curriculum. International Journal of sustainability in Higher Education. 2004
6. Lakshimi, C. (2009). Value Education: An Indian Perspective on the Need for Moral Education in a Time of Rapid Social Change. Journal of College and Character, 10(3).
7. P.S.Grant. Teaching about Indian Culture through its Epic Literature: "The Mahabharata" and "The Ramayana". The Educational Resources Information Center (ERIC). 1988

Career Opportunities in Visual Arts – An Overview

Dr. Meenakshi Thakur

HEAD, Associate Professor,
Coordinator B.Voc. Textile and Commercial Art,
Department of Drawing and Painting, Faculty of Arts,
Dayalbagh Educational Institute, Agra, Uttarpradesh

Abstract

Art is an expression of human imagination, creativity and emotions. The way to express or exhibit the feelings of human heart is called 'Art', where creativeness accompanies aptitude. Visual arts constitute one of the most significant forms of human expression, reflecting the intellectual, emotional, and cultural dimensions of society. The visual art gathers various modes of art, which always work for human welfare along with providing the pleasure of being one with supreme soul. Since ancient times, art has served as a medium for communication, documentation, and aesthetic exploration. It transcends linguistic barriers and functions as a universal language that conveys ideas through visual

elements such as line, color, form, and composition. Traditionally, art was often perceived as a secondary discipline when compared to fields such as science, engineering, and medicine. However, this perception has undergone a significant transformation in recent decades. Today, visual arts are not only associated with cultural enrichment but also with economic productivity and innovation. The integration of art with digital technologies, media platforms, and global markets has significantly broadened its scope, making it a viable and promising career option.

Keyword: Art, creativeness transformation, technological innovation.

Introduction

The discipline of visual arts has undergone a profound transformation in the contemporary era, expanding beyond traditional artistic practices into a multifaceted domain influenced by technological innovation, globalization, and the growth of creative industries. In the 21st century, visual communication has become central to nearly every aspect of life—from digital interfaces and advertising, marketing to entertainment and education. This shift has elevated the importance of visual arts from a purely aesthetic pursuit to a critical component of modern economies and significantly broadened the scope of career opportunities available to individuals with creative abilities.

The scope of visual arts is vast and multifaceted, incorporating both traditional and contemporary disciplines. It includes fine arts such as painting, sculpture, ceramics, drawing, and printmaking, as well as applied fields like graphic design, photography, and visual communication. Traditional areas such as painting, sculpture, printmaking, and

drawing continue to hold cultural and historical significance, preserving artistic heritage and craftsmanship. At the same time, newer domains such as graphic design, digital illustration, animation, and user interface design have emerged as essential components of modern industries. This shift from purely aesthetic creation to functional and communicative design illustrates the interdisciplinary nature of visual arts today. Artists often act as observers and interpreters of society, using their work to reflect social realities, challenge norms, and inspire change. At the same time, visual arts education fosters critical thinking, problem-solving skills, and emotional intelligence, all of which are increasingly valued in today's modern professional environments.

The objective of this research paper is to provide a comprehensive and detailed overview of career opportunities in visual arts, examining both conventional and emerging pathways. It highlights the growing relevance of creative skills in contemporary economies and underscores the need for structured learning, adaptability, and innovation among aspiring professionals. Recent studies in creative industries

suggest that visual arts have become a key contributor to economic development and cultural innovation. Researchers have emphasized the increasing demand for creative professionals in sectors such as advertising, Animation and film production, gaming, and digital media. Additionally, literature highlights the role of visual literacy as an essential skill in the 21st century. Scholars also point out that globalization and digital platforms have enabled artists to reach wider audiences, thereby transforming traditional career models.

- Within traditional visual arts, One of the most recognized careers is that of a **Fine Artist. (Painter, Sculptor, Printmaker)** They research and implement creative ideas to create works that are often displayed in galleries, museums, and exhibitions. **Painting**, one of the oldest forms of visual representation, has evolved from realistic depictions to abstract and conceptual approaches that emphasize emotional and psychological depth. **Sculpture**, as a three-dimensional art form, continues to play a significant role in cultural and religious contexts, while also embracing modern materials and experimental techniques. **Printmaking**, historically associated with reproduction and dissemination, has adapted to contemporary practices through digital and hybrid methods. These traditional forms provide a strong foundation for artistic exploration, enabling artists to engage with both historical traditions and contemporary issues.
- Secondly, the role of a **Graphic Designer** has become indispensable in today's visual-driven market. In contrast to traditional forms, applied arts and visual communication have gained immense prominence in the modern economy. Graphic designers create visual content for branding, advertising, publishing, and digital platforms. A graphic designer uses type and images (photographic or illustrative) to communicate. Graphic designers play a crucial role in branding, advertising, publishing, and digital media, creating visual content that communicates messages effectively. Commercial art focuses on producing artwork for practical purposes, such as designing logos, packaging, advertisements, and promotional materials. With the expansion of businesses and

the increasing reliance on digital platforms, the demand for skilled professionals in graphic design and commercial art has grown exponentially, making it one of the most sought-after career paths within visual arts.

Today we live in the world of Information and Technology, where boundaries separating various media are getting rapidly distorted. The integration of technology has also led to the emergence of innovative career pathways that combine artistic creativity with technical expertise in the field of Contemporary Visual Arts.

- **Animation, VFX, and Multimedia-** Another rapidly growing field is **animation and multimedia**. With the expansion of film industries, OTT platforms, and gaming, professionals such as animators, storyboard artists, and visual effects (VFX) specialists and multimedia professionals are in high demand. These fields require a high level of technical proficiency as well as creative storytelling skills.
- **Illustration and Digital Art** Digital illustration has gained widespread recognition, particularly in publishing, advertising, and online media, where illustrators often work as freelancers or independent creators.
- **UI/UX -UI/UX Designers-** Another rapidly expanding area is user interface (UI) and user experience (UX) design, which focuses on enhancing the usability and accessibility of digital products. **UI/UX designers**, who design user-friendly digital experiences. The rise of social media platforms has also enabled artists to become independent content creators, building personal brands and monetizing their work globally. As technology continues to evolve, these fields are expected to offer substantial career growth and opportunities. These developments highlight the increasing importance of interdisciplinary knowledge in shaping contemporary artistic careers.
- **Photography and Cinematography** also represent significant areas within visual arts, offering diverse professional pathways. From

commercial photography and photojournalism to film-making and content creation, these fields allow individuals to capture and communicate stories through visual imagery.

- Additionally, **Design-Oriented Careers** such as fashion design, interior design, and industrial design illustrate how artistic creativity can be integrated with functionality and innovation. These fields not only contribute to aesthetic enhancement but also address practical and societal needs, further **emphasizing the relevance of visual arts in everyday life.**

In addition to industry-oriented careers, visual arts provide opportunities in areas such as Art Education, Research, Arts Administration, Museum Studies, and Art Conservation provide meaningful avenues for those interested in teaching, preserving, and studying art.

- **Art Education and Research-** Careers in teaching, art history, and research contribute to academic development and knowledge dissemination and play a vital role in preserving and disseminating artistic knowledge.
- **Arts Administration** -Arts administration facilitates the daily operations and long-term goals of cultural organizations, bridging creative vision with business management. These professionals manage finances, marketing, fundraising, and logistics for theaters, museums, and galleries, ensuring organizational sustainability and artistic integrity.
- **Museum Studies and Art Conservation**-These careers involve preserving, managing, and curating artistic and cultural heritage.
- **Art Therapy** - Art therapy has also emerged as a meaningful profession, utilizing creative expression as a tool for emotional healing and psychological well-being.
- **Freelancing and Entrepreneurship:** Furthermore, the rise of digital platforms has enabled artists to pursue freelancing and entrepreneurship, allowing them to reach global audiences and establish independent careers.

Despite the expanding opportunities, a successful career in visual arts requires a comprehensive set of skills that extend beyond artistic talent. It demands a combination of creative, technical, and professional skills. Creativity and originality remain fundamental, but they must be complemented by technical

proficiency in both traditional techniques and digital tools. Critical thinking and problem-solving abilities are essential for conceptual development, while strong communication skills enable artists to convey their ideas effectively. In addition, digital literacy has become increasingly important in navigating modern technologies and platforms. Professional skills such as portfolio development, networking, and self-promotion are equally crucial in establishing a successful career.

Education and training play a pivotal role in preparing individuals for careers in visual arts. Academic programs such as Bachelor of Fine Arts (BFA) and Master of Fine Arts (MFA) provide structured learning environments that foster both technical skills and conceptual understanding. These programs also encourage experimentation, critical analysis, and interdisciplinary collaboration. Institutions across India and globally offer specialized courses in visual arts, contributing to the development of skilled professionals. Additionally, scholarships and fellowships provided by government and private organizations support emerging artists, enabling them to pursue their creative aspirations.

The increasing demand for visual content in contemporary society has significantly enhanced employment prospects in visual arts. Industries such as advertising, media, entertainment, e-commerce, and digital marketing rely heavily on visual communication, creating a constant need for creative professionals. Job roles such as graphic designer, art director, animator, illustrator, photographer, web designer, and museum curator have become integral to these industries. Moreover, the flexibility of working as a freelancer or entrepreneur allows individuals to explore diverse opportunities and achieve financial independence.

However, a career in visual arts is not without its challenges. Artists often face intense competition, fluctuating income, and the need to continuously update their skills in response to technological advancements. The ability to adapt, innovate, and remain persistent is essential for overcoming these challenges. Nevertheless, the future of visual arts appears highly promising, driven by ongoing technological developments and the growing importance of visual communication in a globalized world.

This research paper examines the diverse career opportunities within visual arts, including both conventional practices such as painting and sculpture and emerging fields like digital design, animation, and user experience design. It further explores the role of education, skill development, and technological advancements in shaping career pathways. The findings suggest that visual arts offer sustainable and expanding professional opportunities, provided individuals possess adaptability, creativity, and technical competence.

In conclusion, visual arts have evolved into a multifaceted and interdisciplinary field that offers extensive career opportunities across traditional and contemporary domains. The integration of creativity with technology, communication, and industry has redefined its scope and significance. For aspiring professionals, visual arts provide a platform to transform passion into a meaningful and sustainable career. With the right combination of education, skills, talent, creativity, innovation and imagination individuals can contribute to cultural development,

economic growth, and social innovation. As the world becomes increasingly visual and interconnected, the importance of visual arts will continue to expand, making it a vital field for future generations. The findings suggest that visual arts represent a rapidly evolving field with significant economic, cultural, and professional potential. The integration of creativity with technology and industry demands has redefined its scope and relevance.

In the contemporary times, Visual arts have evolved into a dynamic and interdisciplinary field offering diverse and sustainable career opportunities. The increasing demand for visual content across industries underscores the importance of creative professionals in modern society. Visual Arts is one such field that adds wings to the artists' career. In conclusion, visual arts is no longer just about creating art—it is about creating opportunities, shaping experiences, and influencing the world around us. If you have creativity within you, do not ignore it. Nurture it, develop it, and give it the space it deserves.

References

1. "The Economic Struggles of Emerging Fine Artists in India's Contemporary Art Landscape" Kaavya Mittal, International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology (ISSN: 2454-132X) © 2025, IJARIT - All rights reserved. Website: www.ijariit.com Talk to Counselor: 9056222273 Page: 205 ISSN: 2454-132X Impact Factor: 6.078 (Volume 11, Issue 5 - V11I5-1209) Available online at: <https://www.ijariit.com> Margins and Gateways.
2. "Careers Opportunities in Visual Arts"-October, 2024 published by the National Institute for Career Service (NICS), Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment, Government of India, A-49, Sector 62, NOIDA-201309.
3. "A Career Guide for Studio Art Majors" by Fine Arts Career Services, The University of Texas at Austin, DFA 1.103 <http://www.utexas.edu/finearts/careers> [512] 232-7333, facs@austin.utexas.edu, twitter.com/utfacs, <http://www.facebook.com/utfacs>
4. "Art Career Summary" By Office of Career Education & Development Slippery Rock University, 124 Bailey Library, 724.738.2028 Career. Education@sru.edu, www.sru.edu/career, @SRUCareer.
5. "Employment Opportunities in Fine Arts "Dr. Jai Shankar Mishra The author is Associate Professor and Ex. Head Dept. of Professional Art Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Chitrakoot, Satna (M.P) ,VOL. XL NO. 18 PAGES 48 New Delhi 1 - 7 August 2015.
6. "The Future of Work in the Arts and Entertainment Sector" Report for the Technical Meeting on the Future of Work in the Arts and Entertainment sector (Geneva, 13–17 February 2023) Copyright © International Labour Organization 2023 First edition 2023 Publishing (Rights and Licensing), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland.
7. Arens, W.F. and Bovee, C.L., Contemporary advertising. USA: Irwin, 1994.
8. Frutiger, A. Signs and symbols. New York: Van Nostrand, 1989.
9. Kant, A. Branding India. Noida: Collins Business, 2009.

Educational Technology, Multi-Media Program and Its Opportunities for Employment Generation.

Jagrutiben B. Patel * Dr Gitaben D Dave**

*Research Scholar -Department of Education ,

Hemchandracharya North Gujarat University Patan, Gujarat

** Principal - Shri Saraswati Shikshan Mahavidyalay Unjha,

Hemchandracharya North Gujarat University Patan, Gujarat

Abstract

Educational technology means utilizing technology in education to achieve educational goals and objectives. By using technology in the classroom, teaching can be made interesting, simple, and effective. Using computers, the internet, smartboards, mobile

applications, and online classes, education can be made vibrant.

Keyword: Education technology, Effective, Smartboards, explosion.

Introduction

In today's modern era, technology has become an inseparable part of human life. Today's age is the age of information explosion and the age of science. The use of technology in the field of education is known as Educational Technology.

Educational technology means utilizing technology in education to achieve educational goals and objectives. By using technology in the classroom, teaching can be made interesting, simple, and effective. Using computers, the internet, smartboards, mobile applications, and online classes, education can be made vibrant.

Technology is related to science and Shastra; it is the application of systematic knowledge in educational practice.

- ✓ The modern era is called the "Era of Technology".
- ✓ The scope of technology is increasing in every field, providing new opportunities for employment.
- ✓ Educational technology has brought a revolution in education, making it simpler.
- ✓ It removes the limitations of time and place.
- ✓ Students' interest and enthusiasm increase, and education becomes accessible to all.
- ✓ Teaching becomes lively and effective.
- ✓ The development of educational technology has opened many new paths for employment.

Role Description & Benefits

❖ Educational Technology

1 Online Teacher:

- * Using online platforms, video calls, apps, and digital tools for teaching.
- * Removes time and place constraints.
- * Students can learn easily and interestingly.
- * Provides work-from-home opportunities during pandemics.

2 Content Creator:

- * Preparing educational videos, notes, and courses to earn income.
- * Creating educational materials, blogs, and social media posts.
- * Posting work on YouTube and Instagram to gain employment.
- * Helping students gain new information and knowledge

3 YouTube Education Channel

- * Teachers can create channels to reach students and find employment opportunities.
- * Companies promote products through these videos.
- * Potential to earn monthly fees from subscribers.
- * Teachers can create channels to reach students and find employment opportunities.

4 Software Developer

- * Freelancing and project-based ext income.
- * Developing computers, mobile apps, and educational applications.
- * Jobs in IT companies, starting startups, or developing games.

* Freelancing and project-based extra income.

5 Digital Marketing & Other Fields

* The demand for digital marketing experts has increased to promote education and apps. This includes:

* Social Media Marketing and Search Engine Marketing.

* Email Marketing and Website Promotion.

* Content Marketing.

❖ Multimedia Program and Its Opportunities

Multimedia is the combination of text, audio, images, video, and animation. In today's digital age, multimedia has become an important part of our daily life. It is widely used in education, entertainment, business, and advertising.

Multimedia has created many employment opportunities for people. There are various career options such as Graphic Designer, Video Editor, Animator, Web Designer, and Digital Marketer. People can also work as Content Creators on platforms like YouTube and social media.

To work in the multimedia field, a person needs creativity, technical knowledge, and computer skills. Knowledge of different software and tools is also helpful for better career growth.

Moreover, multimedia offers opportunities for freelancing and self-employment. Many people earn money by working from home through online platforms.

o Educational Technology and Multimedia Program Challenges

✓ Lack of internet and equipment in villages.

✓ Misuse of Multimedia technology and distraction among students.

✓ Distance from traditional education.

✓ Success may not be immediate; requires long working hours.

✓ High competition and time-consuming nature of staying updated.

Conclusion

By using educational technology, digital tools, and the internet, many new employment opportunities have been created, including both self-employment and jobs. Educational technology is a vital tool for the future that helps in making humans self-reliant. multimedia is a growing field with many job opportunities. With proper skills and hard work, one can achieve success and build a bright future in this field.

References

1. Bennett, S., & Maton, K. (2010). Beyond the 'Digital Natives' Debate: Towards a More Nuanced Understanding of Students' Technology Experiences. *Journal of Computer Assisted Learning*, 26(5), 321-331. This article provides insights into how students in rural areas experience and utilize technology, which is essential for understanding the landscape of digital literacy.
2. Lloyd, S. A., & Ghosh, S. (2019). Empowering Rural Entrepreneurs through Digital Literacy: Challenges and Opportunities. *Journal of Business Research*, 98, 366-378. This study discusses how digital literacy can empower rural entrepreneurs, driving economic growth and job creation.
3. Nill, A., & Schermer, B. (2021). The Role of Digital Literacy in the Employment of Older Adults in Rural Areas: A Review. *Journal of Rural Studies*, 84, 167-174. This academic article examines the connection between digital literacy and employment for older adults in rural settings.
4. OECD. (2019). Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills. This report discusses adult skills, including digital literacy, and their impact on employment and economic outcomes, with a focus on different regions, including rural areas.
5. World Bank. (2020). Digital Dividends: World Development Report 2016. While this report broadly discusses the impact of digital technology on development, it includes sections relevant to rural employment and the necessity of digital skills in achieving economic growth.

Teacher Education and Skill Development: A Catalyst for Transformative Learning in the 21st Century

Uddhav Kumar

Assistant Professor, English

M.G. College, Mahwa, Dausa, Rajasthan

Abstract

In the rapidly evolving landscape of the 21st century, education stands at the crossroads of tradition and transformation. Teacher education, once confined to the transmission of pedagogical knowledge, has now emerged as a dynamic process aimed at equipping educators with multifaceted skills. This research paper explores the intrinsic relationship between teacher education and skill development, emphasizing their pivotal role in shaping a progressive and knowledge-driven society. Drawing upon the insights of eminent scholars, contemporary educational theories, and

policy frameworks, the paper highlights the need for a paradigm shift in teacher training programs. It argues that fostering critical thinking, digital literacy, emotional intelligence, and lifelong learning among teachers is indispensable for achieving holistic educational outcomes. The study concludes with strategic recommendations to align teacher education with global standards and national aspirations.

Keywords: Teacher Education, Skill Development, Pedagogy, Professional Competence, Digital Literacy, Educational Reforms

1. Introduction

Education is often described as the “backbone of a nation,” and teachers are its “architects.” As the proverb goes, “A good teacher is like a candle—it consumes itself to light the way for others.” In the contemporary era, however, the role of teachers has transcended beyond mere knowledge dissemination. They are facilitators, mentors, innovators, and lifelong learners.

Teacher education, therefore, must evolve to meet the demands of a knowledge-based economy. Skill development has become the cornerstone of this evolution. In the words of John Dewey, “If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow.” This statement underscores the urgency of redefining teacher education in alignment with modern skill requirements.

2. Conceptual Framework of Teacher Education

Teacher education refers to the structured programs and processes designed to equip prospective and in-service teachers with the knowledge, skills, attitudes, and values necessary for effective teaching.

2.1 Objectives of Teacher Education

- To develop pedagogical competence
- To foster critical and reflective thinking
- To cultivate professional ethics
- To enhance communication and interpersonal skills

According to NCTE (National Council for Teacher Education), teacher education must aim at holistic development, ensuring that teachers are not only subject experts but also socially responsible individuals.

2.2 Changing Paradigms

Traditional teacher education focused on rote learning and rigid methodologies. However, modern approaches emphasize:

- Learner-centered pedagogy
- Experiential learning
- Inclusive education
- Technology integration

As Paulo Freire aptly remarked, “Education does not change the world. Education changes people. People change the world.”

3. Skill Development: The Core of Modern Education

Skill development refers to the process of identifying, nurturing, and enhancing abilities that enable individuals to perform tasks effectively.

3.1 Types of Skills in Teacher Education

a) Cognitive Skills

- Critical thinking
- Problem-solving
- Analytical reasoning

b) Technical Skills

- Digital literacy
- Use of educational technology
- Online teaching competencies

c) Social and Emotional Skills

- Empathy
- Communication
- Classroom management

d) Professional Skills

- Lesson planning
- Assessment strategies
- Curriculum design
- As the saying goes, "Knowledge is power, but skill is the key to unlocking that power."

4. Interrelationship between Teacher Education and Skill Development

Teacher education and skill development are two sides of the same coin. Effective teacher education inherently involves skill acquisition, while skill development is incomplete without pedagogical grounding.

4.1 Enhancing Teaching Effectiveness

- A well-trained teacher with refined skills can:
- Engage students actively
- Simplify complex concepts
- Foster a positive learning environment

4.2 Bridging the Gap between Theory and Practice

One of the major challenges in teacher education is the disconnect between theoretical knowledge and

classroom realities. Skill-based training, including internships and micro-teaching, helps bridge this gap.

4.3 Promoting Lifelong Learning

In the words of Albert Einstein, "Once you stop learning, you start dying." Teacher education must instill a spirit of continuous learning and adaptability.

5. Role of Technology in Teacher Education and Skill Development

The digital revolution has transformed every sphere of life, and education is no exception.

5.1 Integration of ICT

- Information and Communication Technology (ICT) has:
- Revolutionized teaching methodologies
- Enabled virtual classrooms
- Facilitated access to global resources

5.2 Online Learning Platforms

Platforms like MOOCs (Massive Open Online Courses) have democratized education, allowing teachers to upgrade their skills continuously.

5.3 Challenges of Digitalization

- Digital divide
- Lack of infrastructure
- Need for digital literacy training

As Bill Gates once said, "Technology is just a tool. In terms of getting the kids working together and motivating them, the teacher is the most important."

6. Policy Perspectives and Educational Reforms

6.1 National Education Policy (NEP) 2020

- The NEP 2020 emphasizes:
- Multidisciplinary teacher education
- Skill-based learning
- Continuous professional development

6.2 Global Perspectives

- Countries like Finland and Singapore have redefined teacher education by focusing on:
- Research-based training
- Practical exposure
- High professional standards

6.3 Need for Policy Implementation

Policies must not remain on paper; effective implementation is crucial. As the idiom goes, "Actions speak louder than words."

7. Challenges in Teacher Education and Skill Development

Despite significant progress, several challenges persist:

7.1 Lack of Quality Training Institutions

Many institutions fail to provide adequate practical exposure.

7.2 Outdated Curriculum

Curricula often lag behind contemporary needs.

7.3 Inadequate Skill Training

Focus remains on theoretical knowledge rather than practical skills.

7.4 Resistance to Change

Teachers may resist adopting new methodologies.

7.5 Assessment Issues

Traditional assessment methods do not evaluate skill proficiency effectively.

8. Suggestions and Recommendations

To enhance teacher education and skill development, the following measures are recommended:

8.1 Curriculum Reform

Incorporate skill-based modules

Emphasize interdisciplinary learning

8.2 Practical Training

Strengthen internships and fieldwork

Promote experiential learning

8.3 Continuous Professional Development

Organize workshops and training programs

Encourage self-learning through online platforms

8.4 Technology Integration

Provide digital infrastructure

Train teachers in ICT tools

8.5 Collaborative Learning

Foster peer learning and knowledge sharing

8.6 Evaluation Reforms

Introduce skill-based assessment methods

As the proverb goes, "Rome was not built in a day," but consistent efforts can bring transformative change.

9. Role of Teachers in Nation Building

Teachers are the torchbearers of society. Their role extends beyond classrooms to shaping the moral and intellectual fabric of the nation.

In the words of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, "Teachers should be the best minds in the country." This highlights the need for excellence in teacher education.

10. Conclusion

Teacher education and skill development are the twin pillars of a robust educational system. In an era marked by rapid technological advancements and global competition, the need for skilled and competent teachers has never been greater.

This research paper underscores that teacher education must go beyond conventional boundaries and embrace innovation, inclusivity, and adaptability. Skill development should be integrated at every stage of teacher training to ensure holistic growth.

To put it succinctly, "A teacher who is not a learner is like a well without water." Therefore, continuous learning and skill enhancement must become the hallmark of the teaching profession.

By aligning teacher education with the demands of the 21st century, we can pave the way for a brighter, more enlightened future.

References :-

- Dewey, John – Democracy and Education
- Freire, Paulo – Pedagogy of the Oppressed
- National Education Policy (2020)
- NCTE Guidelines on Teacher Education
- UNESCO Reports on Teacher Development
- Radhakrishnan, S. – Educational Philosoph

Environmental Conservation in Indian Knowledge System

Mrs. Anjana Pareek

Assistant Professor

Department of Education

Jagan Nath University, Jaipur, Rajasthan

Abstract

This research paper examines the profound and systematic integration of environmental conservation principles within ancient and traditional Indian knowledge systems. It argues that far from being merely folk traditions, these systems embedded sophisticated ecological wisdom into religious, philosophical, and sociocultural practices, creating a sustainable framework for human-nature interaction. Through an analysis of foundational texts, cultural practices, and traditional lifestyles, this paper identifies key themes such as animism in Vedic literature, reverence for sacred groves as early

biodiversity preserves, the concept of Dharma (duty) as applied to nature, and the promotion of sustainability in daily life through concepts like Aparigraha (non-possessiveness). The findings suggest that these historical paradigms offer valuable conceptual frameworks and ethical imperatives for addressing contemporary global ecological crises, advocating for a critical and creative dialogue between ancient wisdom and modern science.

Keywords: Indian Knowledge System, Environmental Conservation, Sacred Groves, Dharma and Nature, Sustainability Practices, Aparigraha

Introduction:

The global environmental crisis, characterized by climate change, biodiversity loss, and ecological degradation, has prompted a search for sustainable paradigms beyond purely technological solutions. In this context, a re-examination of ancient and traditional ecological knowledge systems has gained significant traction. Indian civilization, one of the world's oldest continuous cultures, offers a rich repository of such knowledge, where environmental ethics were woven into the very fabric of life, philosophy, and social organization. The Indian knowledge system—encompassing Vedic texts, philosophical treatises, folk traditions, and local practices—did not view nature as a mere resource to be exploited but as a sacred, interconnected web of life (Prakriti) of which humanity is an integral part. This paper aims to systematically explore the principles, manifestations, and contemporary relevance of environmental conservation within this system, positing that it represents a sophisticated, albeit non-Western, form of pre-modern ecological science and ethics.

Background and Literature Review:

Scholarly interest in the ecological dimensions of Indian thought has grown in recent decades. Historian Ramachandra Guha's work, particularly 'How Much Should a Person Consume?' (2006), situates Indian environmental thought within a global history of conservation, contrasting Gandhian notions of frugality with Western consumerism. Similarly, Vandana Shiva, in 'Staying Alive: Women, Ecology and Development' (2010), critiques reductionist Western science through the lens of Prakriti (nature), which she posits as a feminist, life-giving principle central to Indian cosmology.

In religious and scriptural studies, scholars have analyzed the ecological underpinnings of Hindu, Buddhist, and Jain traditions. O.P. Dwivedi (2000) has extensively documented how Vedic hymns, the Upanishads, and the epics contain a theology of the sacredness of the natural world. The concept of Panchamahabhuta (the five great elements: earth, water, fire, air, and space) as the foundational constituents of all existence provides a metaphysical

basis for ecological interconnectedness. Beyond Hinduism, Jainism's principle of Ahimsa (non-violence) extends to the most microscopic life forms (jivas), and Buddhism's emphasis on dependent origination (Pratītyasamutpāda) similarly underscores interdependence.

A key area of research focuses on practical conservation institutions. The tradition of Devrai or Sacred Groves—patches of forest dedicated to a deity—has been studied as an indigenous model of biodiversity conservation and watershed protection (Gadgil & Vartak, 1976). These groves, found across India, functioned as inviolable sanctuaries, preserving endemic flora and fauna long before the concept of a national park was formalized.

Methodology

This study employs a qualitative, interdisciplinary methodology, analyzing primary and secondary sources within an interpretative framework.

Primary Sources: Analysis of key textual sources from the Indian knowledge system forms the core of the primary research. This includes relevant hymns from the Rigveda (e.g., hymns dedicated to Prithvi—Earth, and Varuna—the cosmic order), passages from the Atharvaveda, and principles drawn from the Upanishads, the Bhagavad Gita, and Jain and Buddhist canonical literature. These texts are examined for their explicit and implicit environmental ethics.

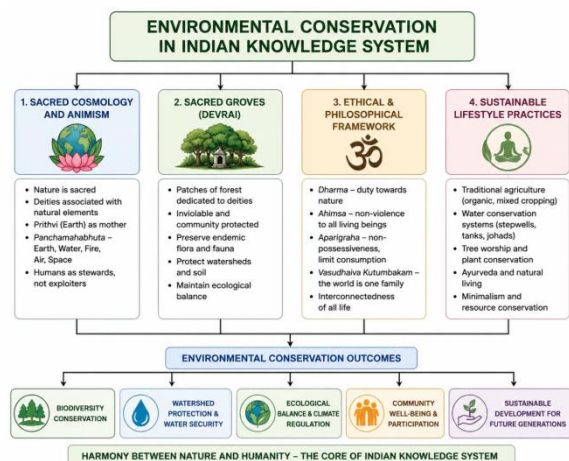
Secondary Sources: Scholarly books, peer-reviewed journal articles, and reports by environmental historians and philosophers provide critical interpretation and contextualization of the primary material. Works by Guha, Shiva, Dwivedi, and Gadgil, among others, are synthesized to construct a coherent narrative of Indian environmental thought.

Thematic Analysis: Data from the sources are organized into coherent themes: Sacred Cosmology and Animism, Institutional Practices (Sacred Groves), Ethical Frameworks (Dharma, Ahimsa, Aparigraha), and Sustainable Lifestyles. This allows for a structured exploration of both the philosophical foundations and practical applications of environmental conservation.

Results:

The investigation reveals a multi-layered and deeply embedded system of environmental conservation.

1. Sacred Cosmology and Animism: Vedic literature is replete with a reverential, animistic view of nature. Deities are associated with natural phenomena: Agni (fire), Vayu (wind), Indra (rain), and Surya (sun). The Earth is personified as the goddess Prithvi, a mother to be revered and protected. The Bhagavad Gita (Chapter 9, Verse 10) explicitly states that nature (Prakriti) works under the divine's supervision, establishing a sacred duty for humans to act as stewards, not masters.
2. The Institution of Sacred Groves (Devrai): These were perhaps the most direct form of pre-colonial conservation. Studies by Gadgil and Vartak (1976) document thousands of such groves across India, protecting unique ecosystems through religious taboo. They served as genetic reservoirs, preserved watersheds, and maintained local microclimates, demonstrating a community-based, sustainable land-use model.
3. Ethical and Philosophical Imperatives: Several key philosophical concepts enforced ecological responsibility. Dharma (righteous duty) includes one's duty to protect the environment. Ahimsa, central to Jainism and Buddhism, mandates non-harm to all living beings. The principle of Aparigraha (non-possessiveness or non-hoarding) in Jainism and Yogic philosophy directly advocates for minimal consumption and simplicity, countering the ethos of exploitation.
4. Sustainable Lifestyle Practices: Traditional Indian lifestyle norms promoted sustainability. The Ayurvedic system underscored the health of the individual and the environment as intertwined. Practices like Vanaspati (worship of specific trees like Peepal and Banyan), fasting on certain days (Ekadashi), and vegetarianism in many communities reduced ecological footprints and fostered mindfulness towards resources.



Discussion:

The findings underscore that environmental conservation in the Indian knowledge system was not an add-on but a constitutive element of a holistic worldview. This system successfully integrated ecological wisdom into daily life through a powerful combination of spiritual belief, ethical mandate, and practical institution-building. However, a critical discussion must acknowledge the gap between this idealized paradigm and contemporary Indian reality, where severe pollution and deforestation are rampant. This divergence can be attributed to colonial resource extraction, post-independence developmental pressures, population growth, and the erosion of traditional community governance structures.

The contemporary relevance of this knowledge lies not in a romantic return to the past, but in extracting its core ethical and conceptual principles. The idea of seeing nature as a sacred, rights-bearing entity resonates with modern concepts like the "Rights of Nature" movement. The community-managed model of Sacred Groves offers insights for participatory forest governance. Most importantly, the ethical call for restraint (Aparigraha) and duty (Dharma) provides a vital counter-narrative to the unsustainable paradigms of endless growth and consumption.

Conclusion:

This paper has demonstrated that the Indian knowledge system housed a sophisticated and holistic

framework for environmental conservation. Rooted in a sacred cosmology that viewed the natural world as intrinsically valuable and interconnected, it operationalized this view through religious institutions like Sacred Groves, ethical principles like Ahimsa and Aparigraha, and sustainable lifestyle practices. While modern challenges are unprecedented in scale and require scientific and technological solutions, the ethical and cultural resources of this ancient system remain profoundly relevant. The path forward may lie in a creative synthesis—where the reverence, restraint, and ecological wisdom of the Indian tradition inform and temper the application of modern science, fostering a truly sustainable and equitable relationship with the planet. Reviving and reinterpreting these principles for the 21st century is not merely an academic exercise but a potential contributor to global ecological discourse and action.

References:

1. Dwivedi, O. P. (2000). *Dharma and ecology of Hindu communities: Sustenance and sustainability*. Routledge.
2. Gadgil, M., & Vartak, V. D. (1976). The sacred groves of Western Ghats in India. *Economic Botany*, 30(2), 152–160.
3. Guha, R. (2006). *How much should a person consume?: Environmentalism in India and the United States*. University of California Press.
4. Shiva, V. (2010). *Staying alive: Women, ecology, and development*. South End Press. (Original work published 1988).
5. Singh, S. (2018). Ecological traditions of India. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 8(4), 414–426. <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-02-2018-0012>
6. The Bhagavad Gita. (E. Easwaran, Trans.). (2007). Nilgiri Press. (Original work circa 2nd century BCE).

A Study on Students Awareness and Satisfaction Towards Mobile Commerce

Dr. Deepika Sharma

Associate Professor

Department of Education

Jagannath University, Jaipur, Rajasthan

Ayasha Badgoti

Teacher Trainee

Department of Education

Jagannath University, Jaipur, Rajasthan

Abstract

Mobile commerce is a buzz today in India. M-Commerce is conducting business by using mobile device; it is an extension of electronic commerce. It is used to banking, buy tickets, paying insurance premium, buying gifts and recharging mobile accounts. Many companies in India started using mobile for doing business financial sector, Telecom sector Banking and Real Estate are some of the sectors using mobile commerce. In spite of M-Commerce is subset of E-commerce it has many advantages like accessible at any place, more secure and convenient. M-Commerce with features like ubiquity, convenience, personalization and timely service, it is going to be next generation mode of business. The 21st century has witnessed a revolution in commerce driven by digital transformation. The combination of internet technology, information

systems, and digital payment infrastructure has reshaped global trade. E-commerce, broadly defined as the exchange of goods and services through electronic networks, enables transactions that go beyond geographical and temporal boundaries. The expansion of e-commerce is not limited to developed countries; it is also growing rapidly in emerging economies such as India and China. With increased internet access, online marketplaces like Amazon, Flipkart, Taobao, and JD.com have democratized retail access. An attempt has been made through this research to find out how much awareness and satisfaction there is among students regarding mobile commerce.

Keywords: Mobile Commerce, Services, Technology, Electronic commerce, Digital Payment

Introduction

The increase of mobile phone usage has produced a new avenue for marketing applications and services. Mobile has become the leading way for accessing communications because setting-up mobile network is cost-efficient but also mobile provides greater flexibility and ease to users than landline phone. Mobile is the latest happening thing not only in India but in the world. By the advent of latest technologies in mobile handsets and sophisticated services by service providers in Indian Mobile telecom market is a buzz. Making India the fastest growing mobile phone market. By using m-commerce we can access advanced mobile applications and high speed services and we can use this devices remotely, anywhere, at any time.

We can use the same hand held device for both Telecommunications and for bill payment and account evaluation. M-commerce is an advanced technology

of e-commerce. In short, Mobile commerce is defined as the buying and selling of products and services through the use of wireless mobile devices. Commerce deals with exchange of goods and services of economic value between producer and consumer. With invention of new technologies and methods, commerce has taken many forms. The way of dealing, exchanging of goods and services has undergone massive changes with days passed on. With competition emerging, consumers becoming more aware and having more choice, marketers searching for innovative ways to deals with customers to be in forefront to break the competition.

The conceptual background and perspective

Before defining the mobile aspects of commerce (Mobile Commerce) and distinguishing them from the mobile aspects of business (Mobile Business), it is imperative to establish working definitions of the terms "commerce" and "business", as they seem to

have transcended their dictionary meanings and acquired new significance since the advent of the Internet economy. In this section we further differentiate between the terms "electronic" and "mobile", so as to clarify the respective concepts by showing their similarities and highlighting their differences.

i) **Commerce:-** Commerce deals with exchange of goods and services of economic value between producer and consumer. With invention of new technologies and methods, commerce has taken any forms. The way of dealing, exchanging of goods and services has undergone massive changes with days passed on. With competition emerging, consumers becoming more aware and having more choice, marketers searching for innovative ways to deals with customers to be in forefront to break the competition.

ii) **E-Commerce:-** E-commerce is buying and selling of products, services by business and consumers through an electronic medium, without using any paper documents. E-commerce, stands for electronic commerce, on the internet, it pertains to a website, which sells products or services directly from the site using a shopping cart or shopping basket system and allows payments through cards, e-banking, cash on delivery. Customers can purchase anything by sitting comfortably in their office or home and gift it to someone sitting miles apart just by click of a mouse. It offers several benefits to businesses like easily reaching to a fast growing online community, providing unlimited shelf place for products and services, merging the global geographical and time zone boundaries and helping to reach national and global markets at low operating costs. Ease of internet access and navigation are the critical factors that will result in rapid adoption of E-commerce. Safe and secure payment modes are essential to popularize E-commerce in India. Though it offers many benefits to users, there are many reasons for not shopping online like are lack of trust, security concerns, uncertainty about product and service quality, delay or non-delivery of goods, and lack of touch-and feel shopping experience.

iii) **Mobile Commerce:-** Mobile Commerce is known as M-Commerce. M-Commerce are used to buy and sell goods by using the wireless devices like cell phones, personal digital assistants and other hand held devices that have operated with Internet access. By using M-Commerce we can access advanced mobile applications and high speed services and we can use this devices remotely, anywhere, at any time. We can use the same hand held device for both Telecommunications and for bill payment and account evaluation. M-commerce is a subset of E-commerce'. The time and space limitation are removed and we can access any time we need. It is a result of combining two strongly emerging trends: electronic commerce and omnipresent computing. It is online anywhere, anytime and on any device and is providing new business opportunities. "Internet +Wireless+ E-Commerce = M-Commerce" Mobile Commerce is still in its development phase in India, here it is primarily used for basic banking, purchase of tickets, payment of utility bill etc.

Mobile payment

This term refers to payments that are made via mobile hand-held devices in order to purchase goods and services. Mobile payment services usually act as an intermediary between consumer and vendor. Prominent examples of such services are "Mobile Wallet", a service by T-Mobile, and the "M-Pay" of Vodafone. It is a hybrid form of payment that combines elements from other methods of payment, e.g. credit cards, prepaid cards, invoicing and telephone bills. Types of Mobile transactions / payments:

1. **Mobile web payments:** Through web pages payment is made under this system, to make payment customer has to enter mobile phone number and password on micro browser of web message from the partner bank is received after verification of password. Customer has to confirm the bank by sending an SMS; finally payment is directly debited from the bank account of the customer.

History of Mobile Commerce

Mobile Commerce in the beginning started with wireless Point of Sale (POS) Swipe terminals and then entered into cellular phones and PDAs (Personal

Digital Assistants). The first enabling M-Commerce technologies were presented through wireless Application Protocol (WAP) and mode mobile internet service. The first mobile commerce was started by Coca-cola in 1997 in Helsinki area in Finland by enabling vending machine to accepting payment sent by mobile phones. First mobile Banking service was launched by Merida bank of Finland in 1997. In 1999 Smart money, a national payment system by Smart was launched in Philippines. In Japan NTT DoCoMo launched first mobile internet platform which was revolutionary.

The following are the features of Mobile commerce, making it one of the effective ways of doing commerce:

- Ubiquity: consumers can avail or buy products/services from anywhere independent of His/her current geographic location. Customer can buy respective of the regions they reside or companies can do business.
- Convenience: Services like GPRS gives convenience and keeps always in touch and connected. This helps the companies to well connect with the customers.
- Personalization: M-Commerce services has been personalized, it can be used as per requirement of the consumer.
- Location based services: a service such as GPS allows companies to offer goods and services as per the location based.
- Timely services: consumers are directly connected; it provides real time availability of service.

Mobile Banking

With mobile commerce or m-commerce technology, consumers can use mobile phones, Personal Digital Assistant (PDA) and laptop computers to access the internet, send and receive messages and make transactions at any time from any places without having tied to a particular location. Mobile banking is a subset of electronic banking which underlies not only the determinants of the banking business but also the special conditions of mobile commerce. Mobile Banking has been gaining increasing popularity amongst various sections of the society for past few years, having recovered from the shock of the dot-com burst. Mobile Banking refers to provision and

availment of banking- and financial services with the help of mobile telecommunication devices. The scope of offered services may include facilities to conduct bank and stock market transactions, to administer accounts and to access customized information. With mobile technology, banks can offer services to their customers such as doing funds transfer while travelling, receiving online updates of stock price or even performing stock trading while being stuck in traffic. Smart phones and 4G connectivity provide some capabilities that older text Message-only phones do not. The convergence of mobile communications and distributed networked computing has provided the foundation for the development of a new channel of electronic business, mobile business. Mobile business (m-business) is defined as the use of the mobile information technologies, including the wireless Internet, for organizational communication and coordination, and the management of the firm. M-Banking is a term used for performing balance checks, account transactions, payments, credit applications etc. via a mobile device such as a mobile phone or Personal Digital Assistant (PDA). It is the convenient, simple, secure, anytime and anywhere banking. Many new e-commerce applications will be possible and Significantly benefit from emerging wireless and mobile networks.

Scope of the study

The application area of M-Commerce is very wide i.e. mobile banking, mobile information services, mobile shopping, mobile ticketing, mobile marketing, mobile entertainment, etc. Due to number of restraint in the form of efforts, resources and time, the proposed study is mainly restricted to mobile banking for selected banks. As the title of the study signifies, scope covers to fulfillment of the objectives, which are cited above, for the study. This research is based on the customers' perception regarding M-Banking services. This research discusses the opinion of the customers regarding the M-Banking services provided by the selected new generation private banks and the qualities of the M-Banking services in the area of reliability, responsiveness, security, easy use, accessibility and efficiency. Also the research analyses the problems faced by the customers while using the M-Banking services. The research evaluates the relationship between the activities undertaken through M-Banking services by the customers, the

qualities of M-Banking services and the problems of M-Banking services.

Objectives of the study

The aim of the study is to specify the way of adopting the M-Commerce technologies as well as to analyze the impact of adopting the M-Commerce services. The M-Commerce features include ubiquity, personalization, flexibility, and localization. The goal of M-Commerce is to combine technology with new ways of operating through which all the activities can be made much more effective, transparent and responsive.

Following are the specific objectives of present study:

- To evaluate, analyze and compare the opinions and satisfaction level of Customers of M-Commerce and M-Banking services provided the banks.
- To understand and compare the problems faced by the customers satisfaction level of M-Commerce services.
- To offer suggestions to improve the M-Commerce customer services.

Tools for mobile commerce

In present market, number of mobile tools available for the companies to engage customer in business, the following are some of the technologies that are help in reaching the customers.

1. SMS: SMS (Short Message Service) is short messaging service which consists of 160 characters of black and white. It is the widely used and cheapest form of mobile marketing. Companies can send bulk messages and customers can also respond in the same form to order a product or service.
2. MMS: MMS (Multi-media Message Service) is Multimedia Message Service. This Consists of time slide show of images, text audio and video. Mobile set with color screen are capable of sending and receiving standard MMS message. Product demonstration, use and other things can be done with help of MMS to convince customers to buy products or services.
3. Mobile Web Applications: Accessing web page on mobile devise is an option. Yahoo, Google and other mobile content providers have been selling advertising placement on their properties.

Customer can access the products or services through the web pages of the companies through mobile phones.

4. Bluetooth: A Bluetooth message can be circulated with in a 10meter range, retailers, mall owners and small business holders use this tool to sell their product to the customers who come to in the proximity of that area.
5. Location-based marketing: Location based marketing helps to locate the customer location via GPS (Global Positioning System) technology and company delivers the contents, offers relating to that particular location.
6. Voice: Voice based marketing over the mobile is emerging form of marketing. Interactive voice Response (IVR) is very popular and companies use to offer various services to their customers. A customer has to follow the instructions recorded on the system at the other end.

Conclusion

Mobile commerce is going to play a major role in conducting business in future. With heated competition in the markets, emerging players, different marketing strategies, and more customer awareness gives a boost to the mobile commerce growth. One in two Indians have mobile connection and mobile technology players creating platforms for transactions in mobile commerce. Mobile i.e.; mobile subscribers touching nearly 600 million, more than 12 players waging war for the market commerce is changing the ways and rules to do the transactions and business. Mobile commerce is not only providing timely services, convenience, personalization and ubiquity but on the whole it is offering value for money to the consumers. Recent applications show the huge acceptance and success of mobile commerce. Mobile payments are developed much to the user advantage and security and lot more change is expected in future. Mobile commerce is the next generation mode of business.

References:

1. Evan Schuman (2010, August 25). More M-commerce proof from China. Store front back talk.
2. Manish Verma & Komal Verma. (June 2009). Mobile Advertising: The Future of Advertising, Advertising Express.

3. Nick (February 19, 2010). M Commerce revenues in Europe to surpass US by end of 2010. Zippy Cart.
4. Olga Kharif (2009, October 11). M-Commerce's Big Moment. Bloomberg Business Week.
5. Onkar Sharma. (February 2010). Sell your products via the mobile, Benefit,12-16
6. Probir Roy. (Jan 2010). Mobile Commerce: The Next Wave in Electronic Payments, The Analyst
7. Surendra Kuila. (2010, January 20).Key drivers of M-commerce, Express Computer.
8. Wolfe, Daniel, American Banker. (4/1/2008). Obopay: Indian System As Global Launching Pad. 00027561, Vol. 173, Issue 62
9. News Bureau (2010, January 25). 90% Growth Expected in M-Commerce in APAC. Telecom Yatra. Retrieved from: <http://telecomyatra.afaqs.com/news/?sid=420>
10. Murugadoss K Panneerselvam, Mobile Commerce - A Mode of Modern Business Group Leader Manufacturing Engineering Department, Bosch Thermo Technology Ltd., Worcester United Kingdom Research Scholar CMJ University Asia Pacific Journal of Marketing & Management Vol.2 (7), July (2013)
11. Rupinder Kaur, Sofia Singh Assistant Professor, PG Department of Computer Science and Applications, Ghg Khalsa College, Gurusar Sadhar, Ludhiana, Punjab, India, Mobile Commerce: Indian Perspectives International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering, Vol. 4, Issue 3, March 2016.

Indian Knowledge Systems and the Evolving Role of the Teacher

Mrs. Rukmani Sharma

Assistant Professor
Department of Education
Jagan Nath University, Jaipur, Rajasthan

Dr. Mukesh Kumar Sharma

Associate Professor
Department of Education
Jagan Nath University, Jaipur, Rajasthan

Abstract

Indian Knowledge Systems (IKS) represent a rich intellectual and cultural heritage developed over thousands of years through the contributions of sages, scholars, philosophers, scientists, and educators. These systems encompass diverse domains such as education, philosophy, ethics, language, mathematics, medicine, yoga, environmental consciousness, governance, and spiritual development. In the contemporary educational landscape, especially after the implementation of the National Education Policy (NEP) 2020, there has been renewed emphasis on integrating Indian Knowledge Systems into mainstream education. This transformation has significantly influenced the role of the teacher. Traditionally, the teacher in Indian education was viewed not merely as an instructor but as a guide, mentor, philosopher, and moral leader responsible for the holistic development of learners. In the present context, the teacher's role is evolving from information provider to facilitator, innovator, value educator, and cultural transmitter.

This research paper explores the conceptual foundations of Indian Knowledge Systems and examines the changing role of teachers in modern

education. The paper highlights how ancient Indian educational ideals such as Guru-Shishya Parampara, experiential learning, ethical instruction, and holistic development remain relevant in today's educational practices. It further analyzes the responsibilities, competencies, and challenges faced by teachers while integrating IKS into contemporary classrooms. The study adopts an analytical and descriptive approach based on secondary sources including books, journals, policy documents, and educational reports.

The paper concludes that Indian Knowledge Systems can contribute significantly toward creating value-based, inclusive, sustainable, and learner-centered education. Teachers are the key agents in implementing this transformation. Therefore, teacher education programs must incorporate IKS-oriented pedagogies, interdisciplinary approaches, and ethical training to prepare educators for the demands of twenty-first-century education.

Keywords: Indian Knowledge Systems, Teacher Education, NEP 2020, Guru-Shishya Tradition, Holistic Education, Value-Based Education, Educational Transformation

Introduction:

India possesses one of the oldest and most comprehensive educational traditions in the world. Ancient Indian education was deeply rooted in spirituality, ethics, social responsibility, intellectual inquiry, and holistic development. Indian Knowledge Systems include a broad spectrum of knowledge traditions preserved through Vedas, Upanishads, Puranas, Ayurveda, Yoga, astronomy, mathematics, literature, arts, architecture, ecology, and philosophical schools.

The educational philosophy of India emphasized the development of body, mind, intellect, and soul. Education was considered a means of self-realization and social welfare rather than mere acquisition of employment-oriented skills. Teachers occupied a highly respected position in society and played a central role in shaping the moral and intellectual character of learners.

In the modern globalized era, education systems are facing several challenges such as moral decline, stress among students, environmental degradation, excessive

commercialization of education, and lack of cultural rootedness. In this context, Indian Knowledge Systems offer sustainable and value-oriented alternatives. The National Education Policy (NEP) 2020 has strongly advocated the integration of Indian Knowledge Systems into curricula, pedagogy, teacher education, and research.

The implementation of IKS in education requires a transformation in the role of teachers. Contemporary teachers are expected not only to impart subject knowledge but also to nurture ethical values, creativity, critical thinking, emotional intelligence, environmental awareness, and cultural understanding among students. Thus, the role of the teacher is evolving from a traditional lecturer to a mentor, facilitator, collaborator, and lifelong learner.

This paper critically examines the relevance of Indian Knowledge Systems and analyzes the changing role of teachers in the contemporary educational framework.

Objectives of the Study:

1. To understand the concept and significance of Indian Knowledge Systems.
2. To analyze the traditional role of teachers in Indian education.
3. To examine the evolving role of teachers in contemporary educational settings.
4. To study the relevance of Indian Knowledge Systems in modern education.
5. To identify the challenges and opportunities in integrating IKS into teaching-learning processes.
6. To suggest measures for strengthening teacher education through Indian Knowledge Systems.

Research Methodology:

The present study is descriptive and analytical in nature. It is based entirely on secondary sources of data. Relevant information has been collected from books, research journals, government reports, policy documents, articles, educational websites, and the National Education Policy 2020. The collected data have been analyzed systematically to understand the role of Indian Knowledge Systems and the evolving responsibilities of teachers in contemporary education.

Concept of Indian Knowledge Systems:

Indian Knowledge Systems refer to the indigenous knowledge traditions developed in India through centuries of intellectual and cultural practices. These systems are interdisciplinary, holistic, experiential, and deeply connected with ethical and spiritual dimensions of life.

Indian Knowledge Systems include the following major components:

1. **Vedic Knowledge:** The Vedas contain profound knowledge related to philosophy, ethics, rituals, science, astronomy, mathematics, and social organization. They emphasize harmony between humans and nature.
2. **Upanishadic Philosophy:** The Upanishads focus on self-knowledge, consciousness, morality, and spiritual realization. They encourage inquiry, dialogue, and reflective thinking.
3. **Ayurveda:** Ayurveda is the traditional Indian system of medicine emphasizing preventive healthcare, balanced lifestyle, natural healing, and holistic well-being.
4. **Yoga and Meditation:** Yoga promotes physical health, mental balance, emotional stability, and spiritual growth. It is highly relevant in modern education for stress management and personality development.
5. **Indian Mathematics and Astronomy:** Ancient Indian scholars like Aryabhata, Brahmagupta, and Bhaskaracharya made significant contributions in mathematics, algebra, geometry, and astronomy.
6. **Environmental Wisdom:** Indian traditions advocate ecological balance, conservation of nature, and sustainable living practices.
7. **Language and Literature:** Sanskrit and regional languages preserve vast literary and philosophical treasures that contribute to intellectual and cultural enrichment.

Indian Knowledge Systems are not limited to ancient traditions; they continue to evolve and remain relevant in contemporary society.

Traditional Role of the Teacher in Indian Education:

In ancient India, the teacher or Guru held a highly respected and sacred position. The Guru was regarded as a spiritual guide, moral instructor, philosopher, and mentor.

- **Guru-Shishya Parampara-:** The Guru-Shishya tradition formed the foundation of Indian education. Students lived with the Guru in Gurukuls and received education through close personal interaction. Learning was experiential, disciplined, and value-oriented.

Characteristics of the Traditional Teacher:

1. **Moral Leadership-** Teachers served as role models for ethical conduct, discipline, honesty, and compassion.
2. **Holistic Education-** The Guru focused on the physical, intellectual, emotional, social, and spiritual development of learners.
3. **Personalized Learning-** Education was learner-centered, and teaching methods were adapted according to the interests and capacities of students.
4. **Experiential Learning-** Students learned through observation, practice, dialogue, meditation, and real-life experiences.
5. **Character Formation-** The primary goal of education was character building and cultivation of virtues such as truthfulness, self-control, humility, and social responsibility.
6. **Lifelong Relationship-** The relationship between Guru and disciple was based on mutual trust, respect, affection, and lifelong guidance.

The traditional Indian teacher therefore played a multidimensional role extending beyond academic instruction.

Relevance of Indian Knowledge Systems in Modern Education:

The modern education system often emphasizes examinations, competition, and information acquisition, leading to stress, moral confusion, and fragmented learning. Indian Knowledge Systems provide valuable insights for addressing these challenges.

1. **Holistic Development-** IKS promotes balanced development of body, mind, emotions, and spirit, contributing to overall personality development.
2. **Value-Based Education-** Indian traditions emphasize ethical values such as truth, non-violence, compassion, tolerance, and social harmony.

3. **Mental Health and Well-being-** Yoga and meditation help reduce stress, improve concentration, and enhance emotional stability among students.

4. **Environmental Sustainability-** Indian ecological wisdom encourages respect for nature and sustainable living practices.

5. **Cultural Preservation-** Integration of IKS helps students understand and appreciate India's cultural heritage and identity.

6. **Interdisciplinary Learning-** Indian Knowledge Systems promote integrated approaches connecting science, philosophy, arts, health, and spirituality.

7. **Critical and Reflective Thinking-** Ancient Indian traditions encouraged dialogue, debate, questioning, and intellectual inquiry.

The inclusion of Indian Knowledge Systems can therefore make education more meaningful, contextual, and human-centered.

Evolving Role of the Teacher in Contemporary Education:

The role of the teacher has undergone significant transformation due to technological advancements, globalization, educational reforms, and changing learner needs.

1. **Teacher as Facilitator:** Modern teachers are expected to facilitate learning rather than merely transmit information. They guide students in discovering knowledge independently.
2. **Teacher as Mentor:** Teachers support the emotional, psychological, and social development of students by providing guidance and motivation.
3. **Teacher as Innovator:** Contemporary education demands creative pedagogies, digital literacy, project-based learning, and experiential teaching methods.
4. **Teacher as Value Educator:** Incorporating Indian values and ethics into classroom practices has become an important responsibility of teachers.
5. **Teacher as Cultural Ambassador:** Teachers play a crucial role in preserving and transmitting India's cultural heritage and indigenous knowledge traditions.

6. **Teacher as Researcher:** Teachers are increasingly expected to engage in research, reflective practices, and continuous professional development.

7. **Teacher as Lifelong Learner:** Rapid changes in knowledge and technology require teachers to continuously update their skills and competencies.

8. **Teacher as Inclusive Educator:** Teachers must address diverse learning needs and ensure equitable educational opportunities for all students.

The evolving role of teachers aligns closely with the principles of Indian Knowledge Systems, which emphasize mentorship, ethics, reflection, and holistic development.

NEP 2020 and Indian Knowledge Systems:

The National Education Policy 2020 has given special importance to Indian Knowledge Systems and teacher empowerment.

Major Provisions Related to IKS:

1. **Integration of Indian Knowledge Traditions:** The policy recommends incorporating Indian languages, arts, culture, philosophy, yoga, and traditional knowledge into education.
2. **Multidisciplinary Education:** NEP 2020 promotes interdisciplinary learning and holistic development.
3. **Experiential Learning:** The policy emphasizes experiential, inquiry-based, and competency-based education.
4. **Teacher Preparation:** Teacher education programs are expected to prepare educators capable of integrating IKS into teaching-learning processes.
5. **Promotion of Indian Languages:** The policy supports multilingualism and the use of Indian languages in education.
6. **Ethical and Constitutional Values:** Education should promote ethics, empathy, respect, and responsible citizenship.

NEP 2020 recognizes teachers as the central pillars of educational transformation and highlights their role in implementing Indian Knowledge Systems.

Challenges in Integrating Indian Knowledge Systems:

Despite the growing recognition of IKS, several challenges exist in its implementation.

1. **Lack of Awareness:** Many teachers and students are not adequately aware of the scope and significance of Indian Knowledge Systems.
2. **Inadequate Teacher Training:** Teacher education programs often lack specialized training related to IKS pedagogy and curriculum integration.
3. **Resource Constraints:** Limited availability of quality teaching materials, translations, and digital resources creates implementation difficulties.
4. **Colonial Mindset:** Certain sections of society continue to perceive indigenous knowledge as outdated or unscientific.
5. **Curriculum Overload:** Integrating additional content into already extensive curricula may create practical challenges.
6. **Language Barriers:** Many original Indian texts are available in Sanskrit or regional languages, limiting accessibility.
7. **Technological Adaptation:** Teachers need training to effectively combine traditional knowledge with modern digital technologies.

Addressing these challenges requires policy support, institutional commitment, and professional development initiatives.

Strategies for Strengthening the Role of Teachers through IKS:

1. **Reform in Teacher Education:** Teacher training institutions should include courses on Indian philosophy, educational traditions, yoga, ethics, and indigenous pedagogies.
2. **Curriculum Development:** Curricula should integrate Indian Knowledge Systems in interdisciplinary and contextual ways.
3. **Professional Development Programs:** Regular workshops, seminars, and orientation programs should be organized for teachers.
4. **Digital Resources:** Development of digital platforms, e-content, and multilingual resources can improve accessibility.

5. **Experiential Pedagogy:** Teachers should adopt activity-based, experiential, and reflective teaching methods.
6. **Research and Innovation:** Educational institutions should encourage research on Indian Knowledge Systems and innovative teaching practices.
7. **Promotion of Ethical Education:** Teachers should incorporate moral and ethical discussions into classroom interactions.
8. **Collaboration with Traditional Knowledge Experts:** Educational institutions can collaborate with scholars, yoga practitioners, Ayurveda experts, and local knowledge holders.

These measures can help teachers effectively integrate Indian Knowledge Systems into contemporary education.

Educational Implications:

The integration of Indian Knowledge Systems has several important implications for education:

1. It promotes culturally rooted and contextually relevant learning.
2. It strengthens ethical and value-based education.
3. It encourages holistic personality development.
4. It supports mental health and emotional well-being.
5. It enhances environmental awareness and sustainability.
6. It fosters critical thinking and creativity.
7. It revitalizes indigenous knowledge traditions and languages.
8. It empowers teachers as transformative educational leaders.

Therefore, Indian Knowledge Systems can contribute significantly toward building an inclusive, sustainable, and humanistic educational system.

Conclusion:

Indian Knowledge Systems represent a profound intellectual and cultural heritage that continues to hold relevance in the modern educational context. These systems emphasize holistic development, ethical values, experiential learning, environmental harmony, and self-realization. The contemporary education

system, which often faces challenges related to moral decline, stress, fragmentation of knowledge, and excessive competition, can greatly benefit from the principles of Indian Knowledge Systems.

The role of the teacher has evolved considerably in response to changing educational needs and societal expectations. Teachers are no longer confined to the role of information transmitters; they are now facilitators, mentors, innovators, researchers, value educators, and cultural ambassadors. This evolving role closely resonates with the traditional Indian concept of the Guru, who guided learners toward intellectual, moral, and spiritual growth.

The National Education Policy 2020 has provided a strong framework for integrating Indian Knowledge Systems into education. However, successful implementation requires adequate teacher preparation, curriculum reforms, research support, resource development, and institutional commitment.

Teachers are the key agents of educational transformation. By integrating Indian Knowledge Systems into pedagogy and classroom practices, teachers can create meaningful, value-oriented, learner-centered, and culturally rooted educational experiences. Such an approach can contribute not only to academic excellence but also to the development of responsible, ethical, and compassionate citizens capable of addressing the challenges of the twenty-first century.

References:

1. Government of India. (2020). *National Education Policy 2020*. New Delhi: Ministry of Education.
2. Kapur, R. (2021). *Indian Knowledge System and Education*. New Delhi: Concept Publishing Company.
3. Radhakrishnan, S. (2017). *Indian Philosophy*. New Delhi: Oxford University Press.
4. Sharma, R. N. (2019). *History of Indian Education*. Meerut: Surya Publications.
5. UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. Paris: UNESCO Publishing.
6. NCERT. (2022). *National Curriculum Framework*. New Delhi: NCERT.

7. Tilak, J. B. G. (2021). "National Education Policy 2020: A Critical Review." *Journal of Educational Planning and Administration*, 35(2), 115–130.
8. Kumar, K. (2018). *What is Worth Teaching?* New Delhi: Orient BlackSwan.
9. Pandey, V. C. (2020). *Bharatiya Shiksha Darshan*. Jaipur: Rajasthan Hindi Granth Academy.
10. Aurobindo, S. (2015). *The Foundations of Indian Culture*. Puducherry: Sri Aurobindo Ashram Publication.
11. Nene, Y. L. (2019). *Indian Knowledge Systems: A Holistic Perspective*. Hyderabad: Asian Agri-History Foundation.
12. Tagore, R. (2016). *Personality*. New Delhi: Rupa Publications.
13. Vivekananda, S. (2018). *Education for Character Building*. Kolkata: Advaita Ashrama.
14. Mishra, A. (2022). "Role of Teachers in Integrating Indian Knowledge Systems." *International Journal of Educational Research*, 11(3), 45–58.
15. Joshi, P. (2023). "Holistic Education and Indian Knowledge Traditions." *Journal of Indian Education*, 49(1), 20–34.

Geography and Indian Knowledge System (IKS): An Interdisciplinary Perspective for Sustainable Development and Environmental Understanding

Mrs. Rukmani Sharma

Assistant Professor

Department of Education

Jagan Nath University, Jaipur, Rajasthan

Ms. Urmila Saini

Teacher Trainee

Department of Education

Jagan Nath University, Jaipur, Rajasthan

Abstract

Geography and the Indian Knowledge System (IKS) share a deep and historical relationship in understanding the interaction between human beings and their environment. Indian civilization has developed extensive geographical knowledge through Vedic literature, Puranas, ancient travel accounts, agricultural practices, astronomy, ecology, and traditional environmental management systems. In the contemporary era, the integration of geography with IKS offers valuable insights for sustainable development, climate adaptation, biodiversity conservation, disaster management, and environmental ethics. This paper explores the interrelationship

between geography and IKS, highlighting traditional Indian perspectives on land, water, climate, settlement patterns, resource management, and ecological balance. It also examines the relevance of indigenous geographical knowledge in addressing present-day environmental challenges. The study concludes that the integration of geographical sciences with Indian Knowledge Systems can contribute significantly to sustainable development goals and environmental sustainability.

Keywords: Geography, Indian Knowledge System, Indigenous Knowledge, Sustainability, Environment, Traditional Ecological Knowledge

Introduction:

Geography is the scientific study of the Earth's surface, physical features, human activities, and their interactions with the environment. It encompasses the study of landforms, climate, vegetation, water resources, population, settlements, and regional development. The Indian Knowledge System (IKS), on the other hand, represents the accumulated wisdom, practices, values, and scientific understanding developed by Indian civilization over thousands of years.

India possesses one of the world's oldest traditions of geographical thinking. Ancient Indian scholars observed natural phenomena, climatic variations, river systems, soil characteristics, and celestial movements with remarkable accuracy. Geographical concepts were embedded in Vedic literature, Upanishads, Puranas, Arthashastra, Buddhist texts, and various regional traditions. These sources reveal a sophisticated understanding of environmental processes and human-environment relationships.

The National Education Policy (NEP) 2020 emphasizes the integration of Indian Knowledge Systems into higher education and research. Geography, as an interdisciplinary discipline, provides an ideal platform for understanding and applying traditional ecological wisdom to contemporary environmental and developmental challenges.

Concept of Geography in Indian Knowledge Tradition:

The roots of geographical understanding in India can be traced to the Vedic period. Ancient Indian texts contain descriptions of landscapes, rivers, mountains, climatic conditions, and human settlements.

The **Rigveda** mentions several rivers, including the Saraswati, Ganga, Yamuna, and Sindhu, demonstrating detailed geographical awareness. The concept of **Prithvi (Earth)** was viewed not merely as a physical entity but as a living system supporting all forms of life.

The **Atharvaveda's Prithvi Sukta** highlights the relationship between humans and the Earth:

"Mata Bhumi Putro Aham Prithivya"
(Earth is my mother, and I am her son.)

This statement reflects a strong environmental ethic and a sustainable approach to resource utilization.

Ancient Indian geographical understanding integrated physical, cultural, spiritual, and ecological dimensions, making it holistic in nature.

Geographical Knowledge in Ancient Indian Literature:

1. Vedic Literature- The Vedas contain references to rivers, mountains, forests, seasons, and climatic cycles. The classification of six seasons (Ritu Chakra) demonstrates an advanced understanding of climatic variations. The six traditional seasons are:
 - Vasanta (Spring)
 - Grishma (Summer)
 - Varsha (Monsoon)
 - Sharad (Autumn)
 - Hemanta (Pre-Winter)
 - Shishira (Winter)

This seasonal classification continues to influence agricultural and cultural practices in India.

1. Puranic Geography- The Puranas provide detailed descriptions of continents, oceans, mountain systems, and sacred landscapes. Although some descriptions are symbolic, they reveal attempts to understand spatial organization and regional diversity.
2. The concept of Jambudvipa represented the known geographical world and reflected ancient cosmological geography.
3. Ramayana and Mahabharata- These epics contain extensive geographical information regarding rivers, forests, mountain ranges, trade routes, and kingdoms. The journeys described in these texts provide valuable insights into ancient Indian landscapes and regional interactions.

Contributions of Ancient Indian Scholars to Geographical Knowledge:

1. Aryabhata (476 CE)- Aryabhata proposed that the Earth rotates on its axis, a revolutionary concept in ancient science. His astronomical

calculations contributed significantly to geographical and cartographic understanding.

2. Varahamihira (505–587 CE)- Varahamihira's work Brihat Samhita contains information on weather forecasting, rainfall prediction, hydrology, environmental indicators, and agricultural geography. His observations regarding cloud formations and monsoon behavior are considered early contributions to climatology.
3. Kautilya (Chanakya)- In the Arthashastra, Kautilya discussed land classification, irrigation systems, resource management, agriculture, forestry, and urban planning. His work demonstrates a practical approach to geographical resource management.
4. Bhaskaracharya- Bhaskaracharya contributed to mathematical geography and astronomy through calculations related to planetary motions and geographical measurements.

Traditional Ecological Knowledge and Geography:

Traditional Ecological Knowledge (TEK) forms an important component of IKS. It refers to the cumulative body of knowledge, beliefs, and practices developed through long-term interactions with the environment. Indian communities have historically developed sustainable methods for managing natural resources.

Examples:

- Sacred groves (Dev Van)
- Community-managed forests
- Traditional irrigation systems
- Rainwater harvesting structures
- Indigenous agricultural practices

These systems demonstrate geographical adaptation to local environmental conditions.

Water Resource Management in Indian Knowledge Systems:

Water resource management has been a central concern in Indian civilization due to dependence on monsoon rainfall and the uneven distribution of water resources. Indian Knowledge Systems (IKS) developed various indigenous techniques for water conservation, storage, and distribution, ensuring

sustainable use of water across different geographical regions. Traditional Water Conservation Systems:

Rajasthan

- **Johads** – Small earthen dams that collect and store rainwater, helping groundwater recharge.
- **Kunds** – Underground rainwater harvesting structures used mainly for drinking water.
- **Baoris (Stepwells)** – Deep wells with steps that provide access to water throughout the year.

Maharashtra

- **Phad Irrigation System** – A community-managed irrigation system that diverts river water through canals for equitable agricultural use.

Tamil Nadu

- **Tank Irrigation System** – A network of interconnected tanks and reservoirs that store rainwater, support irrigation, and recharge groundwater.

Meghalaya

- **Bamboo Drip Irrigation** – An eco-friendly system using bamboo channels to transport water from streams directly to crops with minimal wastage.

Modern India faces increasing water stress due to population growth, urbanization, and climate change. Traditional water management practices provide cost-effective and environmentally sustainable alternatives.

Agricultural Geography and Indigenous Knowledge:

Agriculture has always been closely linked to geography and climatic conditions.

Indian farmers traditionally used:

- Crop rotation
- Mixed cropping
- Organic fertilizers
- Seed preservation techniques
- Seasonal calendars

Ancient agricultural texts such as **Krishni-Parashara** and **Vrikshayurveda** provide detailed guidance on soil management, crop selection, irrigation, and plant health.

Sustainable Agriculture

Indigenous agricultural knowledge promotes:

- Soil conservation
- Biodiversity protection
- Reduced chemical dependency
- Climate resilience

These principles align with modern sustainable agricultural practices.

Biodiversity Conservation through IKS:

India is one of the world's megadiverse countries. Traditional communities have played a significant role in biodiversity conservation.

Sacred Groves: Sacred groves are protected forest patches dedicated to local deities.

Examples:

- Khasi Hills (Meghalaya)
- Western Ghats
- Rajasthan's Orans

These ecosystems preserve:

- Rare species
- Medicinal plants
- Water sources
- Wildlife habitats

Geographically, sacred groves contribute to ecological stability and landscape conservation.

Climate Knowledge in Indian Traditions:

Indian Knowledge Systems contain rich traditions related to climate observation and weather prediction. Traditional indicators include:

- Bird migration patterns
- Animal behavior
- Cloud formations
- Wind direction
- Astronomical observations

The **Panchang** has historically been used to predict seasonal changes and agricultural activities.

Combining traditional climate knowledge with modern meteorological science can improve climate adaptation and disaster preparedness.

Settlement Geography and Traditional Indian Planning:

Ancient India developed advanced settlement planning systems.

Indus Valley Civilization

Cities such as:

- Mohenjo-Daro

- Harappa
- Dholavira

demonstrated:

- Grid planning
- Drainage systems
- Water management
- Urban sustainability

Vastu Shastra

Vastu Shastra provided guidelines for:

- Site selection
- Orientation
- Ventilation
- Environmental harmony

These principles reflect an understanding of local geography and climatic conditions.

Disaster Management and Indigenous Knowledge:

Traditional communities developed mechanisms to cope with natural hazards.

Examples

Coastal Areas

- Elevated housing structures
- Mangrove protection

Himalayan Regions

- Earthquake-resistant architecture

Flood-Prone Areas

- Raised settlements
- Traditional embankments

Indigenous disaster knowledge contributes to resilience and risk reduction.

Geography, Culture, and Sacred Landscapes:

Indian culture has historically integrated geography with spirituality.

Examples include:

- River Ganga
- Mount Kailash
- Arunachala Hills
- Narmada River
- Govardhan Hill

Sacred landscapes encourage environmental conservation through cultural values and community participation. These cultural-geographical

relationships help preserve ecosystems and natural resources.

Indian Knowledge System and Sustainable Development Goals (SDGs):

The United Nations Sustainable Development Goals emphasize environmental sustainability, water conservation, climate action, and biodiversity protection.

IKS contributes to several SDGs:

SDG	Contribution of IKS
Clean Water and Sanitation	Traditional water harvesting
Sustainable Cities	Eco-friendly planning
Climate Action	Indigenous climate adaptation
Life on Land	Sacred groves and biodiversity conservation
Responsible Consumption	Sustainable resource utilization

The integration of geographical sciences and IKS can strengthen sustainable development strategies.

Role of Geography and IKS in Education:

The National Education Policy (2020) advocates the incorporation of Indian Knowledge Systems into curricula. Geography education can integrate:

- Traditional environmental knowledge
- Indigenous mapping practices
- Local resource management
- Sustainable agricultural systems
- Cultural landscapes

Such integration promotes experiential learning and environmental awareness.

Challenges in Integrating Geography and IKS:

Despite its significance, several challenges exist:

1. Lack of systematic documentation.
2. Declining transmission of traditional knowledge.
3. Urbanization and modernization.
4. Limited interdisciplinary research.
5. Inadequate policy support.
6. Insufficient integration into academic curricula.

Addressing these challenges requires collaborative efforts among researchers, educators, policymakers, and local communities.

Future Prospects:

Future research should focus on:

- Geospatial documentation of indigenous knowledge.
- GIS mapping of traditional ecological systems.
- Climate adaptation studies based on local knowledge.
- Integration of IKS with environmental planning.
- Digital preservation of traditional geographical knowledge.

The combination of modern geographical technologies and indigenous wisdom can provide innovative solutions for sustainable development.

Conclusion:

Geography and the Indian Knowledge System are deeply interconnected disciplines that offer a holistic understanding of human-environment interactions. Ancient Indian traditions contain extensive geographical knowledge related to climate, agriculture, water management, biodiversity conservation, settlement planning, and environmental ethics. In the face of contemporary challenges such as climate change, environmental degradation, water scarcity, and biodiversity loss, the integration of geographical science with indigenous knowledge systems has become increasingly important.

The Indian Knowledge System emphasizes harmony with nature, sustainable resource use, and ecological responsibility. These principles align closely with contemporary concepts of sustainability and environmental management. By incorporating traditional geographical wisdom into research, education, and policy-making, India can develop context-specific and culturally relevant approaches to sustainable development. Therefore, the convergence of Geography and IKS represents not only a valuable academic field but also a practical pathway toward environmental sustainability and societal well-being.

References:

1. Aryabhata. (1990). *Aryabhatiya* (K. S. Shukla & K. V. Sarma, Trans.). Indian National Science Academy.
2. Government of India. (2020). *National Education Policy 2020*. Ministry of Education. <https://www.education.gov.in>
3. Kangle, R. P. (2010). *The Kautiliya Arthashastra* (3rd ed.). Motilal Banarsidass.
4. Maheshwari, A. (2019). Indigenous knowledge systems and sustainable development in India. *International Journal of Social Science Studies*, 7(4), 45–53.
5. Rao, M. S. A. (2018). Traditional ecological knowledge and biodiversity conservation in India. *Journal of Environmental Studies*, 12(2), 67–79.
6. Sharma, R. (2022). *Bharatiya Gyan Parampara aur Samkalin Shiksha*. New Delhi: Gyan Prakashan.
7. Singh, R. B. (2017). *Geography of India*. Rawat Publications.
8. UNESCO. (2017). *Local and Indigenous Knowledge Systems (LINKS) Programme*. UNESCO Publishing.
9. Varahamihira. (1996). *Brihat Samhita* (M. Ramakrishna Bhat, Trans.). Motilal Banarsidass.
10. Yadav, Y. (2021). Indian knowledge systems and environmental sustainability. *Journal of Indian Studies*, 5(1), 22–35.
11. Venkatesan, J. (2020). Traditional water management systems in India: A geographical perspective. *Indian Journal of Environmental Management*, 15(3), 101–115.

Impact of Foreign Universities on Indian Higher Education: An Analytical Study

Dr. Bijendra Singh

Principal

Nirmal T.T. College, Hindaun City, Karauli, Rajasthan

Abstract

India, a nation with the world's largest youth population, currently stands at a crucial juncture in the globalization of higher education. The new 2023 guidelines by the UGC (University Grants Commission) have paved the way for the world's top 500 institutions to establish campuses in India.

The conclusion of this study suggests that the arrival of foreign universities has the potential to transform the "Brain Drain" into "Brain Gain" within the Indian educational ecosystem. From an economic perspective, this will help save approximately \$20-30 billion in foreign exchange spent abroad annually and will be instrumental in attracting Foreign Direct Investment (FDI). Academically, it will foster healthy competition among Indian institutions, leading to global improvements in research and teaching quality.

However, this study also points toward some serious challenges, including the excessive commercialization of education, rising socio-economic inequality due to high fee structures, and the potential migration of elite faculty from local institutions.

In conclusion, this study highlights that if the government implements a robust regulatory framework and inclusive scholarship policies, the entry of foreign universities will serve as a catalyst in re-establishing India as a 'Vishwa Guru' (Global Teacher) and achieving the goal of a \$5 trillion economy.

Keywords: Foreign exchange, Investment, commercialization, Knowledge, economic perspective, educational renaissance.

Introduction

In the global landscape of the 21st century, 'Knowledge' is the most powerful currency. India, which was once recognized as a 'Vishwaguru' (Global Teacher) due to its ancient and glorious traditions of universities like Takshashila, Nalanda, and Vikramshila, is once again standing at the threshold of a global awakening in its higher education system. The National Education Policy (NEP-2020) is not merely a document; it is a reflection of India's high aspirations to build a bridge between global competitiveness and local relevance.

Currently, India is home to the world's largest young population, presenting an unprecedented opportunity for a 'Demographic Dividend.' However, the annual migration of hundreds of thousands of Indian students abroad is not only a 'Brain Drain' (loss of talent) but also places a significant annual economic burden of approximately \$28-30 billion on the country's economy. Against this backdrop, the UGC's 2023 new

regulations, which open India's doors to foreign universities, are being hailed as a revolutionary and era-defining step.

According to the latest data presented in Parliament by India's Ministry of External Affairs in December 2025, a total of 1,332,318 students went abroad to study. Of these, 12.54 lakh students went for higher education, while 6.28 lakh children went for school-level education. These students are choosing countries such as Canada, UAE, USA, United Kingdom, Australia, Germany, Kyrgyzstan, and Georgia, among others.

Positive Impacts of the Arrival of Foreign Universities

1. Quality and Global Standards

With the arrival of foreign universities, Indian students will have access to international-level curricula, teaching methodologies, and state-of-the-art technology within India itself. This will make 'global standard' education easily accessible.

2. From 'Brain Drain' to 'Brain Gain'

Every year, lakhs of Indian students go abroad to study, resulting in an outflow of billions of dollars in foreign exchange. By having campuses in India, international degrees will become affordable for middle-class families. Additionally, it will create numerous employment opportunities, and students will be able to receive global education while staying connected to their roots.

3. Economic Impact

According to Reserve Bank of India (RBI) data, Indian students spend approximately \$25–30 billion annually on tuition fees and living expenses abroad. If these institutions open campuses in India, a significant portion of this capital will stay within the country. The cost of a foreign degree for middle-class families could decrease by 50–60%, as expenses for travel, accommodation, and food would be almost eliminated.

4. Rise of Education Tourism

Due to its geographical location and low cost of living, India can become a center of attraction for students from Southeast Asia, the Middle East, and Africa. Just as Dubai and Singapore have become 'Education Hubs', India, with its vast capacity, can attract international students and significantly increase exports in the service sector.

5. UGC Regulations 2023

The "red carpet" laid out by the UGC for foreign institutions has rules that are quite clear and strategic. The UGC has granted significant autonomy to these institutions. Such institutions can independently determine their entrance exams, selection processes, and fee structures, provided they are fair and transparent. Furthermore, there will be flexible rules for repatriating the profits earned back to their home country.

Along with this, the UGC has set a condition that the quality of education provided in India must be at par with their main campus. Degrees and diplomas should be considered equivalent to those in their home country so that students can achieve global recognition. There is a strict condition to follow this rule. Additionally, the curriculum should also be integrated with the Indian context.

6. Hybrid Model and Research Partnership

Instead of just building standalone campuses, foreign institutions should be encouraged to start joint degree programs with Indian universities (such as JNU, DU, BHU, AMU, or private universities). This will lead to a more effective transfer of technology and skills.

7. The Way Forward (Path to the Future)

India needs to recognize its Soft Power in the field of education. The arrival of foreign universities is not just about competition; it is an opportunity for an educational renaissance. To attract foreign institutions, India must further strengthen its digital infrastructure and 5G connectivity so that hybrid and remote learning can function smoothly.

The UGC should establish a Single Window Clearance System so that bureaucratic hurdles do not stand in the way of foreign investment and international cooperation.

Major Challenges and Concerns

1. Digital Divide and Economic Inequality

The tuition fees of foreign universities are likely to be significantly higher than those of Indian institutions. This could lead to the emergence of an "elitist" class in education, where only wealthy students can afford admission. Children from poor and middle-class families may find themselves deprived of the opportunity to study at these institutions.

2. Faculty Brain Drain

This could pose a major challenge, as foreign universities might attract India's best educators through higher salaries and superior facilities. This could lead to a shortage of talented faculty in existing premier Indian institutions such as IITs, IIMs, AIIMS, etc.

3. Cultural Impact

With the introduction of curricula from Western countries, there is a constant fear that traditional Indian knowledge systems and cultural values might be marginalized. There is also an increased possibility of foreign culture dominating Indian culture.

4. Impact on Indian Institutions

The presence of foreign universities is likely to create a "do or die" situation for Indian institutions, forcing them into intense competition to survive.

5. Economic Challenges and Lack of Equality

Since the fees of foreign institutions are expected to be much higher than Indian ones, it could lead to the commoditization of education. Consequently, access may remain limited to the upper-middle class. Furthermore, there is a strong possibility of a dual education system emerging, which could create a deep divide between the "elite class" and the general public.

6. Regulatory and Administrative Challenges

It is also possible that the government might bring these institutions under the same reservation rules and regulatory controls that apply to Indian universities; if so, this would be unfair to local institutions. Additionally, ensuring that foreign universities maintain the same quality in India as their main branches will be a major challenge. It is also possible

that these institutions might start to be viewed merely as a means of generating revenue.

Conclusion

The impact of foreign universities on Indian higher education is multi-dimensional. While on one hand, it opens new doors for quality research and global competitiveness, on the other hand, it presents challenges such as social inequality and cultural disconnection.

Success will depend on how well India can strike a balance between the goals of its National Education Policy (NEP) 2020 and the commercial aspirations of foreign institutions. If managed correctly, this step will not only help India become a \$5 trillion economy but will also prove to be a significant leap toward re-establishing India as a "Vishwa Guru" (Global Teacher).

Bibliography

A. Government Documents & Policies

- Ministry of Education, National Education Policy - 2020, Govt. of India.
- University Grants Commission (2023), Setting up and Operation of Campuses of Foreign Higher Educational Institutions in India, Regulations, New Delhi.

B. Important Books & Academic Works

- Agrawal, P. (2009), Indian Higher Education: Envisioning the Future. SAGE Publications, India.
- Tilak, J.B. (2013), Higher Education in India: In Search of Equality, Quality and Quantity. Orient Blackswan.
- Er. Singh Avneesh Kumar, Naye Bharat Ki Neev: Rashtriya Shiksha Niti - 2020 (Foundation of New India: National Education Policy - 2020).
- Singh Mamta, India's National Education Policy 2020: A Revolutionary Milestone (Hindi Version).
- Arya, Jotaniya, Nanavare, NEP 2020 – Reformation of Indian Education System.

C. Research Papers and Articles

- Bhushan, S. (2005). "Foreign Universities in India: Market Survey." Economic and Political Weekly, 40(26), 2821–2824.
- Varghese, N. V. (2020). "The Internationalization of Higher Education in India: A Reflection on the New Education Policy." Journal of Educational Planning and Administration.

D. Reports

- FICCI & EY (2021). Higher Education in India: Vision 2030.
- British Council (2020). Indian Higher Education: The Internationalization Landscape.

Cross-Cultural Dimensions of Kingship in Early Medieval Kāmarūpa: Bloodline, Ritual Desire, and Sacred Power

*Seema Bai Chandaniya, Research Scholar

**Dr. Manju Sharma, Professor

Department of Education

Jayoti Vidyapeeth Mahila Vishwavidyalay, Bagru, Jaipur, Rajasthan

Abstract

Kingship in early medieval Kāmarūpa (present-day Assam) evolved through the interaction of orthodox and heterodox Brahmanical traditions with diverse tribal cultures. From the later phase of the Śālastambha dynasty, the principal royal tutelary deity was Kamakhya, originally a Kirata goddess associated with menstruation and fertility. Puranic traditions recount that the cult of Kamakhya was incorporated into the Brahmanical fold by the mytho-historical king Naraka. Textual and epigraphic sources describe Naraka as born of Prithvi during her menstrual phase through union with Varaha, thereby linking royal lineage to both divine power and the potent

symbolism of menstrual blood—viewed as impure yet powerful in Vedic and post-Vedic thought. Subsequent dynasties traced their ancestry to Naraka, reinforcing this sacred genealogy. The king functioned as a cultural mediator, ritually channeling these ambivalent forces through Tantric practices to legitimize and consolidate authority. This study argues that early medieval Assamese kingship emerged from a dynamic process of cross-cultural synthesis shaped by tribal and Brahmanical influences.

Keywords: Assam; Hinduization; Kalikapuran. asakta; supernatural; Tantrism; tribal; yogini; yoni

1. Introduction

By integrating inter- and intra-textual analysis with religious, ethnographic, and epigraphic evidence, this essay explores the relationship between political authority and Śākta-Tantric ritual systems in early medieval Kāmarūpa. Often regarded as a major center of Tantrism, the region became associated in literary imagination with practices involving blood sacrifice, esoteric rites, and forms of ritual power that appeared transgressive within orthodox Brahmanical frameworks. Since antiquity, Assam was inhabited by diverse ethno-linguistic tribal communities described in Sanskrit sources as *Kiratas* and *Mlecchas*.

Ritual practice and mythology are crucial for understanding the processes through which goddess cults rose to prominence within Hindu theology across the Indian subcontinent. Numerous local and regional female deities were gradually incorporated into the expanding Hindu pantheon through varied modes of interaction—assimilation, reinterpretation, and theological elevation. In many regions, these

goddesses were eventually established as *iṣṭadevatā* (chosen tutelary deities) of ruling dynasties, symbolizing a political and sacred alliance between Hindu kingship and indigenous tribal communities. India, in this sense, may be understood as a dynamic and adaptive civilizational matrix, responding to social and cultural stimuli through creative transformation rather than rigid uniformity.

The participation of autochthonous cultures—what Geoffrey Samuel has termed “proto-Śākta traditions”—in this cross-cultural synthesis can be traced back to early Vedic mythology. A significant example appears in the R̥gvedic narrative of the primordial incest between father and daughter at the dawn of creation. Though the act is halted by a wild archer because it transgresses ritual and moral codes, the myth underscores a profound cosmological insight: the generative necessity of the feminine principle. While the physical union is interrupted, desire itself cannot be restrained, and a drop of semen falling to the earth becomes the source of life. This

narrative reveals an early dialectic within Brahmanical thought between purity and impurity, taboo and creative potency. The categories of orthodox and heterodox were thus never entirely separate; rather, they were interwoven within the very foundations of Vedic cosmology. Both purity and transgression were symbolically necessary for cosmic regeneration.

The long process of cross-cultural negotiation that began in the early and obscure past of Assam ultimately laid the foundations for the yoni cult centered at the temple of Kamakhya Temple on Nīlācala Hill. Whether the worship of the yoni at Nīlācala—identified in later mythology as the स्थल where the yoni of Satī fell—developed primarily through Brahmanical engagement with local tribal traditions or through influences diffused from other regions of the subcontinent remains debated.

Karel van Kooij has suggested that the Nīlācala yoni cult represented an “eastern offshoot” of a broader religious pattern prevalent among mountain communities of the northwestern and Himalayan regions. The diffusion hypothesis finds some support in the Tīrtha-yātrā section of the Mahabharata, which refers to Himalayan pilgrimage sites symbolizing the womb or breast of the goddess, where ritual bathing conferred purification.

The question of sectarian dominance in this process remains complex. Ronald Davidson has argued that early medieval Hindu traditions—Śaiva, Śākta, Vaiṣṇava, and Smārta—actively pursued the Hinduization of tribal populations.

Though not a historical chronicle, this mytho-historical biography reflects the religio-political tensions of early medieval Assam. Assamese kingship may have rested upon a *saṃkara-jāti* principle, supported by exogamous tribal structures and the relative fluidity of Hindu jāti organization. Such hybridity politically legitimized intermarriage and fusion between tribal chiefs and dvija lineages, embedding cross-cultural synthesis at the very heart of royal ideology.

2. Kamakhya: Myth, Religion, and History

Assam is widely revered as the sacred land of the menstruating goddess Kamakhya, whose cult is believed to have originated in ancient tribal traditions and was later sustained within a Hindu framework by

Naraka, the first mytho-historical king of Kāmarūpa. The mythic origin of the temple is rooted in the well-known narrative of Satī's dismemberment, which followed Śiva's destruction of Dakṣa's sacrifice. According to the legend, Satī and her consort Śiva were deliberately excluded from the sacrificial ritual organized by her father Dakṣa. The impure origin of the first king of ancient Kamarupa was also recounted in the seventh century Dubi Copper Plates of Bhaskaravarman:

one who, in the days of yore, in the form of a boar out of compassion recovered the lost Earth for the stability of the people and put the same in his mouth, begot a superior son, Naraka by name, who was powerful enough even to torment the ambrosia-drinking gods and who was all powerful on earth being the king of kings.

According to the mythic narrative, after Naraka's birth, the earth goddess Pṛthvī entrusted the child to Janaka, king of Mithilā, who discovered him lying within a human skull in his sacrificial enclosure (*yajñavāta*). When Naraka reached the age of sixteen, Pṛthvī revealed his divine parentage as the son of Viṣṇu. Assisted by Viṣṇu, Naraka subdued the local tribes and ascended the throne of Kāmarūpa.

Although the historicity of this account remains unverified, epigraphic evidence suggests that by the mid-fourth century CE political authority had passed from the mytho-historical Naraka-Bhauma lineage to Puṣyavarman, the first historically attested ruler of Kāmarūpa. The timing and nature of Indo-Aryan migrations into Assam remain uncertain, yet the narrative of Naraka's conquest may reflect distant memories of early migratory movements into the Brahmaputra Valley. However, Dinesh Sircar has refused to validate any connections between actual history and the Naraka myth:

The story has here been made a caricature of its older and real Epico-Puranic type and is weaker than most legends of this class. In any case, no serious student can expect any trace of political history in the above legends about Naraka and his descendants.

On the contrary, Jae-Eun Shin has argued that

King Naraka the most important figure in a fabricated genealogy and the consistent source of political authority of every ruling family from the Varmans to Palas Suitable genealogy was probably fabricated when regional state formation reached a crucial

phase around the seventh century in the Brahmaputra Valley.

In this instance it can be supposed that historical processes influenced the Puranic biography of Naraka, but the narrative cannot be considered as a historical chronicle because of a lack of any supporting material evidence, such as archaeological ones. Thus:

myth is everything and nothing at the same time. It is the true story or a false one, revelation or deception, sacred or vulgar, real or fictional, symbol or tool, archetype or stereotype. It is either strongly structured and logical or emotional and pre-logical, traditional and primitive or part of contemporary ideology. Myth is about the gods, but often also the ancestors and sometimes certain men.

The Kalikapurana was compiled during the Śālastambha and Pāla dynasties of Kāmarūpa. Under the Śālastambhas, the Goddess was elevated to the status of *iṣṭadevatā*, likely to consolidate emerging structures of state formation. During the Pāla period, epigraphic evidence indicates active royal patronage of Tantric practitioners. As Pratap Chandra Choudhury observed, this sacred genealogy formed the crucial bridge between Assam's mytho-historical past and its historically attested polity.

The legendary accounts, with which we begin the political history of the land, are as varied and conflicting as doubtful in their authenticity. Much will depend on the tracing of a connection between the legendary proto-historical period and the historical one. The genealogy given in the epigraphs, as far as it goes, is, however, unchallenged.

Unfortunately, during its history, Assam was affected by a great number of floods and earthquakes; thereby, there is a lack of archaeological and iconographic evidence to better understand its ancient and early medieval period, and what the origin of the Assamese Hindu kingship was.

3. Death and Life at Nilacalakamakhyā

Between the ninth and eleventh centuries in northeastern India, the indigenous yoginī cult was codified within the Yoginī Kaula tradition through the compilation of the *Kulajñānanirṇaya*. Originally rooted beyond orthodox Brahmanical structures, the cult evolved through interaction with tribal practices and heterodox Hindu sects. The Kalikapurana both

legitimized the yoginī cult at Kamakhya and elevated it from a regional tradition to a wider pan-Indian Śākta network of sacred sites.

The theological basis of this incorporation was sought in the brahmanical Sakta model which was postulated in the Devimahatmya around the seventh century. In this text the concept of Mula Prakriti or Adīśakti from which all the goddesses emanated as her manifestations was already constructed and promulgated. It gives theological ground to accommodate any individual goddess and bring these diverse goddesses under a unifying umbrella.

In the sacred mythology of Nīlācala, both the goddess Kamakhya and her yoginī attendants are said to have originated from the fall of Satī's yoni at the site. According to northeastern Śākta traditions, when the yoni descended upon the hill, it fragmented into multiple yonis, from which the yoginīs emerged. These yoginīs were thus linked to the sacred geography of the Śākta pīṭhas as guardians and extensions of the generative power embodied in Kamakhya.

The northeastern Śākta Purāṇas portray the pīṭhas as sacred centers dedicated to goddess worship. Earlier Tantric literature, such as the Hevajra Tantra (compiled by the mid-ninth century), refers to *catuḥpīṭhas* associated with cremation grounds, suggesting that these sites were initially linked to transgressive and ascetic practices. During the ninth to eleventh centuries—within what Alexis Sanderson has termed a proto-Tantric reformulation—the pīṭhas were progressively integrated into heterodox Hindu traditions. They evolved from tribal or funerary spaces into esoteric ritual centers where aniconic worship and ascetic rites flourished.

In early medieval Kāmarūpa, the sexual symbolism of the yoni was superimposed upon Nīlācala's archaic funerary associations. Purāṇic and Tantric narratives describe the mountain as formed from the ashes of Kāma—burned by Śiva for disturbing his meditation—or from the ashes of the demon Keśin, incinerated by Kālī. Through these apparent deaths, the Sanskrit scribes maintained a symbolic connection between Nilacala and its primeval function as cremation ground, when it was identified with Heruka, its ancient presiding deity:

The cremation ground at that place, named Heruka, is being of red colour, bearing a knife and its hide looks

extremely terrible; is consuming human flesh, is resplendent by three wreaths of severed human heads from which bloods are dripping down, is crowded by ghosts, stands on a corpse, whose teeth have been bared because of being burnt by the fire, is adorned with ornaments, provided with weapons, and has a mount; the worshipper should worship Heruka (cremation ground) by meditation only.

The garbhagrha of the Kamakhya Temple is dark, narrow, and cave-like, evoking the maternal womb. While such symbolism resonates with the broader Hindu conception of the garbhagrha as homologous to the *hiranyagarbha*, the primordial womb of creation, a deeper meaning may also be discerned. The descent down stone steps into the sanctum suggests a ritual and psychological journey into the subterranean realm—a crossing of thresholds where the practitioner symbolically confronts death, impurity, and transformation before re-emerging into renewed cosmic awareness. Most of the studies on the goddess Kamakhya and her preeminent temple on Nilacala have noticed the extreme relevance of fluids, as Gioia Lussana pointed out in her recent study:

. . . fluid essence is one of the most archaic and universal features of the sacred, closely linked to Mother Earth, whose very nature is arid and dry because through her monthly menstruation she loses her generative power and so needs to reintegrate it constantly by absorbing liquids.

Chthonic symbolism profoundly shapes the sacred character of the Kamakhya Temple, where opposing forces converge and coexist—purity and impurity, masculine and feminine, life and death, terrestrial and aquatic elements. The garbhagrha signifies not only the maternal womb concealing the cosmic matrix, embodied in the yoni, but also a threshold to ancestral and subterranean powers. This link between Nilacala kamakhya and an ancient cult of the ancestors reconnected the sacred site to an ancient tribal cremation ground which was nourished through the blood and corpses of dead people, such as evoked in the following verses of Kalikapurana:

If a human being is sacrificed in the pitha, it is to be sacrificed in the cemetery, called Heruka, which has already been stated.

4. As the presiding deity of Nilacala, Kamakhya appears to have absorbed several attributes of Heruka, once associated with an ancient cremation ground on

the same hill. In Purāṇic descriptions, Heruka emerges as a fierce and bloodthirsty figure, craving flesh and severed heads, resembling a *bhūta*. Karel van Kooij characterizes such deities as belonging to non-Aryan folk traditions in which bloody rites were customary, especially as Vedic sacrificial systems declined.

5. The Assamese Tantric Kingship and the Supernatural Powers

The relationship between Nīlācala–Kamakhya and Assamese kingship is deeply embedded in the myth of Naraka, from whom all early medieval dynasties of Kāmarūpa claimed descent. By tracing their lineage to Naraka—son of Viṣṇu and Pṛthvī—the rulers connected themselves not only to divine authority but also to the ambivalent circumstances of his birth. Naraka was conceived when Pṛthvī was in her menstrual state, symbolically linking kingship to menstrual blood, a substance regarded in Brahmanical discourse as both impure and power-laden.

Exogamous customs among matrilineal communities of Assam would have facilitated such alliances. Politically, this *saṃkara-jāti* (mixed lineage) identity may have strengthened royal legitimacy in a region characterized by ethnic diversity. Religiously, it encouraged the flourishing of heterodox Śākta-Tantric traditions that resonated with local ritual cultures.

It would be reductive, however, to attribute all Tantric developments to tribal substrata. Christian Wedemeyer has cautioned against such sweeping assumptions, noting the absence of early medieval tribal textual sources. In fact, the lack of tribal records regarding their early medieval uses and customs cannot be taken as proof to show that the tribal people did not have such uses and customs. As David V. Zou pointed out:

traces of past survive in diverse linguistic and ideological forms, and local people themselves add a new dimension to custom when they creatively appropriate and translate their historical heritage of headhunting into an evocative metaphor of modern practices.

Śākta-Tantra cannot be uniformly characterized as a purely tribal or non-Aryan religious phenomenon, for it was never a monolithic system. In the Assamese context, it is difficult to sustain the argument of a purely “orthogenetic” evolution of proto-Śākta ideology within Brahmanical orthodoxy alone. While

northeastern India gradually absorbed Indo-Aryan religious and cultural currents, the region had long been shaped by matrilineal tribal societies grounded in agriculture, ancestral cults, and the veneration of sexual symbols. These indigenous traditions significantly informed the evolving religious landscape.

6. The Kings and the Magical Menstrual Blood

According to Purāṇic tradition, Naraka's refusal to allow the sage Vasiṣṭha to enter the shrine of Kamakhya marked his transformation into the guardian of Nilācala and its menstruating goddess. In this narrative, Assamese kingship assumed the role of principal devotee and protector of the Goddess. The king stood as the privileged intermediary: by performing prescribed blood rituals, he received supernatural empowerment from Kamakhya, and he alone determined who might access the sanctum.

The Kalikapurana interprets this sacred water as a supreme elixir issuing from the Goddess's symbolic womb. The ritual consumption of this fluid may have influenced later Tantric descriptions of *rājapāna*—the rite involving intimate contact with the female sexual organ as a means to obtain siddhis, particularly within Kaula traditions.

The Kalikapurāṇa's treatment of menstrual blood remains complex and cannot be reduced to notions of impurity alone. While the extant recension dates between the ninth and eleventh centuries, scholars have speculated about earlier, now-lost versions. According to Sylvia Wendt, the Kalikapurana is divided into three distinct sections:

1. A mythological section, which "includes a number of myths of different levels of narration;
2. ritualistic section that includes "a number of hymns, descriptions of rituals, of mantras, mudras etc.";
3. A geographical section that describes "sacred places, hills and rivers," including "the story of the Brahmaputra connected with that of Parasurama/Renuka and some dynastical chapters are told".

In the mythological section there are no references to the Tantric ritual praxis, although there is a contradictory position on the anti-Vedic elements, such as the menstrual blood. Additionally, throughout the ritualistic section there are many Tantric references, showing a connection between the text

compiler(s) and the Tantric developments of the cult, such as the Yogini Kaula.

Most scholarly studies have considered sakta-tantra systems as a vehicle to spread religious and political ideas, while the Tantric king was considered either as a Tantric specialist or as a non-specialist involved with Tantric practices. Hugh Urban observes:

Hindu Śakta Tantra has often been closely related to kingship and political rule in various periods of South Asian history. For śakti is not simply a spiritual or transcendent sort of metaphysical energy; it is also the material power that flows through the social body and the state as well as the physical body and the cosmos.

7. The Assamese king was symbolically conceived as the bridegroom of the Earth, united with her potent and often dangerous energy. Within the Tantric framework, this union enabled the ruler to channel the volatile forces inherent in sovereignty—rule, warfare, and sanctioned violence. He alone possessed the authority to permit the most extreme form of blood sacrifice, including human offerings.

8. Conclusions

Textual sources and ritual practices indicate that early medieval kingship in Kāmarūpa developed through an osmotic process of cross-cultural interaction. Political authority emerged from sustained exchanges among diverse socio-cultural, ethno-linguistic, and religious communities. Within this pluralistic environment, the compiler of the Kalikapurana constructed a legitimizing mythology around Naraka, presenting him as the first Hindu ruler of Kāmarūpa and the foundational ancestor of subsequent dynasties.

Although the precise origin of the yoni symbol remains uncertain, its association with blood sacrifice, ritual consumption of sexual fluids, and *śmaśāna* symbolism suggests significant cross-cultural influences. Whether locally rooted or shaped by broader currents, the cult appears to have been molded through dialogue between tribal traditions and heterodox Śakta-Tantric theology. In this way, Assamese kingship was profoundly shaped by religious forms born of continuous cultural negotiation and synthesis. Hence, tribal customs were partially transformed and integrated within Hindu cultural and religious folds, resulting in the Hindu sakta-tantra cult of Kamakhya. As Hermann Kulke pointed out:

. . . one of the main problems during this period was the relationship of the Hindu raj as—often themselves descendants of tribal chiefs—with the tribes which surrounded the insulated nuclear areas. On the one hand, the raj as depended on their support for the security of the internal communication and borders.

Consequently, kingship evolved through the incorporation and negotiation of cultural contradictions, forging a state grounded in cross-cultural synthesis. The ruler emerged as the sole figure capable of regulating the potent forces embedded in heterodox ritual practices—especially those involving blood, sexuality, and cremation-ground symbolism, which Vedic orthodoxy deemed impure or taboo. As hero, descendant of Viṣṇu, or ambivalent heir to Naraka's legacy, the king embodied and controlled these dangerous powers, transforming ritual transgression into a foundation of sovereign legitimacy.

References

- Allen, Nicholas J. 2007. Siva and the Indo-European Ideology: On Line of Thought. *International Journal of Hindu Studies* 11: 191–207.
- Anand, Ankita. 2017. Doctoring Evil: The Making and Hunting of Witches in Assam. India Resists. March 3. Available online: <http://www.indiaresists.com/doctoring-evil-making-hunting-witches-assam>
- Babb, Lawrence A. 1975. The Divine Hierarchy: Popular Hinduism in Central India. New York and London: Columbia University Press.
- Chandra Prabodh Bagchi, ed. 1986. Kaulajñānānirṇaya of the School of Matsyendranatha. Translated by Michael Magee. Varanasi: Prachya Prakashan. First published 1948.
- Barua, Archana. 1996. The Tradition of Religion in Assam: A Philosophical Study. Calcutta: Punthi Pustak.
- B.D. Basu, ed. 1916. The Matsya Puranam. Allahabad: The Panini Office, vol. 1.
- Shripad K. Belvalkar, ed. 1954. The Santiparvan. The Twelfth Book of the Mahabharata. Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, vol. 2.
- Benton, Catherine. 2005. God of Desire: Tales of Kamadeva in Sanskrit Story Literature. Albany: Suny Press.

Different Aspects Affecting the Growth and Development of Autistic Children Under Three Years of Age: A Multidimensional Analysis of Biological, Cognitive, Educational, and Environmental Factors

Cristeena Sujith - Research Scholar

Dr. Gaurav Singh - Associate Professor

School of Art, Humanities & Social Science, Nirwan University, Jaipur, Rajasthan

Abstract

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental condition that emerges during early childhood and significantly influences a child's social, cognitive, communicative, and behavioural development. The first three years of life represent a critical period for brain development, making early identification and intervention essential for improving developmental outcomes. The growth and development of autistic children are influenced by multiple interconnected factors, including biological predispositions, cognitive abilities, family environment, parental involvement, socioeconomic conditions, nutrition, healthcare access, and early educational interventions.

This study aims to examine the various aspects affecting the growth and development of autistic

children under three years of age. The research adopts a multidimensional perspective to understand how these factors interact and influence developmental trajectories. Particular emphasis is placed on early intervention programs, family support systems, sensory experiences, communication development, and environmental influences. The findings of the study are expected to contribute to the development of effective educational strategies, family-centered interventions, and policy recommendations that support optimal growth and development.

Keyword: Autism Spectrum Disorder (ASD), Early Childhood Development, Cognitive Development, Social Communication, Language Development, Behavioural Development.

INTRODUCTION

The early years of life are universally recognized as a period of rapid physical, cognitive, emotional, and social development. During the first three years, neural connections are formed at an extraordinary rate, laying the foundation for future learning, behaviour, and overall well-being. For children diagnosed with Autism Spectrum Disorder (ASD), this developmental period is particularly significant because early experiences can substantially influence long-term outcomes.

Autism Spectrum Disorder is characterized by differences in social communication, restricted interests, repetitive behaviors, and sensory processing patterns. Although the exact causes of autism remain complex and multifactorial, research suggests that

genetic, neurological, environmental, and developmental factors contribute to its manifestation. Children with autism often exhibit developmental differences before the age of three, including delayed speech and language development, reduced social responsiveness, sensory sensitivities, and atypical play behaviors.

Growth and development in autistic children are influenced by numerous factors. Biological factors such as genetics, prenatal health, birth complications, and neurological development play an important role. Cognitive factors, including attention, memory, sensory integration, and learning styles, also shape developmental progress. Additionally, environmental influences such as family relationships, parental involvement, socioeconomic status, healthcare

accessibility, nutrition, and early intervention services significantly affect developmental outcomes.

Recent research emphasizes that early diagnosis and timely intervention can improve communication skills, social interaction, adaptive behaviour, and cognitive functioning. Consequently, understanding the various aspects affecting the growth and development of autistic children under three years of age is essential for educators, healthcare professionals, policymakers, and families. The present study seeks to explore these factors comprehensively and identify strategies that can promote positive developmental outcomes during this critical stage of life.

Major Aspects Affecting Growth of Autistic Children Under 3 Years

1. Biological Factors

Biological factors include genetic predisposition, prenatal health conditions, neurological development, birth complications, and brain functioning, all of which influence the developmental trajectory of children with Autism Spectrum Disorder.

- a) Genetic predisposition
- b) Prenatal and perinatal health
- c) Neurological development
- d) Birth complications

2. Cognitive Factors

Cognitive factors refer to the child's abilities related to attention, memory, learning, problem-solving, sensory processing, and information retention, which significantly affect overall development and learning outcomes.

- a) Attention and concentration
- b) Memory development
- c) Sensory processing abilities
- d) Learning and information processing

3. Communication Factors

Communication factors encompass speech development, language acquisition, non-verbal communication, joint attention, and social interaction skills that are essential for effective engagement with others.

- a) Speech and language development
- b) Joint attention

- c) Non-verbal communication
- d) Early social interaction skills

4. Family Factors

Family factors include parental involvement, emotional support, parenting styles, family relationships, and home learning environments that contribute to the child's social, emotional, and cognitive growth.

- a) Parental involvement
- b) Parenting practices
- c) Family support systems
- d) Emotional environment at home

5. Environmental Factors

Environmental factors consist of the physical surroundings, sensory experiences, educational settings, social opportunities, and community resources that influence a child's developmental progress.

- a) Physical surroundings
- b) Sensory stimulation
- c) Access to learning materials
- d) Social opportunities

6. Health and Nutritional Factors

Health and nutritional factors involve proper nutrition, sleep quality, physical health, medical care, and overall well-being, which are critical for healthy brain development and growth.

- a) Balanced nutrition
- b) Sleep quality
- c) Medical care
- d) Physical activity

7. Early Intervention Factors

Early intervention factors include timely diagnosis, therapy services, specialized educational programs, and multidisciplinary support systems that help improve developmental outcomes during the critical early years of life.

- a) Early diagnosis
- b) Therapy services
- c) Educational support
- d) Multidisciplinary intervention programs

CONCLUSION

The growth and development of autistic children under three years of age are influenced by a complex interaction of biological, cognitive, communicative, familial, environmental, and educational factors. Since the first three years represent a critical period of brain development, timely identification and intervention are essential for maximizing developmental potential. Research consistently demonstrates that supportive family environments, effective early intervention programs, appropriate healthcare services, and enriched learning experiences contribute significantly to positive developmental outcomes.

Understanding these multiple dimensions is crucial for developing comprehensive support systems for autistic children and their families. Future educational and healthcare policies should prioritize early screening, family-centered intervention programs, and inclusive developmental services to ensure that young children with autism receive the support necessary for optimal growth and lifelong success.

REFERENCE

- a) American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5th ed., text rev.). Washington, DC.
- b) Catherine Lord, Elsabbagh, M., Baird, G., & Veenstra-VanderWeele, J. (2018). Autism spectrum disorder. *The Lancet*, 392(10146), 508–520.
- c) Sally J. Rogers & Dawson, G. (2010). *Early Start Denver Model for Young Children with Autism*. Guilford Press.
- d) World Health Organization. (2023). *Autism Spectrum Disorders*.
- e) Temple Grandin & Panek, R. (2013). *The Autistic Brain: Thinking Across the Spectrum*. Houghton Mifflin Harcourt.
- f) Uta Frith. (2003). *Autism: Explaining the Enigma* (2nd ed.). Blackwell Publishing.

Declaration Form

Title : PANACEA International Research Journal
ISSN 2347-369X

Language : English and Hindi

Periodicity : Quarterly and Special Issues

Publisher : PANACEA Research Foundation

Nationality : Indian

Address : 'Shanti-Kuteer' 81, Vishvesariya Vistar,
Triveni Nagar, Gopalpura Bypass,
Jaipur-302018; panaceairj@gmail.com;
+91-141-6888889; Mobile: +91-7742321377

Editor's name (Honorary) : Dr G L Sharma

Owner's name : Mrs Pushpa Sharma

I Pushpa Sharma hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge.

– Mrs. Pushpa Sharma

Copyright © 2013, PANACEA Research Foundation, Jaipur

No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise or stored in a database or retrieval system without the prior written permission of the publishers

Cover Design:- **Chetan Kumar**

Printed at:- **S R Print**

Computer Designer:- **Chetan Kumar**

www.journalpanacea.in

ISSN 2347- 369X



(A Quarterly Bilingual Inter-disciplinary Journal)

Published by - PANACEA Research Foundation

Subscription Form

Managing Editor,

Dear Madam,

I would like to be an Annual Member / Life Member / Institutional Member of the PANACEA INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL (ISSN 2347-369X) and therefore remit Rs. 4100/ 21000/- by cash / RTGS / cheque (local) / draft /Money Order (please tick the appropriate) as my membership or subscription fee. I have read all the Rules and Regulations of the PIRJ and agree to abide by them. Yours Sincerely

Signature

Name:.....

Designation:.....

Address:.....

Mobile:..... E-mail :.....

Enclosed Cheque/DD/Ref. No. _____ date: _____,

Amount: _____

Bank & Branch: _____

Subscription Rates

Single Issue 1100/-

One Year (Annual Subscription) 4100/-

Life Membership for Institutions 21000/-

Every contributor author has to subscribe for one year subscription.

For Subscription send crossed Demand Draft/Cheque in favour of **PANACEA RESEARCH FOUNDATION, Jaipur** and send it to-

“Shanti-Kuteer” 81, Vishvesariya Vistar, Triveni Nagar, Jaipur-302018

panaceairj@gmail.com ; +91- 9829264747

The amount may be deposited in the **Current Account no.535501010032608,**

Union Bank of India, Branch- Vishvesariya Nagar, Jaipur, IFSC Code-UBIN0553557.

www.journalpanacea.in

ISSN 2347- 369X



(A Quarterly Bilingual Inter-disciplinary Journal)

Published by - PANACEA Research Foundation

Copyright Declaration Form

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

I/We (Name).....
S/o....., Date of Birth:
College/University/Institution:-.....
Address:.....
Mobile:.....,E-mail.....
do hereby declare that the literary/research work entitled (Title of Paper):
.....
.....

.....
is authored by me/us for and on behalf of PANACEA RESEARCH FOUNDATION, Publisher-
PANACEA INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL, ISSN 2347-369X, Jaipur.

I/We hereby assign all my rights subsisting in the said literary work conferred upon me
as per the provision of The Copyright Act, 1956 in favour of PANACEA RESEARCH
FOUNDATION, in perpetuity, for the entire term of copyright, for both the national and
international territorial extent.

The PANACEA RESEARCH FOUNDATION is entitled to seek revision, up-gradation
etc. of the said literary work and shall have all the rights in the same. The publisher
entitled to seek copyright registration of the said literary work in their favour, in the
records of the registrar of copyrights.

Signature

I/We hereby declared that my/our above research paper is originally written by me/us
and all information is true. I/we will fully responsible for this research paper.

Signature

Name: _____



I.Q.A.C

Mahatma Gandhi T.T. College Mahawa Dausa, Rajasthan

With The Collaboration

Mahatma Gandhi College, Mahwa, Dausa

&

M.G. College, Weir

National Seminar

On

Skill Development, Youth Empowerment, and Nation Building in India

11 - April - 2026

Website-<http://www.mgcollegemahwa.com>

Email-mahatmagandhipgcollege2026@gmail.com

Mobile No.: 9414248140, 9829403099

Off. PANCEA RESEARCH FOUNDATION

"Shanti-Kuteer" 81, Vishvesariya Vistar, Triveni Nagar, Jaipur-302018,
panaceairj@gmail.com, M. 9829264747